देशप्राण
स्वतंत्र हिन्दी दैनिक
शुक्रवार
रांची, 5 अप्रैल, 2024

बच्चों को तनाव देने वाली शिक्षा पद्धति

आखिर क्यों कहा जा रहा है कि शिक्षा के नाम पर यह पीढ़ी जहर प्राप्त कर रही है? इसके पीछे चार कारण हैं। प्रथम, परीक्षाओं को अत्यधिक महत्व देने से सीखने का आनंद जाता रहा। अर्थपूर्ण ढंग से जुड़े रहकर शिक्षा पाने वाली संस्कृति को दरकार होती है तनाव मुक्त वातावरण की, ताकि कोई छात्र अपने निराले स्वभाव और कौशल के मुताबिक आत्म-अन्वेषण और आंतरिक उन्नति कर पाए। अंकों के आधार पर आकलन, सदा अच्छे नंबर लाना और किसी के ज्ञान का तोल भौतिकी, गणित या अंग्रेजी में पाए अंकों से करने का बेलगाम दबाव, वह भी हफ्ते दर हफ्ते, महीना दर महीना और साल दर साल परीक्षाओं के जरिए या फिर अत्यधिक जटिल होते जा रहे अभ्यास, परीक्षा प्रपत्रों को हल करने की शृंखला ने बच्चे की सीखने की नैसर्गिक लय को भंग कर डाला है। साथ ही हद दर्जे का तनाव, भय और मानसिक संत्रास बना डाला है। दूसरी बात यह कि इसने सामाजिक संपर्क की आवश्यकता को भी बिगाड़ दिया है, संयुक्त एवं आपसी संवाद से सीखने की भावना खत्म होती जा रही है। इसकी बजाय, अति-प्रतिस्पर्धा का वायरस, दूसरे की सफलता से जलन, एकाकीपन और स्वार्थीपन युवा छात्रों के मानस में घर करता जा रहा है। शिक्षा की ऐसी संस्कृति की वजह से हमारे बच्चों के लिए सामाजिक मेल-मिलाप से सीखना लगातार मुश्किल बन रहा है जबकि किसी स्वस्थ और लोकतांत्रिक समाज के लिए खुद को बनाए रखने वास्ते जरूरी है विनम्रता, सहृदयता और संवाद के जरिए संयुक्त उत्थान की प्राप्ति, सहयोग और आपसी देखभाल वाली संस्कृति। तीसरी बात यह है कि चूंकि वर्तमान में सफलता गाथाओं के प्रति आसक्ति हावी है। गौर करें कि कैसे नीट या जेईई परीक्षाओं में टॉप करने वालों को अंधाधुंध प्रचार के जरिए रातों-रात पौराणिक कथाओं के विजेता नायकों सरीखा स्टारडम प्रदान कर दिया जाता है। इन 'चमकीले सितारों' के बीच यह हरकत जाने-अनजाने में विफलता की गाथाएं भी पैदा करती जाती है। जी हां, हर साल, हम हजारों-हजार युवाओं को यह मानने को मजबूर करते हैं कि वे किसी काम के नहीं क्योंकि वे फलां-फलां परीक्षा नहीं निकाल पाए, इसलिए वे डॉक्टर या इंजीनियर बनने लायक नहीं हैं, हम उन्हें विफलता का कलंक, कमजोर पड़े आत्म-सम्मान, जख्मी स्वः और आत्महत्या करने की सोच के साथ जीने को मजबूर कर रहे हैं।

बिहार की राजनीति का 'चिराग'

ललित गर्ग

खुद को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हनुमान बताने वाले युवा नेता चिराग पासवान इन दिनों बिहार की राजनीति में लाइमलाइट में हैं। राजनीतिक कौशल एवं प्रभावी रणनीति के तहत तेजी से अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूती देते हुए बिहार की राजनीति का 'चिराग' संभावना का वाहक बन रहा है। चिराग पासवान सक्षम जनप्रतिनिधि के साथ-साथ मौलिक सोच एवं संवेदनाओं के प्रतीक हैं। उन्हें सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी होकर प्रासंगिक एवं अप्रासंगिक के बीच भेदरेखा बनाने एवं अपनी उपस्थिति का अहसास कराने का छोटी उम्र में बड़ा अनुभव है जो भारतीय राजनीति के लिये शुभता का सूचक है। लोकतंत्र का सच्चा जन-प्रतिनिधि वही है जो अपनी जाति, वर्ग और समाज को मजबूत करने के साथ देश को मजबूत करें। 'बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट' की लड़ाई लड़ने वाले चिराग 14 करोड़ बिहारियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये प्रतिबद्ध है।

चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं । वे दलितों के शीर्ष नेता एवं (लोजपा) के संस्थापक रामविलास पासवान के पुत्र हैं। चिराग ने न केवल बिहार की राजनीति में बल्कि समूची देश की राजनीति में युवा संभावनाओं को उजागर करने की खनक पैदा की है। चिराग वोट की राजनीति के साथ-साथ सामाजिक उत्थान की बात भी करते हैं। वे रोजगार के नाम से एक एनजीओ भी चलाते हैं। 'चिराग का रोजगार' एक मौलिक सोच की निष्पत्ति है और चिराग भारत की राजनीति में एक मौलिक सोच के प्रतीक नेता के रूप में उभर रहे हैं। संसार उसी को प्रणाम करता है जो भीड़ में से अपना सिर ऊंचा उठाने की हिम्मत करता है, जो अपने अस्तित्व का भान कराता है। मौलिकता की आज जितनी कीमत है, उतनी ही सदैव रही है।

आगामी लोकसभा चुनाव 2024 चिराग का सशक्त एवं उम्मीदभरा राजनीतिक भविष्य उजागर करते हुए बिहार के शीर्ष नेतृत्व की ओर अग्रसर करे तो कोई आश्चर्य नहीं। इस बात के संकेत इनदिनों की बिहार की राजनीति गतिविधियों से मिलने लगे हैं। गतदिनों भाजपा मुख्यालय से विनोद तावड़े ने बिहार के एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का अपना फॉमूर्ला सार्वजनिक किया, जिसमें भाजपा को 17 सीटें, जदयू को 16 सीटें तो चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा (रामविलास) के खाते में 5 सीटें गईं। वहीं उपेंद्र कुशवाह और जीतनराम मांझी की पार्टी को एक-एक सीट दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास की एक बड़ी तस्वीर सामने आई, जिसमें नीतीश चिराग के कंधे पर हाथ रखे आशीर्वाद की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह का एक चित्र पहले चर्चित हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी चिराग की पीठ थपथपाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

भारतीय राजनीति में युवाओं की भागीदारी को लेकर अक्सर बड़ी-बड़ी बातें हर किसी मंच से होती रहती हैं लेकिन कोई दल उन्हें प्रतिनिधित्व का मौका नहीं देता क्योंकि उनकी नजर में युवा वोट भर हैं। राजनीतिक दल उनका इस्तेमाल भीड़ और ट्रौलिंग के लिए करते रहते हैं। हालांकि इस मिथक को चिराग ने तोड़ा, 2014 के लोकसभा चुनाव में जमुई सीट पर 80 हजार से ज्यादा मतों से विजयी हुए थे तो एक ही संसदीय दौर में उन्होंने जनता का विश्वास इस कद्र जीता कि 2019 के चुनाव में चिराग ने 5 लाख से ज्यादा वोट हासिल करते हुए लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की।

चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं । वे दलितों के शीर्ष नेता एवं (लोजपा) के संस्थापक रामविलास पासवान के पुत्र हैं। चिराग ने न केवल बिहार की राजनीति में बल्कि समूची देश की राजनीति में युवा संभावनाओं को उजागर करने की खनक पैदा की है। चिराग वोट की राजनीति के साथ-साथ सामाजिक उत्थान की बात भी करते हैं। वे रोजगार के नाम से एक एनजीओ भी चलाते हैं। ह्यचिराग का रोजगारह्ण एक मौलिक सोच की निष्पत्ति है और चिराग भारत की राजनीति में एक मौलिक सोच के प्रतीक नेता के रूप में उभर रहे हैं। संसार उसी को प्रणाम करता है जो भीड़ में से अपना सिर ऊंचा उठाने की हिम्मत करता है, जो अपने अस्तित्व का भान कराता है। मौलिकता की आज जितनी कीमत है, उतनी ही सदैव रही है। जिस व्यक्ति के पास अपना कोई मौलिक विचार या कार्यक्रम है तो संसार उसके लिए रास्ता छोड़कर एक तरफ हट जाता है और उसे आगे बढ़ने देता है। मौलिक विचार तथा काम के नये तरीके खोज निकालने वाला व्यक्ति ही समाज एवं राष्ट्र की बड़ी रचनात्मक शक्ति होता है अन्यथा ऐसे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है जो पीछे-पीछे चलना चाहते हैं और चाहते हैं कि सोचने का काम कोई और ही करे।

चिराग ने भारत की राजनीति में युवा पीढ़ी के लिए कुछ नया सोचा है, कुछ मौलिक सोचा है, तो सफलता निश्चित है। वे इसी सोच से प्रदेश की राजनीति से केन्द्र की राजनीति की ओर अग्रसर होकर सफल नेतृत्व देने में सक्षम साबित होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोजपा अब पूरी तरह युवाओं के हाथ में है। चिराग युवा हैं, सक्षम है, प्रखर वक्ता है, कुशल संगठनकार एवं प्रबन्धक हैं और विगत में उन्होंने अनेक अवसरों पर अपनी इन क्षमताओं के साथ-साथ निर्णायकता साबित की है। कई मौकों पर यह बात सामने आई है कि बिहार के साथ-साथ केंद्रीय राजनीति के दांव-पेच और समीकरणों को भी वह अच्छी तरह जानने-समझने लगे हैं। हालांकि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती दलित राजनीति के अगले ध्वजवाहक बनने और अपने लक्षित मतदाता समूह में पिता जैसी स्वीकार्यता पाने की होगी। चिराग नई लकीर खींचने में पारंगत है, वे अपने पिता की प्रतिछाया ही न बनकर कुछ नये प्रतिमान स्थापित करेंगे, राजनीति की नई परिभाषाएं गढ़ेंगे। क्योंकि वे विपरीत स्थितियों में सामंजस्य स्थापित करके भरोसा और विश्वास का वातावरण निर्मित करने में दक्ष है।

युवापीढ़ी और उनके सपनों का मूर्च्छित होना और उनमें निराशा का वातावरण निर्मित होना- एक सबल एवं सशक्त राष्ट्र के लिये एक बड़ी चुनौती है। चिराग ने यह अनुभव किया, यह उनकी सकारात्मक राजनीति एवं मानवतावादी सोच का ही परिणाम है। चिराग इस मामले में अन्य क्षत्रप या नेता पुत्रों से थोड़ा अलग इसलिए भी हैं कि उनका नजरिया और अंदाज भविष्योन्मुखी और विकासवादी प्रतीत होता है। यही कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिराग में राजनीतिक संभावनाओं को गहराई से समझा है। इन सबके बावजूद यक्ष प्रश्न यह है कि क्या चिराग अपने पिता की दलित राजनीति की विरासत को कोई नया आयाम दे पाएंगे। या फिर वह इस विरासत से इतर मुख्यधारा की राजनीति में अपनी काबिलियत दिखाएंगे। चिराग राजनीति की बारीकियों को समझने में माहिर है। राजनीति का मौसम विज्ञान समझने में चिराग ने मोदी की आंधी को भलीभांति भांप लिया है और वह किसी संशय में नहीं है। अपने मतदाता समूह में उनकी मजबूत स्वीकार्यता भी है। हाल के समय में भारतीय राजनीति में नई पीढ़ी के कई नेता पुत्रों ने अभी तक कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं जगाई है। चाहे राहुल गांधी हों या तेजस्वी यादव। इन नामों की तुलना में चिराग के पास कोई बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत तो नहीं है, लेकिन वे अपने होने का अहसास, कुछ अनूठा करने का एवं जनता के दिलों को जीतने का हूनर साबित किया है।

आत्मसमर्पण के खिलाफ लड़ने वाले संपादक

प्रो.(डॉ.) संजय द्विवेदी

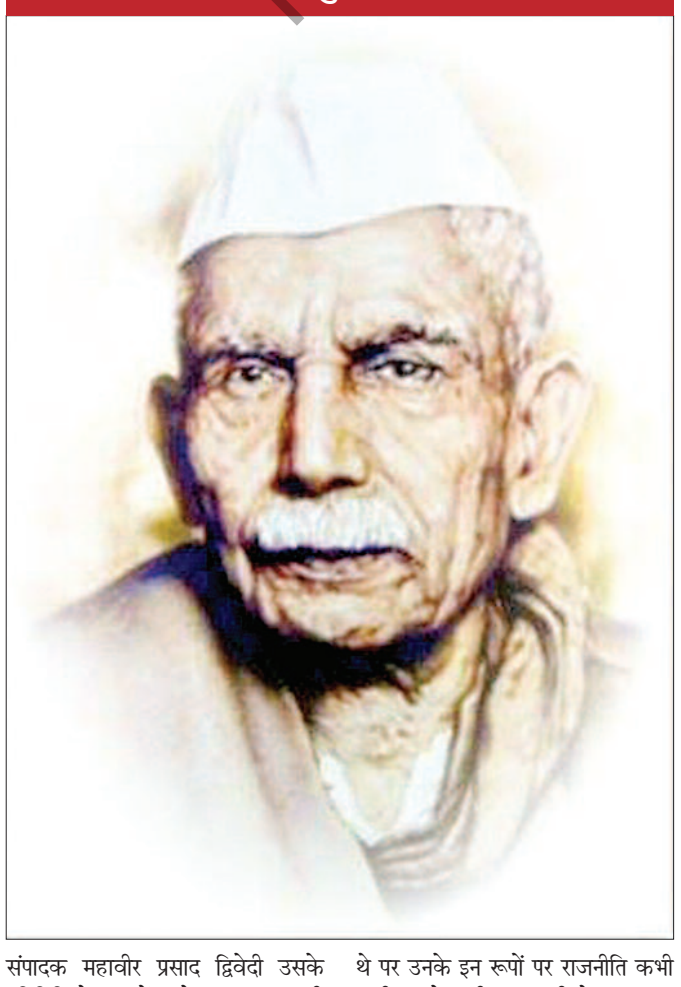

(प्रो. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल)

पं.माखनलाल लाल चतुर्वेदी की जयंती पर विशेष

'कर्मवीर' के संपादक कैसे संपादक थे, इसे बताने के लिए उन्होंने कहा कि झ हम फक्कड़ सपनों के स्वर्गों को लुटाने निकले हैं। किसी की फरमाइश पर जूते बनाने वाले चर्मकार नहीं हैं हम। यह निर्भीकता ही उनकी पत्रकारिता की भावभूमि का निर्माण करती थी। स्वाधीनता आंदोलन की आँच को तेज करने में उनका कर्मवीर अग्रणी बना। कर्मवीर की परिधि व्यापक थी। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विषयों पर समान अधिकार से चलने वाली संपादक की लेखनी हिंदी को सोच की भाषा देने वाली तथा युग चिंतन को भविष्य के परिप्रेक्ष्य में व्यक्त करने वाली थी। कर्मवीर जिस भाषा में अंग्रेजी राजसत्ता से संवाद कर रहा था, उसे देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतीय जनमानस में आजादी पाने की ललक कितनी तेज थी। स्वाधीनता आंदोलन में अपने प्रखर हस्तक्षेप के अलावा कर्मवीर ने जीवन के विविध पक्षों को भी पर्याप्त महत्व दिया। आए दिन होने वाली घटनाओं को मापने- जोखने एवं उनसे रास्ता निकालने की दिव्य दृष्टि भी कर्मवीर के संपादक के पास थी। अपनी पत्रकारिता के माध्यम से राजनीति के अलावा साहित्य कला और संस्कृति को भी उन्होंने महत्व दिया। साहित्यिक पत्रों के संदर्भ में उनकी समझदारी विलक्षण थी वो कहते हैं- हिंदी भाषा का मासिक साहित्य बेढंगें और बीते जमाने की चाल चल रहा है।

पं. माखनलाल चतुर्वेदी और उनकी संपूर्ण जीवन यात्रा, आत्मसमर्पण के खिलाफ लड़ने वाले संपादक की यात्रा है। रचना और संघर्ष की भावभूमि पर खड़ी हुई उनकी लेखनी में अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का जज्बा न चुका, न कम हुआ। वस्तुतः वे एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहे थे और कोई मोर्चा ऐसा न था, जहां उन्होंने अपनी छाप न छोड़ी हो। सही मायने में ह्यकर्मवीरह्ण के संपादक ने अपने पत्र के नाम को सार्थक किया और माखनलाल जी स्वयं कर्मवीर बन गए। 4 अप्रैल, 1889 को होशंगाबाद(मप्र) के बाबई जिले में जन्में माखनलालजी ने जब पत्रकारिता शुरू की तो सारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव देखा जा रहा था। राष्ट्रीयता एवं समाज सुधार की चचाएं और फिरंगियों को देश बदर करने की भावनाएं बलवती थीं। इसी के साथ महात्मा गांधी जैसी तेजस्वी विभूति के आगमन ने सारे आंदोलन को एक नई ऊर्जा से भर दिया। दादा माखनलाल जी भी उन्हीं गांधी भक्तों की टोली में शामिल हो गए। गांधी के जीवन दर्शन से अनुप्राणित दादा ने रचना और कर्म के स्तर पर जिस तेजी के साथ राष्ट्रीय आंदोलन को ऊर्जा एवं गति दी वह महत्व का विषय है।

हालांकि इस दौर में राजनीतिक एवं सामाजिक पत्रकारिता के समानांतर साहित्यिक पत्रकारिता का एक दौर भी चल रहा था। सरस्वती और उसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी उसके प्रतिनिधि के रूप में उभरे। माखनलाल जी ने भी 1913 में प्रभा नाम की एक उच्च कोटि की साहित्यिक पत्रिका के माध्यम से इस क्षेत्र में सार्थक हस्तक्षेप किया। लोगों को झकझोरने एवं जगाने वाली रचनाओं के प्रकाशन के माध्यम से प्रभा शीघ्र ही हिंदी जगत का एक जरूरी नाम बन गयी। दादा की 56 सालों की ओजपूर्ण पत्रकारिता की यात्रा में प्रताप, प्रभा व कर्मवीर उनके विभिन्न पड़ाव रहे। साथ ही उनकी राजनीतिक वरीयता भी बहुत उंची थी। वे बड़े कवि थे, पत्रकार थे पर उनके इन रूपों पर राजनीति कभी हावी न हो पायी। आजादी के बाद 30 अप्रैल, 1968 तक वे जीवित रहे पर सत्ता का लोभ उन्हें स्पर्श भी नहीं कर पाया। इतना ही नहीं 1967 में भारतीय संसद द्वारा राजभाषा विधेयक पारित होने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति को वह पद्म भूषण का अलंकरण भी लौटा दिया जो उन्हें 1963 में दिया गया था। उनके मन में संघर्ष की ज्वाला हमेशा जलती रही। वे निरंतर समझौतों के खिलाफ लोगों में चेतना जगाते रहे। उन्होंने स्वयं लिखा है-

अमर राष्ट्र, उदंड राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र,
यह मेरी बोली
यह सुधार-समझौतों वाली मुझको
भाती नहीं ठिठोली।

माखनलाल जी सदैव असंतोष एवं मानवीय पीड़ा बोध को अपनी पत्रकारिता के माध्यम से स्वर देते रहे। पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई भी जंजीर उन्हें बांध नहीं पायी। उनकी लेखनी भद्रता एवं मयार्दा की तो कायल थी किंतु वे भय, संत्रास एवं बंधनों के खिलाफ थे।

'कर्मवीर' के संपादक कैसे संपादक थे, इसे बताने के लिए उन्होंने कहा कि झ हम फक्कड़ सपनों के स्वर्गों को लुटाने निकले हैं। किसी की फरमाइश पर जूते बनाने वाले चर्मकार नहीं हैं हम। यह निर्भीकता ही उनकी पत्रकारिता की भावभूमि का निर्माण करती थी। स्वाधीनता आंदोलन की आँच को तेज करने में उनका कर्मवीर अग्रणी बना। कर्मवीर की परिधि व्यापक थी। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विषयों पर समान अधिकार से चलने वाली संपादक की लेखनी हिंदी को सोच की भाषा देने वाली तथा युग चिंतन को भविष्य के परिप्रेक्ष्य में व्यक्त करने वाली थी। कर्मवीर जिस भाषा में अंग्रेजी राजसत्ता से संवाद कर रहा था, उसे देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतीय जनमानस में आजादी पाने की ललक कितनी तेज थी।

स्वाधीनता आंदोलन में अपने प्रखर हस्तक्षेप के अलावा कर्मवीर ने जीवन के विविध पक्षों को भी पर्याप्त महत्व दिया। आए दिन होने वाली घटनाओं को मापने- जोखने एवं उनसे रास्ता निकालने की दिव्य दृष्टि भी कर्मवीर के संपादक के पास थी। अपनी पत्रकारिता के माध्यम से राजनीति के अलावा साहित्य कला और संस्कृति को भी उन्होंने महत्व दिया। साहित्यिक पत्रों के संदर्भ में उनकी समझदारी विलक्षण थी वो कहते हैं- हिंदी भाषा का मासिक साहित्य बेढगें और बीते जमाने की चाल चल रहा है। यहां बरसाती कीड़ों की तरह पत्र पैदा होते हैं। फिर भी यह आश्चर्य नहीं कि वे मर क्यों जाते हैं। यूरोप में हर पत्र अपनी एक निश्चित नीति रखता है। हिंदी वालों को इस मार्ग में रीति की गंध नहीं लगी। यह टिप्पणी आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है।

अपने लंबे पत्रकारीय जीवन के माध्यम से दादा ने नई पीढ़ी को रचना और संघर्ष का जो पाठ पढ़ाया वह आज भी हतप्रभ कर देने वाला है। कम ही लोग जानते होंगे कि दादा को इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उनके संपादकीय कार्यालय यानी घर पर तिरसठ बार छापे पड़े, तलाशियां हुयीं। 12 बार वे जेल गए। कर्मवीर को अथार्भाव में कई बार बंद होना पड़ा। लेखक से लेकर प्रूफ रीडर तक सबका कार्य वे स्वयं कर लेते थे। इन अर्थों में दादा विलक्षण स्वावलंबी थे।

कर्मवीर एक ऐसा पत्र था जिसके संपादक आजादी के आंदोलन के अग्रणी नेता थे। इसलिए राष्ट्र प्रथम उसकी वैचारिक नीति भी रही। आजादी के समय देश के बंटवारे का दंश पूरे देशवासियों के मनों को मथ रहा था। इस भावना को व्यक्त करते हुए ह्यकर्मवीरह्ण के 15 अगस्त,1947 को माखनलाल जी लिखते हैं- यह 15 अगस्त है, भारत दो टुकड़े हैं, किंतु आजाद है, क्या पूर्ण आजाद है...? यह जवाहर और जयप्रकाश जानें कि भारत पूर्ण स्वतंत्र होगा या उपनिवेश बनकर रह जाएगा। नोआखली को जाने वाले यात्री गांधी से गांधी से देश ह्यस्वागतह्ण नहीं कह सकता, क्योंकि देश खंडित है। बिदा भी नहीं कह सकते क्योंकि अखंड भारत और पूर्ण स्वातंत्र्य का स्वप्न अभी अपनी मुठ्ठी में लिए वह चला जा रहा है।

यह 15 अगस्त है। इसी तरह पत्रकारिता उनके लिए राष्ट्र सेवा और समाज के जागरण का ही एक माध्यम थी। कर्मवीर के माध्यम से वे यही कर रहे थे। भरतपुर के संपादक सम्मेलन में वे पत्रकारिता जगत का आह्वान करते हुए कहते हैं-ह्ययदि समाचार पत्र संसार की एक बड़ी ताकत है तो उसके सिर जोखिम भी कम नहीं है। पर्वत की जो शिखरें हिम से चमकती हैं और राष्ट्रीय रक्षा की महान दीवार बनती हैं, उन्हें ऊंची होना पड़ता है। जगत में समाचार पत्र यदि बड़प्पन पाए हुए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी भारी है।बिना जिम्मेदारी के बड़प्पन का मूल्य ही क्या है? कर्मवीर अपने समय का एक ऐसा पत्र बना जिसने समकालीन रचनाशीलता को बहुत प्रोत्साहित किया। तमाम उदीयमान लेखक इसके माध्यम से लेखन की दुनिया में आए।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

बढ़ा किराया, यात्री परेशान

रुपेश कुमार सिंह
संपादक
चौथी वाणी

एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर के बीच विस्तारा एयरलाइन के पायलटों के छुट्टी पर चले जाने से हवाई यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। पायलटों की कमी की वजह से फ्लाइट कैंसल हो रही या उड़ानों में देरी हो रही है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर इस पूरे मामले की जड़ क्या है? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को आखिरकार विस्तारा मामले में दखल देना ही पड़ा, जोकि सही भी है। एयरलाइन कंपनी को पायलटों की कमी के कारण बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द करनी पड़ रही हैं। ऐसे में DGCA ने कहा कि कंपनी फ्लाइट्स के कैंसल होने और देरी की जानकारी यात्रियों को डेली बेसिस पर दे। साथ ही, वह उन्हें रिफंड और हर्जाना भी दे।

यात्रियों पर बढ़ा बोझ : DGCA की यह पहल अच्छी है, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि यात्रियों की जो शिकायत थी, वे सारी दूर नहीं हुई हैं। अहम बात यह भी है कि यह मामला भले ही एक कंपनी में पायलटों की कमी से जुड़ा है, लेकिन इसका असर दूसरी एयरलाइंस की सेवाओं पर भी पड़ रहा है। बड़े पैमाने पर विस्तारा की उड़ानों के रद्द होने से फ्लाइट्स की संख्या कम हो गई है, जिससे हवाई टिकटों के दाम बढ़ गए हैं।

क्यों नाराज हैं पायलट : विस्तारा और एयर इंडिया, दोनों ही टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं, जिनका विलय हो रहा है। इसलिए विस्तारा के पायलट एक जैसे सैलरी स्ट्रक्चर की मांग कर रहे हैं। पायलटों की सैलरी में एक बड़ा हिस्सा उन्हें मिलने वाले भत्तों का होता है। एयर इंडिया के पायलटों का सैलरी स्ट्रक्चर ऐसा है, जिसमें 40 घंटों की उड़ान पर मिनिमम अश्योर्ड पे मिलता है। विस्तारा के पायलटों के लिए यह 70 घंटे है। टाटा ग्रुप ने विलय के लिए एयर इंडिया के सैलरी स्ट्रक्चर को मंजूरी दी है। इसके चलते विस्तारा के पायलटों का वेतन घट गया। इसी वजह से विस्तारा के पायलट नाराज हैं। पिछले कुछ दिनों में इनमें से कई मेडिकल लीव पर चले गए हैं, जिससे कंपनी को उड़ानें रद्द करनी पड़ रही हैं।

कब सुलझेगा मसला : खैर, अब DGCA के इस मामले में दखल देने के बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यात्रियों की परेशानी कम होगी और उनकी शिकायतों का निपटारा भी जल्द किया जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी तक कंपनी की ओर से यह आश्वासन नहीं मिला है कि यह मसला कब सुलझेगा।

पीक ट्रैवेल सीजन : विस्तारा का यह मामला गर्मियों की छुट्टी के पीक ट्रैवेल सीजन से पहले आया है, जब यूं भी फ्लाइट्स कम पड़ने के कारण टिकट महंगे हो जाते हैं। यही नहीं, अभी इंडिगो के 75 विमान उनमें लगे प्रैट एंड व्हिटनी इंजनों में दिक्कत के चलते उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। वहीं, गो एयर ने वित्तीय दिक्कतों के चलते पिछले मई से उड़ानें बंद कर रखी हैं, जबकि स्पाइसजेट की फ्लाइट्स की संख्या में भी कमी आई है। इन कंपनियों को बोइंग और एयरबस की ओर से भी वादे के मुताबिक नए विमानों की सप्लाई नहीं हो रही है। इसलिए हवाई क्षेत्र पर पहले से ही दबाव बना हुआ है। ऐसे में बेहतर होगा कि यह विवाद जल्द सुलझे ताकि लोग बिना किसी परेशानी के और वाजिब किराये पर हवाई यात्रा कर सकें।

आओ अपने एक वोट की ताकत को पहचाने-इतिहास एक वोट से हार जीत उदाहरणों से भरा पड़ा है

इतिहास गवाह है,जब एक वोट से भारतीय केंद्र सरकार गिरी,सांसद विधायक चुनाव हारे,अमेरिकी राष्ट्रपति और हिटलर भी एक वोट से ही जीते थे : एडवोकेट किशन भावनानी

लोकसभा चुनाव 2024- हमारे अभूतपूर्व एक वोट में सरकार बनाने गिराने की ताकत

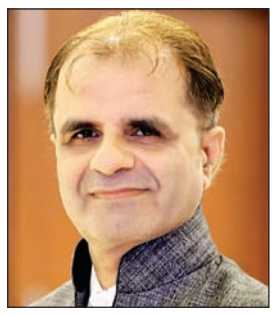

लेखक
किशन सनमुखदास भावनानी
गोंदिया (महाराष्ट्र)

गोंदिया - विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे बड़ी 142 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले भारत देश में लोकतंत्र का महापर्व का प्रथम चरण 19 अप्रैल 2024 से शुरू हो रहा है। इसके प्रचार प्रसार में उम्मीदवार बड़े जोर शोर से भिड़े हुए प्रचार कर रहे हैं। हर उम्मीदवार अपने-अपने विकास के काम गिनाकर वोटरों का उज्जवल भविष्य की बातें कर रहे हैं। जिनके उत्तर में मतदाता का रुझान अपेक्षाकृत कम दिखाई दे रहा है वैसे भी हम पिछले चुनावों का विश्लेषण करें तो पहले ओवरऑल मतदान 50 प्रतिशत के आसपास होता था जो अभी हाल के पांच राज्यों के चुनाव में प्रतिशत तेजी से बढ़ाते दिखाई दिया है मेरा मानना है कि यह चुनाव का मतदान प्रतिशत 90 प्रतिशत से पार करने की जरूरत है, जिस पर हर मतदाता ने विचार कर इसे रेखांकित करना समय की मांग है, क्योंकि अगर हम पिछले इतिहास पर गहराई से नजर डालें तो,आम तौर एक वोट की ताकत को बड़े चुनावों में कम करके आंका जाता है। लोग अक्सर यह कहते सुने जा सकते हैं कि एक वोट से क्या होगा। लेकिन इतिहास खंगालने पर एक वोट की ताकत क्या होती है यह पता चलता है। देश और दुनिया का इतिहास गवाह है कि एक वोट की ताकत कभी कम नहीं रही। एक वोट ने सरकार तक को गिरा दिया तो किसी के मुख्यमंत्री बनने के सपने पर पानी फेर दिया। कहीं एक वोट हिम्मत, साहस और मजबूत इरादे के प्रतीक के तौर पर सामने आया। चूंकि अभी 19 अप्रैल से 4 जून तक हमें लोकसभा चुनाव 2024 के विभिन्न चरणों में वोट करना है,जो हमारेअभूतपूर्व एक वोट की महत्वपूर्ण ताकत है,क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब एक वोट से भारतीय केंद्र सरकार गिरी,सांसद विधायक चुनाव हारे,अमेरिकी राष्ट्रपति और हिटलर भी एक वोट से जीते थे,इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,आओ अपने एक वोट की टीटीताकत को पहचाने इतिहास एक वोट से हार जीत के उदाहरणों से भरा पड़ा है। साथियों बात अगर हम अपने एक वोट की ताकत का आंकलन भारतीय इतिहास में एक वोट से हारने वाले नेताओं की करें तो, आमतौर पर मतदाता एक वोट की ताकत कम करके आंकते हैं और कई बार मतदान करने नहीं जाते हैं। हालांकि इतिहास में चुनावी पर्व में कई बार ऐसे मौके देखे गए, जब एक वोट ने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया।अटल सरकार का गिरना, अप्रैल 1999 भारतीय इतिहास में एक अहम घटना के लिए दर्ज है। इसी दिन 13 महीने पुरानी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ एक वोट से पास हुआ था। प्रस्ताव के पक्ष में 270 वोट पड़े थे और खिलाफ 269 वोट। इसके नतीजे में वाजपेयी सरकार गिर गई थी।सी.पी.जोशी हार, 2008 के राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के सीनियर लीडर सी.पी.जोशी सिर्फ एक वोट से हार गए थे। उनके प्रतिद्वंद्वी बीजेपी के कल्याण सिंह चौहान को 62,216 वोट पड़े थे जबकि उनको 62,215। वह उस समय मुख्यमंत्री पद के मजबूत उम्मीदवार थे लेकिन एक वोट ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।जैसा कि सौभाग्य से हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया की 2013 की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कथित तौर पर सीपी जोशी की मां, बहन और ड्राइवर मतदान के दिन उनके लिए वोट करने नहीं आ सके। संयोगवश, कर्नाटक में भी कृष्णमूर्ति का ड्राइवर मतदान करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि कृष्णमूर्ति ने ही उसे मतदान के दिन अपनी ड्यूटी से छुट्टी नहीं दी थी।ए.आर.कृष्णमूर्ति कर्नाटक विधानसभा के 2004 के चुनाव में ए.आर.कृष्णमूर्ति जनता दल सेक्युलर के टिकट पर लड़े थे। उनके प्रतिद्वंद्वी ध्रुवनारायण को 40752 वोट मिले जबकि उनको 40751। वह विधानसभा चुनाव में एक वोट से हारने वाले पहले शख्स बन गए थे।अहमद पटेल 2017 में गुजरात की तीन राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ था। एक सीट पर कांग्रेस की ओर से अहमद पटेल लड़ रहे थे। कांग्रेस के ही दो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी जिससे अहमद पटेल की जीत मुश्किल हो गई थी। क्रॉस वोटिंग करने वाले दो एमएलए यह भूल गए थे कि वे वोट करते वक्त भी कांग्रेस के सदस्य थे और वे पोलिंग बूथ पर खड़े होकर अपनी बदली हुई वफादारी का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं कर सकते। इससे उनके वोट रद्द हो गए जिससे जीतने के लिए वोटों की संख्या 43.5 हो गई। अहमद पटेल को 44 वोट मिले थे, इस तरह वह आधे वोट से जीत गए। एआर कृष्णमूर्ति ने 2013 के एक प्रेस साक्षात्कार में इसे अच्छी तरह से समझाते हुए कहा कि वह नहीं चाहेंगे कि उनका कट्टर दुश्मन भी इस तरह से यानी सिर्फ एक वोट से चुनाव हार जाए। उम्मीदवार को शून्य वोटउत्तर प्रदेश का मैनपुरी संसदीय क्षेत्र ढाई दशक से भी अधिक समय से समाजवादी पार्टी का गढ़ है। इसके चलते यह हर चुनाव में सुर्खियों में रहता है। हालांकि यह क्षेत्र एक दिलचस्प किस्से का भी गवाह रहा है। यहां एक उम्मीदवार को शून्य वोट मिले थे। शंकर लाल 1957 के लोकसभा चुनावों में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े थे। उन्हें अपना वोट भी नहीं मिला क्योंकि गिनती के दौरान उसे भी अमान्य करार दे दिया गया था। साथियों बात अगर हम 10 से कम वोटो पर जीत के निर्णय की करें तो, 10 से कम वोटों से जीत और हार का निर्णय आंकड़े बताते हैं कि भारतीय चुनाव के इतिहास में कई बार ऐसे मौके आए जब जीत और हार का निर्णय 10 से कम वोटों से हुआ। ताजा उदाहरण 2018 में हुए मिजोरम विधानसभा चुनाव का है। तुइवावल विधानसभा सीट पर मिजोरम नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के लालचंदामा राल्ते ने मौजूदा कांग्रेस विधायक आरएल पियानमाविया को सिर्फ तीन

वोटों से हराया। चुनाव में राल्ते को 5,207 वोट मिले जबकि पियानमाविया को 5,204 वोट मिले। 1989 में कांग्रेस के कोनाथला रामकृष्ण ने आंध्र प्रदेश की अनाकापल्ली सीट से उपविजेता से सिर्फ नौ अतिरिक्त वोट हासिल करके लोकसभा चुनाव जीता था। 1998 में जब भाजपा के सोम मरांडी ने बिहार की राजमहल लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। इस बार भी अंतर महज नौ वोटों का रहा। साथियों बात अगर हम पूरी दुनियां के लोकतांत्रिक देशों में एक वोट से हार जीत के फैसले की करें तो रदरफॉर्ड बी हेज 1876 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रदरफॉर्ड बी.हेज और टिलडन के बीच मुकाबला था। टिल्डन 2,50,000 के अंतर से पॉप्युलर वोट जीत गए थे। लेकिन जब इलेक्टोरल वोट की बारी आई तो उनको सिर्फ 184 वोट मिले थे जबकि रदरफॉर्ड 185 वोट जिससे उनकी जीत सुनिश्चित हुई।मजबूत लीडर के तौर पर उभरीं मारग्रेट थैचरएक वोट ने इंग्लैंड की प्रधानमंत्री रहीं मारग्रेट थैचर की जिंदगी में अहम भूमिका निभाई। साल 1979 की बात है। उन दिनों थैचर विपक्ष की नेता थीं। लेबर पार्टी सत्ता में थी और प्रधानमंत्री जेम्स कैलहैन थे। थैचर ने पीएम जेम्स कैलहैन केखिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव के पक्ष में 311 और खिलाफ 310 वोट पड़े। यानी एक वोट से प्रस्ताव पास हुआ। उसके बाद चुनाव में जीत के साथ मारग्रेट थैचर मजबूत नेता के तौर पर उभरीं। हिटलर के खिलाफ एक वोट1919 में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी। 1921 में हिटलर ने नाजी पार्टी की कमान संभाली थी। नाजी पार्टी की कमान संभालने से पहले पार्टी के कई सदस्य हिटलर के खिलाफ थे। उनका मानना था कि वह बहुत महत्वाकांक्षी है और इस वजह से उनलोगों ने हिटलर की शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की। इससे नाराज होकर हिटलर पार्टी छोड़कर चला गया। फिर उनलोगों को अहसास हुआ कि हिटलर जैसे प्रभावशाली इंसान के जाने से पार्टी पर असर पड़ेगा। इसके नतीजे में हिटलर पार्टी में लौटा तो सही लेकिन अपनी शर्तों पर। 29 जुलाई को हिटलर को पार्टी का चेयरमैन चुनने के लिए वोटिंग हुई। कुल 554 सदस्यों में से सिर्फ एक सदस्य ने हिटलर के खिलाफ वोट दिया। ऐसे समय में जब सारे सदस्य हिटलर के साथ खड़े थे, एक का उसके खिलाफ जाना वाकई में ऐताहिसक और साहसिक कदम था।फ्रांस में राजशाही खत्म और लोकतंत्र शुरू हुआ।1875 : फ्रांस में तो सत्ता का पूरा रूप ही बदल गया था। एक वोट की जीत से ही फ्रांस में राजशाही खत्म हुई और लोकतंत्र का आगाज हुआ। वरना वहां के लोग अब तक राजशाही ही ढो रहे होते।अमेरिका की भाषा बदली वरना मातृभाषा जर्मन होती। 1776 : अमेरिका को एक वोट की बदौलत ही जर्मन की जगह अंग्रेजी के रूप में उनकी मातृभाषा मिली थी। यहां 1910 में रिपब्लिक उम्मीदवार एक वोट से हार गया था और पार्टी मानो शोक में डूब गई थी।

भारतीय संस्कृति, संस्कारों में पश्चिमी दर्शन का समावेश

(वैचारिक क्रांति में अंतर्द्वंद)

भारतीय संस्कृति हमें अपने भारतीय होने का एहसास कराती है। जो हमें विश्व के अन्य देशों से विकास की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भारत में अनेक परंपराएं ऐसी हैं जो सामाजिक जीवन को अधिक सभ्य एवं अच्छा इंसान बनाए रखने में योगदान देती है। जिनसे मनुष्यता का जीवन जीने की प्रेरणा भी मिलती है। यांत्रिक उपकरणों की तरह जिंदगी जीना भी कोई जीना है। यह भारतीय संस्कृति में पाश्चात्य का घालमेल ही है जो मनुष्य के जीवन को यंत्रवत बना देता है। जो आने वाले कल के लिए घातक भी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य दर्शन की कुछ विशेषताएं भी हैं, जो हमारे विचारों को अधिक तार्किक तथा बौद्धिक बनाती है। जिससे हम अपना जीवन कार्तिक तथा बौद्धिक बना सकते हैं। जिन्हें हम अपने जीवन में क्रियान्वित कर अपने मनुष्य जाति के जीवन को अधिक सार्थक एवं सुलभ बना सकते हैं। निसंदेह हमें रूढ़ीवादी या एकदम पुरातन पंथी संस्कृति से लगाव न रखकर पाश्चात्य संस्कृति के जो फायदे हैं, उन्हें अपनाकर अपना जीवन सरल सार्थक एवं सुगम बना सकते हैं। विवेकानंद जी ने कहा है कि वीणा के तार को ईतना भी ना कसो कि वह टूट जाए, और इतना भी ढीला छोड़ो कि वह बज भी ना पाए, मूलतः हमें दोनों संस्कृतियों की समग्र अच्छाइयों को आत्मसात कर उनकी बुराइयों को त्यागना होगा तब ही जीवन सफल हो सकेगा। भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान है। जबकि पश्चिमी सभ्यता भौतिकता लिए होती है, और उसमें भौतिकता की प्रधानता होती है। आध्यात्मिक प्रधान संस्कृति से तात्पर्य भौतिकता वादी दृष्टिकोण से दूर रहकर भौतिकता वादी होने का ही है। प्राचीन काल से ही भारत देश में 'अतिथि देवो भव' और 'वसुधैव कुटुंबकम' वाली संस्कृति रही है। भारत की सांस्कृतिक धरोहर, विश्वास, भावना,आस्था, धर्म, रीति रिवाज जैसे तथ्यों से भरी पड़ी है। धर्म प्रधान संस्कृति होने के कारण ही इसे आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला देश माना गया है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में यदि कहें तो ईश्वरत और त्याग पर्यायवाची शब्द है। संस्कृति और सदाचार उसकी बाह्य अभिव्यक्तियाँ है। परंपरागत दृष्टिकोण से हम अपने धार्मिक तथा अध्यात्मिक दर्शन को लेकर बहुत हद तक अपने आप को एवं देश को महिमामंडित करने में लगे रहते हैं। किंतु आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें पूर्ण रूप से आध्यात्मिक ना होकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर इस तथ्य का मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि 21 सदी में पांचवी एवं छठवीं सदी की मान्यताएं तथा परंपराएं जारी रख उन्हें अपना सकते हैं क्या?, आज जब दुनिया वैज्ञानिक चमत्कारों से भरी पड़ी है। दुनिया विज्ञान की प्रगति से चांद तो क्या सूर्य को भी खंगालने का प्रयास कर रही है। मानव का क्लोन बनाकर ईश्वर की सत्ता को चुनौती देने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में धार्मिक संस्कृति तथा आध्यात्मिकता को आवश्यकता से अधिक महत्व एवं परंपरा में लाना प्रासंगिक एवं तार्किक होगा। निसंदेह नहीं। पाश्चात्य दर्शन भौतिकता प्रधान एवं वैज्ञानिक संस्कृति है। भौतिकता प्रधान युग से तात्पर्य ऐसी परंपरा जो यथार्थवादी दृष्टिकोण को सर्वाधिक महत्व देती है।

लेखक
संजीव ठाकुर
चिंतक, रायपुर (छत्तीसगढ़)

वैसे ही भौतिकता का सामान्य मतलब इंद्रिय बोध से साक्षात संबंध रखने वाली वस्तु से है, अर्थात जो वास्तविकता है एवं यथार्थ है वही पाश्चात्य दर्शन है। पाश्चात्य संस्कृति को इसलिए भी वैज्ञानिक एवं वस्तु परख माना जाता है क्योंकि इसमें सूक्ष्म जांच पड़ताल कर वस्तु स्थिति का सही मूल्यांकन अपनाकर एक सामान्य सिद्धांत एवं नियम बनाया जाता है। जिससे भविष्य की बातों को जानकर जीवन को और अच्छा तथा बेहतर बनाने में मदद मिल सके। वैसे पाश्चात्य संस्कृति में बहुत सी अहितकर बातें भी हैं, जैसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना कमतर होते जा रही है। संयुक्त परिवार की प्रणाली का विघटन होते जा रहा है। पारिवारिक वातावरण संघर्ष तथा तनावपूर्ण होते जा रहा हैं। पाश्चात्य संस्कृति की नकल कर लोग परिवार से अलग होकर स्वतंत्र जीवन यापन करना पसंद करते हैं। उनमे विवाह विच्छेद और अन्य विसंगतियां जन्म लेने लगी हैं। धर्म तथा आध्यात्मिक के प्रति आमजन की सूची धीरे धीरे कम होते जा रही है। ऐसो आराम के सामान खरीदने के कारण लोगों के खर्चे अनाप-शनाप बढ़ चुके हैं। बुजुर्गों की इज्जत तवज्जो होनी कम हो गई है। दादा और नाती के संबंधों में अब वह गर्माहट शेष नहीं रह गई है, जैसी की एक सांस्कृतिक तथा नैतिक परिवार जनों में हुआ करती थी। धीरे-धीरे परिवार के सदस्य अलग होकर अकेलेपन की समस्या से जूझ रहे हैं। आने वाली पीढ़ी अपनी संस्कृति एवं आध्यात्मिक प्रवृत्ति भूलती जा रही है। प्रेम विवाह तथा अंतर जाति विवाह पाश्चात्य सभ्यता के कारण बहुत बढ़ गए हैं। जिससे वैवाहिक संबंध टूटने के कगार पर आ जाते हैं। पर दूसरी तरफ पाश्चात्य सोच के कारण स्त्री सशक्तिकरण को बढ़ावा भी मिला है महिलाएं जहां पहले अपने घरों में कैद थी अब उन्मुक्त होकर शिक्षित होकर समाज में सफल होकर पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर व्यवसायिक दृष्टिकोण अपनाकर बड़े-बड़े पदों में कार्य कर रही हैं। समाज में खुलापन भी आ गया है। विकास रोजगार एवं मानवीय सोच में भी काफी विस्तार आया है, जो विश्व की सभ्यताओं में आज मौजूद है,जो भारत के विकास में सहायक भी हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि हमें आध्यात्मिक भारतीय परंपरा संस्कृति तथा पाश्चात्य दर्शन तथा पाश्चात्य संस्कृति की सकारात्मक बातें आत्मसात कर विकास की एक नई राह खोजनी होगी, एवं सदैव अच्छी बातों के लिए अपने मस्तिष्क को खुला रखना होगा और पाश्चात्य संस्कृति की विसंगतियों को दूर रख भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए।

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जबरदस्त कन्फ्यूजन में है!

उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का माहौल गरमा गया है। पार्टियों ने तकरीबन अपने सभी उम्मीदवार तय कर लिए हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी में लगातार दुविधा की स्थिति बनी हुई है। पार्टी कई सीटों पर अपने घोषित प्रत्याशियों के टिकट काट रही है या बदल रही है । उत्तरप्रदेश की पहले चरण में की आठ सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें से रामपुर और मुरादाबाद की दो सीटों पर जबरदस्त सि?ासी ड्रामा हुआ। अखिलेश यादव ने मुरादाबाद सीट पर अखिरी वक्त में उम्मीदवार बदल दिया। सांसद एस टी हसन ने मंगलवार को नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बुधवार को अखिलेश यादव ने रूचि वीरा को पार्टी का चुनाव निशान देकर मुरादाबाद भेज दिया। उन्होंने भी नामांकन भर दिया। अब समाजवादी पार्टी के निशान पर दो दावेदार हो गए। हालांकि शाम को समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया कि रूचि वीरा ही अधिकृत उम्मीदवार होंगी। इसी तरह रामपुर में पहले आसिम रजा के चुनाव लड़ने की उम्मीद थी, वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन बुधवार को आसिम रजा और रामपुर में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव के बाईकॉट करने का एलान तक कर दिया था। बुधवार को आखिरी वक्त में जैसे ही समाजवादी पार्टी ने मौलाना मोहिबुल्ला नदवी को नामांकन दाखिल करने के लिए भेजा तो आसिम रजा ने भी पर्चा भर दिया। अब रामपुर में भी समाजवादी पार्टी के दो उम्मीदवार मैदान में हैं। रामपुर और मुरादाबाद दोनों सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कन्फ्यूज्ड हैं। सवाल है कि ये कन्फ्यूजन किसने पैदा किया? क्या इसमें जेल में बंद आजम खां का रोल है? क्या आजम खां के इशारे पर ये पहले मुरादाबाद की बात करते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ एस टी हसन ने मंगलवार को पर्चा भरा था, जीत के दावे किए थे। चूंकि एस टी हसन मुरादाबाद से सांसद हैं, लेकिन इसके बाद भी अखिलेश यादव ने उनका टिकट लटकाए रखा, देर से टिकट दिया। एस टी हसन ने पर्चा भर दिया लेकिन रात में खेल हो गया। देर रात ये खबर आई कि मुरादाबाद से एस टी हसन का टिकट कट गया है। अब पूर्व विधायक रूचि वीरा समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ेंगी। इस बीच रुचि वीरा लखनऊ से मुरादाबाद पहुंच गईं लेकिन रुचि के मुरादाबाद पहुंचते ही एस टी हसन के समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद अखिलेश यादव ने चार्टर्ड प्लेन से नरेश उत्तम और समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं को मुरादाबाद भेजा ताकि हालात को काबू में रख सकें। रूचि वीरा मुरादाबाद में पर्चा भरने पहुंच गई, उनके साथ गिने चुने लोग थे, नारा लगाने वाले और पार्टी का झंडा उठाने वाले लोग भी नहीं थे। रूचि वीरा ने वक्त खत्म होने से पहले पर्चा भर दिया, समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान वाला फॉर्म बी जमा कराया। पता ये चला कि एस टी हसन का पत्ता आजम खां के कहने पर कटा है। आजम खां सीतापुर जेल में बंद हैं लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं पर अभी भी आजम खां का जबरदस्त असर है। आजम खां जेल में रहकर भी चुनावी समीकरण बना और बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर टिकटों के बंटवारे पर राय लेने के लिए सीतापुर जेल में आजम खां से मिले थे। आजम खां ने ही मुरादाबाद सीट पर एस टी हसन की जगह रूचि वीरा के नाम का सुझाव दिया जिसे अखिलेश ने मान लिया और रातों रात हसन का टिकट काट दिया। समाजवादी पार्टी के ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता जानते हैं कि रूचि वीरा आजम खां की करीबी हैं, रुचि वीरा बिजनौर से सपा के टिकट पर विधायक रह चुकी हैं। ये तो कोई नहीं मानेगा कि रूचि वीरा एस टी हसन के मुकाबले बड़ी नेता हैं, उन्हें आजम खां की पैरवी पर ही अखिलेश यादव ने टिकट दिया। बाद में हसन ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम ये फैसला कैसे हुआ, किसके कहने पर हुआ और उन्हें बताने की भी जरूरत नहीं समझी गई। हसन ने बड़ी महीन सियासी बात कही। उन्होंने कहा कि पूरा हिन्दुस्तान जानता है आजादी के बाद से अब तक जितने चुनाव हुए, उनमें एक बार छोड़कर मुरादाबाद से हर बार मुसलमान उम्मीदवार ही चुनाव जीता है। दरअसल अखिलेश यादव मुरादाबाद सीट से एस.टी. हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाने के पक्ष में नहीं थे। अखिलेश यादव ने एस.टी. हसन को फिर से प्रत्याशी बनाने के लिए एक पत्र जारी किया था। जिसमें एस.टी. हसन को फिर से मुरादाबाद सीट से सपा का प्रत्याशी बनाया गया था। ये खत रुचि वीरा का नॉमिनेशन होने के बाद जारी किया था। अखिलेश यादव ने रुचि वीरा का नामांकन रद्द करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। ये पत्र लखनऊ से मुरादाबाद चुनाव ऑफिसर के पास भेजा गया, लेकिन समय से पत्र नहीं पहुंचने के कारण लेटर को रिसीव नहीं किया गया। रामपुर में दिल्ली के संसद मार्ग मस्जिद के इमाम मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी और आसिम रजा दोनों सपा की उम्मीदवारी का दावा कर रहे थे । मौलाना को मंगलवार रात लखनऊ से आदेश मिला कि रामपुर पहुंचिए, रामपुर से पर्चा भरना है। मौलाना नदवी रामपुर के रहने वाले हैं लेकिन दिल्ली में पिछले 15 साल से रह रहे हैं। बुधवार को मौलाना ने पर्चा भर दिया। मौलाना नदवी ने कहा कि उनका नाम खुद अखिलेश यादव ने फाइनल किया है, उन्हीं के कहने पर उन्होंने अपना पर्चा भरा है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वही हैं। इसके तुरंत बाद आजम खां के करीबी आसिम रजा भी पर्चा भरने पहुंच गए। उन्होंने भी पर्चा दाखिल कर दिया। इस बात में कोई शक नहीं कि रामपुर पर एक लंबे अर्से तक आजम खान का कब्जा रहा है, वो रामपुर के चप्पे-चप्पे को जानते हैं। यहां के बच्चे-बच्चे को पहचानते हैं लेकिन अब मजबूर हैं। जेल में बंद हैं। उन पर सैंकड़ों केस हैं। योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में उनका दबदबा खत्म कर दिया। रामपुर में आजम खान के उम्मीदवारों को हरा दिया पर आजम खान आसानी से हार मानने वालों में नहीं हैं। वो जेल में रहकर भी इस इलाके की सियासत पर खासा असर डाल सकते हैं। उनका ये सुझाव कि रामपुर से अखिलेश को लड़ना चाहिए, अच्छा था लेकिन अखिलेश इन चुनावों में एक-एक कदम फूंक-फूंक कर रख रहे हैं। अखिलेश के लिए ये चुनाव अस्तित्व का सवाल है। हालांकि वो आजम खान की बात सुनते हैं लेकिन रामपुर से चुनाव लड़ने की बात नहीं मानी, इसीलिए इतना कन्फ्यूजन पैदा हुआ। दूसरी तरफ भाजपा ने जबरदस्त चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ, मथुरा, गाजियबाद में प्रचार कर रहे हैं। रामपुर और मुरादाबाद के बाद मेरठ का भी नाम इसमें जुड़ गया है . ये उत्तर प्रदेश में वो तीन सीट हैं, जिनपर समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिला। हर बार की तरह इस बार भी सपा में टिकट को लेकर भारी असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। मेरठ से जब भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया , तो दूसरी तरफ सपा प्रत्याशी का ऐलान कर बार-बार बदलाव कर रही है। मेरठ लोकसभा सीट पर सपा ने एक बार फिर अपना प्रत्याशी बदला दिया है। अतुल प्रधान की जगह अब पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को उम्मीदवार घोषित किया है।समाजवादी पार्टी ने पहले मेरठ सीट से एडवोकेट भानू प्रताप सिंह को टिकट दिया गया था, लेकिन भानू प्रताप के नाम पर पार्टी के स्थानीय नेताओं ने नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने मेरठ सीट पर सरधना से विधायक अतुल प्रधान को प्रत्याशी घोषित कर दिया। अतुल प्रधान का ऐलान होते ही पार्टी में बगावत छिड़ गई। मेरठ शहर विधायक रफीक अंसारी ने मेरठ सीट पर दावा ठोक दिया है। अब अखिलेश यादव ने पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। वैसे चुनावी मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आज शाम तक और भी कई उम्मीदवारों के टिकट बदले जा सकते है ।

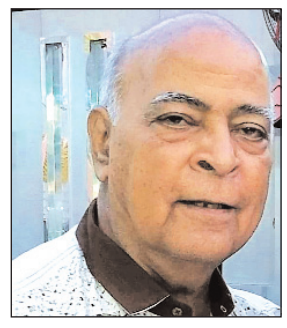

लेखक
अशोक भाटिया
वसई पूर्व, मुंबई

प्रकाशक, संपादक, मुद्रक रूपेश कुमार सिंह, रैप एक्सप्रर्टस प्राइवेट लिमिटेड पटना द्वारा, कॉमी तंजीम पब्लिसर्स प्रा. लिमिटेड, अमीन मंजिल, सब्जीबाग, पटना-800004 से मुद्रित। ज्योति प्रकाश भवन, जकरियापुर एसएफसी कॉलोनी, जीरो माइल गंगा पेट्रोल पंप के नजदीक, पटना से प्रकाशित। संपर्क सूत्र \ 9835055017@7004145686] RNI NO&BIHHIN/2021/85413, RNI TITLE CODE : BIHHIN/11898

आरबीआई की एमपीसी बैठक और यथास्थिति से परे

भारतीय रिजर्व बैंक की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 2024-25 की पहली बैठक अनुकूल आर्थिक माहौल में होने जा रही है। सोमवार को जारी किए गए आंकड़े दर्शाते हैं कि मार्च में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का संग्रह, रिफंड के बिना सालाना आधार पर 18.4 फीसदी बढ़ा। वर्ष का अंत जीएसटी संग्रह में 13.4 फीसदी इजाफे के साथ हुआ। समग्र कर संग्रह के ताजा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देखें तो सरकार राजकोषीय घाटे को 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.8 फीसदी तक रखने के संशोधित आंकड़े को हासिल कर लेगी। सरकार ने मध्यम अवधि में राजकोषीय मार्ग पर टिके रहने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जिससे रिजर्व बैंक को आश्वस्ति मिलनी चाहिए। अधिक व्यापक तौर पर देखें तो अब सरकार को उम्मीद है कि मार्च तिमाही में वृद्धि दर 8 फीसदी रहेगी जो 2023-24 की पूरे वर्ष की 8 फीसदी की वृद्धि को बल देगी। मुद्रास्फीति के मोर्चे पर भी हालात में सुधार हो रहा है। हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति अभी भी 5 फीसदी के स्तर से कुछ ऊपर है, कोर मुद्रास्फीति 4 फीसदी के लक्ष्य से कम है जिससे केंद्रीय बैंक को राहत मिलनी चाहिए। मौद्रिक नीति समिति के ताजा अनुमानों के मुताबिक हेडलाइन मुद्रास्फीति की दर चालू वित्त वर्ष में औसतन 4.5 फीसदी रह सकती है। कोर मुद्रास्फीति जहां चार फीसदी से नीचे हैं, वहीं हेडलाइन दर को लक्ष्य से ऊपर रखने में खाद्य मुद्रास्फीति का बहुत अधिक योगदान है। फरवरी में खाद्य मुद्रास्फीति 8.66 फीसदी थी। ध्यान देने की बात है कि खाद्य मुद्रास्फीति ऊपरी स्तर पर है और ऐसा सरकार के सक्रिय हस्तक्षेप के बावजूद है। केंद्र सरकार ने कई खाद्य वस्तुओं के निर्यात और भंडारण सीमा पर अंकुश लगाया है। उदाहरण के लिए गत सप्ताह सरकार ने कारोबारियों, खाद्य प्रसंस्करण करने वालों तथा प्रमुख खुदरा कारोबारियों से कहा कि वे हर शुक्रवार को गेहूं के अपने भंडार की जानकारी दें क्योंकि 31 मार्च को स्टॉक होल्डिंग सीमा समाप्त हो गई।

आखिर वकीलों ने वकीलों के खिलाफ चिट्ठी क्यों लिखी?

आरती कुमारी

न्यायिक बिरादरी में गलत को सही ठहराने के लिये एक-दूसरे के पैरों के नीचे से फट्टा खींचने की कोशिशें अक्सर होती रही है। भले ही इससे देश कमजोर हो, राष्ट्रीय मूल्यों पर आघात लगता हो। लोकतंत्र के चार स्तंभों में महत्वपूर्ण इस न्यायिक बिरादरी ने राजनीतिक अपराधियों, घोटालों और भ्रष्टाचार के दोषियों को बचाने के लिये शीर्ष वकीलों का एक समूह सक्रिय है, यह हमारी न्याय व्यवस्था का स्वाभाविक हिस्सा है, जो चिन्ता का बड़ा कारण है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा सहित पूरे भारत से 600 से अधिक वकीलों ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर इन लगातार बढ़ रही राजनीतिक अपराधियों को बचाने की स्थितियों पर चिंता जताई गई है, निश्चित ही इन वकीलों का यह प्रयास सराहनीय एवं राष्ट्रीयता से प्रेरित है। न्यायिक प्रक्रिया में हेरफेर करने, अदालती फैसलों को प्रभावित करने और निराधार आरोपों और राजनीतिक एजेंडे के साथ न्यायपालिका की प्रतिष्ठा धूमिल करने के प्रयास करने वाले 'निहित स्वार्थी समूह' की निंदा व्यापक स्तर पर होनी ही चाहिए। एक प्रश्न यह भी है कि आखिर वकीलों को वकीलों के खिलाफ चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी? न्यायपालिका को प्रभावित करने की इन घातक एवं अराष्ट्रीय कोशिशों के खिलाफ 600 वकीलों की चिन्ता गैरवाजिब नहीं है। वकीलों की यह जागरूकता न्याय-प्रक्रिया की प्रतिष्ठा एवं निष्पक्षता के लिये जरूरी हो गयी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वकीलों के इस सार्थक एवं प्रासंगिक प्रयास की सराहना की है। उन्होंने कहा कि दूसरों को डराना और धमकाना पुरानी कांग्रेस संस्कृति है। प्रधानमंत्री ने कहा, पांच दशक पहले ही उन्होंने प्रतिबद्ध न्यायपालिका का आह्वान किया था-वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं।' हमारे राष्ट्र की न्यायिक बिरादरी का यही पवित्र दायित्व है तथा सभी वकील भगवान् और आत्मा की साक्षी से इस दायित्व को निष्ठा व ईमानदारी से निभाने की शपथ लेते हैं। लेकिन अभी कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि हमारे वकीलां का एक खास वर्ग भारतीय न्याय-प्रक्रिया की पवित्रता और गरिमा को अनदेखी किये जा रहा है। चिंता का बड़ा कारण यह है कि यह समूह अपने पक्ष में ऐसे दबाव बना रहा है, जिससे न्यायपालिका की अखंडता के लिए खतरा पैदा हो रहा है। लेकिन पिछले दो दशक से न्यायमूर्तियों में ज्यादा जिम्मेदारी, सजगता व संवेदना देखने को मिली है और उन्होंने देशहित में किसी भी आर्थिक या राजनीतिक दबाव में झुकना स्वीकार नहीं किया है। आजादी के बाद से हमारे देश में एक खास किस्म का वकीली समूह विकसित हुआ है, जिन्हें सत्ताधारी पार्टियों का संरक्षण एवं प्रोत्साहन मिलता रहा है, वे अपराधों पर परदा डालने एवं खुंखार अपराधियों एवं संगीन आरोपों से घिरे राजनीतिक अपराधियों को बचाने में सिद्धहस्त होकर मोटी कमाई के साथ राजनीतिक पदों पर आसीन होते रहे हैं। बड़े लोगों एवं राजनेताओं के मामलों में अक्सर ऐसे बड़े वकील ही सामने आते हैं और वकीलों के बीच आय की असमानता से भी यही पता चलता है कि राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से सक्षम लोग न्याय पाने में आम लोगों से ज्यादा संभावना वाले होते रहे हैं। आम जनता के लिये महंगी होती कानून व्यवस्था एवं निष्पक्ष न्याय की नाउम्मीदी भी ऐसे ही स्वार्थी वकीलों से उपजी है। इसी बड़ी विसंगति एवं विडम्बना ने राजनीति में अपराध को भी प्रोत्साहन दिया है। इससे वकीलों का पेशा विवादास्पद भी बना है एवं न्याय-प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिन्ह लगते रहे हैं। प्रश्न है कि आखिर वकीलों को ऐसी चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि इन दिनों कुछ राजनेता कठघरे में खड़े हैं और उन्हें बचाने के लिए वकीलों का एक खास समूह सक्रिय है, जो सत्य को ढंकने की कुचेष्टा करते हुए राजनीतिक हित में तथाकथित अपराधियों को बचाने के लिये विभिन्न तरीकों से काम करता है। ऐसे स्वार्थी वकील एक खास अंदाज में कथित बेहतर अतीत और अदालतों के सुनहरे दौर की झूठी कहानियां गढ़ते हैं, इसे वर्तमान में होने वाली घटनाओं से तुलना करते हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि जानबूझकर दिए गए बयान हैं, जो अदालत के फैसलों को प्रभावित करने और कुछ राजनीतिक लाभ के लिए अदालतों को शर्मिंदा करने के लिए दिए गए हैं। यह देखना परेशान करने वाला है कि कुछ वकील दिन में राजनेताओं का बचाव करते हैं और फिर रात में मीडिया के माध्यम से न्यायाधीशों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे स्वार्थी वकीलों का यह कहना कि अतीत में अदालतों को प्रभावित करना आसान था, उन पर जनता के विश्वास को हिला देता है। इसीलिये वकीलों के दूसरे पक्ष को पत्र लिखने की जरूरत पड़ी, ऐसे पत्र लिखने का कोई राजनैतिक उद्देश्य नहीं, बल्कि नैतिक एवं राष्ट्रीय आग्रह है। इस पत्र में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वे इस तरह के हमलों से हमारी अदालतों को बचाने के लिए सख्त और ठोस कदम उठाएं। वकीलों ने चिंता जाहिर की कि 'विशेष ग्रुप' अदालतों की कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर उन मुद्दों पर बाधा डालने की कोशिश की जा रही है, जो मामले राजनेताओं और राजनीतिक दलों से जुड़े हैं। इस तरह की रणनीति हमारी अदालतों को नुकसान पहुंचा रही हैं और हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को खतरे में डालती हैं। वकीलों का आरोप है कि उनकी हरकतों से राष्ट्रीयता, विकास, विश्वास और सौहार्द का माहौल खराब हो रहा है, जो न्यायपालिका की कार्यप्रणाली की मूलभूत विशेषता है। चिट्ठी में वकीलों ने न्यायपालिका के समर्थन में एकजुट, समानतापूर्ण, निष्पक्ष रुख अपनाने का आह्वान किया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायपालिका लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ बना रहे। निश्चित रूप से न्यायमूर्तियों को नामी वकीलों या रसूखदार आरोपियों के सामने समान रूप से बिना किसी राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह या दुराग्रह के व्यवहार करना चाहिए और हमारे न्यायमूर्ति ऐसा ही करते हैं। फिर भी कहीं शिकायत की गुंजाइश रह जाती है और कुछ वकीलों को मिलकर ऐसे पत्र लिखने की जरूरत पड़ती है तो यह देश की जागरूकता एवं देश के प्रति निष्ठा को ही दर्शाता है। ऐसे पत्रों की आलोचना नहीं की जा सकती, ऐसे पत्र तो राजनीति की दूषित हवाओं को नियंत्रित करने के औजार है। ऐसे पत्र विशेष रूप से न्यायमूर्तियों से ज्यादा सजगता व संवेदना की मांग करते हैं। समाज के राष्ट्र के किसी भी हिस्से में कहीं भी मूल्यों एवं मानकों के विरुद्ध होता है तो यह सोचकर निरपेक्ष नहीं रहना चाहिए कि हमें क्या? गलत देखकर चुप रह जाना भी अपराध है। इसलिये बुराइयों एवं विसंगतियों से पलायन नहीं, उनका परिष्कार होना चाहिए। वकीलों की यह चिट्ठी ऐसे ही परिष्कार का द्योतक है जो लोकतंत्र के साथ-साथ संविधान को सुस्थापित बनाये रखने के लिये अपेक्षित है। वकीलों के चिट्ठी लिखने वाले समूह के खिलाफ वकीलों का दूसरा समूह सक्रिय हुआ है, उनका सक्रिय होना स्वाभाविक है क्योंकि उनकी मोटी कमाई के साथ गलत मनसूंबों पर पानी फिर गया है। वकीलों के दोनों समूहों के बीच परस्पर आरोप-प्रत्यारोप भी काफी गंभीर व दुखद हैं। चुनावी मौसम में यह एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर आने वाले कुछ दिनों तक बहस जारी रह सकती है। मामला वाकई गंभीर है। ध्यान रहे, 600 वकीलों के पत्र में बेंच फिक्सिंग के मनगढ़ंत सिद्धांत के बारे में भी चिंता जताई गई है, जिसके तहत न्यायिक पीठों की संरचना को प्रभावित करने और न्यायाधीशों की ईमानदारी पर सवाल उठाने का प्रयास शायद नया नहीं है। ऐसे में, यह जरूर कहना चाहिए कि देश में किसी भी स्तंभ या सांविधानिक संस्था की गरिमा धुंधलानी नहीं चाहिए। जनता को न्याय देने वाले मंचों पर अन्याय, स्वार्थ एवं आग्रहों के बादल नहीं मंडराने चाहिए। नया भारत एवं सशक्त भारत को निर्मित करते हुए संविधान को बनाए रखने के लिए काम करने वाले लोगों के रूप में, हमारी अदालतों के लिए खड़े होने एवं उसके अस्तित्व एवं अस्मिता को धुंधलाने के प्रयासों पर कड़ा पहरा देने का समय है।

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जबरदस्त कन्फ्यूजन में है!

अशोक भाटिया

उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का माहौल गरमा गया है। पार्टियों ने तकरीबन अपने सभी उम्मीदवार तय कर लिए हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी में लगातार दुविधा की स्थिति बनी हुई है। पार्टी कई सीटों पर अपने घोषित प्रत्याशियों के टिकट काट रही है या बदल रही है । उत्तरप्रदेश की पहले चरण में की आठ सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें से रामपुर और मुरादाबाद की दो सीटों पर ज़बरदस्त सिय़ासी ड्रामा हुआ। अखिलेश यादव ने मुरादाबाद सीट पर अखिरी वक्त में उम्मीदवार बदल दिया। सांसद एस टी हसन ने मंगलवार को नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बुधवार को अखिलेश यादव ने रूचि वीरा को पार्टी का चुनाव निशान देकर मुरादाबाद भेज दिया। उन्होंने भी नामांकन भर दिया। अब समाजवादी पार्टी के निशान पर दो दावेदार हो गए। हालांकि शाम को समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया कि रूचि वीरा ही अधिकृत उम्मीदवार होंगी। इसी तरह रामपुर में पहले आसिम रज़ा के चुनाव लड़ने की उम्मीद थी, वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन बुधवार को आसिम रज़ा और रामपुर में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव के बाईकॉट करने का एलान तक कर दिया था। बुधवार को आखिरी वक्त में जैसे ही समाजवादी पार्टी ने मौलाना मोहिबुल्ला नदवी को नामांकन दाखिल करने के लिए भेजा तो आसिम रज़ा ने भी पर्चा भर दिया। अब रामपुर में भी समाजवादी पार्टी के दो उम्मीदवार मैदान में हैं। रामपुर और मुरादाबाद दोनों सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कन्फ्यूज़्ड हैं। सवाल है कि ये कन्फ्यूजन किसने पैदा किया? क्या इसमें जेल में बंद आजम खां का रोल है? क्या आजम खां के इशारे पर ये पहले मुरादाबाद की बात करते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ एस टी हसन ने मंगलवार को पर्चा भरा था, जीत के दावे किए थे। चूंकि एस टी हसन मुरादाबाद से सांसद हैं, लेकिन इसके बाद भी अखिलेश यादव ने उनका टिकट लटकाए रखा, देर से टिकट दिया। एस टी हसन ने पर्चा भर दिया लेकिन रात में खेल हो गया। देर रात ये खबर आई कि मुरादाबाद से एस टी हसन का टिकट कट गया है। अब पूर्व विधायक रूचि वीरा समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ेंगी। इस बीच रुचि वीरा लखनऊ से मुरादाबाद पहुंच गईं लेकिन रुचि के मुरादाबाद पहुंचते ही एस टी हसन के समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद अखिलेश यादव ने चार्टर्ड प्लेन से नरेश उत्तम और समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं को मुरादाबाद भेजा ताकि हालात को काबू में रख सकें। रूचि वीरा मुरादाबाद में पर्चा भरने पहुंच गई, उनके साथ गिने चुने लोग थे, नारा लगाने वाले और पार्टी का झंडा उठाने वाले लोग भी नहीं थे। रूचि वीरा ने वक्त खत्म होने से पहले पर्चा भर दिया, समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान वाला फॉर्म बी जमा कराया। पता ये चला कि एस टी हसन का पत्ता आजम खां के कहने पर कटा है। आजम खां सीतापुर जेल में बंद हैं लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं पर अभी भी आजम खां का जबरदस्त असर है। आजम खां जेल में रहकर भी चुनावी समीकरण बना और बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर टिकटों के बंटवारे पर राय लेने के लिए सीतापुर जेल में आजम खां से मिले थे। आजम खां ने ही मुरादाबाद सीट पर एस टी हसन की जगह रूचि वीरा के नाम का सुझाव दिया जिसे अखिलेश ने मान लिया और रातों रात हसन का टिकट काट दिया। समाजवादी पार्टी के ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता जानते हैं कि रूचि वीरा आजम खां की करीबी हैं, रुचि वीरा बिजनौर से सपा के टिकट पर विधायक रह चुकी हैं। ये तो कोई नहीं मानेगा कि रूचि वीरा एस टी हसन के मुकाबले बड़ी नेता हैं, उन्हें आजम खां की पैरवी पर ही अखिलेश यादव ने टिकट दिया। बाद में हसन ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम ये फैसला कैसे हुआ, किसके कहने पर हुआ और उन्हें बताने की भी जरूरत नहीं समझी गई। हसन ने बड़ी महीन सियासी बात कही। उन्होंने कहा कि पूरा हिन्दुस्तान जानता है आजादी के बाद से अब तक जितने चुनाव हुए, उनमें एक बार छोड़कर मुरादाबाद से हर बार मुसलमान उम्मीदवार ही चुनाव जीता है। दरअसल अखिलेश यादव मुरादाबाद सीट से एस.टी. हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाने के पक्ष में नहीं थे। अखिलेश यादव ने एस.टी. हसन को फिर से प्रत्याशी बनाने के लिए एक पत्र जारी किया था। जिसमें एस.टी. हसन को फिर से मुरादाबाद सीट से सपा का प्रत्याशी बनाया गया था। ये खत रुचि वीरा का नॉमिनेशन होने के बाद जारी किया था। अखिलेश यादव ने रुचि वीरा का नामांकन रद्द करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। ये पत्र लखनऊ से मुरादाबाद चुनाव ऑफिसर के पास भेजा गया, लेकिन समय से पत्र नहीं पहुंचने के कारण लेटर को रिसीव नहीं किया गया। रामपुर में दिल्ली के संसद मार्ग मस्जिद के इमाम मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी और आसिम रज़ा दोनों सपा की उम्मीदवारी का दावा कर रहे थे । मौलाना को मंगलवार रात लखनऊ से आदेश मिला कि रामपुर पहुंचिए, रामपुर से पर्चा भरना है। मौलाना नदवी रामपुर के रहने वाले हैं लेकिन दिल्ली में पिछले 15 साल से रह रहे हैं। बुधवार को मौलाना ने पर्चा भर दिया। मौलाना नदवी ने कहा कि उनका नाम खुद अखिलेश यादव ने फाइनल किया है, उन्हीं के कहने पर उन्होंने अपना पर्चा भरा है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वही हैं। इसके तुरंत बाद आजम खां के करीबी आसिम रज़ा भी पर्चा भरने पहुंच गए। उन्होंने भी पर्चा दाखिल कर दिया। इस बात में कोई शक नहीं कि रामपुर पर एक लंबे अर्से तक आजम खान का कब्जा रहा है, वो रामपुर के चप्पे-चप्पे को जानते हैं। यहां के बच्चे-बच्चे को पहचानते हैं लेकिन अब मजबूर हैं। जेल में बंद हैं। उन पर सैंकड़ों केस हैं। योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में उनका दबदबा खत्म कर दिया। रामपुर में आज़म खान के उम्मीदवारों को हरा दिया पर आज़म खान आसानी से हार मानने वालों में नहीं हैं। वो जेल में रहकर भी इस इलाके की सियासत पर खासा असर डाल सकते हैं। उनका ये सुझाव कि रामपुर से अखिलेश को लड़ना चाहिए, अच्छा था लेकिन अखिलेश इन चुनावों में एक-एक कदम फूंक-फूंक कर रख रहे हैं। अखिलेश के लिए ये चुनाव अस्तित्व का सवाल है। हालांकि वो आज़म खान की बात सुनते हैं लेकिन रामपुर से चुनाव लड़ने की बात नहीं मानी, इसीलिए इतना कन्फ्यूजन पैदा हुआ। दूसरी तरफ भाजपा ने जबरदस्त चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ, मथुरा, गाजियबाद में प्रचार कर रहे हैं। रामपुर और मुरादाबाद के बाद मेरठ का भी नाम इसमें जुड़ गया है . ये उत्तर प्रदेश में वो तीन सीट हैं, जिनपर समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिला। हर बार की तरह इस बार भी सपा में टिकट को लेकर भारी असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है।

मेरठ से जब भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया , तो दूसरी तरफ सपा प्रत्याशी का ऐलान कर बार-बार बदलाव कर रही है। मेरठ लोकसभा सीट पर सपा ने एक बार फिर अपना प्रत्याशी बदला दिया है। अतुल प्रधान की जगह अब पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को उम्मीदवार घोषित किया है।समाजवादी पार्टी ने पहले मेरठ सीट से एडवोकेट भानू प्रताप सिंह को टिकट दिया गया था, लेकिन भानू प्रताप के नाम पर पार्टी के स्थानीय नेताओं ने नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने मेरठ सीट पर सरधना से विधायक अतुल प्रधान को प्रत्याशी घोषित कर दिया। अतुल प्रधान का ऐलान होते ही पार्टी में बगावत छिड़ गई। मेरठ शहर विधायक रफीक अंसारी ने मेरठ सीट पर दावा ठोक दिया है। अब अखिलेश यादव ने पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। वैसे चुनावी मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आज शाम तक और भी कई उम्मीदवारों के टिकट बदले जा सकते है ।

मेष राशि– आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसकी बातों से आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। मुमकिन है कि आपके अतीत से जुड़ा कोई शख़्स कल आपसे संपर्क करेगा और इस दिन को यादगार बना देगा। ऑफिस में आपका अच्छा काम देखकर कलीग आपसे कुछ नया सीखेंगे। आप लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे इससे आपको गर्व महसूस होगा। किसी गरीब की सहायता करने से मन को सुकून मिलेगा।

वृष राशि– आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आज व्यापार में अच्छा लाभ होने से आप अपनी नयी ब्रांच ओपन करने का विचार अपने घर के साथ करेंगे। आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलने से कोई बड़ी समस्या का समाधान कर लेंगे। आज प्रैक्टिकल सोच रखेंगे तो आपके संतुलित रवैया से फायदा मिलेगा। इस राशि के जो लोग संगीत के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन शुभ है। आज आप किसी से बेवजह बहस से बचें यही आपके लिए बेहतर रहेगा।

मिथुन राशि– आज आपका दिन बेहतर रहेगा। आप किसी अपने के साथ बहस करने से बचे, जिससे आपका समय बचेगा। ऑफिस में आज आपके ड्रेसिंग सेंस के बारे में तारीफ करेंगे। लवमेट में चल रही अनबन आज समाप्त होगी लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। समाज में आपके अच्छे कामों की वजह से आपका सम्मान बढ़ेगा। बिजनेस को लेकर दूसरे लोगों से संपर्क बनाना बेहतर रहेगा।

कर्क राशि– आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आप जिस काम को काफी दिनों से करने की सोच रहे थे उस काम की शुरुआत आज से कर सकते हैं। दान धर्म के कार्य में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे। भाई व बहनों से चल रही अनबन बातचीत के जरिए समाप्त होगी। जल्द ही आपको काम के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जो लोग आपके विरोधी थे वो लोग भी आज आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं।

सिंह राशि–आज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा रहने वाला है। ज्यादा व्यस्त रहने के कारण आप अपने आसपास ध्यान नहीं दे पाएंगे। अपनों के प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। सभी क्षेत्रों में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप परिवार के सदस्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, क्योंकि आप उनसे किए हुए वादों को पूरा करेंगे। रचनात्मक कार्य में आप सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे।

कन्या राशि– आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है।आज किसी भी कानूनी मामलों में जल्दबाजी न दिखाएं। अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखेंगे तो भविष्य में आने वाली परेशानियों से भी बच जायेंगे। आज अपने काम को सामान्य गति से पूरा करेंगे। किसी नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो दिन शुभ है आप कर सकते हैं आपको काम में सफलता मिलने के अच्छे योग बनते दिख रहे हैं।

तुला राशि– आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त करेंगे। शासन व प्रशासन के मामले में सावधानी बरतें। आज निवेश संबंधी मामलों को गति मिलेगी। आज किसी अजनबी पर सोच समझकर भरोसा करें। विद्यार्थियों को मानसिक बोझ से छुटकारा मिल सकता है। प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। आज आपके दांपत्य जीवन में खुशहाली बढ़ेगी।

वृश्चिक राशि– आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा। आज आपके बढ़ते खर्चे परेशानी का कारण बन सकते हैं इसीलिए बजट बनाकर चलने का प्रयास करें। किसी संपत्ति का सौदा जल्दबाजी में ना करें। राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को बड़े नेताओं से मिलने का अवसर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी उन्नति का मार्ग प्रसस्त होगा।

धनु राशि–आज का दिन आपके लिए निश्चित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपकी योजनाओं को गति मिलेगी। आज आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। अपने जरूरी कामों की सूची बनाएंगे जिससे काफी हद तक करने में सफल रहेंगे। आज आपको बड़ों का साथ व सहयोग भरपूर मात्रा में मिलेगा।

मकर राशि– आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज किसी नए काम को शुरू करने से पहले पूरी योजना बनाएंगे और साथ ही माता-पिता से सलाह लेंगे। आज सरकारी कामों में नीति व नियमों पर पूरा ध्यान देंगे तो आपको काम करने में आसानी होगी। आज आपको आर्थिक मामलों में जल्दबाजी दिखाने से बचना होगा। आप की वाणी की सरलता आपको मान-सम्मान दिलाएगी।

कुंभ राशि– आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज आपका मन धार्मिक कार्यों की तरफ रहेगा। लोगों के बीच आपके काम की तारीफ होगी। आज आर्थिक लाभ पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। माता-पिता अपने बच्चों को मनोरंजन के लिए बाहर घूमाने ले जा सकते हैं। महिलाएं अपने किसी काम की प्लानिंग करेंगी।

मीन राशि– आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। किसी काम के लिए की गई आपकी मेहनत रंग लायेगी। करियर के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। किसी काम के पूरे होने पर आपको प्रसन्नता होगी। आज कार्यस्थल पर हर कोई आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा। आपको काम में सीनियर्स का पूरा-पूरा साथ मिलेगा। आपको व्यापार में अचानक धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा।

भाजपा ने राजनीति को सेवा करने का सर्वोत्तम माध्यम बनाया

डॉ. आशीष वशिष्ठ

देश के राजनीतिक इतिहास में छह अप्रैल का दिन खास अहमियत रखता है। "अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा " भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने आज ही के दिन, 1980 में यानी 44 साल पहले, पार्टी की स्थापना के समय ये शब्द कहे थे। शायद उन्होंने यह बात पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कही होगी लेकिन उस समय पार्टी कार्यकर्ताओं या फिर विपक्षी दलों में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आने वाले दिनों में अटल जी की बातें सही साबित होंगी। 1984 के लोकसभा चुनाव में केवल दो सीटें हासिल करने से लेकर 2019 के चुनाव में 303 सीटें जीतने वाली भाजपा ने अपने इस शानदार सफर में कई उतार-चढ़ाव भी देखे, बड़े झटके भी खाए और मायूसी भी महसूस की। धरातल पर बदलाव लाने के लिए राजनीति सबसे सशक्त माध्यम है। राजनीति के माध्यम से हम समाज के दबे-कुचले लोगों और उपेक्षित समुदायों को ऊपर उठाते हुए सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को दूर करने का भरसक प्रयास कर सकते हैं। एक व्यापक बदलाव लाने का जो कार्य, बड़े से बड़े वेतन वाली प्रतिष्ठित नौकरी करके भी नहीं किया जा सकता है, उसे राजनीति के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। इसी सिद्धांत पर चलते हुए भाजपा ने आरंभ से ही राजनीति को सत्ता की बजाय सेवा का माध्यम माना है। आजादी के बाद के लंबे कालखंड तक भारतीय राजनीति में परिवार और व्यक्ति केंद्रित दलों ने राजनीति को कमाई का जरिया बनाया और सेवा भाव को नदी के जलधारा में प्रवाहित कर दिया। बीच-बीच में केंद्र की सत्ता पर आसीन गैरकांग्रेसी सरकारों ने लोक कल्याण के लिए कुछ करने की सोची तो उन्हें अस्थिर कर दिया गया। 2014 में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में पूर्ण बहुमत की एनडीए सरकार का गठन हुआ, तब से तस्वीर में बदलाव आया है। पिछले दस वर्षों में आम आदमी को इस बात का आभास हुआ है कि राजनीतिज्ञ अगर सेवा करने के भाव से राजनीति करें तो कितना बड़ा और व्यापक बदलाव देश और आम आदमी की जिंदगी में लाया जा सकता है। भाजपा की रीति-नीति और संकल्पों की डगर पर चलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह साबित कर दिया कि राजनीति सेवा का सबसे सशक्त माध्यम है। परिवारवादी दल जो अपने परिवारजनों के विकास और उत्थान में सारी ऊर्जा खपाते हैं, वह राजनीति को सेवा का नहीं, बल्कि मेवा का माध्यम मानते हैं। उनकी डिक्शनरी में परिवार पहले और देश बाद में आता है। तीन मार्च, 2024 को बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली में इंडी अलांयस की रैली में बोलते हुए राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवारवाद वाली टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा था कि उनकी कोई संतान नहीं है। वो पत्नी के साथ नहीं रहते। कैसे जानेंगे कि परिवार क्या होता है? लालू प्रसाद की आपत्तिजनक टिप्पणी के अगले दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तेलंगाना के आदिलाबाद में जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने विपक्ष की ओर से उनके परिवार को लेकर किए गए हमले का परोक्ष रूप से जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, 'मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं, तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार हैं। जिनका कोई नहीं है, वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत ही मेरा परिवार है।' जो दल एक परिवार या व्यक्ति द्वारा द्वारा संचालित हो रहे हैं, उनके लिए परिवार ही सर्वोपरि है। उनकी सारी ऊर्जा परिवार के विकास और कल्याण में ही खर्च होती

है। उनके एजेंडे में आम आदमी का विकास और कल्याण अंतिम पायदान पर होता है। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की विचारधारा ने भारतीय राजनीति की इसी विचारधारा को पलटने का काम किया है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के अन्य नेता कहते हैं कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। विपक्ष के लिए तो फैमिली फर्स्ट इसे सारा देश अब अनुभव करने लगा है। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने भी अर्जुन को राजनीति और कूटनीति के माध्यम से राज्य, धर्म एवं समाज की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया है। धर्म के विपरीत आचरण करने वालों और सत्ता, सुख-संपदा, धन-वैभव एवं ऐश्वर्य के लिए जीने वालों को उन्होंने समस्त संसार के लिए विनाशकारी बताया है। इसलिए हमारी राजनीति के विमर्श में लोकमंगल की भावना होना बहुत आवश्यक है। राजनीति को सत्ता पाने का अवसर मानने वाली अनैतिकता ही अस्वस्थ राजनीतिक परंपरा को पोषित करती रहती है। यदि राजनीति की ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाया जाए और नैतिकता, मूल्यों एवं आदर्श का समावेश करते हुए सेवाभाव से कार्य किया जाए तो एक स्वस्थ, सक्षम एवं सजग समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। भाजपा के चाहे दो सांसद रहे हों या 303 भाजपा ने राजनीति को हमेशा सेवा का माध्यम माना। और ये बात उसके चरित्र और आचरण से झलकती भी है। राजनीति का चरित्र-चित्रण, उसके नेतृत्व में प्रतिबिंबित होता है। सही राजनीतिक नेतृत्व किसी भी संस्था या अभियान को जन-जन के बीच पहुंचा सकता है और उसे जनभागीदारी का प्रतीक बना सकता है। वैश्विक महामारी कोरोना के समय में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वर्तमान भारत सरकार ने जिस प्रकार से गरीबों एवं असहायों की सहायता के लिए राजनीतिक दूरदृष्टि के साथ शासन एवं प्रशासन का कार्य किया है, वह संस्थाओं के नेतृत्व का श्रेष्ठ उदाहरण है। कोरोना के समय विपक्ष ने नकारात्मक भूमिका निभाई। देश में बनी वैक्सीन से लेकर तमाम व्यवस्थाओं का उपहास उड़ाया। देश की जनता को भ्रमित करने का काम किया। इसमें कोई दोराय नहीं है कि विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले भारत जैसे देश में कोरोना के संकट से निपटते हुए गरीबों, मजदूरों, किसानों, शोषितों और वंचितों के हितों की रक्षा करने से लेकर देश की आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने तक का कार्य, किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन संकट के ऐसे समय में प्रधानमंत्री ने देश के सभी राजनीतिक दलों को एक साथ जोड़ने का समेकित प्रयास करते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने और जन-कल्याण करने के लिए सरकार की भावी प्राथमिकताओं और योजनाओं को धरातल पर उतारा है। राजनीति का मूल उद्देश्य जनता के सामाजिक-आर्थिक कल्याण को अधिकतम करना है। यदि राजनीति का पूरी तरह से सही और सकारात्मक दिशा में प्रयोग की जाए तो विकास के नए शिखर छुए जा सकते हैं, मानवता की सेवा की जा सकती है और देश को निरंतर आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी साफ-सफाई जैसे छोटे से बिंदु से लेकर गरीबों को आवास की सुविधा के बारे में एक साथ सोचते हैं। उनकी सोच के दायरे में किसान, महिलाएं, युवा, दलित, आदिवासी, वंचित और देश का एक-एक नागरिक है। प्रधानमंत्री मोदी में सेवा के गुण पार्टी की रीति-नीति और विचारों की वजह से प्रभावी हैं, क्योंकि भाजपा के संस्थापकों ने सेवा भाव से ही राजनीतिक क्षेत्र में कदम बढ़ाया और अपनी आने वाली पीढ़ियों में भी सेवाभाव को कूट-कूट कर भरने का काम किया। कहा जाता है कि व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। प्रधानमंत्री ने देश की और देशवासियों की सेवा करने में दिन-रात एक किया। आज आदमी अपना भला-बुरा सब बहुत अच्छे से समझता है। उसे पता है कि कौन राजनीति को सेवा का माध्यम मानता है, और कौन सत्ता हासिल करके अपना पेट भरना चाहता है। इसलिए देशवासी विपक्ष के दुष्प्रचार, प्रलोभन और मायाजाल में नहीं फंसे। वर्तमान में देश में आम चुनाव का माहौल है। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मैदान में है। देश की जनता भलीभांति यह समझ चुकी है कि उसका कल्याण और उत्थान वही व्यक्ति कर सकता है जो 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार समझता है। जो बिना किसी भेदभाव और पूर्वाग्रह के प्रत्येक व्यक्ति की सेवा में जुटा रहता है। वर्ष 2023 में भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा था, ''आज अस्तित्व के संकट से जूझ रही पार्टियां हमारे खिलाफ साजिश करती रहेंगी। लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि गरीब, वंचित, दलित, आदिवासी 'कमल' की रक्षा कर रहे हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दोहरा मानक

किसी भी ममालेमें दोहरे मानकसे अच्छे परिणामोंकी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। आतंकवाद ऐसा वैश्विक मामला है जिसका दंश पूरा विश्व झेल रहा है। इसका प्रमुख कारण आतंकवादके बारेमें दोहरे मानकका बरकरार रहना है। ऐसी स्थितिमें हम आतंकवादपर पूर्ण अंकुश लगनेकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। भारत आतंकवादके मामलेमें दोहरे मानकका प्रबल विरोधी है और वैश्विक मंचोंसे वह पूरे विश्वके लिए एक समान मानक अपनाये जानेपर जोर देता रहा है लेकिन आजतक इसपर सहमति नहीं बन पायी, जिसका दुष्परिणाम पूरा विश्व भोग रहा है। इस सन्दर्भमें कजाकिस्तानकी राजधानी अस्तानामें बुधवारको आयोजित शंघाई सहयोग संघटन (एससीओ) के सुरक्षा सम्मेलनमें भारतके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभालने आतंकवादके मामलेमें दोहरे मानकके खिलाफ फिर आवाज बुलन्द की है, जो पूरी तरहसे उचित है। उन्होंने कहा कि आतंकवादके खतरेसे निबटनेमें दोहरे मानकको छोड़ना होगा, क्योंकि यह पूरी तरहसे गलत है। इसलिए एक मानक बनाना होगा जिससे कि आतंकवादके साजिशकर्ताओंसे प्रभावी ढंगसे तेजीसे निबटा जा सके। डोभालने यह भी कहा कि सीमापार आतंकवाद सहित कहीं भी अंजाम दिये गये कृत्यको कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने इस मुद्देपर पाकिस्तानपर निशाना साधते हुए लश्कर, जैश जैसे आतंकी संघटनोंका भी उल्लेख किया और कहा कि आतंकवादके दोषियोंपर कठोर काररवाई जरूरी है। पाकिस्तानके आतंकवादी चेहरेको बेनकाब करनेमें भारत कोई कोताही नहीं करेगा। इसका सीधा अर्थ यह कि भारत आतंकवादके मुद्देपर अपनी पुरानी रणनीतिपर अडिग है। यह उन देशोंके लिए सन्देश भी है, जो दोहरे मानकका सहारा लेकर आतंकवादको बढ़ावा देते हैं। पाकिस्तान इसमें सबसे आगे है और आतंकवाद उसकी नीतिका हिस्सा है। डोभालने इस मामलेमें पाकिस्तानके मित्र देश चीनको भी लपेट लिया। उन्होंने मजबूतीसे कहा कि आतंकवादके मुद्देपर दोहरापन अब नहीं चलेगा। सीमापार आतंकवाद सहित आतंकवादकी किसी भी वारदातको जायज नहीं ठहराया जा सकता है। आतंकवादका स्वरूप और उसकी गतिविधियां अत्यन्त भयावह हैं। आतंकवाद मानवके लिए गम्भीर खतरा है। यदि इसे समूल नष्ट करनेका एकजुट प्रयास नहीं किया गया तो इसके गम्भीर परिणामोंसे इनकार नहीं किया जा सकता है। आतंकवादपर तभी प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है जब दोहरे मानकका परित्याग कर एकजुट और समुचित प्रयास किये जायं।

पीओकेपर बड़ा बयान

पाकिस्तानअधिकृत कश्मीर (पीओके) अखण्ड भारतकी जम्मू-कश्मीरका वह हिस्सा है जो पाकिस्तानकी सीमासे लगता है। साल १९४७ में बंटवारेके बाद पाकिस्तानने कबिलाई विद्रोहियोंकी मददसे जम्मू-कश्मीरके इस हिस्सेपर कब्जा कर लिया था। इस सम्बन्धमें पाकिस्तानअधिकृत कश्मीर मीरपुरके अवामी एक्शन कमेटीके प्रमुख नेता आरिफ चौधरीका यह कहना अत्यन्त महत्वपूर्ण और पाकिस्तानी हुक्मरानोंको सचाईसे रू-ब-रू करानेवाला है कि पीओके संवैधानिक रूपसे पाकिस्तानका हिस्सा नहीं है। मीरपुर गुलाम कश्मीरका एक प्रमुख शहर है जहां एक प्रेस कांफ्रेंसमें चौधरीने पाकिस्तानके अनुच्छेद २५७ का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि गुलाम कश्मीर (पीओके) पाकिस्तानका हिस्सा नहीं है। इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है जहां कहनेको पीओकेकी अपनी सरकार है, परन्तु वहांका प्रशासन पाकिस्तान सरकार ही चलाती है। पाकिस्तानकी सरकारने इस क्षेत्रपर अपनी पकड़ मजबूत रखनेके लिए अपने यहां कश्मीर अफेयर्स एण्ड गिलगित बाल्टिस्तान नामसे अलग मिनिस्ट्री बना रखी है। पाकिस्तान पीओकेको दो हिस्सोंमें बांट रखा है। पाकिस्तान पीओकेको छोड़नेके लिए तैयार नहीं है और उसे आजाद कश्मीर बताता है साथ ही सभी वैश्विक मंचोंपर इसे उठाते हुए अनर्गल प्रलापका सहारा लेकर भ्रमित करनेका अथक प्रयास करता है। हालांकि भारत सकार समय-समयपर पीओकेको वापस लेनेकी बात करती रही है। जम्मू-कश्मीरसे धारा ३७० खत्म किये जानेके बाद तो यह मुद्दा ज्यादा गरमा गया है और पीओकेको वापस लेनेकी मांग जोर-शोरसे मुखर होती जा रही है जो सर्वथा उचित है। भारतकी अखण्डताका इस तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। जम्मू-कश्मीर हमेशासे भारतका हिस्सा रहा है और रहेगा। अब समय आ गया है कि गुलाम कश्मीरको वापस लेनेके लिए सरकार कोई ठोस और सार्थक कदम उठाये।

लोक संवाद

गुरु नानकजीका दर्द

महोदय,-मक्कासे अपनी घरवापसीके दौरान श्री गुरुनानक देव जी सैय्यदपुर रुके, जो वर्तमानमें पाकिस्तानमें है, अपने प्यारे सिख लालोको मिलनेके लिए, जो एक गरीब बढ़ई था। सैय्यदपुरके निवासियोंका दर्दनाक हाल देखकर गुरु नानक देव जीने लिखा था कि खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया...। गुरु नानक देव जी एक भयानक कत्लेआमका उत्तर दे रहे थे जो उज्बेक बाबरने अंजाम दिया था, जब वह दिल्लीके तख्तपर कब्जा करनेके लिए लोधियोंसे लड़नेकी तैयारी कर रहा था। गलियां खूनसे लथपथ थीं, हर ओर शवोंके ढेर थे, चारों ओर मौत तथा तबाही थी। गुरुनानक देव जीकी दर्दकी पुकार सिख धर्मके बुनियादी सिद्धांतोंमें एक बन गयी कि आप भयानक अन्याय तथा जुल्मके सामने चुप नहीं रहोगे। लगभग १०-१२ वर्ष पहले मेरी बेटी मेहर कौर, जो उस समय कालेजकी छात्रा थी, ने मेरी एक कवितापर आधारित एक नाटक कुलतारस माइम बनाया जो मैंने कई वर्ष पहले लिखी थी। इस कवितामें १९८४ में दिल्लीमें हुए सिखोंके कत्लेआमकी कहानी बयान की गयी थी। जब हम नाटकको टूरपर ले जानेके लिए तैयार हो रहे थे तो मैं एक अन्य कवितासे वाकिफ हुआ जिसने वही कहानी सुनायी थी। बेशक किसी अन्य समय तथा स्थानसे १९०३ में किशीनेवमें निर्दोष यहूदियोंके कत्लेआम बारे प्रसिद्ध इसरायली कवि हेइम नाहमन बिआलिक द्वारा लिखी इन द सिटी आफ स्लॉटर। मैं अपनी कविता तथा बिआलिककी कविताके बीच समानताओंसे हैरान था। नाटकमें मेहर कौरने मेरी कविताके साथ बिआलिककी कविताके अंश शामिल कर दिये। तब हमने अपने कलाकारोंके साथ दुनियाका दौरा किया तथा कुलतारस माइमको ९० से अधिक बार भावुक श्रोताओंके सामने पेश किया, किशीनेवके यहूदियोंका दर्द दिल्लीके सिखोंके दर्दके साथ मिल गया, क्योंकि सभी जुल्म करनेवाले तथा सभी पीड़ित एक जैसे हो गये हैं। लाखों अन्यकी तरह मैं भी साहित्य, फिल्मों, शानदार वृत्तांतक नावल मौस तथा अन्य कई लेखों द्वारा यहूदी घल्लूघारेके इतिहाससे जुड़ा हूं जो यहूदी लोगोंके दर्द, बहादुरी तथा संघर्षको बयान करते हैं। यह जानकारी मेरे भीतर यहूदी कौमके लिए हमदर्दीकी गहरी भावना तथा उनकी पुनः उबरनेकी शक्तिके लिए कद्र पैदा करती है। बाकी दुनियाकी तरह मैंने वे तस्वीरें देखीं जो हमास द्वारा दो अक्तूबरके वहशी हमलोंके बाद इसरायलसे आयीं। निर्दोषोंको बेदर्दीसे निशाना बनाया गया। एक बार फिर दिल उन निर्दोषोंके लिए तड़पा जो दर्दसे चीख रहे थे। यह पक्का था कि इसरायलका कहर गाजा पर टूटेगा। वह दर्द केवल यहूदी लोग ही समझ सकते हैं। श्रीगुरु नानक देव जीके आदर्शोंके अनुसार जीवन व्यतीत करनेवाले सिख होनेके नाते मैं इस बुनियादी सिद्धांतको त्यागनेके लिए बहुत शर्म महसूस करता हूं। शायद अबतक इस विषयपर चुप रहना एक किस्मका विश्वासघात है। मैं अपनी बेटीको आशीष देता हूं, जिसने इन लफ्जोंसे मेरे सोये हुए जमीरको जगाया है- मैंने बचपनसे आपको गुरुनाकक देवजीके सिद्धांत बारे बात करते सुना है। यहूदियोंका दर्द हमारा दर्द नहीं है। मैं और चुप नहीं रहूंगा। अब रूस हो या इसरायल युद्धको रोकना ही होगा। इसरायल शासनको अपनी रक्षा करनेका पूरा अधिकार है, यहूदी लोगोंके ऐतिहासिक दुख रूसियों और इसरायलियोंको निर्दोष निर्दोषों मारनेका हक नहीं दे सकते। जिनका जमीर अब भी जागता है, चाहे वह कोई भी हो अथवा कहीं भी रहते हों, उनको बुलंद आवाजमें बोलनेकी जरूरत है। उन सभीको मैं गुरु नानक देव जीके इन शब्दोंसे संबोधित करता हूं-

तैं की दर्द न आया
आप चुप कैसे रह सकते हो? -सर्बप्रीत सिंह, वाया ईमेल।

भ्रष्टाचारके मुद्देपर घिरा विपक्ष

भ्रष्टाचारके मुद्देपर विपक्ष बुरी तरह घिर चुका है। यह वह सचाई है, जिससे विपक्ष मुंह तो फेर सकता है, लेकिन बच नहीं सकता। मोदी सरकारने विपक्षकी नसको दबा दिया है। विपक्षकी चीख देशको सुनाई दे रही है। परन्तु लाख यत्नके बाद भी पिछले दस सालोंमें मोदी सरकारके खिलाफ भ्रष्टाचारका कोई मुद्दा खोज नहीं पाया है।

❒ **राजेश माहेश्वरी**

विपक्ष मोदी सरकारपर भ्रष्टाचारके आरोप भले ही लगाता हो, लेकिन उसके पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं जिसे वह देशके सामने रख पाया हो। ऐसेमें बार-बार मोदी सरकारको बदनाम करनेकी नीयतसे जब वह ऐसे आरोप लगाता है तो खुद उसकी छविको गहरी ठेस लगती है। वहीं आम आदमीका उससे विश्वास भी कम होता है। पिछले दस सालोंमें मोदी सरकारकी बढ़ती लोकप्रियता और विपक्षकी घटतीकी साखकी यही वजह है कि विपक्ष केवल सनसनी मचाने और मोदी सरकारको बदनाम करनेकी मंशासे आरोप लगाता है, जबकि उसके हाथमें मोदी सरकारके खिलाफ ठोस प्रमाण है ही नहीं। मोदी सरकारने सत्ता संभालनेके साथ ही भ्रष्टाचारके खिलाफ जो जंग छेड़ी थी, अब वह गति पकड़ती दिखाई देती है। खासकर राजनीतिक भ्रष्टाचारके खिलाफ की जा रही काररवाई सराहनीय है। पूर्वमें राजनीतिक भ्रष्टाचारपर आपसी सहमति रहती थी। मंचसे भले ही नेता एक दूसरेके विरोधमें कड़वी बयानबाजी और विरोधीको भ्रष्टाचारी कहनेके बावजूद सत्तामें आनेके बाद काररवाईसे परहेज करते थे। आजादीके बादसे राजनीतिक भ्रष्टाचारपर चुप्पी साधना एक परम्पराका हिस्सा बन चुका था। लेकिन मोदी सरकारने भ्रष्टाचारके मुद्देपर कोई रियायत देनेकी बजाय राजनीतिक भ्रष्टाचारपर सख्त कदम उठाकर नजीर कायम की है।

२०२४ के आम चुनावोंके ऐलानके बाद दिल्लीके मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवालकी गिरफ्तारीने यह सिद्ध कर दिया है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र तौरपर अपना काम कर रही हैं। यदि ऐसा न होता तो जांच एजेंसी या सरकार किसी विपक्षी नेताको चुनावके मौकेपर गिरफ्तार करनेका रिस्क कभी न लेती। राजनीतिक भ्रष्टाचारपर हो रही लगातार सख्त एक्शनके बाद पिछले दिनों राजधानी दिल्लीके ऐतिहासिक रामलीला मैदानमें विपक्षी गठबंधन इंडियाने रैली कर मोदी सरकारपर कड़े हमले किये। रैलीको संबोधित करनेवाले इंडिया गठबंधनके अधिकतर नेताओंने देशको आगाह किया कि यदि तीसरी बार भी मोदी सरकार बनी तो देशका संविधान बदलनेकी शुरुआत होगी। शासन और भी एकाधिकारवादी हो जायगा। भारत रूस बन सकता है। लोकतंत्रकी आत्मा खत्म कर दी जायगी। जिस तरह रूसपर पुतिनका राज है, उसी तरह भारतमें मोदीकी स्थिति होगी। यह आशंका कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गेने जतायी थी। संविधानको बदलनेकी बात राहुल गांधीने की, जिन्हें किन्हीं भाजपा नेताओंने 'ब्रीफ' किया था। यहांतक आगाह किया गया कि देशमें आग लग जायगी। इसके अलावा विपक्षी नेताओंने रोजगारका संकट, बेरोजगारी, महंगी, किसानोंका एमएसपी, जांच एजेंसियोंकी निरंकुशता और प्रशासन आदिके साझा मुद्दे उठाकर अपने लोकसभा चुनाव अभियानको गति दी। रैलीमें दिल्लीके मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवालकी पत्नी सुनीता केजरीवालने भी अपने संबोधनमें मोदी सरकारपर तीखे हमले तो किये ही वहीं देशकी जनताको गांरटियोंका लालीपाप भी दिया। लोकतंत्र बचानेकी आड़में जिस तरह भ्रष्टाचारके आरोपोंमें घिरे तमाम नेता रैलीके मंचपर मौजूद थे, उससे आम आदमीमें यह संदेश गया कि भ्रष्टाचारियोंके मनमें डर है। जनतामें इस बातकी खुशी है कि कानून अपना काम कर रहा है और भ्रष्टाचारी चाहे किसी पदपर बैठा हो, उसको सलाखोंके पीछे एक दिन जाना ही होगा। जिस दिन विपक्षकी रैली थी उसी दिन दिल्लीसे ७० किलोमीटर दूर क्रांतिधरा मेरठमें प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीने चुनाव अभियानकी शुरुआत की। मेरठ रैलीमें प्रधान मंत्री मोदीने विपक्षपर चुन-चुनकर हमले तो बोले ही। वहीं उन्होंने भ्रष्टाचारपर विपक्षको घेरनेका काम किया। प्रधान मंत्रीने भ्रष्टाचारके मुद्देपर चुनावी लड़ाईकी चेतावनी भी कबूल की और देशसे साझा किया कि भ्रष्टाचारके खिलाफ काररवाई जारी रहेगी, क्योंकि जनताका जो पैसा लूटा गया है, वह उसे लौटा रहे हैं। अभीतक १७,००० करोड़ रुपयेसे अधिक लोगोंको वापस किये जा चुके हैं, यह प्रधान मंत्री मोदीने दावा किया। प्रधान मंत्रीने भ्रष्टाचारके खिलाफ लड़ाईको मोदीकी गारंटी करार दिया और कहा कि वह विपक्षके रुदन और चिल्लानेसे घबरानेवाले नहीं हैं। विपक्षको यह बात गांठ लेनी चाहिए और देशके राजनीतिक इतिहाससे सबक लेना चाहिए कि देशमें जब-जब चुनावका मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान रहा, तब-तब भ्रष्टाचारका बचाव करनेवालोंकी हार ही हुई है। आजादीके तत्काल बादसे ही तत्कालीन कांग्रेस सरकारपर भ्रष्टाचारके आरोप लगने शुरू हो गये थे, परन्तु १९६२ तक लोग कांग्रेस और उसके नेताओंके प्रति मोहित थे। इसलिए बहुत बातें नजरअंदाज होती रहीं। तब प्रतिपक्ष भी काफी बिखरा था। इसके बाद भी कांग्रेस जब भी सत्तामें आयी, उसे ५० प्रतिशतसे कम ही मत मिले। १९६७ में जब गैर-कांग्रेसी दलोंमें सीमित चुनावी एकता हुई तो देशके नौ प्रदेशोंमें कांग्रेस सत्तासे बाहर हो गयी। यदि थोड़ी और अधिक दलीय एकता हुई होती तो केन्द्रकी सत्तासे भी कांग्रेस बाहर हो गयी होती।याद रहे तब चुनावका मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार था। उससे पहले कांग्रेस आत्ममुग्धताकी स्थितिमें थी। कोई घोटाला साबित हो जानेपर भी सत्ताधारी नेता कहा करते थे कि विपक्षमें ताकत है तो चुनावमें दिखाये। जीप घोटालेमें जांच कमेटीने वीके कृष्ण मेननको दोषी माना फिर भी तत्कालीन केन्द्रीय स्वराष्ट्रमंत्रीने संसदमें कह दिया कि इस मामलेको बंद कर दिया गया है। जब विपक्षने दोषीको सजा देनेकी मांगपर जोर दिया तो सरकारने कहा कि इसका फैसला अगले चुनावमें हो जायगा। इसी तरह बारी-बारीसे मूंदड़ा कांड, धर्मतेजा ऋण घोटाला, प्रताप सिंह कैरों घोटाला आदि होते रहे। उस दौरान प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सरकारोंके भ्रष्टाचारके खिलफ देशभरमें अभियान चलाते रहे। मतदाताओंपर उस अभियानका असर हुआ। उन्होंने १९६७ के आम चुनावमें कांग्रेसको काफी हदतक सबक सिखा दिया। आज जिस तरहसे इंडिया गठबंधनके साथ एक-दूसरेके भ्रष्टाचारपर पर्दा डालनेका काम कर रहे हैं। उससे आम जनताके बीच जो संदेश जा रहा है वह साफ है। असलमें देशकी जनता विपक्षका चरित्र और चेहरा काफी हदतक पहचान चुकी है। मोदी सरकार बिना रुके और बिना डरे जिस तरहसे भ्रष्टाचारके खिलाफ काररवाई जारी रखे हुए है वह काबिलेतारीफ है। हां, भ्रष्टाचारके मामलोंमें जांच और काररवाईमें कोई पक्षपात या भेदभाव नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार चाहे सरकारमें बैठे व्यक्तिका हो या विपक्षके नेताका सबपर एक तरहसे काररवाई करके कानूनका राज स्थापित होना चाहिए। इसीमें देश और देशवासियोंका कल्याण निहित है।

विपक्षको इतिहाससे सबक लेना चाहिए कि देशमें जब-जब चुनावका मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान रहा, तब-तब भ्रष्टाचारका बचाव करनेवालोंकी हार ही हुई है। आजादीके तत्काल बादसे ही तत्कालीन कांग्रेस सरकारपर भ्रष्टाचारके आरोप लगने शुरू हो गये थे, परन्तु १९६२ तक लोग कांग्रेस और उसके नेताओंके प्रति मोहित थे। इसलिए बहुत बातें नजरअंदाज होती रहीं। इसके बाद भी कांग्रेस जब भी सत्तामें आयी, उसे ५० प्रतिशतसे कम ही मत मिले। १९७७ में जब गैर-कांग्रेसी दलोंमें चुनावी एकता हुई तो नौ प्रदेशोंमें कांग्रेस सत्तासे बाहर हो गयी।

महाराष्ट्रमें धराशायी विपक्ष

राज ठाकरेके लिए दक्षिण मुंबई और शिर्डी सीटोंपर जीत सुनिश्चित करना अब आसान होगा, क्योंकि राजगमें आनेके बाद राज ठाकरेके सामने केवल शिवसेना (यूबीटी) ही है, जबकि भाजपासे तालमेल न होनेपर तिहरा प्रहार झेलना पड़ता।

❒ **चेतनादित्य आलोक**

लोकसभा चुनावकी तारीखोंका ऐलान होनेके बाद महाराष्ट्रके दोनों प्रमुख गठबंधनों राजग और महाविकास आघाड़ी (एमवीए) के बीच राजनीतिक संग्राम दिनोंदिन तेज होता जा रहा है। हालांकि दोनों गठबंधनोंकी ओरसे जारी दांव-पेंचोंके बीच भाजपाकी ओरसे चली गयी महज एक चालमें ही समस्त विपक्षी पार्टियोंके हौसले पस्त हो गये प्रतीत होते हैं। दरअसल भाजपाने राज्यमें राज ठाकरे नीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के साथ चुनावी तालमेल कर राज्यके तमाम राजनीतिक समीकरणोंको एक झटकेमें ही धराशायी कर दिया है। देखा जाय तो राज ठाकरेके राजगमें आ जानेके बाद शिवसेनाके उद्धव गुट यानी शिवसेना (यूबीटी) पर कांग्रेस और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) वाले महाविकास आघाड़ी यानी वीबीए (फिलहाल एमवीएसे बाहर) की नीतियों और एजेंडेको छोड़ने तथा अपने राजनीतिक एजेंडेमें पहलेकी भांति 'हिंदुत्व' एवं 'मराठी मानुस' को प्रमुखता से शामिल करनेका दबाव काफी बढ़ गया है, क्योंकि ऐसा नहीं करनेपर हिंदुत्व एवं मराठी मानुसके प्रभाववाली सीटोंपर मनसे, शिवसेना शिंदे गुट और भाजपा वाले 'राजग' गठबंधनके मैदान मार ले जानेकी पूरी संभावना है। दरअसल उद्धव ठाकरेको मालूम है कि महाविकास आघाड़ी, विशेष रूपसे कांग्रेसकी राजनीति मुख्यत: हिंदुत्व एवं हिंदू विरोधवाली रही है।

वास्तवमें ये ही वे मुद्दे हैं, जिनको आधार बनाकर शिवसेना दो-फाड़ हुई थी और शिवसेना (यूबीटी) एवं शिवसेना शिंदे गुटका निर्माण हुआ था। फिलहाल राजनीतिक एजेंडेमें 'हिंदुत्व' एवं 'मराठी मानुस' को प्रमुखतासे शामिल करनेके भारी दबावके कारण ही महाविकास आघाड़ीके सभी दल २०२४ के दंगलमें एकला चलोकी नीति अपनानेके लिए मजबूर हुए हैं। वैसे देखा जाय तो लोकसभा चुनाव २०२४ से पहले शिवसेना (यूबीटी) को महाविकास आघाड़ीसे अलग होना लगभग निश्चित ही था, क्योंकि राज ठाकरेके भाजपाके साथ आ जानेसे उसकी 'हिंदुत्व' एवं 'मराठी मानुस' वाली राजनीतिके समाप्त होनेका खतरा मंडराने लगा था। वहीं, दूसरी ओर महाविकास आघाड़ीके इस आंतरिक बिखरावको रोकनेके लिए शरद राव पवारकी बेटी और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की नेता सुप्रिया सुलेने राज ठाकरेको महाविकास आघाड़ीमें आनेका न्योता देकर ठाकरे बंधुओंकी लड़ाईका लाभ भाजपाको लेनेसे रोकनेकी भरपूर कोशिश की, किन्तु बात नहीं बन सकी और राज अंतत: राजगके हो गये। हालांकि राजको सुप्रियाके बुलावेपर शिवसेना उद्धव गुटके नेता संजय राउतने तंज कसते हुए सुप्रियासे अवश्य पूछ लिया कि क्या पवार साहब इस बातपर सहमत हैं। तात्पर्य यह कि महाराष्ट्रमें अब यह सुनिश्चित हो चुका है कि २०२४ के दंगलमें 'ठाकरे बनाम ठाकरे' होकर ही रहेगा। यानी शिवसेना शिंदे गुटके साथ-साथ राज ठाकरेके राजगमें आ जानेसे मराठी वोटरोंको अधिकसे अधिक अपनी ओर आकर्षित करनेमें तो मदद मिलेगी ही, साथ ही लाउडस्पीकरपर मसजिदोंसे अजान सुनाये जानेके मामलेमें अत्यंत मुखरतासे विरोध करनेवाले राज ठाकरेके साथ आनेसे भाजपाको शिवसेना (यूबीटी) के हिस्से वाले पारम्परिक हिंदुत्ववादी वोटरोंको भी अपनी ओर आकर्षित करनेमें मदद मिल सकती है।

देखा जाय तो शिवसेनाके पुराने संमर्थकोंके एक बड़े समूहका झुकाव तो पहले ही शिंदेके आनेसे राजगकी तरफ हो चुका है, अब राज ठाकरेके आ जानेसे भाजपा उद्धव ठाकरेको मिलनेवाली सहानभूति वोटोंको भी अपनी ओर करनेमें सफल हो सकती है।

गौरतलब है कि ऐसी स्थितिमें उद्धव ठाकरेकी शिवसेनासे शिफ्ट होनेवाले मराठी वोटरोंके लिए दो ही विकल्प दिखाई देते हैं या तो वे राज ठाकरेका नेतृत्व स्वीकार कर मनसेके प्रत्याशीको वोट करें अथवा शिवसेनाके शिंदे गुटके पालेमें शिफ्ट हो जायं। दोनों ही स्थितियोंमें भाजपावाले राजग गठबंधनकी ही बल्ले-बल्ले होने वाली है। इनके अतिरिक्त अपने तीखे भाषणों और बेबाकीसे अपना पक्ष रखनेवाले बेलाग नेताके तौरपर प्रसिद्ध राज ठाकरेकी बेहद आक्रमक छविका चुनावी लाभ भी भाजपाको मिलनेकी संभावना है। वहीं, राज ठाकरेको अपने पालेमें करके शिवसेना शिंदे गुटकी ज्यादा लोकसभा सीटोंकी मांग वाली 'प्रेशर पॉलिटिक्स' की काट भी भाजपाने ढूंढ़ निकाली है। तात्पर्य यह कि एकनाथ शिंदेने यदि अधिक मोल-भाव किया और भाजपाने उन्हें गठबंधनसे बाहरका रास्ता दिखा दिया तो वे कहींके नहीं रहेंगे, यह उन्हें भी पता है। जहांतक राज ठाकरेकी बात है तो राजगमें शामिल होनेके बाद उन्होंने महाराष्ट्रमें लोकसभाकी दो सीटें मांगी हैं- दक्षिण मुंबई और शिर्डीकी। बतानेकी जरूरत नहीं कि 'मराठी मानुस' वाली यानी मराठी वोटकी प्रखर राजनीति करनेके कारण राज ठाकरेको उम्मीद है कि उनकी पार्टी मराठीबहुल दक्षिण मुंबई क्षेत्रमें जीत दर्ज कर सकती है और कमोबेश ऐसी ही स्थिति शिर्डी लोकसभा क्षेत्रकी भी है। फिलहाल दक्षिण मुंबई क्षेत्रसे निर्वाचित सांसद अरविंद सावंत हैं, जो उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना (यूबीटी) से आते हैं। पार्टीने एक बार फिर उन्हें ही इस सीटसे प्रत्याशी घोषित किया है। यह समझना मुश्किल नहीं है कि दक्षिण मुंबई क्षेत्रमें चुनाव लड़ानेके लिए भाजपाको भी एक ऐसे नेताकी तलाश थी, जो मराठी वोटरोंकी राजनीति करनेके लिए जाना जाता हो, ताकि आगामी लोकसभा चुनावमें शिवसेना (यूबीटी) से छीनकर भाजपा वह सीट अपने पालेमें कर सके। देखा जाय तो राज ठाकरेके लिए भी दक्षिण मुंबई और शिर्डीकी सीटोंपर जीत सुनिश्चित करना अब पहलेकी अपेक्षा अधिक आसान हो जायगा, क्योंकि राजगमें आ जानेके बाद राज ठाकरेके सामने केवल शिवसेना (यूबीटी) ही होगी, जबकि भाजपाके साथ तालमेल नहीं होनेकी स्थितिमें उन्हें तिहरा प्रहार झेलना पड़ता- भाजपा और शिवसेना शिंदे गुटवाले राजग गठबंधनका, शिवसेना (यूबीटी) एवं एनसीपी (शरदचंद्र पवार) का। संभवत: इस त्रिकोणीय मुकाबलेमें राज ठाकरेका चुनाव जीत पाना बेहद मुश्किल हो जाता, क्योंकि भाजपाके सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट तथा शिवसेना (यूबीटी) के नेता भी हिंदुत्व एवं मराठी वोटरोंकी राजनीति करनेके लिए ही जाने जाते हैं। वहीं, प्रकाश अंबेडकरवाले वीबीएसे राजको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि प्रकाश राज्यकी अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) की राजनीति करनेके लिए जाने जाते हैं।

प्रेरणास्रोत क्या था

❒ **जग्गी वासुदेव**

यदि आप अपने जीवन अनुभवको देखते हैं तो आपको जब भी कोई खुशी होती है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसका प्रेरणास्रोत क्या था। हो सकता है कि आपने सूर्योदय देखा और आप खुशीसे भर गये। हो सकता है कि आपने कोई संगीत सुना और आनन्द विभोर हो गये। हो सकता है कि आपको कोई सफलता मिली और आप खुश हो गये, वह हमेशा आपके भीतरसे ही आयी होती है। वह आपपर कहीं औरसे नहीं बरसी होती है। तो खुशीका स्रोत आपके भीतर ही है। आप अपने जीवनमें जिस भी अनुभवसे गुजरते हैं, वह आखिरकार आपका ही बनाया हुआ है। यदि आप इस बारेमें सचेतन हो सकें कि यह आपका बनाया है। सिर्फ तभी आप होनेका मधुरतम तरीका चुनेंगे। भक्ति अपनी भावनाओंको नकारात्मतासे प्रसन्नतामें रूपांतरित करने तरीका है। भक्ति एक प्रेम-प्रसंगका कई गुना बढ़ा हुआ रूप है। यदि आप किसी आदमी या औरतके प्रेममें पड़ जाते हैं और वे आपकी उम्मीदके मुताबिक नहीं चलते तो वह रिश्ता अंतत: मुश्किलमें पड़ जाता है। इसीलिए लोगोंने ईश्वरको चुना। यह बस एक सीधा प्रेम-प्रसंग है और आप कोई उत्तरकी अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। आपका जीवन अत्यन्त सुन्दर हो जाता है, क्योंकि आपकी भावना बहुत मधुर बन गयी है। उस मधुरताके जरिये व्यक्ति विकास करता है। भक्ति होनेका न सिर्फ मधुरतम तरीका है, बल्कि यह बुद्धिमत्ताका सर्वोच्च रूप भी है। आम तौरपर लोग बुद्धिकी तुलनामें भावनाको हेयदृष्टिसे देखते हैं। जो लोग सोचते हैं कि वे बुद्धिमान हैं, वे भक्तिके किसी भी रूपसे हमेशा दूर रहनेकी कोशिश करते हैं। लेकिन अब लोग भावनात्मक बुद्धिमत्ताकी बात कर रहे हैं, क्योंकि भावनामें कई तरहसे बुद्धिसे अधिक तीव्र होनेकी काबिलीयत है। बुद्धिमें एक खास ठंडापन और पैनापन होता है लेकिन भावना बस हर चीजको गले लगा सकती है। बुद्धि जीवनके टुकड़ोंको जान सकती है, भक्ति जीवनकी पूर्णताको जान सकती है। जीवनके अनुभव और सम्पूर्ण जीवनके बोधके सन्दर्भमें, एक भक्त जो जानता है, उसे एक बौद्धिक इनसान कभी नहीं छुएगा। लोग भक्तिको ऐसी चीज समझते हैं जिसे वे विकसित करते हैं। विकसितकी हुई भक्ति भयंकर चीज है। आप भक्तिको विकसित नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति और भ्रमके बीचकी रेखा बहुत बारीक है।

वोटमें तब्दील होनेवाले मुद्दोंकी तलाश बड़ी चुनौती

❒ **डा. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा**

अट्ठारहवीं लोकसभाके चुनावोंके लिए पहले चरणकी १०२ सीटोंके लिए नामांकनका कार्य पूरा होनेके साथ ही एनडीएने ३१ मार्चको मेरठ और इंडी गठबंधनने नयी दिल्लीसे चुनावी केंपेनका आगाज कर दिया है। लोकसभाके सातों चरणोंके मतदानतक राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव रैलियों, रोड शो सहित विभिन्न मंचोंसे एक-दूसरेपर आरोप-प्रत्यारोपका दौर जारी रहेगा। सौ टकेका सवाल यह है कि दुनियाके सबसे बड़े लोकतंत्रके चुनावोंमें चुनाव अभियानके दौरान आखिर मुख्य मुद्दे क्या बनेंगे। दरअसल देखा जाय तो पिछले कुछ चुनावोंसे चाहे वे लोकसभाके हो या विधानसभाओंके चुनाव हो, सीधे जनतासे जुड़े मुद्दे तो नेपथ्यमें ही रह जाते हैं। तस्वीरका एक पक्ष यह भी है कि जनतासे जुड़े मुद्दोंको आम जनता भी अब मुद्दे या चुनावी एजेंडा नहीं मानने लगी है। किसी जमानेमें गरीबी हटाओं या भ्रष्टाचार मिटाओं या महंगी या बेरोजगारी तो सकारात्मक प्रचार अभियानमें विकासकी बात आदि मुद्दे महत्वपूर्ण होते थे परन्तु अब यह मुद्दे वोटमें तब्दील नहीं हो पा रहे हैं। अब नकारात्मक प्रचार राजनीतिक दलोंपर उलटा पड़ने लगा है। पिछले दो लोकसभाके चुनावोंमें चौकीदार, सेनाके साक्ष्य, चायवाला आदि ऐसे वक्तव्य रहे जिसका जितना अधिक उपयोग हुआ वह भाजपा और नरेन्द्र मोदीके पक्षमें ही गया। एक बात यह भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आजादीके ७५ साल बाद भी किसी दलका वोट प्रतिशत ५० प्रतिशतका आंकड़ा छू नहीं पाया है। दूसरी ओर चुनाव आयोग द्वारा लाख प्रयासोंके बाद भी सौमेंसे ३३ प्रतिशत मतदाताओंको मतदान केन्द्रपर मतदानके लिए ले जानेमें हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। यह अलग विचारणीय मुद्दे हैं। विपक्षका प्रयास है कि सत्तारुढ़ द्वारा संवैधानिक संस्थाओं यथा ईडी, आईटी आदि जांच एजेंसियोंका हथियारके रूपमें उपयोग, चुनावी बाण्ड, बेरोजगारी, महंगी, भ्रष्टाचार आदिको प्रभावी तरीकेसे चुनावी मुद्दा बनाया जाये परन्तु अबतक जो दिखाई दे रहा है उसमें साफ है कि यह मतदाताओंको प्रभावित करनेवाले मुद्दे बन नहीं पा रहे हैं। इसका एक प्रमुख कारण तो विपक्षी खास तौरसे इंडी गठबंधनका जुड़ना-बिखरना जारी है। एक तरफ ममता पश्चिम बगांलमें कांग्रेस द्वारा वामपंथी दलोंके साथ तालमेल कर चुनाव लड़नेको खुलेआम भाजपाको लाभ बतानेवाला निर्णय बता रही हैं वहीं बिहार, महाराष्ट्र, दिल्लीमें कांग्रेसका छोटे पार्टनरके रूपमें सामने आने, पंजाबमें आपसे सीटोंके बंटवारेको लेकर समझौता ही न होने, बसपाका अलग रुख, अजित जनता दलका बीजेपीके साथ आना, ओडीसामें बीजद सहित विरोधाभास सामने आ रहे हैं। वहीं दिल्लीकी रैलीसे साफ हो जाता है कि विपक्षका जो पैनापन होना चाहिए था वह असरदार नहीं दिखा। चुनावी बाण्डका मुद्दा जिस तरहसे उछला वह अपनी धार नहीं दिखा पाया, क्योंकि चुनावी चंदा सभीने लिया चाहे वह कम हो या ज्यादा। दूसरी बात आमजनका यह सोच माना जा सकता है कि सभी राजनीतिक दल चुनावी चंदा लेते हैं और साफ है कि इसका फायदा सत्तारुढ़ दलको अधिक ही मिलता है। इसलिए जिस तरहसे यह बड़ा मुद्दा बननेकी संभावना देखी जा रही थी, वह कहीं पीछे ही रह गयी। इसी तरह केजरीवाल सहित आप नेताओंपर ईडी छापों और जेलका मुद्दा भी अधिक असर दिखाता नहीं लग रहा। साफ है कि केजरीवाल जो भ्रष्टाचारके खिलाफ ही सत्तामें आये थे, उनके नेताओंपर शराब ठेकोंमें भ्रष्टाचारके आरोप लगे। दूसरा,बार बार सम्मन आनेपर भी रेस्पांस नहीं करने और गिरफ्तारीके बाद भी पदपर बने रहनेका आमजनमें नकारात्मक असर ही दिखाई दे रहा है। इस मामलेंमें लोग लालूकी बढ़ाई करने लगे हैं कि लालूने गिरफ्तार होते ही अपना पद त्याग दिया और भले ही राबड़ी देवीको मुख्य मंत्री बनाया परन्तु पदकी गरिमाको तो बनाये रखा। बार-बार सम्मनकी अवहेलना करने और त्यागपत्र न देनेसे लोगोंमें केजरीवालके पदलोलुपताका सन्देश गया अन्यथा निश्चित रूपसे केजरीवालके प्रति सहानुभूति होती और इसका लाभ समस्त विपक्षको मिलता परन्तु लगता है एक अच्छा अवसर खो दिया गया है। इस चुनावमें किसानोंका मुद्दा तो अबतक दिखाई ही नहीं दे रहा। एक बात और चुनाव घोषणा-पत्रोंमें मुफ्तकी सुविधाओंकी भरमार भी अब लोगोंको अधिक लुभानेवाली नहीं लगती। कारण साफ है इससे एक और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर देनेवाला अपनेको ठगा समझने लगा है, लाभार्थी इसे राजनीतिक दलोंकी कमजोरी समझने लगा है। आमआदमी यह भी जानता है कि चुनावोंके लिए चंदा लिया ही जाता है। मजेकी बात यह है कि चंदा देनेवालोंके वोट गिनतीके ही होते हैं। साफ है कि १८वीं लोकसभाके चुनाव प्रचार अभियानमें संवैधानिक संस्थाओंके उपयोग, चुनाव बाण्ड, बेरोजगारी, महंगी, भ्रष्टाचार आदि मुद्दें अधिक चलनेवाले नहीं हैं। राम मंदिर, धारा ३७० या इसी तरहके अन्य मुद्दोंको विपक्ष उठाता भी है तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टीको ही मिलेगा। ऐसेमें विपक्षको चुनावी वैतरणी पार करनेके लिए कोई ठोस मुद्दें खोजने होंगे। हवाहवाई या चलताउ भाषणों, आरोप प्रत्यारोपसे पार पाना मुश्किल रहेगा। विश्लेषक कहते हैं कि इस बारके चुनाव दस नेताओंके इर्द-गिर्द रहेंगे। परन्तु अबतककी रूपरेखाको देखें तो १८वीं लोकसभाके चुनाव नरेन्द्र मोदीके इर्द-गिर्द ही रहनेवाला है। विपक्षका निशाना नरेन्द्र मोदी ही रहेंगे और इसका उजला या स्याह पक्ष यह है कि विपक्ष जितना अधिक नरेन्द्र मोदीके नामका उच्चारण करेगा उसका उतना ही अधिक लाभ नरेन्द्र मोदी और भाजपाको मिलेगा। पिछले दो लोकसभाके चुनाव परिणाम तो यही बताते हैं। ऐसेमें विपक्षको अलग ही तरहकी रणनीति बनानी होगी। विपक्षको सकारात्मक रणनीति बनानी होगी अन्यथा नकारात्मकताको तो नरेन्द्र मोदीको अपने पक्षमें करनेकी महारत हैं। लोकसभाके पिछले दो चुनाव और गत दस सालोंके विधानसभाओंके चुनावोंके परिणाम सबके सामने हैं ऐसेमें विपक्षके सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपाको घेरनेकी है और इसके लिए उसे पूर्व अनुभवोंको ध्यानमें रखते हुए प्रभावी रणनीति बनानी होगी। रैलियों, सभाओंमें प्रमुख नेताओंको भाषणों-वक्तव्योंके दौरान सावधानी बरतनी होगी तभी मोदीसे पार पाया जा सकता है। यह साफ-साफ समझ लेना होगा। इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है कि मोदी विपक्षी नेताओं द्वारा कही गयी बातको तत्काल अपने पक्षमें भुनानेमें सिद्धहस्त है, ऐसेमें विपक्षके सामने प्रमुख चुनौती चुनाव अभियानके दौरान अपनोंके बीच समन्वय एवं समझ बनाये रखनी है तो जनमानसको प्रभावित करनेकी रहेगी तो मोल-तोलके बोलपर भी अधिक ध्यान देना होगा।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

ग्रामीण क्षेत्र पर दबाव

मनरेगा कार्य दिवसों में ग्रामीण क्षेत्रों में अनस्किल्ड लेबर की मांग उचित है, लेकिन अभी भी अच्छे रोजगार की कमी है। इसका असर दुनिया, अर्थव्यवस्था और सरकार पर हो रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के आखिरी दिन आई यह खबर कई लिहाज से परेशान करने वाली है कि मनरेगा के तहत साल भर में मुहैया कराए गए कार्य दिवसों की कुल संख्या 305.2 करोड़ तक पहुंच गई, जो महामारी से पहले (2019-20) के लेवल से 40 करोड़ ज्यादा है। इससे संकेत मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दिक्कत ज्यादा है, जिससे वहां मनरेगा के तहत काम की मांग बढ़ी है। लोगों को वहां अच्छे रोजगार नहीं मिल रहे। मनरेगा ऐसी योजना है, जो देश के ग्रामीण इलाकों में अकुशल श्रमिकों के लिए आजीविका की आखिरी उम्मीद मानी जाती है। साल 2019-20 के दौरान इस योजना में लोगों की भागीदारी बारिश, मॉनसून, सूखा जैसे सामान्य मौसमी कारकों से प्रभावित हुई थी। उस साल इस योजना के तहत 265.3 करोड़ कार्यदिवस दर्ज हुए थे। उसके बाद महामारी और लॉकडाउन के दौरान देश में शहरों से गांवों की ओर असाधारण पलायन हुआ जिसका प्रभाव मनरेगा समेत जीवन के तकरीबन हर क्षेत्र में देखा गया। मनरेगा में उस साल (2020-21) 389.9 करोड़ कार्यदिवस दर्ज हुए, जो अब तक का रेकॉर्ड है। लेकिन महामारी की लहरें शांत होने के बाद जैसे-जैसे इकॉनमी उस झटके से उबरती गई, यह उम्मीद बढ़ी कि ग्रामीण क्षेत्रों के अनस्किल्ड लेबर को विभिन्न क्षेत्रों में आजीविका मिलती जाएगी और मनरेगा पर दबाव कम होगा। लेकिन अगर अभी भी वहां यह दबाव बना हुआ है जिसका अर्थ है कि या तो लोगों को शहरों में गुणवत्ता वाले काम मिलने की उम्मीद नहीं है या वे गांव छोड़कर शहर जाना नहीं चाहते। 2022-23 में भी इस योजना के तहत 293.7 करोड़ कार्यदिवस दर्ज हुए, जो 2019-20 के मुकाबले 28.4 करोड़ ज्यादा थे। यही नहीं, इस साल यानी 2023-24 में यह अंतर बढ़कर 40 करोड़ तक पहुंच गया।

कच्चातिवु जैसे इलाकों को लेने-देने की रवायत पुरानी

(स्मृति पटनायक, रिसर्च फेलो, एमपी-आईडीएसए)

भारत में आम चुनाव की बढ़ती गरमी के बीच कच्चातिवु द्वीप अचानक सुर्खियों में आ गया है। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित यह निर्जन द्वीप करीब डेढ़ किलोमीटर लंबा है और भारतीय तट से लगभग 33 किलोमीटर दूर है। इसका मालिकाना हक विवादित रहा है। यह पूरा इलाका पहले पुर्तगालियों के अधीन था, फिर ब्रिटेन का उपनिवेश बना, इसलिए 1947 में भारत के आजाद होने और भूमि-निर्धारण के बाद यहां भारत व श्रीलंका, दोनों के मछुआरे आते-जाते रहे। वे वहां अपने जाल सुखाते थे और फिर मछली पकड़ने निकल जाते। बाद के वर्षों में श्रीलंका ने इस पर अपना दावा किया, जिसके कारण सन् 1974 में समुद्री सीमा-निर्धारण के वक्त भारत ने अपना अधिकार छोड़ दिया। तब यही माना गया था कि ऐसा करने से दक्षिणी पड़ोसी से भारत के संबंध और मजबूत होंगे। हमारे लिए इस द्वीप का कोई सामरिक महत्व भी नहीं है। यहां पर अब भी सालाना कच्चातिवु त्योहार होता है, जिसमें भारत और श्रीलंका, दोनों देशों के मछुआरे भाग लेते हैं। अब आपसी सौहार्द बढ़ाने में इसकी अहमियत मानी जाती है।

भारत ने जमीनों के ऐसे लेन-देन दक्षिण एशिया के कई अन्य देशों के साथ किए हैं। इसका मूल मकसद आपसी विवाद को खत्म करना रहा है। कभी-कभी परिस्थितिवश भी ऐसा किया गया, जैसे बांग्लादेश के साथ। उसके साथ वर्ष 2015 में हमने भूमि- सीमा के निर्धारण का समझौता किया, जिसके तहत 111 सीमावर्ती एन्क्लेव हमने बांग्लादेश को सौंपे और बदले में 51 एन्क्लेव पर अपना अधिकार हासिल किया। यहां कोई कह सकता है कि हमने जितनी भूमि (करीब 17 हजार एकड़) बांग्लादेश को दी, उसकी तुलना में कम जमीन (लगभग सात हजार एकड़) पर कब्जा हासिल किया, पर सच यही है कि कई एन्क्लेव तक जाने के लिए हमें बांग्लादेश की सीमा में जाना पड़ता था। कुछ यही स्थिति बांग्लादेश की भी थी। चूंकि बांग्लादेशी एन्क्लेव तक बांग्लादेशियों की आवाजाही निर्बाध थी, इसलिए तस्करी का अंदेशा भी बना रहता था, इसलिए इसका समाधान आवश्यक था।

यहां न्यू मूर द्वीप की चर्चा भी प्रासंगिक है। इस पर कभी बांग्लादेश और भारत, दोनों अपना दावा जताते रहे, लेकिन बंगाल की खाड़ी का यह द्वीप अब इसलिए चर्चा में नहीं है, क्योंकि यह समुद्र में समा चुका है। उल्लेखनीय यह भी है कि 2014 में संयुक्त राष्ट्र न्यायाधिकरण ने बांग्लादेश को 25 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक के समुद्री दावे में से लगभग 19 हजार वर्ग किलोमीटर का अधिकार दे दिया, जिसे भारत ने बिना किसी विरोध के स्वीकार किया, क्योंकि हम आपसी संबंधों को ज्यादा अहमियत देते रहे हैं।

हमारा एक सीमा विवाद पाकिस्तान के साथ कच्छ के रण को लेकर भी रहा है। 1965 के ताशकंद समझौते के तहत इस विवाद के निपटारे की पटकथा लिखी गई। यह समझौता हालांकि इसलिए याद रखा जाता है, क्योंकि 1965 के युद्ध में पाकिस्तान की पराजय के बाद इसी के तहत भारतीय सैनिकों को वापस बेड़े में बुलाया गया, लेकिन इस समझौते से कच्च रण का विवाद भी सुलझा और 1969 में आपसी सहमति से कच्छ विवाद का समाधान हो गया। यहां भूटान का जिक्र भी लाजिमी है। हमने 1947 में आजाद होने के बाद भूटान को संप्रभु देश का दर्जा दिया और देओथांग सहित करीब 82 वर्ग किलोमीटर 'द्वार' (पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भूटान के इलाके) उसे वापस लौटा दिए, जिसे अंग्रेजों ने उससे हड़प लिया था।

सीमा-विवाद को लेकर भारत और नेपाल का मसला खासा अहम है और दूसरों से अलग भी। यहां भारत उस सुगौली संधि के तहत अपनी सीमा का दावा करता है, जिसको ब्रिटिश सरकार ने नेपाल के राजा के साथ 1814-16 के दौरान किया था। उस संधि के तहत नेपाल के कुछ मैदानी इलाके पराधीन भारत के पास आ गए थे। नेपाल इन पर अपना दावा जताता रहता है और इसे 'ग्रेटर नेपाल' का हिस्सा बताता है। फिलहाल, इसके निपटारे के प्रयास भी चल रहे हैं। स्पष्ट है, पड़ोसी देशों के साथ सौहार्द बढ़ाने के लिए जमीनों की अदला-बदली की जाती रही है। यह सीमा-विवाद के निपटारे की स्थापित रवायत है। (ये लेखिका के अपने विचार हैं)

भारतीय अर्थव्यवस्था लम्बी छलांग लगाने को तैयार

पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता के चलते भारत में आर्थिक विकास को गति ही मिली है। भारत में लगातार तेज हो रही आर्थिक विकास की दर के कारण भारत में बिलिनियर (100 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की सम्पत्ति वाले नागरिक) की संख्या में सुधार हुआ है। पिछले वर्ष भारत में 94 नए बिलिनियर बने हैं। जबकि चीन में 115 बिलिनियर कम हुए हैं। विश्व में बिलिनियर की संख्या के मामले में भारत चीन एवं अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर आ गया है। भारत में आज 271 बिलिनियर हैं जबकि चीन में 814 एवं अमेरिका में 800 बिलिनियर हैं। मुंबई महानगर में तो अब 92 बिलिनियर निवास कर रहे हैं, जो चीन के बीजिंग महानगर के 91 बिलिनियर से अधिक है। इस प्रकार अब एशिया के किसी भी महानगर में सबसे अधिक बिलिनियर भारत के मुंबई महानगर में निवास कर रहे हैं। पूरे विश्व भारत के मुंबई महानगर से आगे अब केवल अमेरिका का न्यूयॉर्क महानगर (119 बिलिनियर) एवं ब्रिटेन का लंदन महानगर (97 बिलिनियर) ही है। वर्ष 2022-23 में चीन में बिलिनियर की संख्या घटी है। चीन में बिलिनियर की सम्पत्ति 15 प्रतिशत से कम हुई है। जबकि भारत में बिलिनियर की सम्पत्ति में वृद्धि दर्ज हुई है। यह भारत में तेज गति से हो रहे आर्थिक विकास दर के चलते सम्भव हो सका है। एक और कारक जो आगे आने वाले समय में भारत की आर्थिक विकास दर को लगातार उच्च स्तर पर बनाए रखने में सहायक हो सकता है वह है भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय का लगभग 2500 अमेरिकी डॉलर का होना है जो चीन में 13,000 से 14,000 अमेरिकी डॉलर के एवं दक्षिणी कोरीया में 32,000 से 33,000 अमेरिकी डॉलर के बीच की तुलना में बहुत कम है।

(प्रह्लाद सबनानी)

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास के चलते भारत में विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों, व्यवसाइयों, प्रबंधकों, कृषकों आदि की उत्पादकता में भी सुधार दृष्टिगोचर है जो निश्चित ही भारत में आर्थिक विकास की गति को तेज करने में सहायक होगा।

वित्तीय वर्ष 2023-24 की तृतीय तिमाही (अक्टोबर-दिसम्बर 2023) में भारत में आर्थिक विकास की दर 8.4 प्रतिशत रही है। कुछ विदेशी अर्थशास्त्री भारत की आर्थिक विकास दर को कमतर आंकते हुए दिखाई दे रहे हैं जबकि यह लगातार तिमाही दर तिमाही आगे बढ़ती ही जा रही है। अब तो विश्व की कई आर्थिक एवं वित्तीय संस्थानों ने भी वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के सम्बंध में अपने अनुमानों को बेहतर किया है, परंतु अभी भी इन संस्थानों के यह अनुमान वास्तविक आर्थिक विकास दर की तुलना में बहुत कम हैं। दरअसल, विदेशी आर्थिक एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा विशेष रूप से भारत की आर्थिक विकास दर को आंके जाने के सम्बंध में उपयोग किए जा रहे मॉडल अब बोथरे साबित हो रहे हैं। हाल ही के समय में भारत के नागरिकों में 'स्व' का भाव विकसित होने के चलते देश में धार्मिक पर्यटन बहुत तेज गति से बढ़ा है। उदाहरण के लिए अयोध्या धाम में प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर में श्रीराम लला के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात प्रत्येक दिन औसतन 2 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। यह तो केवल अयोध्या की कहानी है इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर, उज्जैन में महाकाल लोक, जम्मू स्थित वैष्णो देवी मंदिर, उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एवं यमनोत्री जैसे कई मंदिरों में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ रही है। भारत में धार्मिक पर्यटन में आई जबरदस्त तेजी के बदौलत रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित हो रहे हैं, जो देश के आर्थिक विकास को गति देने में सहायक हो रहे हैं। परंतु, यह तथ्य विदेशी आर्थिक एवं वित्तीय संस्थानों को दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि केवल भारत की ही विशेषता है।

उक्त तथ्यों के अतिरिक्त अन्य कई कारक भी भारत की आर्थिक विकास दर को अब 9 से 10 प्रतिशत की सीमा में ले जाने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। आज भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना में भारत से आगे चल रही विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर में ठहराव आ गया है। जैसे अमेरिका एवं यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं आगे आने वाले समय में प्रतिवर्ष केवल 2 अथवा 3 प्रतिशत की दर से ही आगे बढ़ पाएंगी। इसी प्रकार चीन की अर्थव्यवस्था भी अब ढलान पर दिखाई दे रही है। जापान एवं जर्मनी की अर्थव्यवस्थाओं में तो आर्थिक मंदी देखी जा रही है। इस प्रकार विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत के अमृत काल में केवल भारतीय अर्थव्यवस्था ही तेज गति आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। वैसे भी भारत में अमृत काल तो अभी शुरू ही हुआ है एवं यह अगले 23 वर्षों अर्थात वर्ष 2047 तक यह खंडकाल जारी रहेगा। कुछ अर्थशास्त्री तो भारत के अमृत काल के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था के इसी तरह तेज गति से आगे बढ़ते रहने की संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि भारत में वर्ष 1991-92 में प्रारम्भ किए आर्थिक एवं

वित्तीय क्षेत्र के सुधार कार्यक्रम को अब 32 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, हालांकि वर्ष 1991-92 के बाद भी भारत में आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रों में सुधार कार्यक्रम लगातार जारी रहे हैं। अत- स्थिर हो चुके इन सुधार कार्यक्रमों के फल खाने का समय अब आ गया है।

भारत द्वारा वर्ष 1947 में राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, पिछले 77 वर्षों के दौरान भारत में लोकतंत्र लगातार मजबूत हुआ है एवं आज पूरे विश्व में भारत इस दृष्टि से प्रथम पायदान पर खड़ा है। भारत में लोकतंत्र के लगातार मजबूत होते जाने से विदेशी निवेशकों का भारत में विश्वास बढ़ा है जिसके चलते भारत में उद्योग जगत को पूंजी की कमी नहीं के बराबर रही है। पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता के चलते भारत में आर्थिक विकास को गति ही मिली है। भारत में लगातार तेज हो रही आर्थिक विकास की दर के कारण भारत में बिलिनियर (100 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की सम्पत्ति वाले नागरिक) की संख्या में सुधार हुआ है। पिछले वर्ष भारत में 94 नए बिलिनियर बने हैं। जबकि चीन में 115 बिलिनियर कम हुए हैं। विश्व में बिलिनियर की संख्या के मामले में भारत चीन एवं अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर आ गया है। भारत में आज 271 बिलिनियर हैं जबकि चीन में 814 एवं अमेरिका में 800 बिलिनियर हैं। मुंबई महानगर में तो अब 92 बिलिनियर निवास कर रहे हैं, जो चीन के बीजिंग महानगर के 91 बिलिनियर से अधिक है। इस प्रकार अब एशिया के किसी भी महानगर में सबसे अधिक बिलिनियर भारत के मुंबई महानगर में निवास कर रहे हैं। पूरे विश्व भारत के मुंबई महानगर से आगे अब केवल अमेरिका का न्यूयॉर्क महानगर (119 बिलिनियर) एवं ब्रिटेन का लंदन महानगर (97 बिलिनियर) ही है। वर्ष 2022-23 में चीन में बिलिनियर की संख्या घटी है। चीन में बिलिनियर की सम्पत्ति 15 प्रतिशत से कम हुई है। जबकि भारत में बिलिनियर की सम्पत्ति में वृद्धि दर्ज हुई है। यह भारत में तेज गति से हो रहे आर्थिक विकास दर के चलते सम्भव हो सका है।

एक और कारक जो आगे आने वाले समय में भारत की आर्थिक विकास दर को लगातार उच्च स्तर पर बनाए रखने में सहायक हो सकता है वह है भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय का लगभग 2500 अमेरिकी डॉलर का होना है जो चीन में 13,000 से 14,000 अमेरिकी डॉलर के एवं दक्षिणी कोरीया में 32,000 से 33,000 अमेरिकी डॉलर के बीच की तुलना में बहुत कम है। इस दृष्टि से भारत को अभी बहुत आगे तक जाना है और यह केवल आर्थिक विकास की औसत दर को 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष के आसपास बनाए रखने से ही सम्भव होगा। इस प्रकार भारतीय नागरिकों में अपनी औसत आय को विकसित देशों की तुलना में बेहतर करने की अभी बहुत गुंजाइश है और यह भावना भारत की आर्थिक विकास दर को बढ़ाए रखने में सहायक होगी। दूसरे, भारत में तकनीकी क्षेत्र विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास की दर बहुत प्रभावकारी है, डिजिटल क्षेत्र में तो भारत आज पूरे विश्व को ही राह दिखाता नजर आ रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास के चलते भारत में विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों, व्यवसाइयों, प्रबंधकों, कृषकों आदि की उत्पादकता में भी सुधार दृष्टिगोचर है जो निश्चित ही भारत में आर्थिक विकास की गति को तेज करने में सहायक होगा।

आज अमेरिका एवं कनाडा में निवासरत एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य कर रहे भारतीय मूल के नागरिक वापिस भारत आकर बसने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रहे हैं क्योंकि अब अमेरिका एवं अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत में लगातार तेज हो रही आर्थिक विकास की दर उन्हें आकर्षित कर रही है। उन्हें आज भारत में अधिक आय अर्जन के अतिरिक्त साधन उत्पन्न होते दिखाई दे रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार, लगभग 38,000 भारतीय जो अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत हैं वे अब भारत वापिस आना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका में कई कम्पनियां (गूगल, एमेजोन, माइक्रोसोफ्ट एवं मेटा सहित) अपने कर्मचारियों की छंटनी करती दिखाई दे रही हैं। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तो स्पष्टत- आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुकी है। जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने अक्टोबर-दिसम्बर 2023 की तिमाही में 8.4 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर हासिल की है। कई विदेशी वित्तीय संस्थानों ने वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को आगे बढ़ा दिया है।

अब तो भारत में, ग्रामीण इलाकों सहित, विभिन्न उत्पादों के खपत का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विकास कार्यों के लिए अपने बजट में खर्च को लगातार बढ़ाया जा रहा है जिससे सामान्य नागरिकों के हाथों में अधिक पैसा पहुंच रहा है तथा इससे नागरिकों के बीच विभिन्न उत्पादों के खपत का स्तर बढ़ता दिखाई दे रहा है। शहरी उपभोक्ता तो रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं के साथ साथ चार पहिया वाहन एवं मकान आदि खरीदने पर भी भारी मात्रा में पैसा खर्च कर रहे हैं। घरेलू खपत में बढ़ौतरी के साथ ही भारत से निर्यात में भी तेजी देखी जा रही है। फरवरी 2024 माह में निर्यात का स्तर पिछले 11 माह में सबसे अधिक रहा है। केंद्र सरकार का अनुमान है कि भारत वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्यात के क्षेत्र में अपने पिछले सारे रिकार्ड तोड़ देगा। मोर्गन स्टैनली के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर यह है कि भारत में निवेश = सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में एक बार फिर सुधार दिखाई दे रहा है। यह अनुपात आज 34 प्रतिशत तक पहुंच गया है और उम्मीद की जा रही है वित्तीय वर्ष 2027 तक यह बढ़कर 36 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। जिससे भारत की आर्थिक विकास दर को और अधिक बल मिलेगा।

हां, भारत में एक क्षेत्र अभी भी ऐसा है जिसके लिए चिंता होना स्वाभाविक है। वह क्षेत्र है आय की असमानता का। भारत की 10 प्रतिशत आबादी के पास देश की 77 प्रतिशत सम्पत्ति जमा हो गई है। एक रिसर्च पेपर में यह बताया गया है कि भारत में आर्थिक विकास के साथ साथ आर्थिक असमानता भी बढ़ी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक भारत की एक प्रतिशत आबादी की देश की कुल आय एवं सम्पत्ति में 22.6 प्रतिशत एवं 40.1 प्रतिशत की भागीदारी रही है। आय की असमानता को देश में आर्थिक विकास को गति देकर ही दूर किया जा सकता है, जिसके लिए केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। (लेखक सेवा निवृत्त उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

बेटियों को भी मिले उचित सम्मान, उन्हें न समझा जाए बोझ

हमारे यहां आज भी बेटी पैदा होते ही उसकी परवरिश से ज्यादा उसकी शादी की चिन्ता होने लगती है। आज महंगी होती शादियों के कारण बेटी का बाप हर समय इस बात को लेकर चिंतित नजर आता है कि उसकी बेटी की शादी की व्यवस्था कैसे होगी। समाज में व्याप्त इसी सोच के चलते कन्या भ्रूण हत्या पर रोक नहीं लग पायी है। कोख में कन्याओ को मार देने के कारण समाज में आज लड़कियों की काफी कमी होने से लिंगानुपात गड़बड़ा गया है। पिछले कुछ वर्षों में देश में जन्म के समय लिंगानुपात में बढ़ोतरी होना शुभ संकेत हैं।

(रमेश सर्राफ धमोरा)

हमारे देश में यह एक बड़ी विडंबना है कि हम बालिका का पूजन तो करते हैं। लेकिन जब हमारे खुद के घर बालिका जन्म लेती है तो हम दुखी हो जाते हैं। देश में सभी जगह ऐसा देखा जा सकता है। देश के कई प्रदेशों में तो बालिकाओं के जन्म को अभिशाप तक माना जाता है।आज हर क्षेत्र में बालिकाओं के आगे बढने के बावजूद भी वह अनेको कुरीतियों की शिकार हैं। ये कुरीतियों उनके आगे बढने में बाधाएं उत्पन्न करती है। पढ़े-लिखे लोग और जागरूक समाज भी इस समस्या से अछूता नहीं है। देश में आज भी प्रतिवर्ष लाखों लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही कोख में मार दिया जाता है। आज भी समाज के अनेक घरों में बेटा, बेटी में भेद किया जाता है। बेटियों को बेटों की तरह अच्छा खाना और अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है। समाज में आज भी बेटियो को बोझ समझा जाता है।

हमारे देश में यह एक बड़ी विडंबना है कि हम बालिका का पूजन तो करते हैं। लेकिन जब हमारे खुद के घर बालिका जन्म लेती है तो हम दुखी हो जाते हैं। देश में सभी जगह ऐसा देखा जा सकता है। देश के कई प्रदेशों में तो बालिकाओं के जन्म को अभिशाप तक माना जाता है। लेकिन बालिकाओं को अभिशाप मानने वाले लोग यह क्यों भूल जाते हैं कि वह उस देश के नागरिक हैं जहां रानी लक्ष्मीबाई जैसी विरांगनाओं ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे।हमारे यहां आज भी बेटी पैदा होते ही उसकी परवरिश से ज्यादा उसकी शादी की चिन्ता होने लगती है। आज महंगी होती शादियों के कारण बेटी का बाप हर समय इस बात को लेकर चिंतित नजर आता है कि उसकी बेटी की शादी की व्यवस्था कैसे होगी। समाज में व्याप्त इसी सोच के चलते कन्या भ्रूण हत्या पर रोक नहीं लग पायी है। कोख में कन्याओ को मार देने के कारण समाज में आज लड़कियों की काफी कमी होने से लिंगानुपात गड़बड़ा गया है। पिछले कुछ वर्षों में देश में जन्म के समय लिंगानुपात में बढ़ोतरी होना शुभ संकेत हैं। संसद में एक सवाल का जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने बालिकाओं के अधिकारों को स्वीकार

करने के लिए जनता की मानसिकता को बदलने की दिशा में सामूहिक चेतना जगाई है।

इस योजना ने भारत में सीएसआर (बाल लिंग अनुपात) में गिरावट के मुद्दे पर चिंता जताई है। यह राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) में 15 अंकों के सुधार के रूप में परिलक्षित होता है। जो कि 2014 में 918 था। जबकि 2022-23 में 15 अंक बढ़कर 933 हो गया। अगर समाज में बेटियों को उचित शिक्षा और सम्मान मिले तो बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नही रहेगी। इसलिए यदि यह कहा जाय की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना नही हम सबकी एक जिम्मेदारी है तो इसमें कुछ गलत नही है। यदि हम सभी एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते है तो हम सबका यही फर्ज बनता है हम इन बेटियों को भी भयमुक्त वातावरण में पढ़ाये। उन्हें इतना सशक्त बनाये की खुद गर्व से कह सके की देखो वह हमारी बेटी है जो इतना बड़ा काम कर रही है। भारत में हर साल तीन से सात लाख कन्या भ्रूण नष्ट कर दिये जाते हैं। इसलिए यहां महिलाओं से पुरुषो की संख्या 5 करोड़ ज्यादा है। समाज में निरंतर परिवर्तन और कार्य बल में महिलाओं की बढ़ती भूमिका के बावजूद रूढिवादी विचारधारा के लोग मानते हैं कि बेटा बुढ़ापे का सहारा होगा और बेटी हुई तो वह अपने घर चली जायेगी। बेटा अगर मुखाग्नि नहीं देगा तो कर्मकांड पूरा नहीं होगा।

आज लड़किया लड़को से किसी भी क्षेत्र में कमतर नहीं हैं। कठिन से कठिन कार्य लड़किया सफलतापूर्वक कर रही हैं। देश में हर क्षेत्र में महिला शक्ति को पूरी हिम्मत से काम करते देखा जा सकता है। लड़कियों ने अपने काम और समर्पण के दम पर कई क्षेत्रों और क्षेत्रों में खुद को साबित किया है। वे अधिक प्रतिभाशाली, आज्ञाकारी, मेहनती और परिवार और अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। लड़कियाँ अपने परिवार और माता-पिता के प्रति अधिक देखभाल करने वाली और प्यार करने वाली होती हैं और वे हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देती हैं। देश की अर्थव्यवस्था में भी महिलाओं का अहम योगदान है। वे श्रम शक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और व्यवसायों की वृद्धि और विकास में योगदान देती हैं। एक तरफ जहां बेटी को जन्मते ही मरने के लिये लावारिश छोड़ दिया जाता है। वहीं झुंझुनू जिले की मोहना सिंह जैसी बालिकायें भी है जो आज देश में फाईटर प्लेन उड़ा कर पूरे देश में जिले का मान बढ़ा रही हैं। समाज में सभी को मिलकर लडका-लडकी में भेद नहीं करने व समाज के लोगों को लिंग समानता के बारे में जागरूक करने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। बालिकाओं का कोख में तो कत्ल कर उन्हे धरती पर आने से पहले ही मारा जा रहा है। उससे भी घिनोना काम जिन्दा बालिकाओं के साथ किया जा रहा है। देश में बालिकाओं के साथ हर दिन बलात्कार, प्रताडना की घटनायें अखबारो की सुर्खिया बनती हैं। बालिकायें कही भी अपने को सुरक्षित नहीं समझती हैं। चाहे घर हो या स्कूल अथवा कार्य स्थल। हर जगह वहशी भेडिये उन पर नजरे गड़ायें रहते हैं। उन्हे जब भी मौका मिलता है नोंच डालते हैं। ऐसे माहौल में देश की बालिकायें कैसे आगे बढ़ पायेगीं।

समाज के पढ़े लिखे लोगों को आगे आकर कन्या भ्रूण हत्या जैसे घिनोने कार्य को रोकने का माहौल बनाना होगा। ऐसा करने वाले लोगों को समझा कर उनकी सोच में बदलाव लाना होगा। लोगों को इस बात का संकल्प लेना होगा कि ना तो गर्भ में कन्या की हत्या करेगें ना ही किसी को करने देगें। तभी देश में कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लग पाना संभव हो पायेगा। सरकार व समाज को मिलकर ऐसे वातावरण का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिये जिसमें बालिकायें खुद को महफूज समझ सकें। बालिकाओं पर अत्याचार करने वालों के मन में भय व्याप्त करने के लिये सरकार को कानून में और अधिक सुधार करना चाहिये। बालिकाओं को कई प्रकार के भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। समाज और राष्ट्र के विकास के लिए बालिकाओं के महत्व को स्वीकार करना और बढ़ावा देना आवश्यक है। शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। एक शिक्षित लड़की ही अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान दे सकती है।

{ संपादकीय }

नई दिल्ली, शुक्रवार 5 अप्रैल 2024

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

कांग्रेस का बोझ हल्का हुआ

मुक्केबाज विजेंद्र सिंह, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर गौरव वल्लभ और पूर्व पत्रकार एवं राजनेता संजय निरूपम, ये तीन नाम बुधवार से लेकर गुरुवार तक चर्चा में छाए रहे। इस चर्चा के पीछे कारण एक ही है कि तीनों ने कांग्रेस छोड़ दी है। चुनाव के वक्त दल-बदल अब आम बात हो गई है। इसलिए इन तीन लोगों का एक पार्टी को छोड़ना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ते वक्त जो तर्क दिए, वो बेहद कमजोर हैं।

विजेंद्र सिंह भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ मूंछों पर ताव देकर कदमताल करते दिखे थे। वे लगातार राहुल गांधी को समर्थन वाले ट्वीट किया करते थे और नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की तीखी आलोचना किया करते थे। 2019 में विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी और उन्हें दक्षिण दिल्ली से उम्मीदवार बनाया गया था, जहां वे चुनाव हार गए थे। फिर भी कांग्रेस में उन्हें सम्मान के साथ जगह मिली रही। मंगलवार तक भाजपा की खिल्ली उड़ाने वाले ट्वीट विजेंद्र कर रहे थे और कुछ घंटों बाद बुधवार को उन्होंने भाजपा का भगवा गमछा अपने गले में डलवा लिया। इसके बाद एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि मैं सो गया और जब सुबह उठा तो मेरे को लगा कि ग़लत प्लेटफॉर्म पर हूं। भारतीय जनता पार्टी में आइए और यहां से सही दिशा में जाएंगे। उनके इस बयान का अब खूब मजाक भी उड़ रहा है कि सोकर उठने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे गलत पार्टी में हैं। लेकिन यहां मजाक से परे एक गंभीर सवाल यह है कि चार साल तक जिन्हें भाजपा सरकार की गलतियां नजर आती रहीं, एक रात में ऐसा क्या हुआ कि विजेंद्र सिंह ने पाला बदल लिया। विजेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं और जब महिला पहलवानों ने भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठाई तो उनके लिए इंसाफ की मांग विजेंद्र सिंह ने भी की। लेकिन अब भाजपा में जाने के बाद विजेंद्र सिंह का मानना है कि भारत के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान-सम्मान मोदी सरकार में आने के बाद मिला है। विजेंद्र सिंह सोकर उठते ही भाजपा में नहीं गए, बल्कि उनके विचार भी रातों-रात बदल गए।

वैचारिक बदलाव का ऐसा ही उदाहरण गुरुवार को भी सामने आया, जब अर्थशास्त्र के प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए पार्टी की सदस्यता छोड़ी और कुछ घंटों में भाजपा के मुख्यालय जाकर भगवा गमछा गले में धारण कर लिया। विजेंद्र सिंह की तरह ही संसद में जाने की नाकाम कोशिश गौरव वल्लभ कर चुके हैं। एक नहीं दो बार दो राज्यों से कांग्रेस ने उन्हें मौके दिए, लेकिन वे सफल नहीं हुए। गौरव वल्लभ की कांग्रेस में रहते हुए एक बड़ी उपलब्धि यही रही कि एक ट्रिलियन में कितने शून्य होते हैं, इस सवाल पर उन्होंने भाजपा को बुरी तरह घेरा था। इस सवाल के कारण गौरव वल्लभ खूब सुर्खियों में आए और इसके बाद चैनलों की कई बहसों में उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर मजबूती से पक्ष रखा। कुछ वक्त पहले कांग्रेस छोड़ने वालों की पोल खोलते हुए उन्होंने कहा था कि जिन्हें लुटियन्स दिल्ली में बंगला और राज्यसभा की सदस्यता चाहिए वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाते हैं। उन्होंने तब भी राहुल गांधी के लिए कहा था कि श्री मोदी को राहुल गांधी ही चुनौती दे सकते हैं, उनसे सीधे सवाल कर सकते हैं। अब गौरव वल्लभ का कहना है कि उन्हें सनातन के विरोध में नारे लगाने वालों से आपत्ति है और साथ ही जिस तरह वेल्थ क्रिएटर्स यानी देश को समृद्ध करने वालों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो भी उन्हें सही नहीं लगता। गौरव वल्लभ के दिए इन कारणों को सुनकर साफ समझ आता है कि उन्हें जातिवार जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस की सोच से तकलीफ हो रही है। सवर्णों के दबदबे वाली मानसिकता अक्सर ऐसी तकलीफ की शिकायत करती है, क्योंकि उसके मुताबिक देश की पूंजी और अवसरों पर अधिकार जताने की आजादी निचले तबकों को नहीं है।

कांग्रेस में पूर्व सांसद संजय निरूपम को भी तकलीफ हो रही थी और वे लगातार पार्टी के विरोध में बयान दे रहे थे। उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष ने छह वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। मगर गुरुवार को उन्होंने जिस तल्खी के साथ अपनी बातें रखीं, उनसे समझ आता है कि वे भी जल्द ही एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। संजय निरूपम पहले शिवसेना में थे, बाद में कांग्रेस में गए और इस बीच पत्रकारिता करने के साथ-साथ वे बिग बॉस जैसे रियलटी शो का हिस्सा भी बने। 2014 और 2019 में कांग्रेस की टिकट पर उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और दोनों बार हार गए, लेकिन तीसरी बार वे उत्तर-पश्चिम मुंबई से अपने लिए टिकट चाहते थे, जबकि यहां महाविकास अगाड़ी में शामिल शिवसेना के नेता अमोल कीर्तिकर को टिकट मिली है। अगर संजय निरूपम को टिकट मिल जाती तो शायद उन्हें कांग्रेस के राम मंदिर पर लिए गए स्टैंड या उसकी संरचना और कार्यप्रणाली से तकलीफ नहीं होती। लेकिन अब संजय निरूपम बता रहे हैं कि कांग्रेस में एक नहीं पांच शक्ति केंद्र हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और के सी वेणुगोपाल और इन सभी का नाम लेते हुए बेहद अभद्र टिप्पणियां संजय निरूपम ने की हैं।

दो दिन में तीन लोगों के कांग्रेस छोड़ने को भाजपा समर्थित पत्रकार कांग्रेस में भगदड़ की तरह पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कांग्रेस कितनी कमजोर हो चुकी है। कांग्रेस के अंत की अनंत भविष्यवाणियां की जा चुकी हैं और शायद आगे भी होती रहेंगी। लेकिन हकीकत ये है कि जिन तीन लोगों ने अभी कांग्रेस छोड़ी है, वे खुद हारे हुए नेता रहे हैं, किसी का मजबूत जनाधार नहीं रहा है। एक तरह से वे कांग्रेस पर बोझ ही थे। लेकिन अब कांग्रेस नेतृत्व को निरीक्षण-परीक्षण कर लेना चाहिए कि ऐसे और कितने बोझ कांग्रेस को दबाए हुए हैं और उनसे जल्द से जल्द छुटकारा पा लेना चाहिए।

गुलाबी आंकड़े, झुलसाती सच्चाई

चुनाव पास आते ही आकर्षक आंकड़ों की बारिश शुरू हो गई है। और मामला सिर्फ बीते साल, महीने या तिमाही के आंकड़ों का नहीं है, अगले साल से लेकर 2047 में भारत को विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाने तक के हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अगले साल के लिए जीडीपी में आठ फीसदी का विकास दर बता दिया है। अभी हाल के समय तक आंकड़ों का खेल ऐसा नहीं था। विदेश व्यापार और औद्योगिक उत्पादन में एक महीने उतार दिखता था तो किसी महीने चढ़ाव। विदेश व्यापार का घाटा कभी रिकार्ड स्तर पर दिखता था तो कभी आयात कम होने से काफी कम। एक गरीबी के ही आंकड़े को लीजिए तो की तरह के आंकड़े हाजिर हैं, जबकि असलियत यही है कि सरकारी स्तर पर आंकड़े जुटाने का काम मनमाने ढंग से हो रहा है। अगर तस्वीर गुलाबी न दिखे तो आंकड़े रोके भी जा रहे हैं और उसके जरा भी अच्छे हिस्से को शोर मचाकर बताया जाता है। हमारे जीवन के निर्वाह और आर्थिक हैसियत को बताने वाली लगभग तीन दर्जन सूचनाओं से लैस जनगणना का काम रोका हुआ है जबकि इसमें अभी ही पांच साल की देरी हो चुकी है। विश्व युद्ध और महामारी में भी न रुकी जनगणना अब क्यों रोकी गई है इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। खैर।

इन बातों से जो धनात्मक बातें हैं उनका महत्व काम नहीं होता। जीएसटी का संग्रह और भविष्य निधि कोष के सदस्यों की संख्या निरंतर बढ़ती गई है जिसे सरकार अपनी उपलब्धि ही नहीं रोजगार बढ़ाने के वायदे को पूरा करने की तरह पेश कर रही है। मोदी राज के ज्यादा समय पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कम रही है और सरकार ने उस अनुपात में आम उपभोक्ताओं को राहत न देकर मोटा राजस्व जमा किया जिसका उपयोग-दुरुपयोग क्या हुआ यह हिसाब भी साफ नहीं है। असल में बजट का अनुशासन अब सिर्फ कहने की चीज रह गई है और नोटबंदी जैसा फैसला भी एक आदमी की मर्जी से ही लिया गया। इससे बड़ी बात है कि पूरी दुनिया कोविड से उबरने के बाद आर्थिक रूप से पुरानी स्थिति में आने की कोशिश कर रही है। इसमें अमेरिका काफी हद तक सफल हुआ है तो चीन और यूरोप अभी भी संकट में दिख रहे हैं। वहां असली समस्या लोगों में उपभोग का स्तर गिरना है जिससे कुछ देशों की अर्थव्यवस्था के बैठने का खतरा बन गया है। न सामान बिक पा रहा है न रोजगार मिल रहा है। रोजगार कम हों तो क्रय शक्ति कम होगी और सामान कम बिकेगा तो अर्थव्यवस्था की रोजगार पैदा करने की शक्ति घटेगी। हमारी अर्थव्यवस्था ने ठीक-ठाक वापसी की है। लेकिन कुछ बड़ी बीमारियां हैं जो पीछा नहीं छोड़ रही हैं।

दुर्भाग्य से अपनी अर्थव्यवस्था को भी यह मर्ज लगा हुआ दिखता है लेकिन न तो शासन को होश है न जानकार लोग ही इसका शोर मचा रहे हैं। सुनहरे आंकड़ों के बीच बड़ी कंपनियों में लगातार यह चिंता पसर रही है कि उनका माल खपत नहीं हो रहा है। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात है कि शहरी और अमीर लोगों की जरूरत वाली कुछ चीजों की मांग तो बढ़ी है लेकिन आम उपभोक्ता और ग्रामीण इलाकों में मांग नहीं बढ़ी है। यह फासला भी बढ़ता जा रहा है। जो लोग इस विरोधाभास पर नजर रखे हुए हैं वे अपने हिसाब से कुछ कारण और समाधान भी बताते हैं लेकिन चुनाव जीतने भर की चिंता वाली सरकार को इन पर ध्यान देने का होश नहीं लगता। वह इस बात से खुश है कि वर्ष 2023-24 में जीएसटी कलेक्शन 20 लाख करोड़ से पार हों गया है।

यह एक आत्मघाती आंकड़ा और मोह है। असल में इसका उत्पादन बढ़ाने से रिश्ता नहीं है। भूमंडलीकरण आने और आईटी के प्रसार से अब काफी सारा कारोबार अनौपचारिक क्षेत्र से निकल कर औपचारिक बनता जा रहा है। छोटे कारोबारी और दूकानदारों का कर के और औपचारिक अर्थव्यवस्था में आना स्वागत योग्य बदलाव है पर आनलाइन कारोबार के देहात तक पहुंचने से कितनी दूकानें बंद हुई हैं या कितने छोटे धंधे वालों की आमदनी कम हुई है यह हिसाब नहीं है। जिस तरह छोटे किसान कमाई कम होते जाने पर भी खेती से चिपके रहते हैं उसी तरह इन लोगों के पास भी उसे धंधे में बने रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बेरोजगार नौजवानों की फौज सुबह छह बजे से रात दस बजे तक कूरियर सेवा देने, ई- रिक्शा चलाने और इसी तरह के कम आमदनी वाले काम करने में होड़ लगाए हुए हैं। पेंशन, प्रॉविडन्ट फंड और दूसरी सुविधाएं कौन मांगेगा जब न्यूनतम मजदूरी मांगने का होश नहीं है। कानून होने के बावजूद खुद सरकार मनरेगा में लाखों लोगों से न्यूनतम मजदूरी डर से काम पर काम कराती है तो बाकी पर कानून कौन लागू कराएगा ?

सेंटर फार मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनामी के अनुसार वर्ष 2023-24 में 27.9 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ। पिछले साल यह आंकड़ा 38.96 लाख करोड़ रुपए का था। सरकार इसे इठलाते हुए पेश करती है लेकिन अनेक लोग इस आंकड़े को हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियादी बीमारी से जोड़ते हैं। अगर विकास का स्तर साल में सिर्फ सात फीसदी हों और निवेश का स्तर जीडीपी के 30 से 35 फीसदी पर आ जाए तो जाहिर है लोग पेट काटकर निवेश कर रहे हैं। उपभोग का स्तर तो चार से पांच फीसदी भी नहीं बढ़ता। और इस पर तुर्रा यह कि राष्ट्रीय आय में श्रम का हिस्सा निरंतर गिर रहा है। माना जाता है कि हमारे यहां महामारी की तुलना में आज करीब डेढ़ करोड़ ज्यादा मजदूर खाली बैठे हुए हैं। पूंजी आए और श्रम का हिस्सा कम होता जाए यह विरोधाभासी विकास तब ज्यादा अच्छी तरह समझ आता है जब हम समाज के एक छोटे हिस्से की बड़े घर, बड़े फ्लैट, बड़ी कार, महंगे सौन्दर्य प्रसाधन, विदेश भ्रमण, बाहर भोजन वगैरह के खर्च को देखें। फिर समझ आता है कि बाहर छूटे बड़े हिस्से के जीवन में और ज्यादा कठिनाई क्यों आती जाती है। अरबपतियों की संख्या बढ़ाना बुरा नहीं है लेकिन देश के करोड़ों लोगों के जीवन में जहर घोलकर नहीं।

अरविन्द मोहन

अपनी अर्थव्यवस्था को भी यह मर्ज लगा हुआ दिखता है लेकिन न तो शासन को होश है न जानकार लोग ही इसका शोर मचा रहे हैं। सुनहरे आंकड़ों के बीच बड़ी कंपनियों में लगातार यह चिंता पसर रही है कि उनका माल खपत नहीं हो रहा है। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात है कि शहरी और अमीर लोगों की जरूरत वाली कुछ चीजों की मांग तो बढ़ी है लेकिन आम उपभोक्ता और ग्रामीण इलाकों में मांग नहीं बढ़ी है।

गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का राजनीति में और मजबूत होकर उभरना निश्चित

■ हरिहर स्वरूप

यह सच है कि अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। पंजाब में आप की अप्रत्याशित जीत और हाल में ही उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी राजनीतिक लोकप्रियता और अधिक ऊंचाई पर पहुंच गई है। दिल्ली में आप-कांग्रेस गठबंधन को आगामी चुनावों में आसानी से जीत हासिल करने की उम्मीद है।

उनके बढ़ते दबदबे से भाजपा जाहिर तौर पर चिंतित है। आगामी लोकसभा चुनाव में केजरीवाल दिल्ली और पंजाब के अलावा अन्य राज्यों में भी कदम रख सकते हैं। उनकी गिरफ़्तारी राजनीति से प्रेरित प्रतीत होती है। उनकी गिरफ़्तारी दिल्ली के मुख्यमंत्री को और अधिक शक्तिशाली बना सकती है क्योंकि उन्हें देश भर के लोगों की सहानुभूति मिलना निश्चित है। कोई नहीं जानता कि उनके खिलाफ आरोप सही हैं या नहीं, लेकिन चुनाव में उनके प्रति सहानुभूति एक कारक होगा।

5 अप्रैल, 2011 की सुबह, जंतर-मंतर से सटी एक गली-राजधानी का विरोध स्थल-जन लोकपाल कानून की मांग के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अभियान के शुभारंभ के लिए एक छोटी सी भीड़ एकत्र हुई थी (जो आने वाले दिनों में बहुत बड़ी संख्या होने वाली थी)। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे - आंदोलन का चेहरा-अपनी भूख हड़ताल शुरू करने के बाद एक ऊंचे मंच पर बैठे थे। मंच के किनारे पर खड़ा एक व्यक्ति सुर्खियों से दूर रहने को उत्सुक था।

जब मीडियाकर्मी जानकारी के लिए मूंछों वाले छोटे कद के व्यक्ति के पास पहुंचे, तो वह मंच से कूद गये और अभियान के बारे में गंभीरता से बात की। ये शख्स थे आंदोलन के सूत्रधार अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल उस समय तक पहले से ही एक प्रसिद्ध पारदर्शिता कार्यकर्ता और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता थे, फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञात नहीं थे। वह बड़े पैमाने पर बदलने वाला था।

इंडिया अगेंस्ट करप्शन अभियान आम आदमी पार्टी के गठन का अग्रदूत था, जो एक साल से अधिक समय बाद हुआ, और इसने केजरीवाल के राजनीति में प्रवेश को चिह्नित किया। भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा और वह व्यक्ति जो व्यवस्था को बदलना चाहता था, अब व्यवस्था के अंदर था।

सीमापुरी की भीड़भाड़ वाली गलियों में एक कमरे के कार्यालय से काम करने वाले एक उत्साही कार्यकर्ता से लेकर स्वतंत्र भारत के सबसे प्रभावशाली आंदोलनों में से एक को चलाने और फिर 2013 में दिल्ली में सबसे चौंकाने वाली चुनावी जीत दर्ज करने तक, यह केजरीवाल के लिए एक तीव्र परिवर्तन था। उनकी पार्टी ने पंजाब में जीत हासिल की और उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। यह विपक्षी इंडिया गठबंधन के सबसे प्रमुख सदस्यों में से एक है, और वह इसके सबसे अच्छे पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक हैं।

हालांकि, पिछले दशक में केजरीवाल के कई हमवतन इंडिया अगेंस्ट करप्शन अभियान में शामिल हुए परन्तु उनमें से अनेक, जो आप के संस्थापक सदस्य भी थे, ने आन्दोलन के मूल मुद्दे के साथ कथित तौर पर किये गये समझौतों के कारण या तो उन्हें छोड़ दिया या रास्ते से हट गये या खुद को आम आदमी पार्टी से किनारे या बाहर कर लिया।

केजरीवाल को 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों पर अपने रुख के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। आलोचकों ने कहा कि वह संतुलन बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे और इस मुद्दे से निपटने में विफल रहे। अक्सर पूछा जाने वाला एक प्रश्न केजरीवाल और उनकी पार्टी की विचारधारा के बारे में है, और इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। उन्होंने कहा है कि वह महात्मा गांधी से प्रेरित हैं और उनके उदाहरण का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अक्सर कहा है कि उनकी विचारधारा कट्टर राष्ट्रवाद है और लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए काम कर रही है।

उनकी पार्टी ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने के पक्ष में मतदान किया। 2020 के दिल्ली चुनावों में, उन्होंने भगवान हनुमान के प्रति अपनी भक्ति की घोषणा करके नागरिकता संशोधन अधिनियम के पारित होने और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में भाजपा द्वारा स्थापित सांप्रदायिक बारूदी सुरंगों पर बातचीत की। हालांकि, पार्टी नेताओं का कहना है कि केजरीवाल या अन्य आप नेताओं द्वारा अपनी हिंदू पहचान रखने में कुछ भी गलत नहीं है। इस पर उन्होंने कहा था कि इसका मतलब यह नहीं है कि वे मुस्लिम विरोधी हैं।

इंडिया अगेंस्ट करप्शन अभियान आम आदमी पार्टी के गठन का अग्रदूत था, जो एक साल से अधिक समय बाद हुआ, और इसने केजरीवाल के राजनीति में प्रवेश को चिह्नित किया। भ्रष्टाचार विरोधी योद्धा और वह व्यक्ति जो व्यवस्था को बदलना चाहता था, अब व्यवस्था के अंदर था।

पावन प्रसंग

कोई भी काम को रुचि से करें

मनुष्य को आंतरिक अभिव्यक्ति उसके काम करने की लगन और भावना से ही परखी जा सकती है। यह जानने के लिए कि यह कार्य उसे पसंद है कि नहीं, उसकी गतिविधियों पर एक निरीक्षण दृष्टि डालिए। उत्साहपूर्वक किया हुआ कर्म यह व्यक्त करता है कि उस व्यक्ति की अभिरुचि उसमें है। अनुत्साह और शिथिलता, कर्म के प्रति अरुचि का भाव परिलक्षित करते हैं। जिस कार्य से हमें प्यार होता है, उसका परिणाम शीघ्र पाने के लिए जैसी ही तत्परता भी होती है। उतनी ही फुर्ती और उत्साह भी होता है। जी करता है कि कितनी जल्दी उसे समाप्त करें और उसके सुखद परिणाम प्राप्त करें। कर्म का सुख वस्तुत: उसकी लगन, भावना और निष्ठा में ही है। उत्साहपूर्वक सम्पन्न किए गए कर्म प्रफुल्लता दे जाते हैं, किंतु अनुत्साहपूर्वक काम करने से निराशा, क्षोभ और असफलता ही हाथ लगती है।

जिस काम को बोझ समझकर करेंगे, उसमें मन लगेगा ही नहीं। शारीरिक शक्ति भी जिस अनुपात से लगनी चाहिए थी वह न लगेगी, वह फिर कार्य के शुभ परिणाम की आशा भी धूमिल ही बनी रहेगी। प्रसिद्ध विचारक स्वेट मार्डेन ने लिखा है- मनुष्य की असफलताएं परमात्मा की देन नहीं, उसकी निजी पैदाइश होती है। यह बात अक्षरश: सत्य प्रतीत होती है। संभव है कि किन्हीं कार्यों के अनुरूप अपनी शक्ति व योग्यता न हो तो उनकी असफलता को तो एक संयोग कह सकते हैं, किंतु जो कार्य हम कर सकते हैं, जो हमारी शक्ति और सामर्थ्य की सीमा में ही हैं, वे कार्य भी यदि अपूर्ण रहते हैं तो यह मानना पड़ता है कि इस काम को लगन और उत्साहपूर्वक नहीं किया गया।

काम करने की एक भावना होनी चाहिए उत्कृष्ट और विशाल भावना। आपका आत्मविश्वास यह कहता हो कि हम इस कार्य को करके ही छोड़ेंगे, इसमें आत्महित है और पुरुषार्थ है तो आप सच मानिए उस कार्य में आपको असीम आनंद आएगा। कमाई करते हुए जब यह भावना होती है कि इस धन से हमारे बच्चे विकसित होंगे, परिवार, राज्य और राष्ट्र समृद्ध बनेगा तो अंत:करण में अपूर्व शक्ति जाग्रत होती है, स्वाभिमान जाग उठता है और प्रसन्नता से अंत:करण भर जाता है। जब तक हम यह अनुभव नहीं करें कि इस उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य का श्रेय भी है,तब तक कर्म का सात्विक आनंद नहीं मिल सकता।

मनुष्य का जीवन एक आदर्श कर्म विद्यालय है। इसमें नैष्ठिक स्नातक वे समझें जाते हैं जो कर्म को जीवन ध्येय मानकर उसे कुशलतापूर्वक निभाते हैं। विद्यार्थी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने का लाभ तब पाता है, जब वह लगनपूर्वक, भावनापूर्वक अध्ययन कार्यों में लगा रहता है। जिस तरह स्वाध्याय की चमक यह व्यक्त करती है कि विद्यार्थी का भविष्य उज्ज्वल है उसी प्रकार कर्म की उत्कट भावना यह बताती है कि इस मनुष्य का हृदय उत्कृष्ट और विशाल है। इन गुणों के कारण ही उसका व्यक्तित्व समुन्नत हो होता है और श्रेय प्राप्त करता है। प्रसन्नतापूर्वक कार्य करने से तो यही अच्छा है कि चुपचाप बैठे रहें। शरीर को शिथिल और निराश बनाने की अपेक्षा उसे कुछ देर विश्राम दे लेना अच्छा है। मनुष्य को विरासत में परमात्मा से सैकड़ों अनुदान मिले हैं। कर्म से शक्तियां जाग्रत होती हैं। कर्म से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। कर्म से मनुष्य ऊंचा उठता है। उस कर्म की पूजा ही परमात्मा की सच्ची उपासना है। इसे भी उसी लगन और भावना से करना चाहिए, जिस तरह परमात्मा की उपासना, श्रद्धा और विश्वासपूर्वक करते हैं। जो शक्ति परिस्थितियों को अनुकूल बनाती है, वह है काम करने की लगन और भावना।

युग निर्माण योजना

आपके पत्र

भारतीय संस्कृति-संस्कारों में पश्चिमी दर्शन का समावेश

भारतीय संस्कृति हमें अपने भारतीय होने का एहसास कराती है। जो हमें विश्व के अन्य देशों से विकास की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भारत में अनेक परंपराएं ऐसी हैं जो सामाजिक जीवन को अधिक सभ्य एवं अच्छा इंसान बनाए रखने में योगदान देती है। जिनसे मनुष्यता का जीवन जीने की प्रेरणा भी मिलती है। यांत्रिक उपकरणों की तरह जिंदगी जीना भी कोई जीना है। यह भारतीय संस्कृति में पाश्चात्य का घालमेल ही है जो मनुष्य के जीवन को यंत्रवत बना देता है जो आने वाले कल के लिए घातक भी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर पाश्चात्य दर्शन की कुछ विशेषताएं भी हैं, जो हमारे विचारों को अधिक तार्किक तथा बौद्धिक बनाती है।जिन्हें हम अपने जीवन में क्रियान्वित कर अपने मनुष्य जाति के जीवन को अधिक सार्थक एवं सुलभ बना सकते हैं। नि:संदेह हमें रूढ़िवादी या एकदम पुरातन पंथी संस्कृति से लगाव न रखकर पाश्चात्य संस्कृति के जो फायदे हैं, उन्हें अपनाकर अपना जीवन सरल सार्थक एवं सुगम बना सकते हैं। विवेकानंद जी ने कहा है कि वीणा के तार को इतना भी ना कसो कि वह टूट जाए, और इतना भी ढीला न छोड़ो कि वह बज भी ना पाए, मूलत: हमें दोनों संस्कृतियों की समग्र अच्छाइयों को आत्मसात कर उनकी बुराइयों को त्यागना होगा तब ही जीवन सफल हो सकेगा।

भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान है। जबकि पश्चिमी सभ्यता भौतिकता लिए होती है, और उसमें भौतिकता की प्रधानता होती है। आध्यात्मिक प्रधान संस्कृति से तात्पर्य भौतिकतावादी दृष्टिकोण से दूर रहकर भौतिकता वादी होने का ही है।

प्राचीन काल से ही भारत देश में 'अतिथि देवो भव' और 'वसुधैव कुटुंबकम' वाली संस्कृति रही है। वैसे पाश्चात्य संस्कृति में बहुत सी अहितकर बातें भी हैं, जैसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना कमतर होते जा रही है। संयुक्त परिवार की प्रणाली का विघटन होते जा रहा है। पारिवारिक वातावरण संघर्ष तथा तनावपूर्ण होते जा रहा है। पाश्चात्य संस्कृति की नकल कर लोग परिवार से अलग होकर स्वतंत्र जीवनयापन करना पसंद करते हैं। उनमें विवाह विच्छेद और अन्य विसंगतियां जन्म लेने लगी हैं। धर्म तथा आध्यात्म के प्रति आमजन की सूची धीरे-धीरे कम होते जा रही है। ऐशो आराम के सामान खरीदने के कारण लोगों के खर्चे अनाप-शनाप बढ़ चुके हैं। बुजुर्गों की इज्जत तवज्जो होनी कम हो गई है। दादा और नाती के संबंधों में अब वह गर्माहट शेष नहीं रह गई है, जैसी कि एक सांस्कृतिक तथा नैतिक परिवार जनों में हुआ करती थी। धीरे-धीरे परिवार के सदस्य अलग होकर अकेलेपन की समस्या से जूझ रहे हैं। आने वाली पीढ़ी अपनी संस्कृति एवं आध्यात्मिक प्रवृत्ति भूलती जा रही है। प्रेम विवाह तथा अंतरजातीय विवाह पाश्चात्य सभ्यता की देखादेखी बहुत बढ़ गए हैं जिससे वैवाहिक संबंध टूटने के कगार पर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाश्चात्य सोच के कारण स्त्री सशक्तिकरण को बढ़ावा भी मिला है महिलाएं जहां पहले अपने घरों में कैद रहती थीं अब उन्मुक्त होकर शिक्षित होकर समाज में सफल होकर पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर व्यवसायिक दृष्टिकोण अपनाकर बड़े-बड़े पदों में कार्य कर रही हैं। समाज में खुलापन भी आ गया है। विकास रोजगार एवं मानवीय सोच में भी काफी विस्तार आया है,जो भारत के विकास में सहायक भी हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि हमें आध्यात्मिक भारतीय परंपरा संस्कृति तथा पाश्चात्य दर्शन तथा पाश्चात्य संस्कृति की सकारात्मक बातें आत्मसात कर विकास की एक नई राह खोजनी होगी, एवं सदैव अच्छी बातों के लिए अपने मस्तिष्क को खुला रखना होगा और पाश्चात्य संस्कृति की विसंगतियों को दूर रख भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए।

संजीव ठाकुर

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770

ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

https://t.me/AllNewsPaperPaid

व्यक्ति को संकट के समय के लिए धन संचय करके रखना चाहिए। अगर आपके पास धन का प्रबंध ठीक है तो आप बड़े से बड़े संकट से निकलने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि संकट के समय सच्चा मित्र धन ही होता है। जिस व्यक्ति के पास संकट के समय धन का अभाव होता है, उसके लिए संकट से उभरपाना बड़ा ही कठिन हो जाता है। चाणक्य

सन्मार्ग
पटना, शुक्रवार, 05 अप्रैल 2024
www.live7tv.com

कच्चाथीवू को गिफ्ट करना एक खतरनाक कारनामा

सुरेश रूंगटा

आजकल कच्चाथीवू द्वीप अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है। लोगों के बीच यह जानने की उत्सुकता है कि यह कच्चाथीवू है क्या और क्यों अखबारों की हेडलाइन बना हुआ है? कच्चाथीवू भारत के रामेश्वरम से 12 मील पूरब और श्रीलंका से लगभग इतनी दूरी पर स्थित एक द्वीप है। श्रीलंका के उत्तरी तट और भारत के दक्षिण-पूर्वी तट के बीच पाक जलडमरूमध्य क्षेत्र है। पाक जलडमरूमध्य में गहरा समुद्र नहीं है। यहां मूंगे की चट्टानों की प्रचुरता है तथा यहां अलग-अलग प्रजाति की मछलियां बहुतायत से पायी जाती हैं। भारत हर साल अरबों डॉलर का सीफूड का निर्यात करता है, इसमें बड़ा हिस्सा कच्चाथीवू से ही आता है। इस इलाके में प्रचुर मात्रा में झींगे मिलते हैं। यह द्वीप 14वीं सदी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बना था। इस द्वीप का क्षेत्रफल लगभग 286 एकड़ है। इस द्वीप पर एक पुराना मंदिर एवं एक चर्च भी है। 2023 में 2600 से अधिक यात्रियों ने रामेश्वरम से कच्चाथीवू की यात्रा की है। हर साल मार्च महीने में प्रार्थना करने हेतु केरल एवं तमिलनाडु से कैथेलिक समुदाय के लोग यहां जाते हैं। कच्चाथीवू बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। सन् 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंका की तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमाव भंडारनायके के साथ एक सामुद्रिक सीमा समझौता के तहत इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। समझौते के वक्त तमिलनाडु की सरकार ने इसे स्वीकार न करते हुए इसका विरोध किया था और यह मांग की थी कि इस समझौते को रद्द कर कच्चाथीवू को श्रीलंका से वापस लिया जाये। इस समझौते पर तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि ने इंदिरा गांधी को विरोध का पत्र भेजा था। सन् 1991 में तमिलनाडु विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से अनुरोध किया गया कि कच्चाथीवू को श्रीलंका से वापस लिया जाये ।

1974 तक कच्चाथीवू भारत का एक हिस्सा था, जो रामनाथपुरम (मदुरई) के राजा की जमींदारी के अंतर्गत था। रामनाथपुरम के राजा को कच्चाथीवू पर नियंत्रण 1902 में तत्कालीन भारत सरकार से मिला था। रामनाथपुरम के राजा ने द्वीप के चारो ओर मछली पकड़ने का अधिकार, द्वीप पर मवेशियों को चराने का अधिकार और अन्य समुद्री गतिविधियों के लिए इसके उपयोग करने का अधिकार पट्टे पर दे रखा था । इसके पूर्व भी 1885 में रामनाथपुरम के राजा और भारत सरकार के राज्य सचिव के बीच कच्चाथीवू के साथ-साथ 11 और द्वीपों के लिए समझौते हुए थे । इस प्रकार ब्रिटिश हुकूमत ने कच्चाथीवू को बराबर भारत के हिस्से के रूप में मान्यता दी, इसे कभी भी श्रीलंका का हिस्सा नहीं माना ।

बृज मोहन खण्डेलवाल नाम के एक व्यक्ति ने 1974 में कच्चाथीवू को श्रीलंका को तोहफे के बतौर देने के सरकारी फैसले के खिलाफ एक याचिका कोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें इसे सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला मानते हुए यह कहा गया था कि सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह देश के किसी भू-भाग को दूसरे किसी देश को सौंप दे। हो सकता है कि भविष्य में दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ने पर इस द्वीप का इस्तेमाल भारत के विरूद्ध ही सैन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार स्थगित रहने के कारण यह याचिका खारिज हो गयी। हालांकि खण्डेलवाल का आज भी यह मत है कि जो सवाल उन्होंने 1974 में उठाया था वो आज भी प्रासंगिक है। आज भी उनका विश्वास है कि किसी भी सरकार को भारत के किसी भी हिस्से का कोई भू-भाग किसी दूसरे देश को गिफ्ट करने का कोई हक नहीं है।

भारत के पहले प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने 10 मई 1961 को संसद में इस द्वीप के संबंध में बोलते हुए कहा था, 'पड़ोसियों के साथ उदारता का भाव रखना चाहिए तथा इस द्वीप पर हमें अपना दावा छोड़ने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए।' 1962 के युद्ध के समय भी अक्साई-चिन का एक बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में जाने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू ने संसद में एक बयान दिया था कि वहां तिनके के बराबर भी घास नहीं उगती है, वह बंजर इलाका है। इन बातों से पूर्वोत्तर के लोगों को गहरा आघात लगा था। यही गलती 1950 में नेहरू ने तब की थी, जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया, तो इसे नजरअंदाज कर गये तथा तिब्बत को उसकी स्वायतता बनाये रखने में सहायता न कर उल्टे चीन की सेनाओं को रसद मुहैया करवाया । इस प्रकार नेहरू की छद्मादर्शवादी नीतियां यथार्थ से कोसों दूर थी, जिसकी कीमत हम आज भी चुका रहे हैं।

चीन श्रीलंका में हबनटोटा बंदरगाह का निर्माण करवा रहा है। चीनी नौसेना की संख्या और गतिविधियां जिस तरह हिंद महासागर में बढ़ी है उसे देखते हुए इस कच्चाथीवू द्वीप का महत्व काफी ज्यादा बढ़ गया है। श्रीलंका में आर्थिक संकट और वहां भारी चीनी निवेश के बीच यह द्वीप सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया है। यह मलक्का जलडमरूमध्य और स्वेज नहर जैसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर हैं जहां से हर साल बड़ी मात्रा में जहाज और तेल टैंकर गुजरते हैं। हाल के वर्षों में हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों ने भारतीय रणनीतिकारों को अधिक चिंतित किया है। चीन ने 'वन बेल्ट वन रोड' प्रोजेक्ट के लिए श्रीलंका में अरबों डॉलर का निवेश किया है। पहले तो चीन ने वहां बंदरगाह विकसित करने के नाम पर इसे लिया, फिर उस पर कब्जा जमाकर बैठ गया। यहां तक कि उसके किनारे की डेढ़ हजार एकड़ जमीन भी हथिया ली है ।

तमिलनाडु के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने कच्चाथीवू को श्रीलंका को सौंपने की सच्चाई जानने हेतु सूचना के अधिकार के तहत सरकार से जानकारी मांगी थी। इस आरटीआई का जवाब देते हुए सरकार ने बतलाया कि 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा एक जलसंधि के अंतर्गत इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया गया था। 1974 के समझौते के अनुसार कच्चाथीवू श्रीलंका को दिये जाने के बावजूद भारतीय मछुआरों को मछली पकड़ने का हक दिया गया था। लेकिन दो साल बाद 1976 में पुनः एक नये समझौते के अंतर्गत इस प्रावधान को रद्द कर दिया गया । 2004 के बाद से करीब 6200 मछुआरों को कच्चाथीवू के नजदीक मछली पकड़ने के आरोप में श्रीलंका ने गिरफ्तार किया है। साथ ही 1175 बड़ी नौकाएं भी जब्त की है। 2022 में श्रीलंका ने इस द्वीप से गिरफ्तार किये गये भारतीय मछुआरों के लिए जमानत राशि के रूप में 10 मिलियन रुपए निर्धारित किये हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक ज्ञापन सौंप कर इस द्वीप पर तमिलनाडु का हक जताया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस द्वीप के सामरिक महत्व को देखते हुए देश-विरोधी इस कार्रवाई पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की जनता कभी भी ऐसे राष्ट्र विरोधियों को माफ नहीं करेगी। आरटीआई द्वारा प्राप्त रिपोर्ट लोगों को चौंकाने वाली है और उनकी आंखें खोलने वाली है। तत्कालीन सरकार ने कैसे निर्दयतापूर्वक भारत माता के एक अंग को काट कर दूसरे देश को दे दिया! इससे हर भारतवासी क्षुब्ध है। भारत की एकता, अखंडता एवं राष्ट्रीय हितों को कमजोर करने वाले कार्यों से दूर रहना ही श्रेयस्कर होगा।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं। ये उनके अपने विचार हैं।)

विपक्ष की रैली का संदेश

दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया की रैली में जुटी भीड़ को लेकर जो भी दावे और प्रतिदावे हों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव के ठीक पहले विपक्षी दलों ने इसके जरिए अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने की काफी हद तक कामयाब कोशिश की है। लगभग सभी प्रमुख दलों के बड़े नेता इसमें शामिल हुए और सबने मोटे तौर पर सत्ता पक्ष की कथित ज्यादतियों और लोकतंत्र पर हो रहे हमलों के इर्दगिर्द ही बातें रखीं। वैसे, इंडिया के घटक दलों के आपसी अंतर्विरोध की छाया भी रैली पर इस रूप में दिखी कि इसके मुख्य मकसद को लेकर दो तरह की बातें सामने आईं। आम आदमी पार्टी की तरफ से जहां इसका मकसद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करना बताया गया, वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि विरोध किसी खास व्यक्ति से जुड़ा नहीं बल्कि मौजूदा सरकार की तानाशाही के खिलाफ केंद्रित है। यह रैली ऐसे समय हुई, जब महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक तमाम राज्यों में टिकट बंटवारे के सवाल पर इंडिया से जुड़े दलों की आपसी खटपट की खबरें आ रही थीं। भले ही ये विवाद गिनी-चुनी सीटों को लेकर थे, नैरेटिव ऐसा बन रहा था कि चुनाव सिर पर आने के बाद भी इंडिया से जुड़े दल एकजुट नहीं हो पा रहे। रामलीला मैदान की रैली के जरिए इन दलों ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि बड़े मुद्दों पर वे एक स्वर में बोल सकते हैं। जहां तक एऊ और अन्य एजेंसियों की कार्रवाई का सवाल है तो इसमें दो राय नहीं कि इन पर सरकार का और इन एजेंसियों का अपना पक्ष है, लेकन इसके बावजूद चुनाव के ठीक पहले राज्यों के निर्वाचित मुख्यमंत्रियों के खिलाफ इस तरह के सख्त कदम अभूतपूर्व हैं और इनके राजनीतिक पहलू भी हैं। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि 2005 से अब तक ईडी के दर्ज किए 5,906 केसों में से मात्र 25 निपटाए जा सके हैं। पिछले 17 वर्षों में 0.42% मामलों का निपटना इस शिकायत को दमदार बनाता है कि इन मामलों में प्रक्रिया ही सजा का रूप लेती जा रही है। यही नहीं, जिस पीएमएलए के तहत राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसके सख्त प्रावधानों पर न केवल तीखी बहस है बल्कि उस कानून के खिलाफ रिव्यू पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सवाल उठता है कि क्या एजेंसियों को चुनाव होने तक विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ अतिवादी कदमों से परहेज करना चाहिए और क्या चुनाव आयोग को इस तरह का कोई निर्देश जारी करना चाहिए? इस पर गंभीरता से विचार करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि किसी लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने ही नहीं चाहिए, होते हुए दिखने भी चाहिए।

महंगा है अकेले सेवानिवृत्ति के बाद जीवनयापन

नारायण कृष्णमूर्ति

जब आपका पाला सेवानिवृत्त हो चुके और होने वाले लोगों से पड़ता है तो कई बार किसी बात के लिए आपकी आलोचना जरूर हो सकती है। हाल ही में मैं अलग-अलग अवसरों और जगहों पर दो अनोखे लोगों से मिला। उनमें सिर्फ एक ही समानता थी कि दोनों अविवाहित थे। एक की उम्र 63 वर्ष थी, जबकि दूसरे की 56 साल। हरि कोविड महामारी के दौरान सरकारी नौकरी में लंबे करियर के बाद सेवानिवृत्त हुए। उमा कुछ साल में सेवानिवृत्त होने वाली हैं। तलाक के बाद वह कई साल से अकेली रह रही हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि किसी जोड़े के सेवानिवृत्त होने के लिए आवश्यक संख्या को दो से विभाजित करने का तरीका अकेले रिटायर होने वाले से ज्यादा सही है। पर, वास्तविकता यह है कि अगर आप अकेले हैं तो आपको जो चाहिए वह उससे अधिक है, जो आप तब प्राप्त करेंगे, जब आप रिटायरमेंट संख्या को दो से विभाजित करेंगे। हां, यह थोड़ा चिंताजनक लग सकता है, लेकिन सच है कि अगर आप अकेले सेवानिवृत्त होने वाले हैं तो जोड़े के रिटायरमेंट की तुलना में आपके खर्च अक्सर ज्यादा होते हैं।

लागत साझा करने के समान अवसर नहीं : अकेले सेवानिवृत्त होने वालों के पास आवास, वाहन और घर चलाने जैसी चीजों की लागत साझा करने के समान अवसर नहीं होते हैं। इसलिए, उन्हें रिटायर के लिए अधिक बचत करनी होगी। अगर आप अकेले हैं और बच्चों का पालन-पोषण नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में आपके पास अपनी उम्र के 30 और 40 के दशक के दौरान बचत करने के कहीं अधिक अवसर होते हैं। जिनके पास बच्चों के लिए धन, घर और कई अन्य चुनौतियां होती हैं और जिनका सामना उन्हें परिवार के पालन-पोषण करते समय करना पड़ता है, उनको ज्यादा खर्च करना होता है।

रिटायरमेंट के समय अपने खर्च पर जरूर रखें नजर : वास्तविकता यह है कि प्रति व्यक्ति खर्च बहुत अधिक है, इसलिए जब रिटायरमेंट की योजना बना रहे हों तो इस पर विचार करने की जरूरत है। परिवारों की तुलना में सिंगल लोग लाइफस्टाइल पर अनजाने में अधिक खर्च करते हैं और इसे वे अपना भी लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक छोटी कार से भी काम हो सकता है तो भी अकेला व्यक्ति सेडान खरीद लेता है। इसके विपरीत, एक दंपती रिटायरमेंट के करीब एक छोटी कार ही पसंद करेगा। चुनौती अधिक बचत करने की जरूरत : सिंगल लोगों को 60 वर्ष की आयु तक समान उम्र वाले जोड़े की तुलना में रिटायर होने पर लगभग 15-20 फीसदी अधिक बचत की जरूरत होगी। रिटायरमेंट बचत से 4-6 फीसदी निकासी यह पता लगाने का एक आसान तरीका है कि रिटायर होने पर आपको वास्तव में कितने पैसे की आवश्यकता होगी। इसका मतलब है कि 4 फीसदी का रेट पाने के लिए आपको रिटायर होने पर वास्तव में जितना पैसा निकालना होगा, उससे 25 से 30 गुना की आवश्यकता होगी।

...तो बढ़ जाती है रिटायरमेंट उम्र : मैंने सेवानिवृत्ति के प्रति दृष्टिकोण को समझने के लिए हरि व उमा दोनों से बातचीत करना शुरू किया। हरि ने कहा, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल व सुरक्षा जैसी कुछ सामान्य सुविधाओं की बात आती है तो साझा लागत का लाभ उठाने के लिए वह रिटायरमेंट कम्युनिटी में चले गए हैं। दूसरी ओर, उमा ने कुछ साल पहले 50 साल की उम्र में उच्च अध्ययन के लिए अपनी लंबी नौकरी से छुट्टी ले ली थी। अब वह अपनी कंपनी में एक बड़े पद, जिम्मेदारी और वेतन पर वापस आ गई हैं, लेकिन इस नए बदलाव ने उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र को 70 साल तक कर दिया है।

स्वास्थ्य भी बड़ी चुनौती : एक महत्वपूर्ण पहलू जो सिंगल लोगों के लिए चुनौती बन सकता है, वह है उनका स्वास्थ्य। अक्सर अकेले रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य की देखभाल महंगी साबित होती है।

चुनौती- व्यक्ति अकेले तो बढ़ जाती है रिटायरमेंट की लागत : सिंगल लोगों के लिए रिटायरमेंट लागत अधिक होती है क्योंकि खर्च साझा करने वाला कोई नहीं होता है। उदाहरण के लिए, यात्रा करते समय होटल के डबल रूम की लागत सिंगल रूम की तुलना में थोड़ी अधिक हो सकती है। लेकिन, दो लोगों के डबल रूम में ठहरने की प्रति व्यक्ति लागत सिंगल कमरे की तुलना में कम हो जाती है। अमूमन, किसी कपल को जिन चीजों के लिए 100 रुपये की जरूरत होगी, उसके लिए अकेले व्यक्ति को 60 से 70 रुपये खर्च करने होंगे।

पुरानी कर व्यवस्था में निवेश कर बचाएं पैसे

विवेक एस अग्रवाल

सं अजीत सिंह

अगर आपकी आय टैक्स श्रेणी में आती है, तो कर गणना के लिए पुरानी और नई कर व्यवस्था में एक को चुनना होगा। नई कर व्यवस्था में दरें कम हैं। पुरानी कर व्यवस्था ज्यादा छूट की सुविधा देती है। इससे टैक्स वाली आय कम हो जाती है और देनदारी कम हो जाती है। नई कर व्यवस्था में आय 7 लाख रुपये या उससे कम है तो कोई टैक्स नहीं देना होगा। आप सैलरी वाले हैं तो 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड कटौती भी मिलेगी। यदि टैक्स की आय 7.5 लाख से अधिक है, तो पूरी आय पर टैक्स देना होगा। नई व्यवस्था में विभिन्न धाराओं जैसे 80सी, 80डी, 24 आदि के तहत कटौती का दावा नहीं कर सकते हैं। कर योग्य आय 7.5 लाख से अधिक है तो पुरानी टैक्स व्यवस्था अपनाना सही होगा।

टैक्स बचत और निवेश का दोहरा लाभ : पुरानी टैक्स व्यवस्था निवेश करने के साथ टैक्स बचत में मदद करती है। धारा 80सी के तहत निवेश पर 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। यदि जीवनसाथी और बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली है, तो 60 वर्ष से कम आयु होने पर प्रीमियम के रूप में भुगतान किए गए 25,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर 50,000 रुपये तक का दावा कर सकते हैं। नियोक्ता के माध्यम से एनपीएस में निवेश करने और कर योग्य वेतन को कम करने का मौका दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में हैं।

एनपीएस के जरिये अतिरिक्त कर बचत : ज्यादातर समय 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये की सीमा ईपीएफ योगदान, बच्चों की शिक्षा फीस और होम लोन मूलधन पुनर्भुगतान से समाप्त हो जाती है। ऐसे में धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत एनपीएस में 1.5 लाख रुपये की सीमा से अधिक निवेश कर 50,000 रुपये अतिरिक्त बचा सकते हैं।

एचआरए में भी फायदा, होम लोन पर भी दावा : अगर आप किराये पर रहते हैं और अपने वेतन के एक हिस्से के रूप में मकान किराया भत्ता (एचआरए) प्राप्त कर रहे हैं, तो कटौती का दावा कर सकते हैं। कुछ स्थितियों में, घर किसी दूसरे शहर में है और किराये पर दी गई संपत्ति है, तो आप होम लोन के बावजूद एचआरए लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, होम लोन लेने वाला व्यक्ति ब्याज भुगतान के कारण धारा 24 (बी) के तहत हर वित्त वर्ष 2 लाख रुपये तक की कटौती का दावा कर सकता है। आप पात्र संस्थानों को किए गए दान के लिए धारा 80जी के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं। पुरानी कर व्यवस्था ज्यादा छूट की सुविधा देती है। इससे कर वाली आय कम हो जाती है और देनदारी कम हो जाती है। नई कर व्यवस्था में आय 7 लाख रुपये या उससे कम है तो कोई टैक्स नहीं देना होगा।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक जलते दीप

जोधपुर, शुक्रवार 5 अप्रैल 2024

हमारे अंदरूनी मामलों में बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका, जर्मनी और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों की टिप्पणियों पर भारत सरकार ने सख्त एतराज जताया था। अब विदेशमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आगाह किया है कि उन्हें भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से परहेज करना चाहिए, नहीं तो इसका बहुत कड़ा जवाब मिलेगा। आमतौर पर अपेक्षा की जाती है कि हर राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान करे और उनके आंतरिक मामलों में दखल देने से परहेज करे, मगर अक्सर देखा जाता है कि कमजोर देशों के मामलों में ताकतवर देश हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं। इसी आदत के चलते जर्मनी, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने भारत सरकार को लोकतांत्रिक मूल्यों का पाठ पढ़ाने की कोशिश की थी। ऐसा नहीं माना जा सकता कि उन राजनयिकों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि भारत किस कदर भ्रष्टाचार और धनशोधन संबंधी मामलों को लेकर गंभीर है। ऐसे मामलों के आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाता है। फिर भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी की तो उससे यही जाहिर हुआ कि वे भारत के विपक्षी दलों के सुर में सुर मिला रहे हैं। उनकी टिप्पणियों से विपक्षी दलों को सरकार की आलोचना करने का आधार मिल गया था। यह ठीक है कि यह पहला मौका था जब किसी मुख्यमंत्री को पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया। उस गिरफ्तारी में समय के चुनाव को लेकर भी सवाल उठे, क्योंकि तब तक आम चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी थी। इस तरह चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को समान सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराने का सैद्धांतिक पक्ष बाधित नजर आने लगा। मगर इस पर नजर रखने और कार्रवाई करने का अधिकार भारत के निर्वाचन आयोग और अदालतों को है, न कि संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका या जर्मनी के किसी राजनयिक को। यह भी ठीक है कि हर देश अपने राजनयिकों के जरिए दूसरे देशों की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखता, वहां के चुनावों की खोज-खबर लेता रहता है, मगर वह चुनाव प्रक्रिया या वहां के राजनीतिक विवादों में पक्षकार की तरह शामिल नहीं हो सकता। वैसे भी अमेरिका, जर्मनी और संयुक्त राष्ट्र पर अनेक बार सवाल उठते रहे हैं कि वह अपने मित्र राष्ट्रों में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन तक पर चुप्पी साधे रहते हैं। फिलिस्तीन के खिलाफ नियम-कायदों को ताक पर रख कर चलाई जा रही इजराइल की कार्रवाइयों पर वे क्यों मुखर होकर नहीं बोलते या तन कर खड़े होते! अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कोई ऐसा मामला नहीं था, जिसका अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर कोई बुरा और व्यापक असर पड़ता हो। यहां की जांच एजंसियों ने कानून के दायरे में रहते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की और उसको केजरीवाल की तरफ से अदालत में चुनौती भी दी गई। उसके गलत या सही होने का निर्णय अदालत को करना है। उनके पहले भी इसी मामले में कई दूसरे नेता गिरफ्तार किए जा चुके थे। अमेरिका, जर्मनी, संयुक्त राष्ट्र या किसी भी दूसरे देश को उसमें हस्तक्षेप करने का कोई तुक नहीं बनता। हर देश की अपनी संप्रभुता है और वह अपने नियम-कायदों, कानूनों के जरिए चलता है। संयुक्त राष्ट्र को उसके किसी फैसले पर तभी कोई टिप्पणी करने का हक है, जब उससे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होता हो। इसलिए भारत के विदेश मंत्रालय ने उचित ही अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ऐसी टिप्पणियों के प्रति आगाह किया है।

सत्ता की धारा में डुबकी लगाओ, दूध से धुल जाओ

पिछले साढ़े सात दशक के भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक पराभव के अक्स गाहे-बगाहे उजागर होते रहते हैं। सत्ता के खेल जो विद्रूप न दिखा दें वो कम ही है। सत्ता केंद्रित राजनीति ने भ्रष्टाचार और पाक-साफ होने की अपनी-अपनी परिभाषा गढ़ ली है। कल तक विपक्ष में जो नेता दागदार होते थे, सतारूढ़ दल में शामिल होने के बाद कहा जाता है कि ये दाग अच्छे हैं। सफाई की इस कार्रवाई में निगरानी करने वाली संवैधानिक एजेंसियों की खामोशी भी विचलित करती है। ऐसे तमाम सवाल इस देश के नागरिकों को उद्वेलित करते रहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि दागी नेता सत्ता की धारा में डुबकी लगाकर दूध का धुला घोषित हो जाता है। विपक्षी नेता आरोप लगाते रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल को दाग धोने वाली वॉशिंग मशीन बना लिया गया है। जिसके चलते नियामक संस्थाओं से ड्राइक्लीनिंग की चिट हासिल हो जाती है। विपक्ष के ऐसे तमाम आरोपों की तार्किकता हाल में आई एक रिपोर्ट दर्शाती है। जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2014 के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का सामना कर रहे 25 विपक्षी नेताओं के सत्तारूढ़ दल में शामिल होने के बाद उनमें से 23 को राहत मिल गई है। इनमें से तीन मामले बंद हो गए हैं और बीस की जांच रुकी हुई है। दलील दी जा रही है कि जांच बंद नहीं हुई है, आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। यूं तो जब ये नेता विपक्ष में होते हैं और जांच एजेंसियां उन पर कार्रवाई करती हैं तो सत्तारूढ़ दल की दलील होती है कि कानून अपना काम करता है। जबकि विपक्षी नेताओं का आरोप रहता है कि यह प्रक्रिया तभी तक चलती है जब तक यह राजनीति से प्रेरित न हो। उल्लेखनीय है कि भाजपा में जो पच्चीस राजनेता शामिल हुए हैं उनमें कांग्रेस, राकांपा, शिवसेना, टीएमसी, टीडीपी, एसपी और वाईएसआर कांग्रेस के नेता शामिल हैं। विडंबना है कि राजनीतिक निष्ठा बदलना इन नेताओं के लिये राहतकारी साबित हुआ है। वजह यह कि इन नेताओं से जुड़े बीस मामले ठंडे बस्ते में डाल दिये गए हैं। दलील यह दी जाती है कि मामले बंद नहीं हुए हैं, जरूरत पड़ी तो जांच और कार्रवाई भी होगी। जो विपक्ष के उन आरोपों की पुष्टि करते हैं कि यह कार्रवाई राजनीतिक दुराग्रह के रूप में की जाती रही है। यही वजह है कि दल बदलने का फैसला राहत का रास्ता मान लिया जाता है। ऐसे में आम आदमी के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि अचानक जांच एजेंसियां निष्क्रिय क्यों हो जाती हैं? क्यों किसी एजेंसी को लेकर अदालत को कहना पड़ता है कि फलां एजेंसी पिंजरे में बंद तोता है और मालिक की बोली बोलता है। विपक्ष तो आरोप लगाता रहता है कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद से ईडी और सीबीआई ने मुख्यत- बड़े राजनेताओं के खिलाफ ही कार्रवाई की है। यही वजह है कि विपक्ष सत्ता पक्ष को ऐसी वॉशिंग मशीन की संज्ञा देता है जिसमें कथित दागों की धुलाई हो जाती है। तब उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसा भी नहीं है कि तमाम ऐसी कार्रवाई सिर्फ केंद्र में राजग सरकार के दौरान ही हुई हो। यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में सपा-बसपा के साथ संबंध सुधरने के बाद सीबीआई ने इन दलों के नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के मामलों में रुख बदल लिया था। इतना ही नहीं, विगत में सरकार बनाने और बहुमत जुटाने के लिये जो निष्ठा बदलने का खेल हुआ, उसके निहितार्थों में एजेंसियों की छाया महसूस होने की बात विपक्ष करता रहा है। यहां तक कि कई दलों के विभाजन के मूल में एजेंसियों की कार्रवाई के भय की भूमिका बतायी जाती रही है। दल-बदल के बाद उन पर चल रहे मामले या तो बंद हो गए या फिर ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। वहीं कई ऐसे मामले भी होते हैं जो खुले तो रहते हैं लेकिन उनमें कार्रवाई होती नजर नहीं आती। निश्चिय ही यह स्थिति किसी लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिये शुभ नहीं कही जा सकती।

प्रसंगतः उदारता की राह

कविवर रवींद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। न सिर्फ देश से बल्कि दुनिया के कोने-कोने से बधाई संदेश आने लगे। उनके घर पर अतिथियों का तांता लग गया। उनका एक पड़ोसी यह सब टकटकी लगाकर देखता रहा। उन्हें बधाई देने की बात तो दूर, उसने उन्हें नमस्कार तक नहीं किया। टैगोर को यह व्यवहार अखरा लेकिन उन्होंने इसे भुलाने की कोशिश की। पर भुला नहीं पाए। बार-बार उनके सामने उसका चेहरा सामने आ जाता था। वह जब-जब उसके बारे-बारे में सोचते, क्रोध से भर जाते। अगली सुबह वह समुद्र के किनारे टहल रहे थे। सूर्य की किरणें पड़ने से सागर चांदी सा दमक उठा था। टैगोर भाव-विभोर होकर लहरें देखते रहे। तभी उनकी नजर करीब ही पानी से भरे एक गड्ढे पर पड़ी। वहां भी सूर्य की किरणें बराबर पड़ रही थीं। गड्ढे का जल भी चमक रहा था। तभी टैगोर को ख्याल आया कि सूर्य ने तो सब पर बराबर किरणें फैलाई हैं। उसने तो समुद्र और गड्ढे में अंतर नहीं किया। टैगोर को अपनी गलती का अहसास हुआ। वह तो बेकार ही एक छोटी सी बात को लेकर बैठे हुए थे। अगर दूसरा अपनी उदारता छोड़ रहा है तो वो क्यों छोड़ें। वह तत्काल उस पड़ोसी के घर गए। उस समय वह जलपान कर रहा था। टैगोर ने फौरन उसके चरण स्पर्श किए। पड़ोसी की आंखें गीली हो गईं। वह बोला, 'आप जैसे देवतुल्य व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिलना ही चाहिए था।' यह कह कर उसने टैगोर के चरण स्पर्श किए। दोनों के बीच की दूरी मिट गई।

सिंधी ब्रह्म खत्री समाज, जयपुर विशेष

स्वामी लीला शाह के बताए पथ पर अग्रसर सिंधी ब्रह्म खत्री समाज

- विनोद शर्मा

स्वामी लीला शाह सेवा समिति जयपुर

जयपुर में सेवा कार्य करने के उद्देश्य से स्वामी लीला शाह सेवा समिति जयपुर (रजि.) का गठन सन 1978 में किया गया और 1980 में इसे पंजीकृत कराया गया।

समिति के कार्य सुचारू रूप से संचालित करने हेतु 22 व्यक्तियों की कार्यकारिणी चुनी हुई है। समिति की आय के मुख्य स्त्रोत चंदा और दान है।

समिति के उद्देश्यः समाज की उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना, समाज में राष्ट्रीय भावना और चरित्र का विकास करना, शिक्षा, साहित्य और ज्ञान वृद्धि के कार्यों का आयोजन करना, सार्वजनिक उपयोग हेतु वाचनालय, पुस्तकालय, मंदिर और धर्मशाला बनाना और संचालन करना।

समाज के बंधुओं के सहयोग से समिति द्वारा किये गये कार्य :

स्वामी लीला शाह का जन्मोत्सव प्रति वर्ष मनाया जाता है। इस अवसर पर सिंधी ब्रह्म खत्री समाज के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कक्षा 1 से कॉलेज तक की शिक्षा के विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

अखिल भारतीय सिंधी ब्रह्म खत्री सहायता विद्या ट्रस्ट की ओर से मेट्रिक और उससे अधिक कक्षाओं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को मिलने वाले पदक एवं प्रशंसा पत्र उनमें वितरित किए जाते हैं।

सिंधी ब्रह्म खत्री लीला शाह भवन का निर्माण रोशन नगर ब्रह्मपुरी रोड में करवाया गया जिसमें 2 हॉल, दो कमरे, स्नान घर और शौचालय बनाये गए हैं। यह भवन सार्वजनिक उपयोगार्थ रखा गया है।

आदर्श नगर में संत लीला शाह मार्केट का निर्माण करवाया गया जिसमें 2 बड़े अंडर ग्राउंड इसके ऊपर 6 दुकानें और कार्यालय बनवाये गये हैं।

समाज सेवा के विभिन्न कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु एक बड़े भू खंड की आवश्यकता महसूस करते हुए राजस्थान आवासन मंडल से 3000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित करायी गयी जिस पर स्वामी लीला शाह भवन का निर्माण करवाया गया जिसमें 2 बड़े हॉल, 34 कमरे और 2 डोरमेट्री निर्मित है।

जरूरतमंद रोगियों की दवाई की खरीद हेतु सहायता दी जाती है इसके अलावा आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

जरूरतमंद विद्यार्थियों को कक्षावार निश्चित सहायता राशि दी जाती है।

स्वामी लीला शाह धार्मिक ट्रस्ट गठित करते हुए राजा पार्क में कुलदेवी हिंगलाज माता का मंदिर बनवाया गया। इस मंदिर परिसर में शिव परिवार, बजरंगबली, रामापीर और स्वामी लीला शाह की मूर्तियां स्थापित है।

उपरोक्त लगातार चलने वाले कार्यों के अलावा समिति की ओर से सिंधी ब्रह्म खत्री समाज के लिए सामूहिक विवाह के आयोजन वर्ष 1985 से किये जा रहे हैं 2022 तक 1380 युगलों के विवाह किये जा चुके हैं जिसमें संपूर्ण भारत के राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और दिल्ली से हजारों मेहमानों ने भाग लिया।

स्वामी लीला शाह द्वारा प्रारंभ किये गये सामूहिक विवाह के पुनीत कार्य से प्रेरणा लेकर समिति की ओर से वर्ष 2022 में सत्रहवां सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। समिति को कार्य संचालन में जो कामयाबी मिली है वह महानगर जयपुर की सभी सिंधी ब्रह्म खत्री पंचायतों की वजह से मिली है। विशेषकर युवाओं, सिंधी खत्री महिला मण्डल जयपुर, नवयुवक मण्डल जयपुर, सांगानेर, मानसरोवर, प्रताप नगर एवं पुष्कर द्वारा कड़ी मेहनत से समारोह को सफ़ल बनाया गया है।

'संत की महिमा वेद न जाने, जेता कहे तेता बखाने'

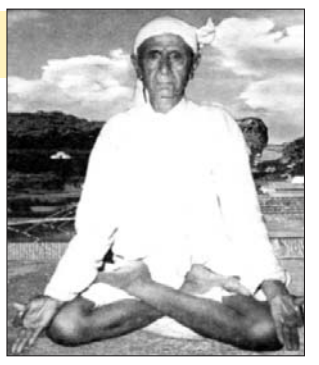

जिस तरह पेड़, नदियां, बादल इत्यादि अपने लिये पैदा नहीं होते बल्कि उनका जीवन परमार्थ हेतु दूसरों की भलाई के लिए होता है। उसी तरह सच्चे साधु संत महात्मा भी अपना जीवन यज्ञमय बनाते हैं। ऐसे महापुरुष समय समय पर संसार में आते हैं। वे स्वयं तो भवसागर में तर जाते हैं साथ ही औरों को भी भवसागर से पार पहुंचा देते हैं। ऐसे संतों के लिए सुखमनी साहिब में आया है कि संत की महिमा वेद न जाने, जेता कहे तेता बखाने। सच्चे संतों के बारे में किसीने कहा है पारस और संत में बड़ा फर्क जान, वह लोहा कंचन करे , वह करे आप समान पारस तो लोहे को स्पर्श कर उसे सोना बना देता है उसमे यह गुण नहीं होता है कि लोहे को पारस बना सके लेकिन संत महात्मा में यह गुण होता है कि वे लोगों और सच्चे जिज्ञासूओं को जो उनकी संगत में आता है उनको अपने जैसा बना देते हैं।

सुखमनी साहिब में आया है कि आप तरे तारे संसार, नानक ऐसे संत को सदा नमस्कार।

ऐसे ही जग वंदनीय संत महात्माओं में शामिल है स्वामी लीला शाह महाराज जिनका संपूर्ण जीवन यज्ञ मय था उन्होंने अपना पूरा जीवन लोक कल्याणार्थ समर्पित कर दिया था। सिंधी में एक कहावत है जिसका हिन्दी में अर्थ है कि गुलशन में फूल तो कितने ही होते हैं, परंतु सदैव सुगंधित गुलाबी एवं सदाबहार फूल कम ही होते हैं, जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ खुशबू देकर , मनुष्य के नेत्रों में ठंडक पहुंचाकर दिमाग को आनंदित करते हैं।

ऐसे ही सच्चे मनुष्य, लोक उपकारी पुरुष जगत रूपी गुलशन के सदाबहार कभी न मुरझाने वाले फूल थे स्वामी लीला शाह महाराज। जिनका गुणगान शब्दों मे करना असंभव है। स्वामी लीला शाह का संक्षिप्त परिचयः

जन्म नामः लीलाराम खत्री, जन्म तिथिः 23 फाल्गुन वि. सं. 1037 सन 1881 ई, माता का नामः श्रीमती हेमा बाई, पिता का नामः टोपणदास टाटारिया, जन्म स्थानः महिराब चांडियो जिला हैदराबाद सिंध, गुरु का नामः संत केशवराम, टंडो महमद खान, निवासः नगर से दूर कुटिया बनाकर अथवा बाग बगीचों में रहना। स्वामी जी बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मश्रोत्रिय, ब्रह्मनेष्टि, ब्रह्मज्ञानी , संत शिरोमणि, महा योगी, महा त्यागी, पूर्ण तपस्वी, कुदरती ईलाज के माहिर, देश भक्त, समाज सुधारक, धर्म प्रचारक, गौ पालक, हरिजन उद्धारक, गरीबों और अबलाओं के हमदर्द, पंचायतों के लिए रहबर, बेसहारा के सहारा और अच्छा साहित्य छपवा कर बांटने वाले और कर्म वीर थे। गीता की शिक्षा उनके रग रग में समायी थी उनकी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं था। सादा जीवन था। स्वामी जी ने अनेक पाठशालाएं, नारी शालाएं, गौ शालाओं, धर्म शालाएं एवं व्यायाम शालाएं कायम करवायी। काफी संख्या में कुएं खुदवाये, दहेज प्रथा उन्मूलन हेतु एवं मातृ भाषा हेतु प्रचार किया। मानव कल्याण एवं सनातन धर्म हेतु उतर सिंध के कस्बों में हरिजन उद्धार का कार्य प्रारंभ किया वहां व्यायाम शालाएं और पाठशालाएं बनवायी। 1930 में सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय भाग लेकर सफल बनाने में पूर्ण सहयोग दिया। 1942 में सामाजिक चेतना का कार्य किया और आयोजित चुनाव के दौरान कांग्रेस को पूर्ण सहयोग दिया। 1943 में बंगाल में अकाल राहत कार्य में सहयोग के रूप में दस हजार मन चावल भेजे। गढ़वाल राज्य के उतर काशी में गंगा नदी पर दो पूल का निर्माण करवाया।

साहित्य सेवा के रूप में धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन करवाकर मानव उत्थान हेतु छोटी-छोटी पुस्तकों का वितरण किया और वेदांत मत का प्रचार किया। विभाजन के पश्चात भारत आ गए और शरणार्थी और पुरुषार्थी के कामों में जुट गए। जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय वेदांत सम्मेलन में प्रवचन दिए एवं सभापति पद को भी सुशोभित किया। अजमेर में 1957 में आयोजित अखिल भारतीय सिंधी समाज सम्मेलन में आपने दहेज प्रथा के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया 1964 में आयोजित सिंधी ब्रह्म खत्री सम्मेलन को अखिल भारत पंचायत के रूप में स्थापित करवाया, जिसमें शिक्षा प्रचार हेतु एक लाख रुपये की राशि का कोष स्थापित किया। गीता प्रेस की कुछ आध्यात्मिक पुस्तकों का सिंधी भाषा में अनुवाद करवा कर वितरित करवायी।

सिंधी भाषा एवं मातृ भाषा का प्रचार किया। चाय, धूम्रपान शराब और मांस इत्यादि के सेवन के विरुद्ध प्रचार किया। अपने स्वयं के लिए मंदिर स्थान नहीं बनवाया। विदेशाटन के लिए करीब 15- 20 देशों की यात्राएं की जहां पर मानव कल्याण हेतु लोगों को जागरूक किया। स्वामी जी सच्चे साधु और धर्म प्रचारक थे। स्वामी लीला शाह जब सत्संग आदि करते थे तब श्रद्धालुओं से बीच-बीच में जय राम जी की और हरि ओम तत् सत बुलवाते थे। मानव कल्याणार्थ कार्य करते हुए स्वामी जी 4 नवंबर 1973 को अनन्त ज्योति में ब्रह्मलीन हो गए।

अखिल भारत सिंधी ब्रह्म खत्री सहायता विद्या ट्रस्ट

अखिल भारत सिंधी ब्रह्म खत्री सहायता विद्या फंड की स्थापना वर्ष 1964 में की गयी, 1987 में इसका नाम अखिल भारत सिंधी ब्रह्म खत्री सहायता विद्या ट्रस्ट कर दिया गया। ट्रस्ट अध्यक्ष किशन रामनानी ने बताया कि इस ट्रस्ट में कुल 11 सदस्य है जिसमें 1 चेयरमैन, 1 वॉयस चेयरमैन, 1 सचिव, 1 कोषाध्यक्ष और 7 ट्रस्टी हैं।

ट्रस्ट का उद्देश्य एवं कार्य : गरीब एवं जरूरतमंद विधवाओं, असहाय परिवारों के भरण पोषण हेतु प्रति माह सहायता राशि दी जाती है, यदि कोई विधवा औरत स्वयं का रोजगार प्रारंभ करना चाहती है तो उसे 15,000 तक की राशि रोजगार प्रारंभ करने हेतु प्रदान की जाती है इस सहायता के पश्चात उसे भरण पोषण की राशि नहीं मिलती है।

शिक्षा के क्षेत्र मे कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा सहायता और स्नातक एवं प्रोफेशनल डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स के लिए बिना ब्याज लोन, मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, मेडल एवं प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया जाता है।

विद्यार्थियों के मार्गदर्शन हेतु सेमिनार आयोजित करना और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं को सम्मानित करना इत्यादि।

इसके अलावा संस्था द्वारा वर्ष 2023-24 में किये गये कार्य : विधवा सहायता भरण पोषण 189, असहाय परिवार 29, शिक्षा सहायता 254, बगैर ब्याज लोन 46, छात्रवृत्ति 40, मेधावी विद्यार्थियों को मेडल एवं प्रमाणपत्र 150, विद्यार्थियों के मार्गदर्शन हेतु सेमिनार 1 और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली 4 संस्थाओं को वर्ष 2022 में मोमेंटो और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया।

अखिल भारतीय सिंधी ब्रह्म खत्री मेडिकल सहायता ट्रस्ट

अखिल भारतीय सिंधी ब्रह्म खत्री मेडिकल सहायता ट्रस्ट की स्थापना 24 अगस्त 2004 सांगानेर में अखिल भारत सिंधी ब्रह्म खत्री समाज के सम्मेलन में की गयी। ट्रस्ट सचिव जयकिशन छंछंरिया ने बताया कि इस संस्था में एक नॉमित पद पैटर्न पांच पदाधिकारी, एक चेयरमैन, एक वॉयस चेयरमैन, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष, एक संयुक्त सचिव और छह ट्रस्टी होते हैं जो समाज के हितों के लिए कार्य करते हैं।

दान दाताओं से सहायता राशि एकत्रित कर संस्था सिंधी ब्रह्म खत्री समाज के गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के ईलाज की व्यवस्था करती है जिसके तहत साधारण बीमारी के लिए 2500 रुपए तक और गम्भीर बीमारी के लिए जैसे टीबी, ब्रेन ट्यूमर, लीवर, ब्रेन डेमेज, किडनी, कैंसर और लकवा इत्यादि तथा बड़े ऑपरेशन हेतु अधिकतम राशि उपलब्ध करायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 26 जरूरत मन्द रोगियों को इलाज के लिए मेडिकल सहायता उपलब्ध करवायी जा चुकी है संस्था की स्थापना से अब तक लगभग 500 रोगी लाभान्वित हो चुके हैं।

संस्था द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किये जाते हैं , शुगर, बी पी की जांच, दांतों एवं आँखों के इलाज के लिए भी शिविर लगाए जाते हैं और शिविर में निःशुल्क दवा दी जाती है।

समाज सेवा के कार्यों में तन-मन-धन से समर्पित है जयकिशन खत्री

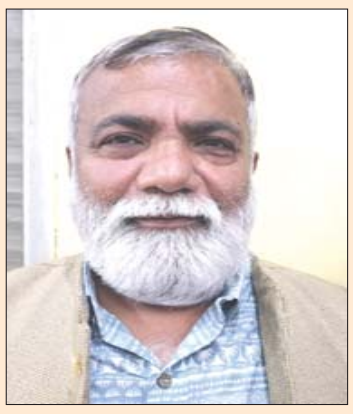

सुप्रसिद्ध समाजसेवी स्व. मुखी भगवानदास जी खत्री के सुपुत्र जयपुर निवासी सुप्रसिद्ध उद्यमी एवं समाजसेवी 58 वर्षीय जयकिशन खत्री जे के इंटरप्राईजेज के बैनर तले प्लास्टिक एवं पेपर (कोरोगेटेड) पैकिंग मेटेरियल का उत्पादन कर रहे हैं।

आपके पिताजी स्व. भगवानदास खत्री लंबे समय तक समाज के मुखिया रहे और समाज सेवा में समर्पित रहे। अपने पिताजी की प्रेरणा से जयकिशन खत्री भी बाल्यकाल से ही समाज सेवा की तरफ आकर्षित हुए और गत कई वर्षों से समाज सेवा के कार्यों में संलग्न है। समाज एवं मानव सेवा के उद्देश्य से आप अनेक संस्थाओं से जुड़े हैं जिनमें प्रमुख है लायंस क्लब पूर्व सचिव, रोटरी क्लब वर्तमान अध्यक्ष, सीतापुरा इंडस्ट्रियल

एसोसिएशन के कोर मेंबर, अखिल भारतीय सिंधी खत्री मेडिकल सहायता ट्रस्ट में गत पांच वर्षों से सचिव पद पर है, स्वामी लीला शाह समिति जयपुर की कार्यकारिणी सदस्य एवं इसके अधीनस्थ स्वामी लीला शाह भवन के संयोजक पद पर है।

हाल ही में आपके पिताजी की पुण्य तिथि पर लघु भारती के तत्वावधान में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 200 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया इस शिविर में अनेक गणमान्य व्यक्तियों एवं राजनेताओं ने भाग लिया। जयकिशन जी समाज सेवा के कार्यों में हर समय तन मन धन से सहयोग करने में सदैव अग्रणी रहते हैं हर कार्य में आपका आर्थिक योगदान रहता है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

मछलीशहर : जातियता के जकड़न में मोदी-योगी का छौंका

-सुरेश गांधी

आजादी के बाद मछलीशहर के लोग फूलपुर लोकसभा के लिए 1952 और 1957 तक वोटिंग करते रहे और 1984 तक कांग्रेस का कब्जा रहा। लेकिन अब यहां पार्टी अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। खास यह है कि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके सूरापुर (सुल्तानपुर) के मूल निवासी श्रीपति मिश्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नागेश्वर द्विवेदी, राम मंदिर आंदोलन के अगुवा स्वामी चिन्मयानंद और राम विलास वेदांती जैसे दिग्गज नेताओं ने संसद में नुमाइंदगी कर चुके है, लेकिन विकास के नाम पर नतीजा ढाक के तीन पात वाला ही रहा। 2009

तापमान भले ही 40 डिग्री से ऊपर हो, लेकिन चुनावी माहौल ठंडा है। गांवों में न चुनाव कार्यालय दिख रहे है न झंडे-बैनर। किसान खेत खलिहानों में फसल निकालने में जुटा है, तो कार्यकर्ता बिना प्रत्याशी के जीत की बाजी अपने पक्ष में करने के लिए हाडतोड मेहनत कर रहे हैं। यह अलग बात है कि पिछली बार मुकाबले से बाहर रहे सपा व बसपा इस बार भी भाजपा को सीधी टक्कर दे रहे है। यही वजह है कि कार्यकर्ता हो या आम मतदाता सबकी जीत की गणित जाति ही है और इसी जातियता को तोडने के लिए भाजपाई लोगों में राम मंदिर, योगी बाबा का बुलडोजर, धारा 370 की दुहाई देकर देशभक्ति की अलख यहकर जगा रहे है कि ह्यमोदी-योगी है तो सब मुमकिन है फिरहाल, मतदाता मौन है, लेकिन मुद्दों की बात करने पर जफर कहते है लोकसभा में स्थानीय मुद्दे ज्यादा मायने नहीं रखते। आम मतदाता राष्ट्रीय सुरक्षा, महंगाई, भ्रष्टाचार, तीन तलाक जैसे मुद्दों पर ही भाजपा, सपा व बसपा की सोच, नीतियों और घोषणाओं को परख रहा है। भाजपा को उम्मीद है कि 2019 में बीपी सरोज भले ही मात्र 182 वोट से जीते सके, लेकिन इस बार प्रत्याशी के सहारे दलितों के वोट तो बरसेंगे ही मोदी-योगी की लोकप्रियता और राम मंदिर व देशभक्ति कार्ड के सहारे उसकी नैया पार हो सकती है। बाजी किसके हाथ लगेगी, ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन गोपालपुर के प्रदीप जायसवाल कहते है जातियता के जकड़न में मोदी-योगी का छौंका इस बार भी लगेगा। संतोष जायसवाल कहते है पिंडरा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों उद्घाटित बनास अमूल डेरी इस क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल के लिए रोजगार का बड़ा माध्यम बनेगा

में एक बार फिर चुनाव आयोग की परिसीमन की कवायद की जद में यह क्षेत्र आ गया। इस बार बड़े भौगोलिक बदलाव के साथ इसे सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र घोषित कर दिया गया। परिसीमन के बाद इस क्षेत्र में तत्कालीन सैदपुर (सु) लोकसभा क्षेत्र को समाप्त कर जफराबाद (बयालसी), केराकत (सु), मछलीशहर, मडि?ाहूं व वाराणसी जनपद की पिंडरा विधान सभा को शामिल किया गया। इस बदलाव के बाद पहले चुनाव में सैदपुर के सपा सांसद तूफानी सरोज चुने गए। अगले 2014 के चुनाव में मोदी की सुनामी का असर रहा कि भाजपा के रामचरित्र निषाद व 2019 में बीपी सरोज भाजपा बनकर लोकसभा के सदस्य बने। लेकिन समस्या जस की तस मुंह बाएं खड़ी है। इस सीट के मतदाता दलों को ताश के पत्तों की तरह फेंटते रहे हैं। यह भी कम दिलचस्प नहीं कि तमाम मतदाता भाजपा और सपा प्रत्याशियों का नाम तक भी नहीं जानना चाहते। इनके लिए लोकतंत्र के इस सबसे बड़े समर में उनके लिए चुनाव-चिह्न ही काफी है।

बड़ागांव के कहीं एक दुकान पर गरमा गरम जलेबियों और बेसन मिलाकर तल मिर्च का स्वाद ले रहे जयंत यादव और ललित वाल्मीकि पटेल मिलते हैं। जयंत कहते हैं, हमारे क्षेत्र में तो इस बार भी कमल के आगे रहने की उम्मीद है। जबकि नेवादा के सफीक अंसारी मानते हैं कि सपा इस बार अच्छी फाइट देगी। हालांकि, सपा प्रत्याशी की जीत को लेकर वे उतने मुतमईन नहीं, जितना कि भाजपा प्रत्याशी को लेकर बनवारी व सावंत दिखते हैं। मड़ियाहूं बेलवा मार्ग पर ही आगे बढ़ने पर पराउगंज में मनोहर कोयले की भट्ठी में हंसिया और दरांती ढालते हुए मिलते हैं। युवा योगेन्द्र गेहूं काटने के लिए पंजाब जाने की तैयारी में हैं। बताते हैं, हमारे इलाके में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। किसी फैक्टरी में काम करने जाएं तो खा-पीकर बमुश्किल 4-5 हजार ही बचा पाते हैं। सियासी चर्चा आगे बढ़ी तो योगेन्द्र के ही साथी जनार्दन मौर्य कहते हैं, तहसील-थानों और कचहरी के भ्रष्टाचार आज भी बदस्तूर जारी है। चुनाव आते-जाते हैं, पर व्यवस्था नहीं बदलती। क्या वोट नहीं देंगे? जनार्दन कहते हैं- वोट काहे न देंगे। फिर खुद ही सवाल कर डालते हैं-भाजपा के सामने कौन है? बात काटते हुए महेश कश्यप कहते हैं, अगर मुकाबले में सपा ने किसी स्थानीय को उतारा तो इस तरह का सवाल पैदा ही नहीं होगा। खैर, इन सभी की परेशानी का सबब यह है कि हर बार उनका वोट कट जाता है। पर यहां के नेता ध्यान नहीं देते। कठिराव के नंदलाल जायसवाल आपस में बतियाते हुए मिले, तो हम भी उनमें शामिल हो लिए। कहते हैं कि 5 किलो राशन से परिवार नहीं चलता। इस बार जनता परिवर्तन का मूड बना रही है। संजय जायसवाल कहते हैं कि माहौल तो हर तरफ भाजपा का ही दिख रहा है। गुंडागर्दी कम हुई है। हालांकि भ्रष्टाचार इस सरकार में भी कम नहीं हुआ है। मुख्तार हाशमी कहते हैं, इस बार बसपा प्रत्याशी भी मजबूती से लड़ाई में रहेंगे। अपनी बात को पुख्ता करने के लिए वह दलील देते हैं कि आज सरकारी बहुत चालाक हो गए हैं। अपने दिल की बात नहीं बताते हैं। वहीं, मडियाहूं निवासी शमीलां बताती हैं कि मोदी ने उन्हें क्या नहीं दिया है, मान-सम्मान के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें ही नहीं अधिकांश महिलाओं को मिला है, इस बार महिला शक्ति मोदी के लिए समर्पित रहेगी।

मोकलपुर के अजय कन्नौजिया कहते है मुद्दों की बात करें तो यहां बिजली कटौती, उबड खाबड सडके, बेरोजगारी, कल कारखानों का अभाव, उच्चशिक्षा की कमी सहित समस्याएं कई है। लेकिन अब जाति व व्यक्ति आधारित वोट मिलते है। इसलिए प्रत्याशी की कर्मठता व योगदान को देखकर ही वोट करेंगे। पिंडरा के मनोज पटेल कहते है वास्तव में यहां जातिवादी राजनीति का गणित चलेगा। लंबे समय में यहां कोई बड़ा कल कारखाना नहीं लगा है। लेकिन चुनाव के समय मुद्दे गायब हो जाते है, जातिवाद ही चलता है। पटेल बाहुल क्षेत्र होने के चलते इस सीट पर भाजपा का पलड़ा भारी रहेगा। क्योंकि भाजपा से गठबंधन करने वाली अपना दल की अनुप्रिया पटेल का समर्थन है। बनिया, ठाकुर, ब्राह्मण, पासी, मौर्या आदि वोट भाजपा के पक्ष में जा सकता है। वैसे भी चुनाव में राष्ट्रीय नेताओं और मुद्दों पर ही वोट डाले जायेंगे। केराकत के मई गांव में निवासी ब्रह्मराज कहते है 15 साल गुजर जाने के बाद भी उनकी टीस बरकार है। 2004 नाव से नदी पार करते वक्त नाव डूब जाने से पांच से छह लोगों की मौत हो गई थी। वर्तमान में भी यहां के लोगो को नदी पार कर जिला मुख्यालय जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है या फिर 30 किमी की अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। अगर ये पुल बन जाता है तो जिला मुख्यालय जाने के लिए लोगो के मात्र 18 से 20 किमी की दूरी तय करनी पड़ेगी। बता दें, 15 सितंबर 2011 में तत्कालीन बसपा सरकार में 4 करोड़ 22 लाख की लागत से नाबार्ड वित्त पोषित योजना के अंतर्गत मई पसेवा मार्ग पर बसपा सरकार के मंत्री निसिमुद्दीन सिद्दीकी ने इस पुल की नींव रखी थी। जिसका समय भी 18 महीने निर्धारित किया गया था, लेकिन पुल का निर्माण कार्य अधूरा है और काम पूरी तरह बंद है। जिसके ग्रामीणों में नाराजगी है। भाउपुर-गोपालापुर के मो. हादी बबलू अपने कुछ साथियों के साथ बैठे हुए मिलते है। बिना झिझके बताते हैं कि उनका वोट तो सपा को ही जाएगा, क्योंकि सपा मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं करती है। बसपा की हकीकत भी मुसलमान समझ चुके हैं। हालांकि, उनके साथ ही बैठे रोशन लाल वर्मा, कैलाश चंद्र और रूप लाल कश्यप मोदी सरकार में मिल रही सुविधाएं गिनाने लगते हैं। राहुल गुप्ता और देवांश शर्मा भी उनकी हां में हां मिलाते है। कहते हैं कि कुछ समय पहले शारदा नदी के धनौरा घाट पर पुल मंजूर होने से आम लोग काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं।

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जबरदस्त कन्फ्यूजन में है!

अशोक भाटिया

उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का माहौल गरमा गया है। पार्टियों ने तकरीबन अपने सभी उम्मीदवार तय कर लिए हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी में लगातार दुविधा की स्थिति बनी हुई है। पार्टी कई सीटों पर अपने घोषित प्रत्याशियों के टिकट काट रही है या बदल रही है।

उत्तरप्रदेश की पहले चरण में की आठ सीटों पर वोटिंग होनी है। इनमें से रामपुर और मुरादाबाद की दो सीटों पर जबरदस्त सि?ासी ड्रामा हुआ। अखिलेश यादव ने मुरादाबाद सीट पर अखिरी वक्त में उम्मीदवार बदल दिया। सांसद एस टी हसन ने मंगलवार को नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बुधवार को अखिलेश यादव ने रूचि वीरा को पार्टी का चुनाव निशान देकर मुरादाबाद भेज दिया। उन्होंने भी नामांकन भर दिया। अब समाजवादी पार्टी के निशान पर दो दावेदार हो गए। हालांकि शाम को समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया कि रूचि वीरा ही अधिकृत उम्मीदवार होंगी। इसी तरह रामपुर में पहले आसिम रजा के चुनाव लड़ने की उम्मीद थी, वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन बुधवार को आसिम रजा और रामपुर में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव के बाईकॉट करने का एलान तक कर दिया था। बुधवार को आखिरी वक्त में जैसे ही समाजवादी पार्टी ने मौलाना मोहिबुल्ला नदवी को नामांकन दाखिल करने के लिए भेजा तो आसिम रजा ने भी पर्चा भर दिया। अब रामपुर में भी समाजवादी पार्टी के दो उम्मीदवार मैदान में हैं। रामपुर और मुरादाबाद दोनों सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कन्फ्यूज्ड हैं। सवाल है कि ये कन्फ्यूजन किसने पैदा किया? क्या इसमें जेल में बंद आजम खां का रोल है? क्या आजम खां के इशारे पर ये पहले मुरादाबाद की बात करते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ एस टी हसन ने मंगलवार को पर्चा भरा था, जीत के दावे किए थे। चूंकि एस टी हसन मुरादाबाद से सांसद हैं, लेकिन इसके बाद भी अखिलेश यादव ने उनका टिकट लटकाए रखा, देर से टिकट दिया। एस टी हसन ने पर्चा भर दिया लेकिन रात में खेल हो गया। देर रात ये खबर आई कि मुरादाबाद से एस टी हसन का टिकट कट गया है। अब पूर्व विधायक रूचि वीरा समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ेंगी। इस बीच रुचि वीरा लखनऊ से मुरादाबाद पहुंच गईं लेकिन रुचि के मुरादाबाद पहुंचते ही एस टी हसन के समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद अखिलेश यादव ने चार्टर्ड प्लेन से नरेश उत्तम और समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं को मुरादाबाद भेजा ताकि हालात को काबू में रख सकें। रूचि वीरा मुरादाबाद में पर्चा भरने पहुंच गई, उनके साथ गिने चुने लोग थे, नारा लगाने वाले और पार्टी का झंडा उठाने वाले लोग भी नहीं थे। रूचि वीरा ने वक्त खत्म होने से पहले पर्चा भर दिया, समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान वाला फॉर्म बी जमा कराया। पता ये चला कि एस टी हसन का पत्ता आजम खां के कहने पर कटा है। आजम खां सीतापुर जेल में बंद हैं लेकिन अखिलेश यादव को लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं पर अभी भी आजम खां का जबरदस्त असर है। आजम खां जेल में रहकर भी चुनावी समीकरण बना और बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर टिकटों के बंटवारे पर राय लेने के लिए सीतापुर जेल में आजम खां से मिले थे। आजम खां ने ही मुरादाबाद सीट पर एस टी हसन की जगह रूचि वीरा के नाम का सुझाव दिया जिसे अखिलेश ने मान लिया और रातों रात हसन का टिकट काट दिया। समाजवादी पार्टी के ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता जानते हैं कि रूचि वीरा आजम खां की करीबी हैं, रुचि वीरा बिजनौर से सपा के टिकट पर विधायक रह चुकी हैं। ये तो कोई नहीं मानेगा कि रूचि वीरा एस टी हसन के मुकाबले बड़ी नेता हैं, उन्हें आजम खां की पैरवी पर ही अखिलेश यादव ने टिकट दिया। बाद में हसन ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम ये फैसला कैसे हुआ, किसके कहने पर हुआ और उन्हें बताने की भी जरूरत नहीं समझी गई। हसन ने बड़ी महीन सियासी बात कही। उन्होंने कहा कि पूरा हिन्दुस्तान जानता है आजादी के बाद से अब तक जितने चुनाव हुए, उनमें एक बार छोड़कर मुरादाबाद से हर बार मुसलमान उम्मीदवार ही चुनाव जीता है। दरअसल अखिलेश यादव मुरादाबाद सीट से एस.टी. हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाने के पक्ष में नहीं थे। अखिलेश यादव ने एस.टी. हसन को फिर से प्रत्याशी बनाने के लिए एक पत्र जारी किया था। जिसमें एस.टी. हसन को फिर से मुरादाबाद सीट से सपा का प्रत्याशी बनाया गया था। ये खत रुचि वीरा का नॉमिनेशन होने के बाद जारी किया था। अखिलेश यादव ने रुचि वीरा का नामांकन रद्द करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा था। ये पत्र लखनऊ से मुरादाबाद चुनाव ऑफिसर के पास भेजा गया, लेकिन समय से पत्र नहीं पहुंचने के कारण लेटर को रिसीव नहीं किया गया।

रामपुर में दिल्ली के संसद मार्ग मस्जिद के इमाम मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी और आसिम रजा दोनों सपा की उम्मीदवारी का दावा कर रहे थे । मौलाना को मंगलवार रात लखनऊ से आदेश मिला कि रामपुर पहुंचिए, रामपुर से पर्चा भरना है। मौलाना नदवी रामपुर के रहने वाले हैं लेकिन दिल्ली में पिछले 15 साल से रह रहे हैं। बुधवार को मौलाना ने पर्चा भर दिया। मौलाना नदवी ने कहा कि उनका नाम खुद अखिलेश यादव ने फाइनल किया है, उन्हीं के कहने पर उन्होंने अपना पर्चा भरा है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वही हैं। इसके तुरंत बाद आजम खां के करीबी आसिम रजा भी पर्चा भरने पहुंच गए। उन्होंने भी पर्चा दाखिल कर दिया। इस बात में कोई शक नहीं कि रामपुर पर एक लंबे अर्से तक आजम खान का कब्जा रहा है, वो रामपुर के चप्पे-चप्पे को जानते हैं। यहां के बच्चे-बच्चे को पहचानते हैं लेकिन अब मजबूर हैं। जेल में बंद हैं। उन पर सैंकड़ों केस हैं। योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में उनका दबदबा खत्म कर दिया। रामपुर में आजम खान के उम्मीदवारों को हरा दिया पर आजम खान आसानी से हार मानने वालों में नहीं हैं। वो जेल में रहकर भी इस इलाके की सियासत पर खासा असर डाल सकते हैं। उनका ये सुझाव कि रामपुर से अखिलेश को लड़ना चाहिए, अच्छा था लेकिन अखिलेश इन चुनावों में एक-एक कदम फूंक-फूंक कर रख रहे हैं। अखिलेश के लिए ये चुनाव अस्तित्व का सवाल है। हालांकि वो आजम खान की बात सुनते हैं लेकिन रामपुर से चुनाव लड़ने की बात नहीं मानी, इसीलिए इतना कन्फ्यूजन पैदा हुआ। दूसरी तरफ भाजपा ने जबरदस्त चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ, मथुरा, गाजियबाद में प्रचार कर रहे हैं।

रामपुर और मुरादाबाद के बाद मेरठ का भी नाम इसमें जुड़ गया है . ये उत्तर प्रदेश में वो तीन सीट हैं, जिनपर समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिला। हर बार की तरह इस बार भी सपा में टिकट को लेकर भारी असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। मेरठ से जब भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया , तो दूसरी तरफ सपा प्रत्याशी का ऐलान कर बार-बार बदलाव कर रही है। मेरठ लोकसभा सीट पर सपा ने एक बार फिर अपना प्रत्याशी बदला दिया है। अतुल प्रधान की जगह अब पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को उम्मीदवार घोषित किया है।समाजवादी पार्टी ने पहले मेरठ सीट से एडवोकेट भानू प्रताप सिंह को टिकट दिया गया था, लेकिन भानू प्रताप के नाम पर पार्टी के स्थानीय नेताओं ने नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद अखिलेश यादव ने मेरठ सीट पर सरधना से विधायक अतुल प्रधान को प्रत्याशी घोषित कर दिया। अतुल प्रधान का ऐलान होते ही पार्टी में बगावत छिड़ गई। मेरठ शहर विधायक रफीक अंसारी ने मेरठ सीट पर दावा ठोक दिया है। अब अखिलेश यादव ने पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। वैसे चुनावी मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आज शाम तक और भी कई उम्मीदवारों के टिकट बदले जा सकते है।

उत्तर प्रदेशः प्रथम चरण-मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट

-अजय कुमार

18 में छह : लाख मुस्लिम वोटर, फिर भी एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं

उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण में पश्चिमी यूपी की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भी मतदान होना है। यूपी की एक बेहद खास लोकसभा सीट है मुज्जफरनगर, जहां का मुकाबला साल 2013 में हुए दंगों के बाद से बेहद रोचक और सुर्खियों में रहा है।यहां कुल 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इस क्षेत्र को जाटलैंड के नाम से भी जाना जाता हैं. बीजेपी के पास इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने का मौका है. इस सीट से चौधरी चरण सिंह ने अपने जीवन का पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था. हालांकि उनको जीत नहीं मिल पाई थी. इस लोकसभा क्षेत्र में जाट और मुस्लिम वोटर्स की बहुलता है.हैरत की बात ये है कि 18 लाख की आबादी में से 6 लाख मुस्लिम वोटर होने के बाद यहां किसी राजनीतिक दल ने मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा. इसके अलावा किसी मुस्लिम प्रत्याशी ने निर्दलीय नामांकन भी नहीं किया है.

मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से बीजेपी ने एक बार फिर से संजीव बालियान को मैदान में उतारा है. पिछली बार यानी साल 2019 आम चुनाव में बालियान ने मामूली अंतर से जीत हासिल की थी. उधर, इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक को उम्मीदवार बनाया है. बहुजन समाज पार्टी ने रियल एस्टेट कारोबारी दारासिंह प्रजापति को टिकट दिया है. साल 2019 आम चुनाव में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार संजीव बालियान ने आरएलडी मुखिया चौधरी अजीत सिंह को हराया था. बालियान को 5 लाख 73 हजार 780 वोट मिले थे. जबकि चौधरी अजीत सिंह को 5 लाख 67 हजार 254 वोट हासिल हुए थे. संजीव बालियान मुजफ्फरनगर के साथ-साथ मेरठ, शामली व बागपत सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय नेता के तौर पर जाने जाते हैं। बात उम्मीदवारों की सियासी रूख की कि जाये तो बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान ने राज्य मंत्री के रूप में पब्लिक के बीच रहकर हमेशा उनके दुख और सुख को साझा किया है और अब लोकसभा चुनाव 2024 में भी भाजपा ने संजीव बालियान पर ही विश्वास जताते हुए उन्हें प्रत्याशी घोषित किया है। बता दें कि इस बार भाजपा के एनडीए गठबंधन में राष्ट्रीय लोक दल भी शामिल हो गया है।

समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व राज्यसभा सांसद हरेंद्र मलिक जनपद मुजफ्फरनगर के कद्दावर नेताओं मे गिने जाते हैं। उनके पास विधानसभा और लोकसभा के 9 चुनाव खुद लड़ने और 4 चुनाव अपने बेटे पंकज मलिक को चुनाव लड़ाने का तजुर्बा है। हरेंद्र मलिक खतौली और बागरा विधानसभा से कई बार विधायक बनें जिसके बाद 1996 में किसान कामगार पार्टी जो अब राष्ट्रीय लोकदल के नाम से जानी जाती है, से चुनाव हारे। उसके बाद वर्ष 1998, 1999, 2009 में मुजफ्फरनगर से तो साल 2019 में कैराना लोकसभा सीट से सांसद का चुनाव हारे और फिर 2002 में हरेंद्र मलिक को हरियाणा की इनेलो पार्टी से राज्यसभा सदस्य बनाया गया। अब 2024 में मुजफ्फरनगर लोकसभा से सपा व कांग्रेस के इंडी गठबंधन से फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हरेंद्र मलिक अपने बेटे पंकज मलिक को विधायक बनाने में कामयाब रहे। पंकज मलिक एक बार बघरा से तो एक बार शामली से और फिर तीसरी बार चरथावल विधानसभा से विधायक बना। बात बसपा प्रत्याशी की कि जाये तो प्रजापति समाज के नेता और रियल एस्टेट कारोबारी दारा सिंह प्रजापति ने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कर दिया है। उन्होंने नामांकन पत्र के साथ अपनी संपत्ति और परिवारजनों का ब्योरा प्रस्तुत किया है। दारा सिंह प्रजापति की उम्र 55 साल हैं। पत्नी कमलेश, बेटी नेहा प्रजापति और एक बेटा ऋषभ प्रजापति हैं। इनके खिलाफ कमिश्नरी कार्यालय मेरठ में धरने के दौरान भड़काऊ भाषण देने और विकास प्राधिकरण मेरठ की ध्वस्तीकरण कार्यवाही को रोकने संबंधित मामले दर्ज हैं। पिछले दिनों प्रजापति समाज को सामाजिक हक दिलाने के लिए हरिद्वार से गाजियाबाद तक एक स्वाभिमान यात्रा निकाली गयी थी। जिसपर गाजियाबाद में लाठीचार्ज हुआ था। इस दौरान ही दारा सिंह चर्चाओं में आये थे। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर दारा सिंह प्रजापति के नामांकन के बाद मुकाबला त्रिकोणीय बनता नजर आ रहा है।

बात एक भी मुस्लिम प्रत्याशी के मैदान में नहीं होने की ही कि जाये तो आश्चर्य होता है कि यह सब तब हुआ है जबकि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर साल 1967 से अलग-अलग समय में मुस्लिम प्रत्याशी जीतते रहे. इसके पीछे यहां मुस्लिम वोटर की संख्या है. मुजफ्फरनगर की कुल आबादी 18 लाख है. इसमें से 6 लाख मुस्लिम हैं.लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर सपा, बसपा और भाजपा सहित 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें एक भी प्रत्याशी मुस्लिम नहीं है। ये हालात तब हैं। जब 1967 के बाद से मुजफ्फरनगर सीट पर कई मुस्लिम नेता सांसद चुने जा चुके हैं। इनमें लताफत अली खां, मुफ्ती मोहम्मद सईद और कादिर राना सरीखे दिग्गज मुस्लिम नेता शामिल हैं।

यूपी की मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट मुस्लिम राजनीति के लिए इतनी मुफीद साबित रही कि साल 1999 से 2014 तक लगातार 15 साल तक यहां मुस्लिम सांसद ही रहे। साल 1999 में कांग्रेस के सईदुज्जमां ने भाजपा के सोहनवीर सिंह को हराया। साल 2004 में सपा के मुनव्वर हसन ने भाजपा के ठाकुर अमरपाल सिंह को हराया। साल 2009 में बसपा के कादिर राना ने रालोद की अनुराधा चौधरी को हराया। यहां पहले लोकसभा की दो सीटें मुजफ्फरनगर और कैराना थी। बाद में कैराना लोकसभा सीट शामली जिले में चली गई। इन दोनों सीटों पर तीन बार दो-दो मुस्लिम नेता चुनाव जीते। पहली बार 1967 में मुजफ्फरनगर से लताफत अली खां और कैराना से गय्यूर अली खां चुनाव जीते। दोनों मामा-भांजे थे। साल 1999 में मुजफ्फरनगर से सईदुज्जमा और कैराना से अमीर आलम खां चुनाव जीते। 2009 में मुजफ्फरनगर से कादिर राना और कैराना से तबस्सुम हसन चुनाव जीतीं।

गोचर भूमि के बिना कैसे बच सकेगी गायें

-आत्माराम यादव पीव वरिष्ठ पत्रकार

आज गायें सड़कों पर, बाजार में कचरा घरों में भोजन की तलाश में पॉलीथिन चबाकर अपना पेट भर रही है और बीमार हो रही है और खेतों में किसान गेहूं की फसल प्राप्ति के बाद अगली फसल की हवस में नरवाई को आग लगाकर उसके चारे को समाप्त कर उनके भोजन की सारी संभावनाओं पर विराम लगा रहा है। हमें शुद्ध गाय का दूध चाहिए, दही चाहिए, मक्खन चाहिए पनीर चाहिए और शुद्ध घी चाहिए किन्तु हम स्वार्थी इतने है कि गाय को चारा दिए बिना उससे यह सब अमृत लेना चाहते है, इससे ज्यादा स्वार्थ क्या होगा । गाय के लिए आरक्षित गोचर भूमि राजनीति के कुचक्र में लोगों ने हथिया ली ऐसे में गायें सड़कों पर गलियों में कचरा घरों पर मारी मारी घूम रही है। अगर गोचर भूमि पर लोगों का अतिक्रमण नहीं होता तो गायों सहित अन्य पालतू जानवर भरपूर भोजन प्राप्त कर अपने प्राणों को बचा सकते थे, पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। हमारे देश में मानव आवासीय भूमि के साथ गोचर भूमि की प्रचुरता थी। राज्य सरकार, जिला सरकार, ग्राम सरकार सहित राज वर्ग तथा प्रजा वर्ग सभी की ओर से गोचर भूमि छोड़ी जाती थी। कुछ धनिक वर्ग अपने पूर्वजों के यश हेतु पुण्य लाभ की दृष्टि से गोचर भूमि खरीद कर कृष्णार्पण करने की प्रतिस्पर्धा में जुटे रहते आए है, यह हर युग में एक प्रथा की भांति चलते आ रहा था, जिस पर अब विराम लग गया है।

शहरी क्षेत्र में लोग गाय-भैंसों को एक स्थान पर बांधकर दूध का कारोबार करते है, वे पशु चौबीसों घंटे खूंटी से बंधे खाते रहते है किन्तु उन्हें चलने फिरने न देने के कारण उनके शरीर में अनेक गंभीर रोग के साथ उनके मानसिक संतुलन पर भी असर पडता है किन्तु हम ऐसे बंदी असहज अवस्था में पहुँच चुके जानवरों का दूध पाकर खुद को गौरवान्वित मानकर अपने पूर्वजों की गाय पालने एवं चराने की परम्परा को भूल गए है। आज भी वे गोचर भूमियाँ विद्यमान हैं और उनके दान पत्र में स्पष्ट अंकित है पर सरकार की लापरवाही एवं राजनीति के अधोपतन के कारण राजनीतिक स्वार्थ के दलदल में धंसा हुआ छद्म भेषधारी नेता अनीति की ओर अग्रसर है, परिणामस्वरूप वोटों की राजनीति का कुचक्र संरक्षित व सुरक्षित गोचर भूमि को निगलते जा रहा है और गोचर भूमि समाप्ति की ओर होने से गायों के चराने के सारे रकबे गायब होने से गायों को पर्याप्त मात्रा में चारा नहीं मिल रहा है वहीं गोपालक किसान भी गायों के लिए आरक्षित मेढों से मिलने वाले चारे से गाय का हिस्सा मिटाकर ज्यादा फसल की चाह में चरनोई चारा समाप्त कर चुका है।

सभी जानते है कि गोचर भूमि में चरने वाली गाय हरी घास या वनस्पति के प्रभाव से नीरोग और हृष्ट-पुष्ट रहतीं और उनका दूध सुपाच्य तथा पुष्टिकारक होता था। उन गायों का मूत्र सर्व रोगों-विशेषकर उदर, नेत्र तथा कर्ण-रोग को समूल नष्ट करने की क्षमता रखता था। आज गोदुग्ध-मूत्रादिमें वैसा चमत्कार न देखने का यही मुख्य कारण है कि हमारे देश में गोचर भूमि की समुचित व्यवस्था नहीं है और सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए पूर्व से प्रत्येक गॉव-शहर में आरक्षित रहने वाली गोचर भूमि को संरक्षण से मुक्त रख कर बंदरबांट कर दी है। होना तो चाहिए कि गायों के चरने के ग्रामीण क्षेत्रो के गोचर मैदान, खेत, जंगल एवं पहाड़ जहॉ पर्याप्त चारा सुलभ हो वहां गायों को चराने से वे शुद्ध वायु के साथ पर्याप्त मात्रा में व्यायाम कर स्वस्थ रहती है। ह्यगोचर भूमि को रोकने या बाधा पहुंचाने वाले तथा वृक्षों को नष्ट करने वाले इक्कीस पीढ़ी तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। चरती हुई गौओं को बाधा पहुँचाने वालों को समर्थ ग्रामरक्षक दण्ड दे, ऐसा पद्म पुराण में लिखा गया है।

हमारे पूर्वजों ने व्यवस्था दी थी कि यह सारी धरती गोपाल की है अर्थात गोपालक किसान के साथ गायों का भी इस धरा पर एक बडा भाग था। उसे चिन्हित करने के लिए गांव के मुखिया और पूरा गांव गांव के निकट चारों ओर चार सौ हाथ यानी तीन बार फेंकने से लकड़ी जहाँ जाकर गिरे, वहाँ तक की भूमि और नगर के निकट चारों ओर इससे तिगुनी भूमि यानी बारह सौ हाथ भूमि गोचारण के लिये छोड़ने का विधान था यदि उतनी भूमि के अंदर की किसी ऐसी कृषिको, जिसके चारों ओर बाड़ न लगे हों, ग्रामके पशु नष्ट कर दें तो यह उनका अपराध नहीं और इसके लिये पशु रक्षक को राजदण्ड नहीं मिलता था उसे सिर्फ हँकवा देते थे। महर्षि याज्ञवल्क्य का भी यही मत है। उन्होंने पर्वत की तराई के गांव के निकट आठ सौ हाथ तथा नगर के निकट सोलह सौ हाथ गोचर भूमि छोड़ने की व्यवस्था दी है। लिखा है- धनुश्शतं परीणाहो ग्रामे क्षेत्रान्तरं भवेत। द्वे शते खर्वटस्य स्यात्रगरस्य चतुश्शतम ॥ (याज्ञवल्क्यस्मृति २।१६७)

गोचर भूमि हड़पने वाले नराधमों के पाप की भयंकरता का एक प्रसंग है कि - एक बार एक चाण्डाल की पत्नी चितागिन में नर-कपाल रखकर उसमें कौवे का मांस पकाया और उसको उसने कुत्ते के चमड़े से ढक कर रख दिया ।एक व्यक्ति को यह देखकर स्वभावतः कौतूहल हुआ और उसने चाण्डालिनी से पूछा- 'तूने ऐसी घृणित चीज को भी क्यों ढक रखा है?' उसने बड़ा ही मार्मिक उत्तर दिया था' मैंने इसे इस भय से ढक रखा है कि मेरा यह स्थान खेतों के समीप है। यदि किसी ऐसे महा पापी व्यक्ति की, जिसने गोचर भूमि को अपने खेत में मिला लिया है, दृष्टि पड़ जाएगी तो मेरा यह आहार ग्रहण करने लायक नहीं रह जायगा।' इस से समझा जा सकता है कि गोचर भूमि हड़पने वाले का दण्ड कितना रौरव नर्क प्रदान करने वाला है।

गाय के लिए गोचर भूमि छोड़ना महा- पुण्य का काम है और उसे नष्ट करना या हड़पना महापाप है। हमारे देश में गोवध की भांति गोचर भूमि भी एक समस्या के रूप में उपस्थित है। गोचर भूमि का हमारे यहां पर्याप्त मात्रा में थी पर अब उसका अभाव चारों ओर दिखाई दे रहा है, यह सरकारी तंत्र की विफलता एवं वोटों की राजनीति के कारण गोचर भूमि पर कब्जा करने वालों को अभय देना एक बड़ी दुर्व्यवस्था है। आज हमें और सरकार को विचार कर गोचर भूमि को पुनः गायों के लिए संरक्षित कर वर्तमान जनगणना के आधार पर उसके रकबे को चौगुना कर कब्जाधारियों से वापिस दिलाकर शेष अन्य रकबा भी आरक्षित करना होगा ताकि शहरों में गायों के चारे को लेकर कोई समस्या न हो और शहरी लोग अपने शहर से उन्हें मुख्य सड़कों- हाईवे पर खुला भूख से तडपता छोड़कर उन्हें भारी वाहनों की चपेट में आकर दर्दनाक मौत से बचाया जा सके, यह तभी संभव होगा जब गोचर भूमि की प्रचुरता होने पर निर्धन से निर्धन व्यक्ति ही नहीं अपितु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में ये पशु अपने मूल चारे को प्राप्त कर निश्चितता के साथ जी सके। साथ ही सरकार पूरी निष्ठा से गोचर भूमि को गायों के लिए रखकर गायों के भोजन की व्यवस्था करें एवं गोचर भूमि पर कब्जा करना एक गंभीर अपराध हो जिसमें गोचर भूमि पर कब्जा धारी को अर्थदण्ड के साथ कानूनी दण्ड व सामाजिक प्रतिबंधों की सजा भी भुगतनी पडे और उसका सामाजिक बहिष्कार हो तो निश्चित रूप से इस दिशा में लिए गए ऐसे कठोर निर्णय सरकार की ओर से गौ सुरक्षा एवं संरक्षण की दिशा में अभिनन्दनीय कदम होगा।

बढ़ती बेरोजगारी की समस्याएं

-विक्रम दयाल

देश में निरंतर हो रहे विकास कार्यों के बावजूद बेरोजगारी एक समस्या बनके उभर रही है। बहुत से लोग उच्च शिक्षा लेने के बावजूद भी इधर-उधर अच्छी नौकरी के लिए भटक रहें हैं। जो लोग कम पढ़े लिखें हैं वह लोग भी निम्न स्तर के कार्य करते हुए अपना गुजारा करं रहें हैं। केवल पेट ही भरने की बातें नहीं है। उन लोंगों को परिवार भी तो चलाना पड़ता है। बच्चों के स्कूल की फीस, युनीफार्म, स्कूल बस के खर्च, किताबें और कांपियाँ, अन्य घर के खर्चों को पूरा करने के लिए पैसों की ही जरूरते पड़ती है। आजकल बढ़ती बेरोजगारी के साथ ही दूसरी समस्या मंहगाई की भी तो है। जितनी रफ्तार से मंहगाई बढ़ी है, उतनी ही रफ्तार से बेरोजगारी भी बढ़ी है। बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियों में ताले लग गये हैं। शहर के सड़कों की पटरियों पर धंधे करने वालों के धंधे बंद हो रहे हैं। क्यों कि पैदल चलने वालों को तकलीफें न उठानी पड़े, इसलिए। शहर साफ-सुथरें रहें। धंधे उन्हीं सड़कों पर चलते हैं, जिन रास्तों से आम लोंगों का आना जाना अधिक होता है। बेरोजगारी की समस्यायें शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक है। ग्रामीण लोग भी नौकरी के लिए इस शहर से उस शहर तक नित्य दौड़ लगाते रहते हैं। नौकरी की समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे दोनों ही परेशान है। किसी के पैर स्थाई रूप से कहीं नही टिक रहें हैं। सरकारी कार्यालयों में अब नवीन भर्तियाँ कम होने लगी है। जरूरत पड़ने पर कंट्रैक्ट पर कर्मचारी लिए जारहें हैं। स्थाई नौकरियाँ खत्म होती जारही हैं। शिक्षित लोगों की इज्जत खत्म होने लगी है। क्यों कि पढ़ लिख कर वह घर पर ही बैठे हैं या गुजारा करने के लिए कोई छोटे मोटे काम करने लगे हैं। इसतरह देश में अब बेरोजगारी की भी समस्यायें उत्पन्न होने लगी है। खाद्य समाग्रियों की कीमतों में भी काफी वृद्धि होने से महंगाई पर सीधा असर पड़ा है। देश में बातें विकास पर ही होती रहती है। कभी मंहगाई पर चर्चायें नहीं होती हैं। मंहगाई की मार गांव और शहर दोनों तरफ है। आजकल सभी का ध्यान तीव्र गति से विकास की तरफ ही आकर्षित किया जा रहा है। देश में मंहगाई और बेरोजगारी पर चर्चायें होनी चाहिए और इसके निवारण हेतु कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

सम्पादकीय

प्रतियोगी परीक्षाओं का पूरा सिस्टम ही दोबारा से जांचा जाएं

आरपीएससी का पिछले कम से कम पन्द्रह साल का रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए। आरपीएससी की जितनी बुरी स्थिति सामने आई है। जितनी बदनामी हुई है, उससे ये लगने लगा है कि सरकारी नौकरियों में जो भी चुने गए हैं, पिछले पन्द्रह सालों में क्या वे सभी करप्ट सिस्टम से चुने गए हैं। जिस तरह से एसओजी ने अपनी ही पुलिस के एसआई को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ में सामने आया है कि वे लीक पेपर से ही नौकरी प्राप्त किए हैं, उससे साफ हो गया है कि अब तो कम से कम पन्द्रह साल की सारी नियुक्तियों की ही जांच होनी चाहिए और ऐसे फर्जी कर्मचारियों से अब तक दी तन्ख्वाह और सुविधाओं की पुनश्च: वसूली होनी चाहिए। कितने अफसोस की बात है कि लोगों ने प्रतियोगिता परीक्षाओं में डमी कंडीडेट के रूप में बैठने का धंधा बना लिया है। एसओजी ने डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा में बैठने वाले सरकारी टीचर रोशनलाल मीणा को गिरफ्तार किया है। वह 20 से ज्यादा परीक्षा में डमी कैंडिडेट के रूप में बैठ चुका है। उसने आरपीएससी में डमी बनकर इंटरव्यू भी दिया। आरोपी ने पुलिस को 6 लोगों की जानकारी दी है, जिनके लिए उसने डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी थी। इनमें से 5 लोग मौजूदा समय में सरकारी नौकरी कर रहे हैं। दौसा निवासी सरकारी टीचर रोशन लाल मीणा साल 2017 से सरकारी टीचर है। फिलहाल सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल, प्यारीवास (दौसा) में ग्रेड थर्ड टीचर हैं। वह राज्य सरकार की 16 और भारत सरकार की 4 परीक्षा में बैठा है। सरकारी टीचर लगने से पहले से वह डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा में बैठ रहा था। राजस्थान पुलिस की आईबी यूनिट में तैनात साल 2018 बैच के एसआई मनीष मीणा, उसके सगे भाई दिनेश मीणा के लिए भी आरोपी ने डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दी थी। दिनेश मीणा अभी एलडीसी के पद पर तैनात हैं। रोशन मीणा ने साल 2021 में भी मनीष मीणा के भाई दीपक मीणा के लिए एसआई भर्ती परीक्षा डमी कैंडिडेट के रूप में दी थी। दीपक मीणा लिखित परीक्षा में पास हो गया, लेकिन फिजिकल में फेल हो गया था। मनीष मीणा का मामा महेश मीणा के लिए भी आरोपी रोशन परीक्षा में बैठा था, महेश अभी दौसा में एलडीसी के पद पर तैनात है। एक और व्यक्ति है सागर मीणा, जिसके लिए आरोपी ने पटवारी भर्ती परीक्षा दी थी। रोशन मीणा अपने सगे भाई के लिए भी परीक्षा में बैठ चुका है, जो आज पटवारी है। अभी तक की जानकारी के अनुसार आरोपी 6 लोगों के लिए डमी कैंडिडेट के रूप में बैठा था, जिसमें से 5 सरकारी नौकरी में हैं। आरोपी रोशन मीणा वर्ष 2018 में एसआई मनीष मीणा के लिए न केवल परीक्षा में डमी कैंडिडेट के रूप में बैठा, बल्कि आरपीएससी में इंटरव्यू में भी बैठा था। एसओजी की इस कार्रवाई के बाद सभी आरोपी फरार हो गए हैं।

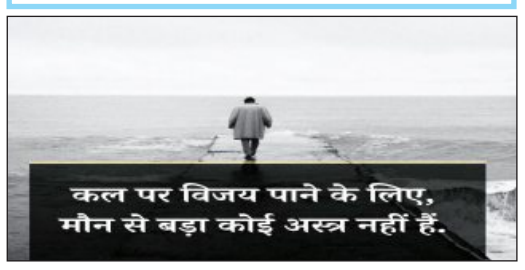

भारतीय अर्थव्यवस्था लम्बी छलांग लगाने को तैयार

भारत द्वारा वर्ष 1947 में राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, पिछले 77 वर्षों के दौरान भारत में लोकतंत्र लगातार मजबूत हुआ है एवं आज पूरे विश्व में भारत इस दृष्टि से प्रथम पायदान पर खड़ा है। भारत में लोकतंत्र के लगातार मजबूत होते जाने से विदेशी निवेशकों का भारत में विश्वास बढ़ा है जिसके चलते भारत में उद्योग जगत को पूंजी की कमी नहीं के बराबर रही है। पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता के चलते भारत में आर्थिक विकास को गति ही मिली है। भारत में लगातार तेज हो रही आर्थिक विकास की दर के कारण भारत में बिलिनियर (100 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक की सम्पत्ति वाले नागरिक) की संख्या में सुधार हुआ है। पिछले वर्ष भारत में 94 नए बिलिनियर बने हैं। जबकि चीन में 115 बिलिनियर कम हुए हैं। विश्व में बिलिनियर की संख्या के मामले में भारत चीन एवं अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर आ गया है। भारत में आज 271 बिलिनियर हैं जबकि चीन में 814 एवं अमेरिका में 800 बिलिनियर हैं। मुंबई महानगर में तो अब 92 बिलिनियर निवास कर रहे हैं, जो चीन के बीजिंग महानगर के 91 बिलिनियर से अधिक है। इस प्रकार अब एशिया के किसी भी महानगर में सबसे अधिक बिलिनियर भारत के मुंबई महानगर में निवास कर रहे हैं।

प्रह्लाद सबनानी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 की तृतीय तिमाही (अक्टूबर-दिसम्बर 2023) में भारत में आर्थिक विकास की दर 8.4 प्रतिशत रही है। कुछ विदेशी अर्थशास्त्री भारत की आर्थिक विकास दर को कमतर आंकते हुए दिखाई दे रहे हैं जबकि यह लगातार तिमाही दर तिमाही आगे बढ़ती ही जा रही है। अब तो विश्व की कई आर्थिक एवं वित्तीय संस्थानों ने भी वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के सम्बंध में अपने अनुमानों को बेहतर किया है, परंतु अभी भी इन संस्थानों के यह अनुमान वास्तविक आर्थिक विकास दर की तुलना में बहुत कम हैं। दरअसल, विदेशी आर्थिक एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा विशेष रूप से भारत की आर्थिक विकास दर को आंके जाने के सम्बंध में उपयोग किए जा रहे मॉडल अब बोथरे साबित हो रहे हैं।

हाल ही के समय में भारत के नागरिकों में स्व का भाव विकसित होने के चलते देश में धार्मिक पर्यटन बहुत तेज गति से बढ़ा है। उदाहरण के लिए अयोध्या धाम में प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर में श्रीराम लला के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात प्रत्येक दिन औसतन 2 लाख से अधिक श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। यह तो केवल अयोध्या की कहानी है इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर, उज्जैन में महाकाल लोक, जम्मू स्थित वैष्णो देवी मंदिर, उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एवं यमनोत्री जैसे कई मंदिरों में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ रही है। भारत में धार्मिक पर्यटन में आई जबरदस्त तेजी के बदौलत रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित हो रहे हैं, जो देश के आर्थिक विकास को गति देने में सहायक हो रहे हैं। परंतु, यह तथ्य विदेशी आर्थिक एवं वित्तीय संस्थानों को दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि केवल भारत की ही विशेषता है।

उक्त तथ्यों के अतिरिक्त अन्य कई कारक भी भारत की आर्थिक विकास दर को अब 9 से 10 प्रतिशत की सीमा में ले जाने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। आज भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना में भारत से आगे चल रही विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर में ठहराव आ गया है। जैसे अमेरिका एवं यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं आगे आने वाले समय में प्रतिवर्ष केवल 2 अथवा 3 प्रतिशत की दर से ही आगे बढ़ पाएंगी। इसी प्रकार चीन की अर्थव्यवस्था भी अब ढलान पर दिखाई दे रही है। जापान एवं जर्मनी की अर्थव्यवस्थाओं में तो आर्थिक मंदी देखी जा रही है। इस प्रकार विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत के अमृत काल में केवल भारतीय अर्थव्यवस्था ही तेज गति आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। वैसे भी भारत में अमृत काल तो अभी शुरू ही हुआ है एवं यह अगले 23 वर्षों अर्थात वर्ष 2047 तक यह खंडकाल जारी रहेगा। कुछ अर्थशास्त्री तो भारत के अमृत काल के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था के इसी तरह तेज गति से आगे बढ़ते रहने की संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि भारत में वर्ष 1991-92 में प्रारम्भ किए आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्र के सुधार कार्यक्रम को अब 32 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, हालांकि वर्ष 1991-92 के बाद भी भारत में आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रों में सुधार कार्यक्रम लगातार जारी रहे हैं। अत: स्थिर हो चुके इन सुधार कार्यक्रमों के फल खाने का समय अब आ गया है। पूरे विश्व भारत के मुंबई महानगर से आगे अब केवल अमेरिका का न्यूयॉर्क महानगर (119 बिलिनियर) एवं ब्रिटेन का लंदन महानगर (97 बिलिनियर) ही है। वर्ष 2022-23 में चीन में बिलिनियर की संख्या घटी है। चीन में बिलिनियर की सम्पत्ति 15 प्रतिशत से कम हुई है। जबकि भारत में बिलिनियर की सम्पत्ति में वृद्धि दर्ज हुई है। यह भारत में तेज गति से हो रहे आर्थिक विकास दर के चलते सम्भव हो सका है। एक और कारक जो आगे आने वाले समय में भारत की आर्थिक विकास दर को लगातार उच्च स्तर पर बनाए रखने में सहायक हो सकता है वह है भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय का लगभग 2500 अमेरिकी डॉलर का होना है जो चीन में 13,000 से 14,000 अमेरिकी डॉलर के एवं दक्षिणी कोरीया में 32,000 से 33,000 अमेरिकी डॉलर के बीच की तुलना में बहुत कम है। इस दृष्टि से भारत को अभी बहुत आगे तक जाना है और यह केवल आर्थिक विकास की औसत दर को 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष के आसपास बनाए रखने से ही सम्भव होगा। इस प्रकार भारतीय नागरिकों में अपनी औसत आय को विकसित देशों की तुलना में बेहतर करने की अभी बहुत गुंजाइश है और यह भावना भारत की आर्थिक विकास दर को बढ़ाए रखने में सहायक होगी। दूसरे, भारत में तकनीकी क्षेत्र विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास की दर बहुत प्रभावकारी है, डिजिटल क्षेत्र में तो भारत आज पूरे विश्व को ही राह दिखाता नजर आ रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास के चलते भारत में विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों, व्यवसाइयों, प्रबंधकों, कृषकों आदि की उत्पादकता में भी सुधार दृष्टिगोचर है जो निश्चित ही भारत में आर्थिक विकास की गति को तेज करने में सहायक होगा। आज अमेरिका एवं कनाडा में निवासरत एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य कर रहे भारतीय मूल के नागरिक वापिस भारत आकर बसने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रहे हैं क्योंकि अब अमेरिका एवं अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत में लगातार तेज हो रही आर्थिक विकास की दर उन्हें आकर्षित कर रही है। उन्हें आज भारत में अधिक आय अर्जन के अतिरिक्त साधन उत्पन्न होते दिखाई दे रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार, लगभग 38,000 भारतीय जो अमेरिका में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत हैं वे अब भारत वापिस आना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका में कई कम्पनियां (गूगल, एमेजोन, माइक्रोसोफ्ट एवं मेटा सहित) अपने कर्मचारियों की छंटनी करती दिखाई दे रही हैं। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था तो स्पष्टत: आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुकी है। जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने अक्टोबर-दिसम्बर 2023 की तिमाही में 8.4 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर हासिल की है। कई विदेशी वित्तीय संस्थानों ने वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को आगे बढ़ा दिया है। अब तो भारत में, ग्रामीण इलाकों सहित, विभिन्न उत्पादों के खपत का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विकास कार्यों के लिए अपने बजट में खर्च को लगातार बढ़ाया जा रहा है जिससे सामान्य नागरिकों के हाथों में अधिक पैसा पहुंच रहा है तथा इससे नागरिकों के बीच विभिन्न उत्पादों के खपत का स्तर बढ़ता दिखाई दे रहा है। शहरी उपभोक्ता तो रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं के साथ साथ चार पहिया वाहन एवं मकान आदि खरीदने पर भी भारी मात्रा में पैसा खर्च कर रहे हैं।

आज का इतिहास

5 अप्रैल की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- जेकब रोजरविन ने 1722 में पूर्वी आयरलैंड की खोज की।
- ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने 1843 में हॉगकॉग को ब्रिटिश कॉलनी में शामिल किए जाने की घोषणा की।
- महात्मा गांधी अपने अनुयायियों के साथ 1930 में नमक कानून तोडने् के लिए दांडी पहुंचे।
- भारत स्काउट एण्ड गाइड की स्थापना 1949 को हुई।
- विस्टन चर्चिल ने 1955 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया।
- देश में 1957 में पहली बार और दुनिया में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से केरल में संपन्न चुनाव के बाद कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई और ईएमएस नम्बूदरीपाद ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया।
- भारत सरकार की ओर से प्रायोजित पहली 'इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी' की स्थापना 1961 में हुई।
- नौसेना ने 1964 में पहली बार राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया।
- सउदी अरब के राजा फैजल की 1975 में हत्या हुई।
- देश का पहला नौसेना संग्रहालय 1979 में मुम्बई में खुला।
- अंतरिक्ष यान एसटीएस 37 (अटलांटिस 8) का प्रक्षेपण 1991 में किया गया।
- मलेशिया में हेंड्रा नामक वायरस से बचाव के लिए 1999 से 8 लाख 30 हजार सुअरों की सामूहिक हत्या करने की शुरुआत की गई।
- भारत, म्यांमार व थाइलैंड के बीच 2002 में मोरे-कलावा-मांडले सड़क परियोजना पूरी करने हेतु सहमति।
- अमेरिकी संसद में पाक की आर्थिक मदद में कटौती का प्रस्ताव 2003 में पेश किया।
- सिंगापुर में 45 भारतीयों को आव्रजन अपराधों में 2006 को गिरफ्तार किया गया।
- ईरान ने 2007 में 15 ब्रिटिश नौ सैनिकों को रिहा किया गया।
- पार्वती ओमनाकुट्टन 2008 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड बनी।
- इराक में हुए 2008 में हुए आत्मघाती हमले में तक़रीबन 10 लोग मारे गए।
- अमेरिकी राज्य वेस्ट वर्जीनिया के कोयला खदान में 2010 को हुए विस्फोट से 22 लोगों की मौत हुयी।
- लोकसभा में फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान विधेयक 2017 में पारित हो गया।

5 अप्रैल को जन्मे व्यक्ति

- सिक्खों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास का जन्म 1479 में हुआ।
- भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री एवं राजनेता बाबू जग जीवन राम का जन्म 1908 में हुआ।
- राजनेता रफ़ीक़ ज़करिया का जन्म 1920 में हुआ।
- ब्रिटिश फुटबॉल खिलाड़ी टॉम फ़िनी का जन्म 1922 में हुआ।
- ब्रिटिश अभिनेता (मिस्टर बेलवेडर) क्रिस्टोफर ह्युएट्ट का जन्म 1922 में हुआ।
- अमेरिकी गायिका और अभिनेत्री गैल स्टोर्म का जन्म 1922 में हुआ।
- उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल तथा केन्द्रीय निर्माण एवं आवास मंत्रालय में उपमंत्री रहे मो. उस्मान आरिफ़ का जन्म 1923 में हुआ।

युवा आगे आएंगे तभी होगा राष्ट्र-समाज का कल्याण

अरुण कुमार दीक्षित।

राजनीति में युवाओं की अहम भूमिका है। युवा अपने विचारों से हर क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। वे जिस विचार की ओर अग्रसर होते हैं, समाज उससे प्रभावित होता ही है। आज दुनिया में सर्वाधिक मांग युवाओं की है। भारत की राजनीति में सबसे अधिक मांग युवा विचारों के साथ युवाओं की ही रहती है।भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को युवाओं ने ही धार दी थी। युवाओं के आकर्षण का केंद्र राजनीति है। वह राजनीति उन्हें आकर्षित करती है। भारत की राजनीति ने युवा मन को निराश किया है। राजनीति युवाओं में विराट लक्ष्य नहीं देखती। राजनीतिक दलों से जुड़े युवा कभी इस दल तो कभी उस दल के हाईकमान का जयघोष करते हैं। ऐसा कर वे एक तरह से अपने ही श्रम-समय का नुकसान करते हैं। युवा सपने देखते हैं और सफल होते हैं। विफल भी होते हैं। टूटते हैं। आज युवा बेरोजगारी से टकरा रहे हैं। युवाओं पर पढ़ाई के साथ परिवार वालों का भी दबाव होता है कि कुछ कर दिखाना है। अनेक युवा भारतीय राजनीति में आए। उन्होंने लगातार समाज के वंचितों के लिए काम किया। समाचार पत्र निकाले। समाज-राष्ट्र की समस्याओं के समाधान को अपने जीवन का मिशन बनाया। बड़े राजनेता बने। पत्रकार बने ।अधिकारी बने। ऐसे युवाओं की बड़ी संख्या है कि वह पहले प्रशासनिक अधिकारी बने। बाद में सीधे राजनीति में कूदे । कुछ को सरकारों ने ही पुरस्कृत किया। कुछ आजीवन संघर्षरत रहे। सरकारों ने युवा नीति को लेकर अब तक क्या किया, यह भी समझना आवश्यक है। भारत में पहली बार युवानीति सन् 1988 में संसद के दोनों सदनों में रखी गई। युवा मामलों और खेल विभाग को इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई। उद्देश्य था कि युवा नीति उनके व्यक्तित्व व कार्य क्षमता को मजबूत बनाए। वर्ष 2003में फिर युवा राष्ट्रनीति पर चर्चा हुई। 2003 में 13 से 35 वर्ष के आयु के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित किया गया। वर्ष 2014 में भाजपा सरकार ने युवाओं के समग्र विकास की वचनबद्धता दोहराई। वर्ष 2023 मे केंद्र सरकार ने युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा की आवश्यकता बताते हुए कहा कि यह शिक्षा व्यावसायिक कौशल सिखाती है। समग्र विकास में सहायक है। इस नीति का उद्देश्य युवाओं को आत्मविश्वास से मजबूत करना है। उन्हें आर्थिक मजबूती देनी है और उन्हें शारीरिक और मानसिक स्तर पर सबल बनाना है। उनका समग्र विकास करना है।

विशेष आलेख

बेटियों को भी मिले उचित सम्मान, उन्हें न समझा जाए बोझ

रमेश सर्राफ धमोरा।

आज हर क्षेत्र में बालिकाओं के आगे बढने के बावजूद भी वह अनेको कुरीतियों की शिकार हैं। ये कुरीतियों उनके आगे बढने में बाधाएं उत्पन्न करती है। पढ़े-लिखे लोग और जागरूक समाज भी इस समस्या से अछूता नहीं है। देश में आज भी प्रतिवर्ष लाखों लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही कोख में मार दिया जाता है। आज भी समाज के अनेक घरों में बेटा, बेटी में भेद किया जाता है। बेटियों को बेटों की तरह अच्छा खाना और अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है। समाज में आज भी बेटियो को बोझ समझा जाता है।

हमारे देश में यह एक बड़ी विडंबना है कि हम बालिका का पूजन तो करते हैं। लेकिन जब हमारे खुद के घर बालिका जन्म लेती है तो हम दुखी हो जाते हैं। देश में सभी जगह ऐसा देखा जा सकता है। देश के कई प्रदेशों में तो बालिकाओं के जन्म को अभिशाप तक माना जाता है। लेकिन बालिकाओं को अभिशाप मानने वाले लोग यह क्यों भूल जाते हैं कि वह उस देश के नागरिक हैं जहां रानी लक्ष्मीबाई जैसी विरांगनाओं ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। हमारे यहां आज भी बेटी पैदा होते ही उसकी परवरिश से ज्यादा उसकी शादी की चिन्ता होने लगती है। आज महंगी होती शादियों के कारण बेटी का बाप हर समय इस बात को लेकर चिंतित नजर आता है कि उसकी बेटी की शादी की व्यवस्था कैसे होगी। समाज में व्याप्त इसी सोच के चलते कन्या भ्रूण हत्या पर रोक नहीं लग पायी है। कोख में कन्याओ को मार देने के कारण समाज में आज लड़कियों की काफी कमी होने से लिंगानुपात गड़बड़ा गया है। पिछले कुछ वर्षों में देश में जन्म के समय लिंगानुपात में बढ़ोतरी होना शुभ संकेत हैं। संसद में एक सवाल का जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने बालिकाओं के अधिकारों को स्वीकार करने के लिए जनता की मानसिकता को बदलने की दिशा में सामूहिक चेतना जगाई है। इस योजना ने भारत में सीएसआर (बाल लिंग अनुपात) में गिरावट के मुद्दे पर चिंता जताई है। यह राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) में 15 अंकों के सुधार के रूप में परिलक्षित होता है। जो कि 2014 में 918 था। जबकि 2022-23 में 15 अंक बढ़कर 933 हो गया।

अगर समाज में बेटियों को उचित शिक्षा और सम्मान मिले तो बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नही रहेगी। इसलिए यदि यह कहा जाय की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना नही हम सबकी एक जिम्मेदारी है तो इसमें कुछ गलत नही है। यदि हम सभी एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते है तो हम सबका यही फर्ज बनता है हम इन बेटियों को भी भयमुक्त वातावरण में पढ़ाये। उन्हें इतना सशक्त बनाये की खुद गर्व से कह सके की देखो वह हमारी बेटी है जो इतना बड़ा काम कर रही है। भारत में हर साल तीन से सात लाख कन्या भ्रूण नष्ट कर दिये जाते हैं। इसलिए यहां महिलाओं से पुरुषो की संख्या 5 करोड़ ज्यादा है।

समाज में निरंतर परिवर्तन और कार्य बल में महिलाओं की बढ़ती भूमिका के बावजूद रूढिवादी विचारधारा के लोग मानते हैं कि बेटा बुढ़ापे का सहारा होगा और बेटी हुई तो वह अपने घर चली जायेगी। बेटा अगर मुखाग्नि नहीं देगा तो कर्मकांड पूरा नहीं होगा। आज लड़किया लड़को से किसी भी क्षेत्र में कमतर नहीं हैं। कठिन से कठिन कार्य लड़किया सफलतापूर्वक कर रही हैं। देश में हर क्षेत्र में महिला शक्ति को पूरी हिम्मत से काम करते देखा जा सकता है। लड़कियों ने अपने काम और समर्पण के दम पर कई क्षेत्रों और क्षेत्रों में खुद को साबित किया है। वे अधिक प्रतिभाशाली, आज्ञाकारी, मेहनती और परिवार और अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। लड़कियाँ अपने परिवार और माता-पिता के प्रति अधिक देखभाल करने वाली और प्यार करने वाली होती हैं और वे हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देती हैं। देश की अर्थव्यवस्था में भी महिलाओं का अहम योगदान है। वे श्रम शक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और व्यवसायों की वृद्धि और विकास में योगदान देती हैं। एक तरफ जहां बेटी को जन्मते ही मरने के लिये लावारिश छोड़ दिया जाता है। वहीं झुंझुनू जिले की मोहना सिंह जैसी बालिकायें भी है जो आज देश में फाईटर प्लेन उड़ा कर पूरे देश में जिले का मान बढ़ा रही हैं। समाज में सभी को मिलकर लडका-लडकी में भेद नहीं करने व समाज के लोगों को लिंग समानता के बारे में जागरूक करने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। बालिकाओं का कोख में तो कत्ल कर उन्हे धरती पर आने से पहले ही मारा जा रहा है। उससे भी घिनोना काम जिन्दा बालिकाओं के साथ किया जा रहा है। देश में बालिकाओं के साथ हर दिन बलात्कार, प्रताडना की घटनायें अखबारो की सुर्खिया बनती हैं। बालिकायें कही भी अपने को सुरक्षित नहीं समझती हैं। चाहे घर हो या स्कूल अथवा कार्य स्थल। हर जगह वहशी भेडिये उन पर नजरे गड़ायें रहते हैं। उन्हे जब भी मौका मिलता है नोंच डालते हैं। ऐसे माहौल में देश की बालिकायें कैसे आगे बढ़ पायेगीं। समाज के पढ़े लिखे लोगों को आगे आकर कन्या भ्रूण हत्या जैसे घिनोने कार्य को रोकने का माहौल बनाना होगा।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, आपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारम्परिक संबंधों में भी, जहां यह स्थानान्तरण हमें संताप और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष
अपनी वाणी और व्यवहार को संयमित रखना आपके ही हित में रहेगा। आज आपकी नौकरी और व्यवसाय में रुचि बढ़ेगी। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथी कर्मचारियों का साथ मिलेगा। संतान की चिंता आपको हो सकती है।

वृष
मानसिक रूप से आप में भावुकता की मात्रा अधिक रहेगी। किसी बात को लेकर ज्यादा विचलित ना हों। अपनी कल्पनाशक्ति से साहित्य-सृजन में आप नवीनता ला पाएंगे। सुख-शांति बनी रहेगी। व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी।

मिथुन
सुबह का समय दोस्तों के साथ घूमने-फिरने, खान-पान एवं मनोरंजन में बीत सकता है। पार्टनरशिप काम में ध्यान रखें। व्यापार में ज्यादा लाभ की उम्मीद नहीं है। दोपहर के बाद आप को प्रतिकूलता का सामना करना पड़ सकता है।

कर्क
स्वभाव में उग्रता हो सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। आप मनोरंजन की ओर ज्यादा बढ़ेंगे। मित्रों और स्नेहीजनों के साथ प्रवास या पर्यटन का योग है। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रह पाएंगे। आज कोई महत्वपूर्ण डिसीजन आप ले पाएंगे।

सिंह
आज का आपका दिन लाभकारी है। पारिवारिक और प्रोफेशनल दोनों ही क्षेत्रों में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। घर-परिवार में आनंद का वातावरण आप को खुश रखेगा। बहुत दिनों से अटके सरकारी कामों में सफलता मिलेगी।

कन्या
आज के दिन बौद्धिक काम, नए सृजन और साहित्यिक गतिविधि में आप उलझे रहेंगे। किसी धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है। व्यापार में लाभ का अवसर मिलेगा। आज आपको कार्यालय और व्यापार में थोड़ा संभलकर चलना होगा। स्नेहीजनों के साथ घनिष्ठता बढ़ेगी।

तुला
आज वाणी पर संयम रखें. स्नेहीजनों के साथ किसी बात पर विवाद हो सकता है। आय की अपेक्षा व्यय अधिक रहेगा। किसी उलझन में दिन गुजरेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। आप नए काम का आरंभ कर सकेंगे।

वृश्चिक
दोस्तों के साथ मुलाकात होगी। किसी तरह का आर्थिक लाभ भी हो सकता है। हालांकि, स्वास्थ्य को लेकर उतार-चढ़ाव बना रहेगा। गृह एवं संतान सम्बंधी शुभ समाचार आप को मिलेंगे। पुराने और बचपन के दोस्तों से मुलाकात हो सकती है।

धनु
मित्रों का सहयोग भी आप को प्राप्त होगा। विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए निरर्थक वाद-विवाद न करें। धन और प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है। आप की रचनात्मकता में सकारात्मक वृद्धि होगी।

मकर
दवाई खरीदने या अस्पताल की फीस पर आकस्मिक खर्च हो सकता है। आज दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास के साथ हर काम को आसानी से बना पाएंगे। गृहस्थ जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।

कुंभ
व्यापार में किसी तरह का लाभ होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पूंजी निवेश में सावधानी बरतें। धार्मिक काम के पीछे धन खर्च हो सकता है। कोर्ट-कचहरी के विषय में संभलकर चलें।

मीन
स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोपहर के बाद पारिवारिक जीवन में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहेगा। आज कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। पिता से आपको लाभ होगा। ज्योतिष और आध्यात्मिक विषयों में आपकी रुचि बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,हमीदपुरा रोड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 ''प्रतीक्षा'' सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान*। प्रधान संपादक-राम बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

संपादकीय

दाग का राग

पिछले साढ़े सात दशक के भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक पराभव के अक्स गाहे-बगाहे उजागर होते रहते हैं। सत्ता के खेल जो विद्रूप न दिखा दें वो कम ही है। सत्ता केंद्रित राजनीति ने भ्रष्टाचार और पाक-साफ होने की अपनी-अपनी परिभाषा गढ़ ली है। कल तक विपक्ष में जो नेता दागदार होते थे, सतारूढ़ दल में शामिल होने के बाद कहा जाता है कि ये दाग अच्छे हैं। सफाई की इस कार्रवाई में निगरानी करने वाली संवैधानिक एजेंसियों की खामोशी भी विचलित करती है। ऐसे तमाम सवाल इस देश के नागरिकों को उद्वेलित करते रहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि दागी नेता सत्ता की धारा में डुबकी लगाकर दूध का धुला घोषित हो जाता है। विपक्षी नेता आरोप लगाते रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल को दाग धोने वाली वॉशिंग मशीन बना लिया गया है। जिसके चलते नियामक संस्थाओं से ड्राइक्लीनिंग की चिट हासिल हो जाती है। विपक्ष के ऐसे तमाम आरोपों की तार्किकता हाल में आई एक रिपोर्ट दर्शाती है। जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2014 के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का सामना कर रहे 25 विपक्षी नेताओं के सत्तारूढ़ दल में शामिल होने के बाद उनमें से 23 को राहत मिल गई है। इनमें से तीन मामले बंद हो गए हैं और बीस की जांच रुकी हुई है। दलील दी जा रही है कि जांच बंद नहीं हुई है, आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। यूं तो जब ये नेता विपक्ष में होते हैं और जांच एजेंसियां उन पर कार्रवाई करती हैं तो सत्तारूढ़ दल की दलील होती है कि कानून अपना काम करता है। जबकि विपक्षी नेताओं का आरोप रहता है कि यह प्रक्रिया तभी तक चलती है जब तक यह राजनीति से प्रेरित न हो। उल्लेखनीय है कि भाजपा में जो पच्चीस राजनेता शामिल हुए हैं उनमें सभी राजनीतिक दलों के नेता हैं। जिसमें कांग्रेस, राकांपा, शिवसेना, टीएमसी, टीडीपी, एसपी और वाईएसआर कांग्रेस के नेता शामिल हैं।

विडंबना है कि राजनीतिक निष्ठा बदलना इन नेताओं के लिये राहतकारी साबित हुआ है। वजह यह कि इन नेताओं से जुड़े बीस मामले ठंडे बस्ते में डाल दिये गए हैं। दलील यह दी जाती है कि मामले बंद नहीं हुए हैं, जरूरत पड़ी तो जांच और कार्रवाई भी होगी। जो विपक्ष के उन आरोपों की पुष्टि करते हैं कि यह कार्रवाई राजनीतिक दुराग्रह के रूप में की जाती रही है। यही वजह है कि दल बदलने का फैसला राहत का रास्ता मान लिया जाता है। ऐसे में आम आदमी के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि अचानक जांच एजेंसियां निष्क्रिय क्यों हो जाती हैं? क्यों किसी एजेंसी को लेकर अदालत को कहना पड़ता है कि फलां एजेंसी पिंजरे में बंद तोता है और मालिक की बोली बोलता है। विपक्ष तो आरोप लगाता रहता है कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद से ईडी और सीबीआई ने मुख्यत¬ बड़े राजनेताओं के खिलाफ ही कार्रवाई की है। यही वजह है कि विपक्ष सत्ता पक्ष को ऐसी वॉशिंग मशीन की संज्ञा देता है जिसमें कथित दागों की धुलाई हो जाती है। तब उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसा भी नहीं है कि तमाम ऐसी कार्रवाई सिर्फ केंद्र में राजग सरकार के दौरान ही हुई हो। यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में सपा-बसपा के साथ संबंध सुधरने के बाद सीबीआई ने इन दलों के नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के मामलों में रुख बदल लिया था। इतना ही नहीं, विगत में सरकार बनाने और बहुमत जुटाने के लिये जो निष्ठा बदलने का खेल हुआ, उसके निहितार्थों में एजेंसियों की छाया महसूस होने की बात विपक्ष करता रहा है। यहां तक कि कई दलों के विभाजन के मूल में एजेंसियों की कार्रवाई के भय की भूमिका बतायी जाती रही है। दल-बदल के बाद उन पर चल रहे मामले या तो बंद हो गए या फिर ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। वहीं कई ऐसे मामले भी होते हैं जो खुले तो रहते हैं लेकिन उनमें कार्रवाई होती नजर नहीं आती। निश्चिय ही यह स्थिति किसी लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिये शुभ नहीं कही जा सकती।

खुशियों-उत्कंठा से महरूम करती शिक्षा पद्धति

पूरी तरह पक्का नहीं है कि क्या हमारे बच्चों को इस विषैली संस्कृति से बचा पाना संभव होगा कि नहीं। तथापि, सकारात्मकता के तौर पर, हम यानी अध्यापक और अभिभावकों को अपनी आवाज़ उठानी होगी ताकि शिक्षा की नई पद्धति बन पाए। वे सब जिन्हें अभी भी शिक्षण के पेशे से प्यार है, उनके लिए जरूरी है कि वे उदारवादी शिक्षा या लोकतांत्रिक कक्षा के माहौल को जीवित रखें। जब तक कि हम अध्यापक इस बारे में खड़े नहीं होंगे, अपने ऊपर काम नहीं करेंगे

पिछले कुछ वक्त से, जिस युवा विद्यार्थी से मेरा जुड़ाव गहरा है, उसमें बदलाव होते देख रहा हूं। एक समय था जब वह खिलंदड़ हुआ करता था। साइकिल चलाने से लेकर फुटबॉल के मैदान में या गुणवत्तापूर्ण साहित्य पढ़ने से लेकर अपने मनोभावों को लेखों और लघु कहानियों में पिरोने का आनंद उठाने तकङ्क वह असीम सृजनात्मक ऊर्जा से लबरेज़ हुआ करता था। लेकिन इन दिनों लगता है वह निरंतर तनाव, भय में है और उखड़ा-उखड़ा रहता है। कुछ दिन पहले ही उसने 12वीं कक्षा की बोर्ड-परीक्षा दी है। उसे चिंता है कि क्या वह परीक्षा में कम से कम 97 फीसदी अंक ले पाएगा या नहीं। इसके अलावा प्रवेश परीक्षाओं की एक लंबी शृंखला को लेकर भी उसमें तनाव व्याप्त है। मसलन, जेईई, नीट, सीक्यूईटी इत्यादि, में अपनी कुव्वत सिद्ध करने के लिए इनमें बैठना ही पड़ेगा। इस चिंता ने उसकी हंसी, उसकी अलमस्ती, उसकी नींद और उसकी जीवन ऊर्जा छीन ली है।

हालांकि यह केवल किसी एक बच्चे की कहानी नहीं है। यदि आप अपने इर्द-गिर्द देखें। युवा विद्यार्थियों से बात करें। उनकी रोजमर्रा की व्यथा सुनेंङ्क स्कूल से लेकर कोचिंग सेंटर तक कीङ्क आपको वाकई महसूस होगा कि एक विषैली शिक्षा संस्कृति हमारे बच्चों को बर्बाद कर रही है, उन्हें उनकी खुशियों और उत्कंठा से महरूम कर रही है। एक अशांत एवं नाखुश पीढ़ी पैदा करती जा रही है। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि शिक्षा के नाम पर यह पीढ़ी ज़हर प्राप्त कर रही है? इसके पीछे चार कारण हैं। प्रथम, परीक्षाओं को अत्यधिक महत्व देने से सीखने का आनंद जाता रहा। अर्थपूर्ण ढंग से जुड़े रहकर शिक्षा पाने वाली संस्कृति को दरकार होती है तनावमुक्त वातावरण की, ताकि कोई छात्र अपने निराले स्वभाव और कौशल के मुताबिक आत्म-अन्वेषण और आंतरिक उन्नति कर पाए। अंकों के आधार पर आकलन, सदा अच्छे नंबर लाना और किसी के ज्ञान का तोल भौतिकी, गणित या अंग्रेजी में पाए अंकों से करने का बेलगाम दबाव, वह भी हफ्ते दर हफ्ते, महीना दर महीना और साल दर साल परीक्षाओं के जरिए या फिर अत्यधिक जटिल होते जा रहे अभ्यास, परीक्षा प्रपत्रों को हल करने की शृंखला ने बच्चे की सीखने की नैसर्गिक लय को भंग कर डाला है। साथ ही हद दर्जे का तनाव, भय और मानसिक संत्रास बना डाला है।

दूसरी बात यह कि इसने सामाजिक संपर्क की आवश्यकता को भी बिगाड़ दिया है, संयुक्त एवं आपसी संवाद से सीखने की भावना खत्म होती जा रही है। इसकी बजाय, अति-प्रतिस्पर्धा का वायरस, दूसरे की सफलता से जलन, एकाकीपन और स्वार्थीपन युवा छात्रों के मानस में घर करता जा रहा है। शिक्षा की ऐसी संस्कृति की वजह से हमारे बच्चों के लिए सामाजिक मेल-मिलाप से सीखना लगातार मुश्किल बन रहा है जबकि किसी स्वस्थ और लोकतांत्रिक समाज के लिए खुद को बनाए रखने वास्ते जरूरी है विनम्रता, सहृदयता और संवाद के जरिए संयुक्त उत्थान की प्राप्ति, सहयोग और आपसी देखभाल वाली संस्कृति।

तीसरी बात यह है कि चूंकि वर्तमान में सफलता गाथाओं के प्रति आसक्ति हावी है। गौर करें कि कैसे नीट या जेईई परीक्षाओं में टॉप करने वालों को अंधाधुंध प्रचार के जरिए रातों-रात पौराणिक कथाओं के विजेता नायकों सरीखा स्टारडम प्रदान कर दिया जाता है। इन 'चमकीले सितारों' के बीच यह हरकत जाने-अनजाने में विफलता की गाथाएं भी पैदा करती जाती है।

जी हां, हर साल, हम हजारों-हजार युवाओं को यह मानने को मजबूर करते हैं कि वे किसी काम के नहीं क्योंकि वे अलां-फलां परीक्षा नहीं निकाल पाए, इसलिए वे डॉक्टर या इंजीनियर बनने लायक नहीं हैं, हम उन्हें विफलता का कलंक, कमजोर पड़े आत्म-सम्मान, जख्मी स्वः और आत्महत्या करने की सोच के साथ जीने को मजबूर कर रहे हैं। चौथी बात यह कि शिक्षा की यह संस्कृति इसलिए भी विषैली है क्योंकि यह एकल-आयामी है। जैसा कि इन दिनों यंत्रवत सोच बन गई है कि किन्हीं उच्च तकनीक-कॉर्पोरेट्स में ऊंचे वेतनमान वाली नौकरी पा लेना ही शिक्षित होने और उच्चता पाने का द्योतक है, जो कुछ हमें दिखाया जा रहा है, वह व्यवस्थित ढंग से अन्य पेशों के सम्मान को कमतर करना है। इसके अलावा, यह करना मानवेतर शिक्षा के मूल्यों को कमजोर करना है। मानो, यह खेल चलाने वाले नीति-निर्माता और अकादमिक प्रबंधक ऐसी पीढ़ी को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, जो केवल विशेषज्ञों की बनी हो, जैसे कि रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञ। लेकिन उन्हें न तो आत्मा को जगाने वाले महान काव्य, साहित्य और आध्यात्मिक लेखों से सरोकार है न ही व्यक्ति को अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले, ईर्ष्यागत प्रवृत्ति से हटाकर सहचर की ओर ले जाने वाली शिक्षा में दिलचस्पी है। वास्तव में आज हमारे सम्मुख तकनीक रूप से उन्नत किंतु नैतिकताविहीन पीढ़ी है। यह परम विद्रूपता है।

पूरी तरह पक्का नहीं है कि क्या हमारे बच्चों को इस विषैली संस्कृति से बचा पाना संभव होगा कि नहीं। तथापि, सकारात्मकता के तौर पर, हम यानी अध्यापक और अभिभावकों को अपनी आवाज़ उठानी होगी ताकि शिक्षा की नई पद्धति बन पाए। वे सब जिन्हें अभी भी शिक्षण के पेशे से प्यार है, उनके लिए जरूरी है कि वे उदारवादी शिक्षा या लोकतांत्रिक कक्षा के माहौल को जीवित रखें। जब तक कि हम अध्यापक इस बारे में खड़े नहीं होंगे, अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, आत्म-विश्वास से परिपूर्ण भूमिका नहीं निभाते या अन्य शिक्षाविदों और जन-बुद्धिजीवियों को नहीं जगाते तब तक न तो नौकरशाही की मशीन की तीलियां हिलेंगी न ही बच्चों की दुनिया से पूरी तरह कटे पड़े तकनीकी-प्रबंधकों-कॉर्पोरेट्स के कर्ता-धर्ताओं द्वारा बनाई उन नीतियों को सिर झुकाकर मानते चले जाने वाला चलन बदलेगा। इतना ही नहीं, उनमें सीखने-सिखाने के उचित तौर-तरीकों का शऊर भी नहीं है। शिक्षा को बचाने की मुहिम चलाए बिना कोई उम्मीद नहीं है।

इसी प्रकार, अभिभावकों के लिए भी अहम है यह महसूस करना और प्रोत्साहित करना कि हरेक बच्चा अपने-आप में अलग होता है। किसी की बुद्धिमत्ता को साझा पैमाने से या सामान्यकृत कर दिए गए अंकों से नापने वाली पद्धति के जरिए आंकना सही नहीं। यदि आपके बच्चे को विज्ञान पसंद नहीं है या उसे मैथ्स-ऑलिम्पियाड परीक्षा में भाग लेने की ललक नहीं तो यह कोई अप्राकृतिक घटना नहीं है। उसके अंतस को जानने में, सहानुभूति वाली समझ बनाने से आपको पता चल सकता है कि वह किसी अन्य किस्म के कौशल अथवा कला या योग्यता से परिपूर्ण है, मसलन, पेंटिंग, संगीत, खेती या फिर सामाजिक कार्य में। हम कब महसूस करेंगे कि बाजार के प्रचलित मूल्यों की एक नैतिक हद होती है और इसमें कुछ गलत नहीं यदि हमारा बच्चा अपेक्षाकृत कम आय वाले काम-धंधे में भी खुश रहे।

आज का इतिहास

- जेकब रोजरविन ने 1722 में पूर्वी आयरलैंड की खोज की।
- ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने 1843 में हॉगकॉग को ब्रिटिश कॉलनी में शामिल किए जाने की घोषणा की।
- महात्मा गांधी अपने अनुयायियों के साथ 1930 में नमक कानून तोडने़ के लिए दांडी पहुंचे।
- भारत स्काउट एण्ड गाइड की स्थापना 1949 को हुई।
- विस्टन चर्चिल ने 1955 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया।
- देश में 1957 में पहली बार और दुनिया में पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से केरल में संपन्न चुनाव के बाद कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आई और ईएमएस नम्बूदरीपाद ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया।
- भारत सरकार की ओर से प्रायोजित पहली 'इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी' की स्थापना 1961 में हुई।
- नौसेना ने 1964 में पहली बार राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया।
- सउदी अरब के राजा फैजल की 1975 में हत्या हुई।
- देश का पहला नौसेना संग्रहालय 1979 में मुम्बई में खुला।
- अंतरिक्ष यान एसटीएस 37 (अटलांटिस 8) का प्रक्षेपण 1991 में किया गया।
- मलेशिया में हेंड्रा नामक वायरस से बचाव के लिए 1999 से 8 लाख 30 हजार सुअरों की सामूहिक हत्या करने की शुरुआत की गई।
- भारत, म्यांमार व थाइलैंड के बीच 2002 में मोरे-कलावा-मांडले सड़क परियोजना पूरी करने हेतु सहमति।
- अमेरिकी संसद में पाक की आर्थिक मदद में कटौती का प्रस्ताव 2003 में पेश किया।
- सिंगापुर में 45 भारतीयों को आव्रजन अपराधों में 2006 को गिरफ़्तार किया गया।
- ईरान ने 2007 में 15 ब्रिटिश नौ सैनिकों को रिहा किया गया।
- पार्वती ओमनाकुट्टन 2008 में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड बनी।
- इराक में हुए 2008 में हुए आत्मघाती हमले में तक़रीबन 10 लोग मारे गए।
- अमेरिकी राज्य वेस्ट वर्जीनिया के कोयला खदान में 2010 को हुए विस्फोट से 22 लोगों की मौत हुयी।
- लोकसभा में फुटवियर डिजाइन और विकास संस?थान विधेयक 2017 में पारित हो गया।
- सिक्खों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास का जन्म 1479 में हुआ।
- भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री एवं राजनेता बाबू जग जीवन राम का जन्म 1908 में हुआ।
- राजनेता रफ़ीक़ ज़करिया का जन्म 1920 में हुआ।
- ब्रिटिश फुटबॉल खिलाड़ी टॉम फ़िनी का जन्म 1922 में हुआ।
- ब्रिटिश अभिनेता (मिस्टर बेलवेडर) क्रिस्टोफर ह्युएट्ट का जन्म 1922 में हुआ।
- अमेरिकी गायिका और अभिनेत्री गैल स्टोर्म का जन्म 1922 में हुआ।
- उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल तथा केन्द्रीय निर्माण एवं आवास मंत्रालय में उपमंत्री रहे मो. उस्मान आरिफ़ का जन्म 1923 में हुआ।

कुएं बचाने से ही बच पायेगा जीवन

अभी गर्मी शुरू ही हुई है, इसके बावजूद बुंदेलखंड के बड़े शहरों में से एक छतरपुर के हर मोहल्ले में पानी की त्राहि-त्राहि शुरू हो गई है। तीन लाख से अधिक आबादी वाले इस शहर में सरकार की तरफ से लगाए गए कोई 2100 हैंडपंपों में से अधिकांश या तो हांफ रहे हैं या सूख गए हैं। ग्रामीण अंचलों में भी हर बार की ही तरह हैंडपंप से कम पानी आने की शिकायत आ रही है। पानी की कमी के चलते छुट्टा मवेशियों की समस्या रबी की फसल के लिए खतरा बन गई है। सारे देश में बरसात के बीत जाने के बाद पानी की त्राहि-त्राहि अब सामान्य बात हो गई है। हताश जनता को जमीन की छाती चीर कर पानी निकालने या बड़े बांध के सपने दिखाये तो जाते हैं लेकिन जमीन पर कहीं पानी दिखता नहीं। आखिर नदियों में भी तो प्रवाह घट ही रहा है। आने वाले साल मौसमी बदलाव की मार के कारण और अधिक तपेंगे और पानी की मांग बढ़ेगी। ऐसे में हमारे पारंपरिक कुएं ही मानव-अस्तित्व को बचा सकते हैं।

हमारे आदि-समाज ने कभी बड़ी नदियों को छेड़ा नहीं, वे बड़ी नदी को अविरल बहने देते थेङ्क साल के किसी बड़े पर्व-त्योहार पर वहां एकत्र होते बस। खेत-मवेशी के लिए या तो छोटी नदी या फिर तालाब-झील। घर की जरूरत जैसे पीने और रसोई के लिए या तो आंगन में या फिर बसाहट के बीच का कुआं काम करता था। यदि एक बाल्टी की जरूरत है तो इंसान मेहनत से एक ही खींचता था। किफायत से खर्च करता। अब की तरह नहीं कि बिजली की मोटर से एक गिलास पानी की जरूरत के लिए दो बाल्टी पानी बर्बाद कर दिया जाए।

पंजाब की प्यास भी बड़ी गहरी है। पांच नदियों के संगम से बना यह समृद्ध राज्य खेती के लिए अंधाधुंध भूजल दोहन के कारण पूरी तरह 'डार्क ज़ोन' में है। यहां 150 में से 117 ब्लॉक में भूजल लगभग सिमट चुका है। कुछ साल पहले पलट कर देखें तो पाएंगे कि इस राज्य को खुश और हराभरा बनाने वाले दो लाख कुएं थे। जो अब बंद पड़े हैं। गुरु की नगरी अमृतसर में ही 1200 कुएं हुआ करते थे। इस शहर में पाइप से पानी घर तक भेजने का काम सन?् 1886 में शुरू हुआ था और तब शहर

की प्यास बुझाने का जिम्मा 1200 कुओं पर था। जो अब या तो लुप्त हो गए या बेपानी हैं।

भारत के लोक जीवन में परंपरा रही है कि घर में बच्चे का जन्म हो या फिर नई दुल्हन आए, घर-मोहल्ले के कुएं की पूजा की जाती है- जिस इलाके में जल की कीमत जान से ज्यादा हो वहां अपने घर के इस्तेमाल का पानी उगाहने वाले कुएं को मान देना तो बनता ही है। बीते तीन दशकों के दौरान भले ही प्यास बढ़ी हो, लेकिन सरकारी व्यवस्था ने घर में नल या नलकूप का ऐसा प्रकोप बरपाया कि पुरखों की परंपरा के निशान कुएं गुम होने लगे। अब कुओं की जगह हैंडपंप पूज कर ही परंपरा पूरी कर ली जाती है। वास्तव में हर नए जीवन को सीखना होता था कि आंगन का कुआं ही जीवन का सार है। समझना होगा कि असली समस्या कम बरसात या तीखी गर्मी नहीं है, वह तो यहां सदियों, पीढ़ियों से होता रहा है। पहले यहां के बाशिंदे कम पानी में जीवन जीना जानते थे। आधुनिकता की अंधी आंधी में पारंपरिक जल-प्रबंधन तंत्र नष्ट हो गए और उनकी जगह सूखा और सरकारी राहत जैसे शब्दों और नैसर्गिक जल साधनों के अधिक से अधिक शोषण की नीतियों ने ले ली। बड़े करीने से यहां के आदि-समाज ने बूंदों को बचाना सीखा था। दो तरह के तालाब- एक केवल पीने के लिए, दूसरे केवल मवेशी व सिंचाई के। पहाड़ की गोदी में बस्ती और पहाड़ की तलहटी में तालाब। तालाब के इर्दगिर्द कुएं ताकि समाज को जितनी जरूरत हो, उतना पानी ले। पिछले साल ही संसद में बताया गया कि छठवें लघु सिंचाई गणना के आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी भी 82 लाख 78 हजार 425 कुएं बकाया हैं। इनमें सबसे अधिक 27 लाख 49 हजार 88 उस महाराष्ट्र में हैं जहां किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा सर्वाधिक है। उसके बाद उस मध्य प्रदेश में 13 लाख 36 हजार 682 कुओं की चर्चा अकारण होगी जहां प्यास और पलायन के कारण बदनाम बुंदेलखंड है। तमिलनाडु में इससे अधिक 15 लाख 77 हजार 198 कुएं हैं लेकिन आज भी इस राज्य में ऐरी पद्धति के चलते दूरस्थ अंचल तक तालाब-कुओं का प्रबंधन बेहतर है। दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में महज 85224 कुओं का रिकार्ड मिल पाया। अकेले लखनऊ में 12653 कुओं व तालाब का रिकार्ड तो सरकारी फाइल में ही है।

यदि बुंदेलखंड में ही देखें तो आज भी कुओं के नाम पर सार्वजनिक नल-जल योजनाएं चल रही हैं। कुओं का रखरखाव कम खर्चीला है। कुओं के इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन से धरती को गर्म नहीं करते। कुओं को थोड़ी-सी बरसात होने पर भी हर बूंद को एकत्र करने का पात्र बनाना बहुत सरल होता है। प्राचीन जल संरक्षण व स्थापत्य के बेमिसाल नमूने रहे कुओं को ढकने, उनमें मिट्टी डाल कर बंद करने और उन पर दुकान-मकान बना लेने की रीत वर्ष 90 के बाद तब शुरू हुई जब लोगों को लगने लगा कि पानी, वह भी घर में मुहैया करवाने की जिम्मेदारी सरकार की है। फिर आबादी के बोझ ने जमीन की कीमत को प्यास से अधिक महंगा बना दिया। तरह-तरह की मशीन बेचने वालों ने खुले कुएं के पानी को अशुद्ध और बीमारी का घर बताने के प्रचार किये। सनद रहे जब तक कुएं से बाल्टी डाल कर पानी निकालना जारी रहता है उसका पानी शुद्ध रहता है, जैसे ही पानी ठहर जाता है, उसकी दुर्गति शुरू हो जाती है।

कई करोड़ की जल-आपूर्ति योजनाएं अब जल-स्रोत की कमी के चलते अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रही हैं। यह समझना जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन के साल दर साल गहराने के चलते भारत में लघु व स्थानीय परियोजनाएं ही जल संकट से जूझने में समर्थ हैं। अभी भी देश में बचे कुओं को कुछ हजार रुपये खर्च कर जिंदा किया जा सकता हे। एक बार कुओं में पानी आ गया तो समाज फिर खुद लोक परंपरा और प्यास दोनों के लिए कुओं पर निर्भर हो जाएगा।

अमेठी व रायबरेली का सवाल

यह सावाल पूरी तरह वाजिब है क्योंकि उत्तर प्रदेश को गांधी परिवार हल्के में नहीं ले सकता है क्योंकि इस परिवार की पूरी विरासत में उत्तर प्रदेश की मिट्टी की गंध रमी हुई है। पहले सुना जा रहा था कि राहुल गांधी की बहन श्रीमती प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं क्योंकि उनकी मताश्री सोनिया गांधी इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहीं।

कांग्रेस पार्टी और उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति में एक-दूसरे के पर्याय समझे जाते रहे हैं क्योंकि स्वतन्त्रता संग्राम के महानायक पं. जवाहर लाल नेहरू से लेकर देश की सर्वाधिक शक्तिशाली मानी जाने वाली उनकी पुत्री प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी का यह प्रदेश कर्म स्थल रहा है। पं. नेहरू ने तो इंग्लैंड से भारत आने के बाद सर्वप्रथम इलाहाबाद से ही अपना राजनैतिक जीवन शुरू किया और आसपास के गांवों का गहन दौरा करके उन्होंने असली भारत की हकीकत को पहचानने की कोशिश की। इसी प्रकार जनवरी 1966 में बतौर राज्यसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बनने के बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1967 का अपना पहला लोकसभा चुनाव राज्य की रायबरेली सीट से लड़ा। इतना ही नहीं 1971 में जब इन्दिरा जी के छोटे बेटे संजय गांधी राजनीति में आये तो उन्होंने अपना पहला चुनाव 1977 में राज्य की अमेठी लोकसभा सीट से लड़ा। हालांकि वह इसमें इमरजेंसी के चुनावी प्रभाव के चलते असफल रहे परन्तु जब 1982 में उनके बड़े भाई राजीव गांधी राजनीति में आये तो उन्होंने भी अमेठी व आसपास के सुल्तानपुर आदि इलाकों को ही अपनी कर्मभूमि बनाना उचित समझा। इन्दिरा जी व उनके पुत्र राजीव गांधी की निर्मम हत्याओं के बाद जब गांधी परिवार की बड़ी बहू श्रीमती सोनिया गांधी ने राजनीति में चरण रखा तो उन्होंने 1998 का पहला चुनाव रायबरेली से लड़ा। जहां तक नेहरू जी का सवाल है तो वह इलाहाबाद के निकट की सीट फूलपुर से चुनाव लड़ा करते थे।

1964 में उनकी मृत्यु होने के बाद इस सीट का प्रतिनिधित्व 1967 में उनकी बहन श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने किया। मगर 1970 में इन्दिरा गांधी से मनमुटाव हो जाने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया। इसी प्रकार नेहरू-गांधी परिवार की तरफ से जब श्री राहुल गांधी ने पदार्पण किया तो उन्होंने अपना पहला चुनाव 2004 में अमेठी से लड़ा और 2019 तक इसी सीट से लड़ते रहे मगर इस बार उनकी पराजय हो गई । संयोग से उन्होंने 2019 में केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ा था जहां से वह लोकसभा में पहुंचे। आगामी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस उत्तर प्रदेश की केवल 17 सीटों से ही चुनाव लड़ रही है। राज्य की कुल 80 सीटों में से शेष सीटें उसने अपने इंडिया गठबन्धन की सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दी हैं। कांग्रेस के खाते में 17 सीटों में अमेठी व रायबरेली सीटें भी आयी हैं। इन सीटों पर मतदान पांचवें चरण में 20 मई को होना है। 3 मई नामांकन पत्र भरे जाने का अन्तिम दिन है। अतः कहा जा सकता है कि अभी पर्याप्त समय है मगर पार्टी ने सातवें व अन्तिम चरण में होने वाले मतदान की सीटों जैसे महाराजगंज आदि पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अतः राजनैतिक क्षेत्रों में जिज्ञासा है कि क्या अमेठी व रायबरेली सीटों पर गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा अथवा नहीं।

यह सावाल पूरी तरह वाजिब है क्योंकि उत्तर प्रदेश को गांधी परिवार हल्के में नहीं ले सकता है क्योंकि इस परिवार की पूरी विरासत में उत्तर प्रदेश की मिट्टी की गंध रमी हुई है। पहले सुना जा रहा था कि राहुल गांधी की बहन श्रीमती प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लह सकती हैं क्योंकि उनकी मताश्री सोनिया गांधी इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहीं। वह राजस्थान से राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित हो चुकी हैं। सोनिया जी ने यह फैसला अपने स्वास्थ्य के कारणों से लिया लगता है। जहां तक अमेठी का सवाल है तो श्री राहुल गांधी द्वारा यहां से भी नामांकन दायर करने की प्रतीक्षा यहां के लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं अतः वह भारत के दो क्षेत्रों उत्तर-दक्षिण से यदि चुनाव लड़ते हैं तो इससे उनकी पार्टी की ही स्वीकार्यता बढ़ेगी। बेशक कांग्रेस पार्टी की सरकार उत्तर भारत में केवल हिमाचल प्रदेश में ही है मगर लोकसभा चुनावों में भाजपा के मुकाबले एकमात्र यही राष्ट्रीय पार्टी है। दक्षिण भारत के राज्यों कर्नाटक व तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें हैं जबकि केरल में यह प्रमुख विपक्षी पार्टी है और पिछले लोकसभा चुनाव में इस राज्य की कुल बीस सीटों में से इसके सर्वाधिक प्रत्याशी भी जीते थे परन्तु उत्तर प्रदेश की हैसियत अलग है क्योंकि भारत में यह कहावत बहुत प्रचिलित है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ होकर ही जाता है।

भारत ने किया तेल का खेल

अमेरिका ने भारत पर भी रूस पर अपनी निर्भरता कम करने के? लिए बहुत दबाव बनाया। किसी दबाव में न आते हुए भारत ने कूटनीति से काम लिया। भारत ने दो टूक शब्दों में अपने हितों का हवाला देकर रूस से कच्चे तेल का आयात जारी रखने का फैसला किया।

रूस पर नए अमेरिकी प्रतिबंधों से इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी कि भारत को रूसी तेल की बिक्री कम हो सकती है, जो समुद्र के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। पहले ऐसा डर जताया गया था कि रूसी टैंकर समूह पर लगे प्रतिबंध के कारण भारत को तेल आयात करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। पश्चिमी देशों की कोई भी टैंकर कम्पनी रूसी तेल को नहीं ढोएगी। वहीं, तीसरे देशों की कम्पनियां अमेरिकी प्रतिबंधों के डर से रूसी तेल को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगी। अगर कोई कम्पनी तैयार भी हुई तो वह ज्यादा भाड़ा वसूल करेगी जिससे भारत को रूस से तेल की खरीद में ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो भारत को तेल की खरीद के लिए किसी और देश का रुख करना होगा। हालांकि, यह चिंता बेकार साबित हुई और भारत लगातार रूस से तेल का आयात कर रहा है।

अमेरिका ने यूक्रेन पर रूस के हमले की दूसरी वर्षगांठ मनाने और विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी की मौत का बदला लेने के लिए फरवरी में प्रतिबंधों का ऐलान किया था। अमेरिकी प्रतिबंधों के निशाने पर रूस का प्रमुख टैंकर समूह सोवकॉम्फ्लोट था। अमेरिका ने इस रूसी टैंकर समूह पर रूसी तेल पर जी-7 की मूल्य सीमा का उल्लंघन करने में शामिल होने का आरोप लगाया था। सोवकॉम्फ्लोट के पास 14 कच्चे तेल टैंकर का बेड़ा है। अमेरिका को उम्मीद थी कि रूसी टैंकरों पर लगे प्रतिबंध से उसके तेल निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा लेकिन भारत ने न तो पहले अमेरिकी और उसके पिट्ठू देशों के प्रतिबंधों की परवाह की है और न ही नए प्रतिबंधों से डरा है। मार्च महीने में भारत का रूस से तेल आयात 6 प्रतिशत बढ़ गया है। तेल से भरे रूसी टैंकर भारतीय बंदरगाहों पर पहले की तरह पहुंच रहे हैं। इससे पहले भारतीय तेल कम्पनियों ने कहा था कि वे रूस से तेल के आयात में अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित कम्पनी के टैंकरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन अब भारतीय कम्पनियों ने अमेरिकी प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ा दी हैं। इससे साफ है ि?क भारत अपने ि?हतों की रक्षा अच्छी तरह से कर रहा है। फरवरी 2022 में यूक्रेन-रूस जंग शुरू होने पर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए तो यूरोपीय देशों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया।

अमेरिका ने भारत पर भी रूस पर अपनी निर्भरता कम करने के? लिए बहुत दबाव बनाया। किसी दबाव में न आते हुए भारत ने कूटनीति से काम लिया। भारत ने दो टूक शब्दों में अपने हितों का हवाला देकर रूस से कच्चे तेल का आयात जारी रखने का फैसला किया। रूस ने भी भारत को सस्ता तेल देने की पेशकश की और भारत ने इसका पूरा लाभ उठाया। भारत को 60 डॉलर से भी कम मूल्य पर रूस से तेल हासिल हुआ। भारत पहले इराक से सबसे ज्यादा तेल खरीदता था लेकिन अब इराक को पछाड़ कर रूस सबसे बड़ा देश बन गया है। सस्ता तेल मिलने से भारतीय रिफाइनरियों को बहुत लाभ हुआ। भारतीय रिफाइनरियों ने यूरोपीय बाजार के बड़े हिस्से पर कब्जा कर ? लिया। हुआ यूं कि जिस यूरोपीय कम्पनियों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे उन्हीं देशों को भारत ने तेल का निर्यात किया। पाकिस्तान ने भी भारत की तरह रूस से कच्चा तेल खरीदने की कोशिश की लेकिन अमेरिका के दबाव के आगे उसकी एक न चली। भारत की सफल कूटनीति के चलते कोरोना काल में और जंग से पहले घाटे में चल रही भारतीय तेल कम्पनियों की भरपाई हुई और भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई। जबकि दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था डांवाडोल चल रही है और वहां महंगाई से हा-हाकार मचा हुआ है। भारत यह अच्छी तरह जानता है कि रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत की आर्थिक स्थिरता को खतरा है। भारत की घरेलू मुद्रास्फीति और पैट्रोल कीमतों का प्रबंधन नरेन्द्र मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर है। भारत के बढ़ते आर्थिक कद को रोकने में अमेरिका का निहित स्वार्थ है। अमेरिका की नीति एक दुश्मन को निशाना बनाना और अन्य देशों को उस दुश्मन के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए उकसाना है।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • शुक्रवार • 5 अप्रैल • 2024
www.rashtriyasahara.com

उपभोक्ताओं की तौहीन

टाटा समूह की एयर लाइन्स विस्तारा ने एक दिन में 26 उड़ाने रद्द कीं। उन्होंने बताया कि चालक दल की अनुपलब्धता के कारण ऐसा करना पड़ा। दो दिनों में कंपनी की सौ से अधिक उड़ाने रद्द की गईं। कंपनी के अनुसार शीर्ष अधिकारी चालकों के साथ बैठकें कर रहे हैं। कहा जा रहा है, संशोधित वेतन संरचना के विरोध में चालकों ने बीमार होने की सूचना देकर अवकाश लिया है। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा विस्तारा से उड़ाने रद्द होने व देरी के लिए विस्तृत जानकारी मांगी गई है। पिछले ही दिनों उड़ाने रद्द करने के विरोध में यात्रियों ने दिल्ली एअरपोर्ट पर काफी बवाल किया था। क्रोधवश वे हवाई पट्टी पर जाकर बैठ गए और हल्ला-गुल्ला किया था।

उड्डयन मंत्रालय की तरफ से आनन-फानन सभी एयर लाइंसों को सख्त निर्देश जारी किए गए थे। सोचने वाली बात है कि उड़ानों को रद्द करने या बहुत देर होने से यात्रियों को समस्याओं का ही सामना नहीं करना पड़ता बल्कि कई दफा उनके महत्त्वपूर्ण कार्यों में व्यवधान आ जाता है। यात्री मंहगे किराये चुका कर सुविधाओं व समय की बचत चाहते हैं। मगर इस तरह की अव्यवस्था से उन्हें मानसिक तौर प्रताड़ित भी किया जाता है। परिवारी से मृत्यु शैय्या पर मिलना हो, शव यात्रा में शामिल होना हो या विवाहोत्सव में भाग लेना हो। लोग सुविधाजनक यात्रा के लिए काफी पहले से अपना टिकट बुक कराते हैं। उड़ान रद्द होना उनके लिए त्रासद सिद्ध होता है। सरकार ने उड़ान में होने वाली देरी के लिए मुआवजा भी तय किया है और उड़ान रद्द होने पर यात्रियों के ठहरने के लिए उचित प्रबंधन व भोजन की व्यवस्था करने के नियम बनाए हैं। यदि हवाई कंपनियां इसकी अवहेलना करती हैं तो सरकार को सख्त कार्रवाई करने से नहीं हिचकना चाहिए। यह कंपनी की आंतरिक मसला है, जो उसे चालक दल के साथ बैठ कर सुलझाना चाहिए। अमूमन इस तरह के अवरोध, हड़ताल व काम बंद जैसी हरकतें सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाती रही हैं, जिनसे उपभोक्ता हमेशा त्रस्त रही है। निजी कंपनियों के काम-काज व व्यवस्था को लेकर लोगों के मन में जो सम्मान है, उसे इस तरह की अव्यवस्था द्वारा तेजी से तबाह किया जा रहा है। जो किसी भी व्यवसाय के हित में नहीं कहा जा सकता। तकनीकी कारणों के अतिरिक्त मानवजन्य व्यवधानों के प्रति सख्ती की जानी जरूरी है।

प्रचार की वैधता-नैतिकता

चुनाव में प्रचार का बड़ा रोल होता है। मतदाताओं को उम्मीदवारों और उनकी संबद्ध पार्टी के बारे में जनाने के लिए यह किया जाता है। इसमें पोस्टर-बैनरों और विभिन्न संचार माध्यमों पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों की भूमिका और भी महती होती है। अतः इसकी प्रस्तुतियों के तरीकों और उनमें दिए गए संदेशों की वैधता-अवैधता पर प्रतिद्वंद्वियों की परस्पर नजर रहती है। हालांकि चुनाव आयोग की स्पष्ट मार्गदर्शिका के बावजूद पार्टियां विज्ञापनों के मामले में कभी-कभार उन हदबंदियों से बाहर चली जाती हैं। ऐसा 2024 की जारी चुनाव प्रक्रिया में दो मामलों में देखने को मिला है। पहला, उदाहरण महाराष्ट्र का है। यहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार धड़ा) ने

अजित पवार की असली राकांपा की तरफ से जारी विज्ञापनों में सर्वोच्च अदालत के निर्देशों की अवमानना की चुनौती दी है। दरअसल, अजित पवार के नेतृत्व में गत वर्ष राकांपा में हुए बड़े विभाजन के बाद उनके गुट को चुनाव आयोग ने असली राकांपा की मान्यता दी थी। शरद पवार इसके विरुद्ध सर्वोच्च अदालत की शरण में हैं। अदालत ने 19 मार्च की सुनवाई में अपनी अंतरिम व्यवस्था देते हुए अजित गुट को इस अस्वीकरण के साथ ही विज्ञापन जारी करने को कहा था कि 'चुनाव चिह्न घड़ी आवंटन का मामला विचाराधीन है।' लेकिन विज्ञापनों में यह अस्वीकरण नहीं है, जो सरासर अवमानना है। इससे मतदाताओं में गलत संदेश जाता है कि 'घड़ी' अंतिम रूप से अजीत पवार की राकांपा का अधिकृत चिह्न है। वे ऐसा नहीं कर सकते कि वे राज्य के उपमुख्यमंत्री हैं। उन्हें जारी विज्ञापनों को वापस ले कर, अस्वीकरण के साथ ही जनता में जाना चाहिए। दूसरा, मामला कांग्रेस की तरफ से उसके किसी नेता की तस्वीर के बिना ही विज्ञापन जारी किए जाने का है। अलबत्ता, उन पर कांग्रेस के चुनाव चिह्न 'हाथ' है। भाजपा को इस पर आपत्ति है। उसे लगता है कि ऐसा न कर कांग्रेस जवाबदेही से भाग रही है। यह सही है कि विज्ञापनों पर किसी सक्षम नेता के नाम वोटरों में कंटेंट को प्रामाणिक बनाते हैं। वैसे ये कंटेंट आपत्तिजनक नहीं हैं और वे आचार संहिता तथा सरकार की कार्यनीतियों की स्वस्थ आलोचना के दायरे में हैं। भाजपा की ये आपत्तियां खामख्वाह हैं।

परिधि/राजीव मंडल

इनकी 'सर्जरी' जरूरी

देश का सबसे बड़ा अस्पताल दिल्ली एम्स चर्चा में है। खबर है कि यहां प्रशिक्षित सहायक (ट्रेंड अटेंडेंट्स) और सफाईकर्मियों की भारी कमी है। किसी भी अस्पताल में डॉक्टरों और नर्स के बाद इन दो कर्मचारियों की भूमिका सबसे महत्त्वपूर्ण होती है। चूंकि दिल्ली में देश भर के मरीज इलाज के लिए आते हैं, लिहाजा ऐसी कमी अक्षम्य मानी जाएगी। नर्स यूनियन ने अस्पताल के निदेशक को पाती लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।

दरअसल, ऑपरेशन थियेटर (ओटी) और गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू) में इन दोनों विभाग के ट्रेंड लोगों का सबसे अमूल्य योगदान रहता है। साफ-सफाई से लेकर गंभीर मरीजों का सारा काम यही लोग करते हैं। स्वाभाविक है कि इनकी कमी से इलाजरत मरीजों के साथ ही इलाज करा रहे बाकी मरीजों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। खुद यहां कार्यरत डॉक्टरों का ऐसा मानना है कि यहां इस तरह के कर्मचारियों की कमी है, जिसे किसी भी सूरत में इस स्थिति में नहीं होना चाहिए। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक भले यह स्वीकारें कि नर्स यूनियन की मांगों पर विभाग संजीदगी से विचार कर रहा है, मगर लाख टके का सवाल यही कि इस तरह के हालात पैदा ही क्यों हुए? आखिर इतने बड़े और सुसज्जित अस्पताल में भी हालात कामचलाऊ स्तर के क्यों हैं? सिर्फ इतना कह देने भर से किसी की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती कि स्टाफ की कमी को दूर कर दिया जाएगा या मांगों पर महकमा गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है।

आजादी के 7 दशक बाद भी देश की स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। वैसे भी दिल्ली एम्स की तर्ज पर देश के अलग-अलग जगहों पर एम्स की स्थापना के बावजूद लोगों का भरोसा दिल्ली एम्स पर ही है। इसकी एकमात्र वजह इस अस्पताल का गुणवत्तापूर्ण इलाज और सर्वश्रेष्ठ आधारभूत संरचना है। अगर एम्स दिल्ली में भी लचर तरीके से चीजों को हैंडल किया जाएगा तो बाकी अस्पतालों की कल्पना ही की जा सकती है। लंबे वक्त से इन कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया ठंडी पड़ी है। क्या कोई इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या इस तरह की लापरवाही करने वालों पर एम्स प्रशासन सख्ती करेगा? जहां लोग एक-एक सांस के लिए कुछ भी कर गुजरने की जद् दोजहद करते हैं, वहां ऐसी लापरवाही बर्दाश्त के बाहर है। एम्स के इन गैरजिम्मेदार अधिकारियों की 'सर्जरी' जरूरी है।

अनमोल वचन

अपना समय औरों के लेखों से खुद को सुधारने में लगाइए, ताकि आप उन चीजों को आसानी से जान पाएं जिसके लिए औरों ने कठिन मेहनत की है

-सुकरात

सभी की राह में रोड़े

बिहार

प्रेमकुमार मणि

बिहार में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। कुल चालीस लोक सभा सीटों के लिए सात चरणों में चुनाव होंगे। दो चरणों के चुनाव के नामांकन संपन्न हो चुके हैं। 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने जमुई से चुनावी सभाओं का आरम्भ भी कर दिया है। समय से पहले लू चलने लगी है इसलिए मौसम का मिजाज गर्म है, लेकिन चुनावी गर्मी अभी महसूस नहीं हो रही है। शायद पूरे चुनाव में न भी हो। इसलिए कुल मिलाकर एक राजनीतिक सुस्ती दिख रही है।

राजनीतिक सुस्ती का कारण मोटे तौर पर चुनाव में मुद्दों का अभाव कहा जा सकता है, लेकिन यह भी होता है कि मुद्दे सुप्तावस्था में हों, मुखर नहीं हों। 1980 के चुनाव में ऐसी ही स्थिति थी। किसी को शायद ही इंदिरा गांधी की शानदार वापसी का अनुमान था। कांग्रेस का मुख्य नारा था 'चुनिए उनको जो सरकार चलाना जानते हों।' यह नारा से अधिक जनता की सोच थी। जनता पार्टी वाले स्पष्ट बहुमत पाकर भी लगातार आपसी कोहराम मचाए हुए थे। चरण सिंह को लगता था कि इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी से कांग्रेस खत्म हो जाएगी। जैसे आज मोदी जी को लग रहा है उनकी जांच एजेंसियां विपक्ष को खत्म कर देंगी। 2019 में पुलवामा मामले को विपक्ष ने गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन जनता ने लिया। इस बार चुनावी चंदे के मामले को पक्ष गंभीरता से नहीं ले रहा है, लेकिन यह मुद्दा जनता के जहन में सुलग रहा है। लोगों को यह भी महसूस हो रहा है लोकतंत्र में बदलाव होते रहने चाहिए।

बिहार में आमने-सामने दो राजनीतिक मोर्चे हैं। भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए और राजद के नेतृत्व वाला महागठबंधन या इंडी गठबंधन। नीतीश की एनडीए में वापसी से भाजपा को देश के पैमाने पर इस रूप में फायदा हुआ कि प्रतिपक्ष का इंडी गठबंधन बिखर गया। इसकी कितनी हवा बनी, नहीं बनी; इसका आकलन नहीं हुआ है, लेकिन बिहार में भाजपा के लिए इससे जमीनी मुश्किलें खड़ी हो गई है। जद (यू) को जरूर इससे लाभ मिलता दिख रहा है। उसने 2019 के आधार पर इस बार भी 16 सीटें अपने लिए गठबंधन में हासिल कर ली हैं। भाजपा के वोट बैंक के आधार पर वह उससे कहीं सीटें जीत सकती है, जो राजद के साथ जीत सकती थी। इसलिए उसकी निश्चिंतता समझी जा सकती है, लेकिन भाजपा की मुश्किल है कि नीतीश के अलग होने के बाद उसने जिस तरह बिहार एनडीए का कुनबा विस्तार किया था, उसके लिए अब मुसीबत बन गई है। 2019 में जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा राजद गठबंधन में थे। इस बीच एनडीए

में आए, लेकिन पीछे से नीतीश भी चले आए। ऐसे में बिहार एनडीए 'ज्यादा जोगी मठ उजाड़' की स्थिति में हो गई। भाजपा ने अपने जिस सामाजिक ताने-बाने को इस बीच विकसित किया था, उसे चुनाव में संभालना मुश्किल हो गया है। मसलन; नीतीश से जुड़े वोटबैंक को साधने के लिए भाजपा ने सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा की कमान सौंपी। वह सफल भी रहे थे। नीतीश के प्रभाव वाला वोट बैंक भाजपा की तरफ तेजी से मुखातिब हो रहा था।

दरअसल, इस बिखरते सामाजिक आधार से परेशान होकर ही नीतीश ने राजनीतिक पाला बदला था, लेकिन इस सामाजिक आधार पर नीतीश ने अपना दावा फिर से किया और भाजपा को इसे स्वीकार लेना पड़ा। भाजपा की मुश्किलें यहीं से शुरू हुईं। समझौते में पराजित पक्ष को हारी हुई जमीन सौंपना इतिहास के हर दौर में विजेता पक्ष के लिए नुकसानप्रद रहा है। बिहार भाजपा के लिए ऐसा ही हुआ। नतीजा यह निकला कि अपनी सोलह सीटों में नीतीश ने अतिपिछड़े और कुशवाहा-कुर्मी को पर्याप्त सीटों का प्रबंध कर लिया, लेकिन भाजपा अपनी सत्रह सीटों में न किसी कुशवाहा, कुर्मी को समायोजित कर पाई, न अतिपिछड़े वर्ग को। उसके सत्रह उम्मीदवारों में ग्यारह सामान्य यानि ऊंची जाति से हैं। तीन यादवों के अलावा केवल एक अतिपिछड़ा, एक दलित और एक वैश्य को वह टिकट दे सकी। इससे सामाजिक स्तर पर कार्यकर्ताओं का आंतरिक विक्षोभ स्वाभाविक है। भाजपा अभी सत्तासीन है इसलिए विद्रोह सतह पर नहीं आएगा, लेकिन दबा हुआ विद्रोह चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। इसके मुकाबले महागठबंधन ने कई तरह के प्रयोग किए। कांग्रेस और वाम के साथ राजद की चुनावी केमिस्ट्री सहज दिख रही है।

उसकी सबसे बड़ी मुसीबत लालू प्रसाद हैं। इस बार भी एनडीए ने लालू प्रसाद के चेहरे को ही मुद्दा बनाया है। जमुई की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने लालू प्रसाद के भ्रष्टाचार पर हमला बोला। वह जानते हैं कि जनता उन्हें नापसंद करती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने अपनी पार्टी का नेतृत्व किया था और उसके बेहतर परिणाम आए थे। इस बीच लालू प्रसाद के हस्तक्षेप ने परेशानियां पैदा की हैं। राजद का परिवारवाद एक बार फिर सामने दिख रहा है, जिस में लालू प्रसाद ने अपनी दो बेटियों को उम्मीदवार बनाया है। तेजस्वी ने अपने हस्तक्षेप से स्थितियां संभालने की संभव कोशिशें की हैं। पप्पू यादव और हिना सहाब जैसे मामलों पर कड़ा रुख अख्तियार कर राजद ने जनता के बड़े हिस्से में प्रशंसा भी हासिल की है। कि प्रश्नांकित चेहरों से वह दूरी बना कर रहेगा, लेकिन लोगों में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि पप्पू यादव और सहाब को रोकने के लिए जिस तरह वीटो का इस्तेमाल तेजस्वी ने अपने दल में किया, वैसा अपनी बहनों को रोकने के लिए क्यों नहीं किया।

बावजूद इसके एनडीए से खफा पिछड़े तबकों के लिए राजद ने अधिक सीटें मुहैया करा कर राजनीतिक दांव खेला है। उसके छब्बीस उम्मीदवारों में गैर यादव पिछड़ों को अधिक सीटें मिली हैं। इसका कितना चुनावी लाभ उसे इस बार मिलेगा यह तो चार जून को पता चलेगा, किन्तु अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजद ने अपनी मजबूत बिसात जरूर बिछा दी है। इस चुनाव में महागठबंधन को खोने के लिए कुछ नहीं है। पिछली बार उसे केवल एक सीट मिली थी। भाजपा-जदयू-लोजपा गठबंधन को 39 सीटें मिली थीं। भाजपा के लिए चार सौ पार का जो महालक्ष्य प्रधानमंत्री ने रखा है उसमें चालीस सीटें बिहार की है। वह यदि सभी चालीस जीत जाती है तो उसे केवल एक सीट का लाभ होगा, लेकिन गणित थोड़ा भी इधर-उधर हुआ तो ग्राफ धड़ाम हो सकता है। कितना होगा, कहना मुश्किल है, लेकिन बिहार में जो स्थिति उभरती दिख रही है उसके आधार पर आने वाले नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं।

> इस चुनाव में महागठबंधन को खोने के लिए कुछ नहीं है। पिछली बार उसे केवल एक सीट मिली थी। भाजपा-जदयू-लोजपा गठबंधन को 39 सीटें मिली थीं। भाजपा के लिए चार सौ पार का जो महालक्ष्य प्रधानमंत्री ने रखा है उसमें चालीस सीटें बिहार की है। वह यदि सभी चालीस जीत जाती है तो उसे केवल एक सीट का लाभ होगा, लेकिन गणित थोड़ा भी इधर-उधर हुआ तो ग्राफ धड़ाम हो सकता है। कितना होगा, कहना मुश्किल है

- भारत के इंजीनियरिंग उद्यमी वैश्विक स्तर पर भारतीय उत्पादों के लिए विश्व में बड़ा बाजार देख रहे हैं। दो दर्जन से ज्यादा देशों में भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है
- अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात और रूस आदि भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों के बड़े आयातक हैं
- इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मुताबिक, विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर जो वार्ताएं चल रही हैं, उनसे इंजीनियरिंग उद्योग को बड़ी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं

(स्रोत : मीडिया इन्पुट्स)

तेल-संपन्न अरब शेखों और अमेरिका-इस्राइल की सहापराधिता ही गाजा युद्ध की असल कहानी है, जिसे इस रविवार को छह महीने हो रहे हैं और अब अब तक इस युद्ध में 35 हजार फिलिस्तीनी और इस्राइली मारे जा चुके हैं।

मिन्हाज मर्चेंट, लेखक
@MinhazMerchant

जनता को जानने का हक

ईवीएम-वीवीपैट **रजनीश कपूर**

पिछले दिनों देश की शीर्ष अदालत ने एक जनहित याचिका का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। नोटिस में अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा कि भारत की चुनाव प्रणाली में इस्तेमाल की जाने वाली 'इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन' (ईवीएम) और उसके साथ जुड़ी 'वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल' (वीवीपैट) मशीन का शत प्रतिशत मिलान क्यों न किया जाए? चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से याचिकाकर्ता की इस मांग को उचित मानते हुए सर्वोच्च अदालत ने ये नोटिस जारी किया। विपक्षी दलों द्वारा इस मिलान की मांग काफी समय से की जा रही है, परंतु न तो चुनाव आयोग और न ही शीर्ष अदालत ने इन मांगों पर ध्यान दिया। सभी को यही लगता था कि जब भी विपक्ष चुनाव हारता है तभी ईवीएम पर शोर मचाता है।

ऐसा नहीं है कि किसी एक दल के नेता ही ईवीएम की गड़बड़ी या उससे छेड़-छाड़ का आरोप लगाते आए हैं। इस बात के अनेकों उदाहरण हैं जहां हर प्रमुख दलों के नेताओं ने कई चुनावों के बाद ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग की बात करें तो वो इन आरोपों का शुरू से ही खंडन कर रहा है। आयोग के अनुसार ईवीएम में गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। 1998 में दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के विधान सभा की कुछ सीटों पर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था, परंतु 2004 के आम चुनाव में पहली बार हर संसदीय क्षेत्र में ईवीएम का पूरी तरह से इस्तेमाल हुआ। 2009 के चुनावी नतीजों के बाद इसमें गड़बड़ी का आरोप भाजपा द्वारा लगा। गौरतलब है कि दुनिया के 31 देशों में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ परंतु खास बात यह है कि अधिकतर देशों ने इसमें गड़बड़ी कि शिकायत के बाद वापस बैलट पेपर के जरिये ही चुनाव किए जाने लगे। वीवीपैट व्यवस्था के तहत वोटर डालने के तुरंत बाद कागज की एक पर्ची छपती है। इस पर्ची पर वोटर द्वारा जिस उम्मीदवार को वोट दिया गया है, उनका नाम और चुनाव चिह्न छपा होता है। इससे वोटर को इस बात की संतुष्टि हो जाती है कि उसने जिसे वोट दिया उसी को वोट मिला। इसके साथ ही किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में ईवीएम में पड़े वोटों का इन पर्चियों से मिलान भी किया जा सके। 2013 में वीवीपैट को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक

कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। 2014 में चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया कि 2019 के आम चुनावों में सभी ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल हो। ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका को दूर रखने की मंशा से फिलहाल हर निर्वाचन क्षेत्र की किसी भी 5 रैंडम ईवीएम का ही वीवीपैट से मिलान होता है। याचिका में मांग की गई कि चुनाव आयोग ने लगभग 24 लाख वीवीपैट खरीदने के लिए 5 हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं, परंतु केवल 20,000 वीवीपैट की पर्चियों का ही मिलान होता है। जनता के कर से दिए गए पैसों से बनी इन मशीनों का जब सभी मतदान केंद्रों पर इस्तेमाल होता है तो इसका मिलान करने में दिक्कत क्या है? आखिर मतदाता को इस बात की जानकारी लेने का पूरा हक है कि उसके द्वारा दिए गए वोट, उसी के द्वारा चुने गए उम्मीदवार को मिले किसी अन्य को नहीं। याचिका में कहा गया है कि 'चुनाव न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए क्योंकि सूचना के अधिकार को भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1)(ए) और 21 के संदर्भ में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है। कोर्ट ने इसी अधिकार के तहत इस याचिका को स्वीकार किया और नोटिस जारी किया। जब भी कभी कोई प्रतियोगिता होती है तो उसका संचालन करने वाले शक के घेरे में न आएं इसलिए उस प्रतियोगिता के हर कृत्य को सार्वजनिक रूप से किया जाता है। आयोजक इस बात पर खास ध्यान देते हैं कि उन पर पक्षपात का आरोप न लगे। इसीलिए जब भी कभी आयोजकों को कोई सुझाव दिए जाते हैं तो यदि वे उन्हें सही लगें तो उसे स्वीकार लेते हैं।

ऐसे में उन पर पक्षपात का आरोप नहीं लगता। ठीक उसी तरह एक स्वस्थ लोकतंत्र में होने वाली सबसे बड़ी प्रतियोगिता चुनाव हैं। उसके आयोजक यानी चुनाव आयोग को उन सभी सुझावों को खुले दिमाग से और निष्पक्षता से लेना चाहिए। चुनाव आयोग एक संविधानिक संस्था है, इसे किसी भी दल या सरकार के प्रति पक्षपात होता दिखाई नहीं देना चाहिए। यदि चुनाव आयोग ऐसे सुझावों को जनहित में लेती है तो मतदाताओं के बीच भी एक सही संदेश जाएगा, कि चाहे ईवीएम पर गड़बड़ियों के आरोप लगें पर चुनाव आयोग किसी भी दल के साथ पक्षपात नहीं करता। यदि ईवीएम की गुणवत्ता पर और उसकी कार्यपद्धति पर चुनाव आयोग को पूरा विशवास है तो इस याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया सर्वोच्च अदालत में अविलंब दे देनी चाहिए। यदि चुनाव आयोग को याचिका की मांगों पर आपत्ति नहीं है तो आगामी लोक सभा चुनावों में ऐसा प्रयोग कर ही लेना चाहिए। इतना ही नहीं भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र को और मजबूती भी मिलेगी।

परिवार **श्रीराम शर्मा आचार्य**

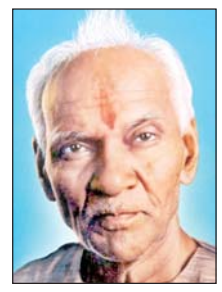

परिवार बसा लेना आसान है, लोग आए दिन बसाते ही रहते हैं, उसका पालन भी कोई विशेष कठिन नहीं। सभी उसका पालन करते हैं, किन्तु परिवार को समुन्नत एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए उसका निर्माण करना एक श्रम साध्य कर्त्तव्य है। अधिकतर लोग परिजनों के लिए अधिकाधिक सुख-सुविधाएं देने, उनके लिए अच्छा भोजन, वस्त्र तथा आराम की चीजें जुटाना ही पारिवारिक जीवन का उद्देश्य मान बैठे हैं। वे यह कभी नहीं सोच पाते कि भोजन, वस्त्र तथा शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ परिवार की एक सर्वोपरि आवश्यकता भी है और वह है उसे सुणी बनाना। आपके पास एक ऐसी प्रेम की रस्सी होनी चाहिए, आपके पास ऐसी मिठास की रस्सी होनी चाहिए, आपके पास अपने व्यक्तिगत जीवन का उदाहरण पेश करने की ऐसी रस्सी होनी चाहिए, जिससे प्रभावित करके आप आदमी के हाथ जकड़ सकें, पैर जकड़ सकें, काम जकड़ सकें। सारे के सारे को जकड़ करके जिंदगी भर अपने साथ बनाए रख सकें। अपने उद्धार के लिए नारी को स्वयं भी जागरूक होना पड़ेगा। अपने आपको आत्मा, वह आत्मा जो पुरुषों में भी है समझना होगा। मातृत्व के महान पद की प्रतिष्ठा को पुनर्जीवित रखने के लिए उसे सीता, गौरी, मदालसा, देवी, दुर्गा, काली की सी शक्ति, क्षमता और कर्त्तव्य का उत्तरदायित्व ग्रहरण करना होगा। कामिनी, विलास की सामग्री न बनकर अपने आपको आदर्श, पूजनीय गुणों का आधार बनाना होगा, तभी वह गिरी हुई अवस्था से उठ सकती है। नारी का उत्तरदायित्व बहुत बड़ा है। पुरुष से भी अधिक कह दिया जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। वह गृहिणी है, नियत्री है, अन्नपूर्णा है। नारी में ममतामयी मां का अस्तित्व निहित है, तो नारी पुरुष की प्रगति, विकास की प्रेरणा सोत जाह्नवी है। नारी अनेकों परिवारों का संगम स्थल है। नारी मनुष्य की आदि गुरु है, निर्मात्री है, इसमें कोई संदेह नहीं कि मानव समाज में नारी का बहुत बड़ा स्थान है और नारी की उन्नत अथवा पतित स्थिति पर ही समाज का भी उत्थान-पतन निर्भर करता है। इसलिए नारी का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। जिस समाज ने नारी की बेइज्जती की, उसका विनाश तय है।

रीडर्स मेल

चुनाव में डीपफेक का साया

पिछले तमाम चुनावों के मुकाबले इस बार चुनाव आयोग को न सिर्फ नेताओं का मिथ्या प्रचार, दुष्प्रचार और पैसे का लेनदेन से जूझना है बल्कि डीपफेक वीडियो से भी जूझना है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बल पर अपना असर दिखाना शुरू कर चुका है। इसकी शुरुआत तमिलनाडु से हो चुकी है। वहां जे. जयललिता एवं करुणानिधि लोक सभा चुनाव से पहले जीवित हो चुके हैं। दोनों एक बार फिर से एक दूसरे को प्रहार भी करना शुरू कर दिया है। जयललिता को एक ध्वनि संदेश में राज्य की वर्तमान सत्ताधारी पार्टी की गहरी आलोचना करते हुए दिखाया गया है, जिसका नेतृत्व कभी कट्टर प्रतिद्वंद्वी एम करुणानिधि ने किया था। वहीं करुणानिधि एआई-जनरेटेड वीडियो में-अपने ट्रेडमार्क काले धूप का चश्मा पहने हुए-अपने बेटे एमके स्टालिन की प्रशंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है यह टेक्नोलॉजी सिर्फ तमिलनाडु तक सिमित नहीं रहेगा। लगता नहीं कि इसके द्वारा किए जाने वाले दुष्प्रचार को रोक पाना चुनाव आयोग के लिए संभव है।

जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

दूर हो सकती है बेरोजगारी

देश में बेरोजगारी की समस्या दिनो-दिन बढ़ती जा रही है। इसका प्रमुख कारण यूं तो जनसंख्या वृद्धि है। इसके अलावा मनुष्य की सोच और सरकारी नीति भी कम दोषी नहीं है। प्रायः देश का नागरिक सरकारी नौकरी को ही रोजगार समझता है, यह सोच दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बाद निजी क्षेत्रों को रोजगार के अवसर माना जाता है, जबकि यूरोप और पश्चिमी देशों में नौकरी की अपेक्षा निजी व्यवसाय को श्रेयस्कर माना जाता है। सरकार भी यदि थोड़ा सा अपनी नीति में बदलाव ले आए तो कुछ हद तक बेरोजगारी कम हो सकती है। यदि एक ऐसा कानून बना दिया जाए कि पति- पत्नी में से केवल एक को ही सरकारी नौकरी मिलेगी तो बेरोजगारी 10 फीसद तक कम हो सकती है। क्योंकि प्रायः देखने में आता है कि अनेक ऐसे परिवार हैं, जिनमें पति और पत्नी दोनों ही सरकारी सेवा में हैं और उनके पालन के लिए एक ही संतान है। दूसरी ओर ऐसे अनेक परिवार हैं, जिनमें पति-पत्नी योग्य होते हुए भी सरकारी सेवा से वंचित हैं और संतानें भी 2 या तीन हैं।

डॉ. नरेन्द्र टोंक, मेरठ

हर हाल में बचाना होगा जल

पानी प्रकृति का ऐसा वरदान है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। बढ़ते प्रदूषण से तापमान में बढ़ोतरी के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कहीं बाढ़ कही सूखे के हालात पैदा हो रहे हैं। इससे जल संकट पैदा हो रहा है। मानव की गतिविधियों के कारण हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। इससे जल संकट भी पैदा हुआ है। जहां एक ओर लोग जलवायु परिवर्तन स्वरूप बाढ़ जैसी आपदाओं का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शुद्ध पेयजल की एक-एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण प्रभावित हो रही जल गुणवत्ता संपूर्ण विश्व के लिए चुनौती है। यदि हम वर्षा जल को संरक्षित नहीं कर सके, तो हालात गंभीर हो सकते हैं। बेंगलुरु जल संकट हमारे लिए प्रकृति की चेतावनी है, जिससे हमें सबक सीखने होंगे और पानी की एक-एक बूंद का रक्षण करना ही होगा। प्राकृतिक जल स्रोत तेजी से सूख रहे हैं। इस विषय पर गहन चिंतन करने की आवश्यकता है।

अंकित कुमार सोनी, मनावर, मप्र

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-33, अंक 233
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित। । समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

संपादकीय

क्या गरीब-अमीर खाई जरूरी मुद्दा नहीं है?

शीर्ष संस्थाओं पर बैठे लोग कभी-कभी अजीबोगरीब तर्क देते हैं। एक ऐसा ही तर्क लेख के माध्यम से वित्त-आयोग के एक अधिकारी ने दिया है। उनके अनुसार गरीब को तब चिंता नहीं होती जब किसी धन्नासेठ की आय बढ़ती है, लेकिन चिंता तब होती है जब पड़ोसी उससे ज्यादा खुशहाल होता है। उनका लेख दो हफ्ते पहले आई 'भारत की आय और संपत्ति की असमानता' रिपोर्ट की प्रतिक्रिया में लिखा गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में आय और संपत्ति की खाई पिछले सौ वर्षों में आज सबसे ज्यादा है। लेख में तर्क था, 'गरीबी उन्मूलन के लिए पूंजी निर्माण चाहिए। सन् 1990 तक विरले डॉलर-अरबपति होते थे, तो अति-गरीबी होती थी। आज ढेरों अरबपति हैं, अति-गरीबी भी इतिहास बन गई है'। दरअसल अति-गरीबी एक अर्थशास्त्रीय श्रेणी है। अगर भारत इन वर्षों में मात्र अति-गरीबी (न कि गरीबी) ही खत्म कर सका है तो ऐसी अर्थव्यवस्था की निंदा की जानी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर देश के 167 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति पर मात्र दो प्रतिशत सुपररिच टैक्स ले लिया जाए तो देश के शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण के लिए अच्छा-खासा धन मिल जाएगा। लेकिन लेख इसे 'भारी-भरकम' टैक्स बताकर कहता है कि ज्यादातर पूंजी का निवेश उच्च-लाभ के लिए होता है और टैक्स के डर से उद्यमिता पर रोक लग जाएगी।

प्रेरणा

हम हमेशा यह नहीं चुन सकते कि कौन हमारे जीवन में आएगा, लेकिन उनसे सीख जरूर सकते हैं। **- सीवी रमन**

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

अपने भीतर के महात्मा को जानें, जीवन में शांति आएगी

यह सवाल बार-बार पूछा जाता है कि हम शांत कैसे रहें। इसे यूं समझना पड़ेगा- हम तीन बातों से बने हैं, शरीर, मन और आत्मा। शरीर पर टिककर कोई शांत रह नहीं सकता। मन अशांति का केंद्र है। शांति तो आत्मा पर जाकर ही मिलेगी। उसके लिए ध्यान करें। ध्यान का मतलब ही है कि मन को लांघ जाना, आत्मा पर पहुंचना। और जब हम आत्मा पर पहुंचते हैं, तो बीच में एक महात्मा आता है, जो हमारे ही भीतर है। महात्मा के बाद आत्मा, और आत्मा के बाद सीधे परमात्मा है। और परमात्मा का एक स्वरूप शांति है। महात्मा शब्द आते ही हमें गांधी जी की याद आती है। राम को भी दो लोगों ने महात्मा कहा था। वनवास जाते समय दुखी होकर राजा दशरथ ने राम को महात्मा पुकारा था। गुरु विश्वामित्र ने भी श्रीराम को शस्त्र विद्या देने के बाद महात्मा कहा था। राम को देखकर लगता है कि जो दूसरों की पीड़ा सहकर, उसे दूर करके, खुद धैर्य के साथ जिए, वो महात्मा है। राम हमेशा दूसरों के लिए जिए। जब वो दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते थे, सहयोग करते, तो उसमें दिखावा-स्वार्थ नहीं था। यही लक्षण महात्मा के हैं। जो भी अपने महात्मा होने के आंतरिक व्यक्तित्व को जान गया, उसके जीवन में अपने आप शांति आएगी। • Facebook: Pt. Vijayshankar Mehta

विश्लेषण • आज वैसा विपक्षी नेतृत्व कहां?

विपक्ष को समझना होगा कि यह 1977 का भारत नहीं है

राजदीप सरदेसाई
वरिष्ठ पत्रकार
rajdeepsardesai52@gmail.com

'बीजेपी बनाम डेमोक्रेसी' : यह रामलीला मैदान में विपक्ष की 'लोकतंत्र बचाओ' रैली में एक विशाल बैनर पर लिखा हुआ था। यही 2024 का उनका चुनावी एजेंडा भी है। विपक्ष के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एकत्र हुए थे और 'लोकतंत्र को तानाशाही से बचाने' की बात उनके भाषणों में रह-रहकर आ रही थी। इससे पहले जब आखिरी बार विपक्ष ने इस तरह के नैरेटिव पर ध्यान केंद्रित किया था, वह 1977 का ऐतिहासिक चुनाव था, जिसमें शक्तिशाली इंदिरा गांधी एक संयुक्त विपक्ष से हार गई थीं। लेकिन हकीकत को परखें तो पाएंगे कि 2024 का साल 1977 नहीं है।

अव्वल तो यही कि दो विपक्षी मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी की तुलना 21 महीने चली इमरजेंसी से नहीं की जा सकती, जिसमें सैकड़ों नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में ठूंस दिया गया था। हां, अगर केंद्रीय एजेंसियों को 'हथियार' बनाकर विपक्षी नेताओं के खिलाफ उनके बेलगाम इस्तेमाल की बात करें तो आपातकाल की उपमा को थोड़ी दूर तक खींचा जा सकता है। यह भी सच है कि विपक्षी दलों को चुनाव लड़ने के समान अवसर नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके आधार पर यह कहना कि हम एक 'विपक्ष-मुक्त भारत' की ओर बढ़ रहे हैं, अतिशयोक्ति होगी। महाराष्ट्र का ही उदाहरण लें, जहां सीट-दर-सीट कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है।

दूसरे, 1977 में विपक्षी नेतृत्व वर्तमान के असंगठित 'इंडिया' गठबंधन की तुलना में कहीं अधिक अनुभवी और सम्मानित था। उसने एकजुट मोर्चा बनाने के लिए खासा संघर्ष किया था। जनता पार्टी का गठन जनसंघियों और समाजवादियों जैसी एक-दूसरे से अलग ताकतों द्वारा किया गया था, जो गैर-कांग्रेसवाद के नारे पर संगठित हुई थीं। उन्हें जयप्रकाश नारायण जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के दिग्गज नेता द्वारा नैतिक दिशानिर्देश दिया जा रहा था। क्या रामलीला मैदान में एकत्र लोगों में से कोई भी जेपी जैसी सैद्धांतिक नेतृत्व की भावना का आह्वान कर सकता है? यह सच है कि तमाम विपक्षी दल मोदी-विरोध की साझा-शर्त पर एकजुट हुए हैं, लेकिन उनके जमीनी विरोधाभास आज भी कायम हैं। पंजाब में 'आप' बनाम कांग्रेस, बंगाल में टीएमसी बनाम वाम-कांग्रेस गठबंधन, और यहां तक कि केरल में भी वामदल और कांग्रेस आमने-सामने हैं।

तीसरे, जब विपक्ष 'लोकतंत्र खतरे में है' की बहस छेड़ता है तो खुद उसका दामन साफ नहीं होता। पिछले दशक में कई विपक्षी मुख्यमंत्रियों पर निरंकुश व्यवहार के आरोप लगे हैं : पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र (जब यह महाराष्ट्र विकास अघाड़ी शासन के अधीन था) में असहमति की आवाजों को भी दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। यदि ईडी केंद्र सरकार का हथियार रहा है, तो राज्यों की राजधानियों में स्थानीय पुलिस यही काम करती है। चौथे, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की आवश्यकता और उनमें आम नागरिकों की रुचि के बीच अंतर बढ़ रहा है। 1977 में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का गला घोंटने के खिलाफ जनता में साफतौर पर नाराजगी थी और यह मुख्य रूप से उत्तर भारत में प्रकट हुई थी, जहां इंदिरा सरकार के जबरन 'नसबंदी' अभियान के कारण खासी ज्यादतियां की गई थीं। जबकि दक्षिण भारत आपातकाल से लगभग अप्रभावित रहा था।

इसके अलावा, 1970 के दशक की तुलना में शहरी मध्यम वर्ग अब एक बहुत अलग सामाजिक-आर्थिक श्रेणी बन चुकी है। तेजी से बढ़ती, तकनीक-संचालित अर्थव्यवस्था में, एक ऐसी पीढ़ी का उदय हुआ है, जो

कई विपक्षी सीएम पर निरंकुश व्यवहार के आरोप लगे हैं : पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र में असहमति की आवाजों पर कार्रवाइयां हुई हैं। यदि ईडी केंद्र सरकार का हथियार है, तो राज्यों में स्थानीय पुलिस यही काम करती है।

'मी फर्स्ट' का नारा लगाती है और उसे राजनीति से ज्यादा सरोकार नहीं है, बशर्ते उसके व्यक्तिगत हित सीधे तौर पर दांव पर न लगे हों। उदाहरण के लिए, बार-बार पेपर लीक होने से नाराज युवा सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन अधिकतर 'क्लिक-बेट एक्टिविज्म' से ही संतुष्ट हैं, जिसमें किसी वायरल वीडियो को उत्साहपूर्वक शेयर करने भर से अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली जाती है। इसकी तुलना में 1970 के दशक में- जो अभी भी जुझारू ट्रेड यूनियनों, प्रतिबद्ध सिविल लिबर्टी समूहों और आदर्शवादी राजनीति की भावना से भरा हुआ था- लोकतांत्रिक स्पेस के लिए जमीनी लड़ाई लड़ना मायने रखता था। अब तो यह शायद ही कभी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स से आगे बढ़ता है।

पुनश्च : इस साल फरवरी में एक प्यू सर्वेक्षण में पाया गया कि 67% भारतीय यह मानते हैं कि 'एक ऐसी प्रणाली, जिसमें एक मजबूत नेता संसद या अदालतों के हस्तक्षेप के बिना निर्णय ले सकता हो, देश के लिए अच्छी है।' 2017 में यह आंकड़ा 55% ही था। लोकतंत्र की किसे चिंता है?

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

इकोनॉमी • इन रिफॉर्म से दुनिया भी बेहतर स्थिति में

उभरते हुए बाजार अब सुधारों की राह अपनाने लगे हैं

रुचिर शर्मा
ग्लोबल इन्वेस्टर व बेस्टसेलिंग राइटर
breakoutnations@gmail.com

भारत और इंडोनेशिया जैसी उभरती हुई वैश्विक-ताकतों ने हाल के वर्षों की उथल-पुथल को ठोस तरीके से झेला है और वे इसके लिए व्यापक रूप से पहचाने जा रहे हैं। अब विकासशील दुनिया की कई संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थाएं भी अपने में सुधार करते हुए बेहतरी की दिशा में बढ़ रही हैं। और बाजार उन्हें इसके लिए पुरस्कृत भी करने लगा है। इनमें तुर्किये, अर्जेंटीना, मिस्र, नाइजीरिया और केन्या प्रमुख हैं। आर्थिक सुधार करने वाले ये देश आज दुनिया की 40 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से हैं। उनकी प्रगति से दुनिया की इकोनॉमिक रिकवरी भी मजबूत हो रही है।

जब 2022 में वैश्विक ब्याज दरें तेजी से बढ़ीं तो महंगाई, कर्ज और घाटे से त्रस्त इन देशों का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो रहा था। उनके पास बदलाव के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया था। उनके नेता- जो कि अर्जेंटीना, केन्या और नाइजीरिया में सुधारों के लिए मिले जनादेश के साथ ही नए-नए चुने गए थे- भले इस बात को जोर देकर नहीं कहें, लेकिन उनकी योजनाएं 'वॉशिंगटन सर्वसम्मति' से निकलकर आ रही थीं।

सुधार करने वाले इन पांच देशों की अभी भी व्यापक रूप से सराहना नहीं की जा रही है। ठीक एक साल पहले उनका घाटा उनके जीडीपी के 5% से ऊपर था। उनकी मुद्रास्फीति दर औसतन उच्च दोहरे अंकों में थी, और अर्जेंटीना में तो यह 200% से अधिक हो गई थी। निवेशक या तो अपने सॉवरेन बांड को रखने के लिए भारी प्रीमियम की मांग कर रहे थे या उनसे दूर हो रहे थे। यदि 'उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं' शब्द अभी भी चलन में नहीं होता, तो इन्हें इस दशक की 'पांच सबसे खस्ताहाल इकोनॉमी' का तमगा भी दिया जा सकता था।

जैसे-जैसे पूंजी उनसे दूर हुई, विदेशी मुद्रा भंडार निम्नतम स्तर पर पहुंच गए। उनमें औसतन एक तिहाई की अधिकतम गिरावट दर्ज की गई। पहले तो सरकारों ने नियंत्रण के माध्यम से मुद्राओं को स्थिर करने की कोशिश करते हुए इन दबावों का विरोध किया। इससे केवल इतना ही हुआ कि निवेशक काला बाजारों की ओर रुख करने लगे। फिर भाग्य ने पलटी खाई। इन संकटग्रस्त देशों ने बाजार की वास्तविकताओं के आगे झुकना शुरू कर दिया। ताजा-तरीन घटना मिस्र की है, जहां अब्देल फतह अल-सिसी ने एक दशक तक सत्ता में रहने के बाद नवीनतम सुधारों की घोषणा की है। उनकी सरकार ने नई मेगा परियोजनाओं पर खर्च में कटौती करते हुए घाटे को कम करने के लिए कदम उठाए। मिस्र को इसलिए भी सुधारों के लिए मजबूर होना पड़ा है, ताकि आईएमएफ और विश्व बैंक से राहत पाने की शर्तें पूरी कर सके। यही हालत केन्या और अर्जेंटीना की है। अर्जेंटीना तो शेष चारों देशों की तुलना में और रसातल में चला गया था। उसे अपने बॉन्ड्स पर अधिकतम प्रीमियम चुकाना पड़ा था।

नतीजा ये रहा कि अर्जेंटीना सबसे ज्यादा जोर-शोर से सुधारों में लगा। पिछले नवंबर वहां नए राष्ट्रपति चुने गए थे- हावियर मिलेई। उन्होंने राष्ट्रीय मुद्रा का आधे से अधिक अवमूल्यन कर दिया है, सरकारी विभागों को आधा करके नौ कर दिया है, सार्वजनिक पेरोल को कम कर दिया है और सैकड़ों शासकीय कंपनियों को बेचते हुए निजी जेट और अन्य आधिकारिक भत्तों को खत्म कर दिया है। जनवरी में, वहां का बजट सरप्लस में रहा, जबकि 1900 के बाद के 10 वर्षों को छोड़ वहां हर साल घाटे का बजट पेश किया जाता रहा है।

यहां तक कि जिन देशों ने अंतरराष्ट्रीय राहत की मांग नहीं की थी- तुर्किये और नाइजीरिया- उन्हें भी

बजट-अनुशासन और बाजार की ताकतों पर ध्यान देना ही अंतिम नीतिगत विकल्प होता है, और इसे तभी अपनाया जाता है, जब कोई देश दिवालियेपन की कगार पर आ गया हो। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं इसी नीति का परिचय दे रही हैं।

पुनर्विचार के लिए मजबूर होना पड़ा। एर्दोआन के नेतृत्व में तुर्किये- जहां सुधार की ना के बराबर गुंजाइश मानी गई थी- ने टेक्नोक्रेट्स को काम पर रखा, जिन्होंने ब्याज दरों में 35% से अधिक की बढ़ोतरी की है, और अब वे अत्यधिक क्रेडिट वृद्धि पर अंकुश लगा रहे हैं।

अब इन पांचों देशों में पूंजी लौटने लगी है। दुनिया भर में कमजोर हो रहा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उनके लिए असामान्य रूप से लचीला है। बॉन्ड प्रीमियम अपने उच्चतम स्तर से कम से कम 40% गिर गया है। अर्जेंटीना के शेयरों में 60% की बढ़ोतरी हुई है। नाइजीरिया में काला बाजार की मुद्रा छूट गायब हो गई है, और मिस्र में भी यही हाल है। ये सच है कि राष्ट्र अक्सर संकटों में सुधार करते हैं और तूफान बीत जाने पर पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। इस दुष्चक्र से बचने के लिए ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता होती है, जो निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध हो। फिलहाल तो इन देशों में रिफॉर्म हो रहा है और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले की तुलना में बेहतर स्थिति में नजर आ रही है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

भास्कर खास

ब्रांड सक्सेस स्टोरी

एनवीडिया | टेक्नोलॉजी कंपनी, **कब बनी**- 1993, **मार्केट कैप**- 183 लाख करोड़ रु.

एनवीडिया : टेस्ला से गूगल तक...40 हजार कंपनियां इसकी चिप पर निर्भर

अगर सीपीयू या प्रोसेसर, कंप्यूटर और लैपटॉप का दिमाग है तो जीपीयू या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स एआई का दिमाग है। इन्हीं अत्याधुनिक चिप की मदद से दुनियाभर के सुपर कंप्यूटर्स, रोबोट्स और सेल्फ ड्राइविंग कार संचालित हो रही हैं। और यह चिप बनाने वाली कंपनी है, एनवीडिया। साल 2022 में दुनिया को हिलाकर रख देने वाले चैटजीपीटी को जिस सुपर कंप्यूटर पर प्रशिक्षित किया गया, उसमें एनवीडिया के दस हजार जीपीयू लगे हुए थे। टेस्ला, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एमेजॉन जैसी दिग्गज समेत कुल 40 हजार कंपनियां अपने एआई प्रोजेक्ट्स के लिए एनवीडिया की चिप पर निर्भर हैं। 183 लाख करोड़ रु. मार्केट कैप वाली यह कंपनी आखिर तीन दशक में कैसे इस मुकाम तक पहुंची, इस हफ्ते की ब्रांड स्टोरी में पढ़ते हैं।

माइक्रोसॉफ्ट, एपल के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है एनवीडिया

एनवीडिया के तीनों संस्थापकों में से जेनसेन हुआंग ही बीते दो दशकों से कंपनी का चेहरा हैं। कर्टिस ने 2003 में निजी कारणों का हवाला देते हुए रिटायरमेंट ले लिया था। वहीं मैलाचोस्की कंपनी में वरिष्ठ पद पर हैं। सीईओ जेनसेन हुआंग (6.52 लाख करोड़ रु. नेटवर्थ) की यह तस्वीर हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम की है, जहां वह नई चिप दिखा रहे हैं। कंपनी ने एआई के लिए विशेष ग्राफिक प्रोसेसर लॉन्च किए हैं। एक प्रोसेसर की कीमत 30 से 40 हजार डॉलर के बीच हो सकती है।

शुरुआत : गेमिंग के शौकीन तीन दोस्तों को रेस्तरां में आइडिया सूझा

साल 1993 में कैलिफोर्निया के डैनीस रेस्तरां में तीन नवयुवक जेनसेन हुआंग, क्रिस मैलाचोस्की और कर्टिस प्रीम बैठकर कॉफी पी रहे थे। तीनों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और गेमिंग में रुचि रखते थे। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और गेमिंग-मल्टीमीडिया के बाजार में थ्री-डी ग्राफिक्स लाने के लिए स्टार्टअप शुरू करने पर सहमति बनी। उस समय ये चिप एक कार्ड जैसी होती थीं, जिसे गेम खेलने वाले वाले लोग कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगाते थे। इससे थ्री-डी ग्राफिक्स बेहतर हुए। मैलाचोस्की बताते हैं, 1993 में ग्राफिक्स प्रोसेसिंग का कोई बाजार नहीं था। लेकिन हमें दिख रहा था कि आने वाले समय में इसकी लहर आ रही है। कंपनी ने 1995 में एनवी-1 चिप लॉन्च की। लेकिन यह असफल साबित हुई और दिवालिया होने तक की नौबत आ गई।

- माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स और सोनी प्लेस्टेशन के वीडियो गेम कंसोल में इस्तेमाल जीपीयू से ही एनवीडिया सबसे ज्यादा चर्चित हुई थी।

प्रयोगों के साल : ग्राफिक कार्ड यूएसपी रही, मोबाइल चिप में फेल

1990 से पर्सनल कंप्यूटर्स का सुनहरा दौर शुरू हुआ। इंटेल के प्रोसेसर्स का एकतरफा राज था। लेकिन एनवीडिया ने भविष्य भांपते हुए जीपीयू पर निवेश जारी रखा। साल 1999 में 'जीफोर्स 256' नाम से पहला ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) बाजार में पेश किया। इससे पैरेलल कंप्यूटिंग आसान हुई। साल 2006 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च में पाया कि जीपीयू, रेगुलर चिप की तुलना में कंप्यूटर के मैथ्स ऑपरेशन में तेजी ला सकते हैं। इसके बाद एनवीडिया ने सीयूडीए नाम से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पेश की और इसके माध्यम से बाजार को अपने ग्राफिक कार्ड की ताकत बताई। 2012 में इमेज को वर्गीकृत करने वाला एआई टूल एलेक्सनेट मार्केट में आया। इसने एनवीडिया के जीपीयू का इस्तेमाल किया था।

- एनवीडिया ने मोबाइल प्रोसेसर चिप में भी दांव लगाया था। लेकिन ज्यादा बैटरी उपयोग करने के कारण इसके प्रोसेसर मोबाइल में असफल साबित रहे।

मार्केट : एनवीडिया की 40 फीसदी कमाई टेक दिग्गजों से

एनवीडिया के सबसे बड़े कस्टमर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एमेजॉन और मेटा हैं। इन कंपनियों ने 2016 के पहले से डाटा सेंटर्स के लिए एनवीडिया चिप खरीदना शुरू कर दिया था।

- साल 2014 से गूगल की क्रोमबुक में एनवीडिया की चिप का इस्तेमाल हो रहा है।
- टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कारों में एनवीडिया की एआई चिप होती हैं। इसके अलावा टेस्ला एनवीडिया हार्डवेयर का भी इस्तेमाल करता है।
- मेटा, अपने एआई प्रोजेक्ट्स के लिए एनवीडिया से 6 लाख जीपीयू (एच100) खरीद रही है।
- माइक्रोसॉफ्ट अपने विभिन्न प्रोडक्ट्स में एनवीडिया की चिप का इस्तेमाल कर रही है।
- सीबी इनसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक मशीन लर्निंग में इस्तेमाल जीपीयू में 90 फीसदी एनवीडिया कंपनी के ही हैं।

- कंपनी की सबसे ज्यादा कमाई डाटा सेंटर्स से हो रही है। इसके बाद गेमिंग और फिर प्रोफेशनल विजुलाइजेशन से कंपनी सर्वाधिक कमा रही है।

50 लाख करोड़ रु. कमाई कर चुकी है इस वित्त वर्ष में, 183 लाख करोड़ रु. का मार्केट कैप है

45 लाख डेवलपर्स और कुल 40 हजार कंपनियां एनवीडिया की सेवाओं का इस्तेमाल करती हैं

400 से ज्यादा गेम्स और एप्लिकेशन एनवीडिया आरटीएक्स का इस्तेमाल करते हैं

26 हजार से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं कंपनी में, कुल 50 ऑफिस हैं दुनियाभर में इसके

72 हजार करोड़ रुपए शोध व विकास कार्यों पर खर्च किए कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 में

260% बढ़ चुके हैं शेयर के दाम पिछले एक साल में इसके, अभी 897 डॉलर है एक शेयर की कीमत

पीपुल भास्कर

चर्चा में | जस्टिस बी. वी नागरत्ना, सुप्रीम कोर्ट की जज

पिता के फैसले की भी समीक्षा कर रहीं जस्टिस नागरत्ना, बन सकती हैं पहली महिला सीजेआई

जन्म: 30 अक्टूबर 1962, पांडवपुरा, कर्नाटक
परिवार: पति- बी.एन. गोपाल कृष्ण, दो बेटियां- नयनतारा और प्रेरणा।
शिक्षा: दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ में डिग्री।

अपने फैसलों से चर्चा में रहने वाली जस्टिस नागरत्ना ने मोदी सरकार के नोटबंदी के निर्णय को कालेधन को सफेद करने का जरिया बताया है

साल 2009, कर्नाटक हाई कोर्ट में विरोध कर रहे वकीलों के एक समूह ने जस्टिस बी. वी नागरत्ना को एक अन्य जज और कर्नाटक हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस पी.डी दिनाकरन के साथ न्यायालय परिसर में ही कैद कर दिया। वकील चीफ जस्टिस दिनाकरन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विरोध कर रहे थे। तब पहली बार नागरत्ना ने सार्वजनिक रूप से कहा था 'हमें इस तरह दबाया नहीं जा सकता। हमने संविधान की शपथ ली है।' जज के रूप में बुलंद हुई यह आवाज तब से लगातार और ऊंची ही हुई है। फिर चाहे 2012 में समाचार चैनलों की सनसनी पर लगाम लगाने के लिए नियंत्रण की बात हो या फिर 2023 में नेताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर बिगड़ी हुई भाषा पर पार्टियों को गाइड लाइन बनाने की। उनकी अलग राय और फैसलों ने लोगों के बीच हमेशा सुर्खियां बटोरी हैं। एक चैनल से साक्षात्कार के दौरान काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा था कि 'एक कहावत है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, लेकिन मैं कहूंगी कि हर सफल महिला के पीछे एक परिवार होता है। मुझे अपने परिवार से पूरा सहयोग मिला है।

जस्टिस बीवी नागरत्ना वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की उस पीठ का हिस्सा हैं, जो राजस्व से जुड़े एक मामले में केंद्र और राज्यों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए 'औद्योगिक शराब' और 'नशीली शराब' के बीच अंतर स्पष्ट करने में लगी हुई है। 1989 में सात जजों की पीठ ने इस मामले पर फैसला दिया था, जिसमें उनके पिता और तत्कालीन सीजेआई ईएस वेंकटरमैया भी शामिल थे।

कर्नाटक में एक सम्मान समारोह के दौरान जस्टिस नागरत्ना

परिवार : सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं पिता

उनका पूरा नाम जस्टिस बी. वेंकटरमैया नागरत्ना है। उनका जन्म कर्नाटक के मांड्या जिले के पांडवपुरा में हुआ था। पिता ईएस वेंकटरमैया भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। जस्टिस नागरत्ना की 10वीं तक की पढ़ाई बेंगलुरू में ही हुई। उसके बाद की पढ़ाई दिल्ली से की। भारतीय विद्याभवन के मेहता विद्यालय से 12वीं के बाद स्नातक के लिए दिल्ली के जीसस एंड मेरी कॉलेज में दाखिला लिया। दिल्ली विवि से ही कानून में स्नातक किया है। उनकी शादी बीएन गोपाल कृष्ण से हुई है। गोपाल कृष्ण एमएस रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंस, बेंगलुरु में रजिस्ट्रार (प्रशासन) हैं। उनकी एक बेटी नयनतारा लॉ की प्रैक्टिस करती हैं जबकि दूसरी बेटी प्रेरणा फिल्म मेकर हैं।

करियर : 21 साल लॉ फर्म में काम किया, फिर बनीं हाईकोर्ट जज

जस्टिस बी.वी नागरत्ना ने 1987 में लॉ फर्म से करियर शुरू किया। वे फर्म से 21 साल तक जुड़ी रहीं। वकील के तौर पर उन्होंने प्रशासनिक, संवैधानिक, भूमि अधिग्रहण, सेवा, पारिवारिक और व्यावसायिक मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट, कई हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट में भी बहस की है। वे कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (केएसएलएसए) का भी प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। जज के तौर पर फरवरी 2008 में कर्नाटक हाईकोर्ट में एडिशनल जज के रूप में पारी शुरू की। फरवरी 2010 में वे स्थायी जज बनीं। 30 अगस्त 2021 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया । सबकुछ सही रहा तो वरिष्ठता के आधार पर 2027 में वे देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं। उनका कार्यकाल 24 सितंबर से 29 अक्टूबर 2027 तक लगभग 36 दिन रहेगा। इसके बाद वे रिटायर हो जाएंगी।

चर्चित फैसले/राय : बिलकिस बानो केस में दोषियों को दोबारा जेल भेजा

- 2002 के गुजरात दंगों में बिलकिस बानो से गैंगरेप के 11 दोषियों को जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की दो सदस्यीय बेंच ने यह कहते हुए वापस जेल भेज दिया कि सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है। पीड़ित की तकलीफ की चिंता करनी होगी। गुजरात सरकार ने दोषियों को रिहा कर दिया था।
- 2023 में मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच में जहां 4 ने अतिरिक्त पाबंदियों के लिए मना किया था वहीं नागरत्ना ने कहा कि सभी पार्टियों को यह तय करना होगा कि किसको क्या और कितना कहना है।
- कोविड-19 के दौरान कर्नाटक सरकार द्वारा कोविड प्रभावित क्षेत्रों में मिड-डे मील बंद करने के प्रस्ताव को उनकी बेंच ने निरस्त कर दिया था।
- कर्नाटक हाईकोर्ट में जज रहने के दौरान नाजायज संतानों को लेकर की गई टिप्पणी में कहा था कि नाजायज माता-पिता हो सकते हैं बच्चे नहीं।

कल्पमेधा

जो व्यक्ति काम करने के तरीके या उसका सिद्धांत समझे बिना अभ्यास करने लगता है, उसकी स्थिति ऐसे नाविक की तरह होती है, जिसे मालूम नहीं होता कि जाना किस दिशा में है।

– लिओनार्दो दा विंची

बेलगाम बदजुबानी

मुद्दों के आधार पर तर्कों के जरिए अपने प्रतिद्वंद्वी राजनेताओं के खिलाफ बयानबाजी करते हुए भाषा में तल्खी का इस्तेमाल अनुचित नहीं है, लेकिन अगर ऐसा करते हुए बदजुबानी या अभद्रता हावी होने लगे तो यह हर लिहाज से गलत है। अफसोसनाक यह है कि इस मसले पर अक्सर विवाद उभरने और ज्यादातर मामलों में माफी मांगने या सफाई देने की नौबत आने के बावजूद राजनीतिक शख्सियतों के बीच आरोप-प्रत्यारोप अक्सर बेलगाम बोल में तब्दील हो जाते हैं। न तो निजी स्तर पर अपनी सोच-समझ का ध्यान रखा जाता है, न ही चुनावों के संदर्भ में लागू आचार संहिता का। इससे एक ओर स्वस्थ बहस की स्थितियां बाधित होती हैं, वहीं कई बार ऐसी बातें बोल दी जाती हैं कि बाद में किसी मौके पर एक दूसरे का सामना करने में भी असहज होना पड़े। अपनी बात कहने के क्रम में नाहक ही किसी शब्द का इस्तेमाल करने से उभरे विवाद के बाद किसी नेता की ओर से सफाई के तौर पर भले यह कहा जाता है कि उनकी बातों को आधे-अधूरे संदर्भ में या फिर तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया, मगर सवाल है कि बिना किसी जरूरत के किसी को लक्षित करके वैसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है, जिसके लिए सफाई देना या माफी मांगना पड़े!

विडंबना यह है कि ऐसे असुविधाजनक हालात और उनके हश्र बार-बार सामने आने के बावजूद कुछ नेताओं को न तो अपने प्रतिद्वंद्वियों की और न अपनी गरिमा का खयाल रखना जरूरी लगता है। फिलहाल आम चुनावों का कार्यक्रम घोषित होने के बाद सभी राजनीतिक दल अपने-अपने स्तर पर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इस क्रम में कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने अपने भाषण में जिस तरह भाजपा की एक महिला नेता की गरिमा का हनन करने वाले शब्दों का प्रयोग किया, वह सिर्फ एक उदाहरण है कि कई वरिष्ठ नेता भी अपनी जुबान पर काबू रखना जरूरी नहीं समझते। जब अवांछित शब्दों से विवाद खड़ा हो गया और मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया तब सफाई के तौर पर सुरजेवाला ने कहा कि उनकी बातों को आधे-अधूरे तरीके से पेश किया गया। मगर सभी जानते हैं कि गैरजरूरी तरीके से कुछ बोल जाने के बाद इस तरह की सफाई का कोई मतलब नहीं होता। यह अकारण नहीं है कि इस मसले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया।

यह अकेला मामला नहीं है जिसमें किसी नेता ने अमर्यादित टिप्पणी की हो। अक्सर राष्ट्रीय पार्टियों के शीर्ष नेताओं के बोल भी बहक जाते हैं और किसी की गरिमा को चोट पहुंचा जाते हैं। अफसोसनाक यह भी है कि इस तरह बोलते हुए इसका खयाल रखना जरूरी नहीं समझा जाता कि किसी महिला को लक्ष्य बना कर अभद्र या मजाक उड़ाने की भाषा का प्रयोग करने का क्या असर पड़ता है। इस तरह की बदजुबानी से न केवल किसी अन्य नेता के सम्मान को चोट पहुंचती है, बल्कि ऐसी बातें बोलने वाले के व्यक्तित्व में छिपी कुंठा भी सामने आती है। सवाल है कि भाषणों में बदजुबानी या गलत तरीके से कुछ बोलने के जरिए चुनाव में जीत की कोशिश करने वाले नेता क्या अपना सम्मान इसी तरह सुनिश्चित करना चाहते हैं! आमतौर पर चुनाव आयोग भी ऐसा करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर कोई ठोस संदेश नहीं देता। लोकतंत्र में सहमति-असहमति एक जरूरी प्रक्रिया है। मगर इस क्रम में कोई भी नेता अगर किसी के खिलाफ अभद्र और अशिष्ट शब्द या लहजे का प्रयोग करता है, तो यह राजनीति में गिरावट का ही संकेत है।

बाधित शिक्षा

देश में शिक्षा की सूरत में सुधार के लिए समय-समय पर की जाने वाली तमाम कवायदों के बावजूद हालत यह है कि बहुत सारे बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। खासतौर पर जब किसी राज्य में संसाधनों की कमी न हो, फिर भी बहुत सारे बच्चे स्कूली पढ़ाई बीच में ही छोड़ रहे हों तो यह सोचने की जरूरत है कि नीतियां बनाने और उन्हें अमल में लाने के तौर-तरीकों में क्या खामी है। गौरतलब है कि हरियाणा में जब वर्ष 2023-24 में वार्षिक परीक्षा परिणाम के आधार पर विद्यार्थियों के आंकड़ों को अद्यतन किया गया तो यह दुखद तस्वीर सामने आई कि राज्य के सभी राजकीय स्कूलों में कक्षा पहली से ग्यारहवीं तक में पढ़ने वाले चार लाख चौंसठ हजार बच्चों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। अगर इन बच्चों ने पुराने स्कूल को छोड़ने के बाद कहीं और दाखिला नहीं लिया, तो जाहिर है कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। ऐसे बच्चे आमतौर पर अभावों से जूझ रहे परिवारों से आते हैं। यह छिपा नहीं है कि वंचित तबकों के बच्चे कितनी जद्दोजहद से गुजर कर स्कूल के परिसर में शिक्षा हासिल करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में अगर राजकीय स्कूलों से इतनी बड़ी तादाद में बच्चे बाहर निकल कर जीवन चलाने के लिए कोई अन्य रास्ता अख्तियार कर रहे हैं तो यह एक अफसोसनाक तस्वीर है।

सवाल है कि किसी भी वजह से अगर इतनी भारी संख्या में बच्चे स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर हो रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है! बीते कई दशक में सबसे ज्यादा जोर इस बात पर रहा है कि दूरदराज तक में स्थित ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्कूलों में दाखिला कराया जाए। इसका असर भी देखने में आया था। मगर अब आर्थिक और अन्य परिस्थितियों की वजह से अगर बच्चे स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ रहे हैं तो एक तरह से यह समूचे सरकारी तंत्र की विफलता है। इसमें विकास में असंतुलन की वजह से एक ऐसा सामाजिक तबका खुद को इस बात के लिए लाचार पा रहा है कि वह अपने बच्चों को स्कूल में बिना बाधा के पढ़ा-लिखा सके।

मनुष्य से संघर्ष करते वन्यजीव

वन्यजीवों सहित सभी तरह की पर्यावरण संबंधी चीजों की रक्षा करना और उनको बढ़ावा देना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। फिर अधिकार के लिए आंदोलित होने वाला मानव समाज क्यों अपने कर्तव्यों के निर्वहन से दूर भागता है?

सोनम लववंशी

देश के विभिन्न हिस्सों में हाथियों के हमले बढ़ रहे हैं। बीते दिनों झारखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में गुस्सैल हाथियों के उपद्रव की कई घटनाएं सामने आईं, जिनमें करीब दस लोगों की जान चली गई। आए दिन हाथी और इंसानों के बीच टकराव की घटनाएं देखी जा रही हैं। इसकी बड़ी वजह कहीं न कहीं हमारी बढ़ती लालसा है। आधुनिकीकरण के नाम पर हमने उनके आशियाने उजाड़ दिए हैं। जंगल सिमटने लगे हैं। यही वजह है कि हाथी अपनी भूख-प्यास मिटाने के लिए रिहाइशी इलाकों में आ रहे हैं। 2020-21 में हाथियों ने 545 लोगों की जान ले ली। बीते वर्ष हाथियों की नाराजगी के चलते करीब 605 लोगों को अपने प्राण गंवाने पड़े। ऐसा नहीं कि इन हमलों में केवल इंसानों की जान गई, पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों पर गौर करें तो करीब तीन सौ हाथियों की जान इंसानों ने ले ली। यह स्थिति तब है जब हाथियों को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया जा चुका है।

'डब्लूडब्लूएफ इंडिया' की 'द क्रिटिकल नीड आफ एलिफेंट' रपट के मुताबिक इस समय दुनिया में हाथियों की संख्या मात्र पचास हजार है, जिसमें साठ फीसद हाथियों का निवास भारत में है। दुनिया भर में हाथियों के संरक्षण के लिए गठित आठ देशों के संगठन में भी भारत शामिल है। बावजूद इसके, हाथियों पर संकट मंडरा रहा है। हाथी पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के लिए महत्त्वपूर्ण कड़ी हैं, मगर एक आरटीआइ के जवाब में पर्यावरण मंत्रालय ने बताया कि पिछले तेरह सालों में भारत के जंगलों में 1357 हाथियों की मौत हो चुकी है। इसका अर्थ है कि देश में हाथी संकट में हैं और कहीं न कहीं यह संकट मानवीय है। ऐसे में, सोचने वाली बात है कि हमारे देश में पेड़-पौधे, पशु-पक्षियों को पूजने की परंपरा रही है, तो अब क्यों हम पशु-पक्षियों से दूर होते जा रहे हैं? इसका जवाब है कि मानवीय संवेदना तेजी से क्षरित होती गई है। इंसान का बढ़ता लालच और विकास की चाह इस हद तक बढ़ गई है कि मानव अपने ही विनाश की वजह बनता जा रहा है। बढ़ती आधुनिकता और भौतिकतावाद मानव को क्रूर और निर्दयी बनाने को आतुर है।

इंसान के स्वार्थी हो जाने की सजा न सिर्फ वन्यजीव भुगत रहे हैं, बल्कि इससे पारिस्थितिकी असंतुलन भी पैदा हो रहा है। इसका दुष्परिणाम अब इंसानों को भी भुगतना पड़ रहा है। बीते दिनों केरल के वायनाड जिले में एक जंगली हाथी का घर में घुसकर इंसान की जान लेने का मामला मीडिया की सुर्खियां बना था। यह हादसा मानव-पशु संघर्ष की स्थिति बयान करता है। केरल वन विभाग की ताजा रपट में मानव-पशु संघर्ष की करीब नौ हजार घटनाएं दर्ज हुई हैं। इनमें चार हजार से ज्यादा मामले जंगली हाथियों से जुड़े हैं। 2018 में केरल में हाथियों के हिंसक होने को लेकर 'पेरियार टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन' ने एक अध्ययन किया। उसमें निष्कर्ष निकला कि जंगलों में अब पारंपरिक पेड़ नष्ट हो गए हैं और उनके स्थान पर

बबूल और नीलगिरी जैसे पेड़ लगाए जा रहे हैं। पेड़ों की ये किस्में जमीन से पानी भी अधिक सोख रही हैं। इससे हाथियों के लिए भोजन और पानी दोनों का संकट पैदा हो रहा है। अपनी भूख-प्यास मिटाने के लिए हाथी उग्र और हिंसक हो रहे हैं। इसके लिए हम निरीह

> **हमारे देश में पेड़-पौधे, पशु-पक्षियों को पूजने की परंपरा रही है, तो अब क्यों हम पशु-पक्षियों से दूर होते जा रहे हैं? इसका जवाब है कि मानवीय संवेदना तेजी से क्षरित होती गई है। इंसान का बढ़ता लालच और विकास की चाह इस हद तक बढ़ गई है कि मानव अपने ही विनाश की वजह बनता जा रहा है। बढ़ती आधुनिकता और भौतिकतावाद मानव को क्रूर और निर्दयी बनाने को आतुर है। इंसान के स्वार्थी हो जाने की सजा न सिर्फ वन्यजीव भुगत रहे हैं, बल्कि इससे पारिस्थितिकी असंतुलन भी पैदा हो रहा है। इसका दुष्परिणाम अब इंसानों को भी भुगतना पड़ रहा है।**

जानवर को जिम्मेदार मानते हैं, जबकि हकीकत यह है कि इस संघर्ष के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं।

एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक, देश में हाथियों की संख्या करीब तीस हजार है। आंकड़े बताते हैं कि 2014 से 2019 के बीच देश में पांच सौ हाथियों की अकाल मौत हो गई। वहीं 2012 से 2017 के बीच हाथियों की संख्या में दस फीसद तक कमी दर्ज की गई है। अगर हर पांच वर्ष में दस फीसद हाथी कम होते रहे, तो तीस हजार के करीब हाथियों की विलुप्ति में ज्यादा समय नहीं लगने वाला। जबकि गौर करने वाली बात है कि पर्यावरण मंत्रालय ने हाथियों की मौत की जो रपट आरटीआइ के माध्यम से दी, वह प्राकृतिक मौत नहीं है। रपट के अनुसार बीते तेरह वर्षों में 898 हाथी बिजली के तारों में उलझ कर मारे गए। इसके अलावा, हाथियों की मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण ट्रेनों की चपेट में आ जाना है। बढ़ते आधुनिकीकरण और लगातार बढ़ते नगरीकरण की वजह से अब रेल की पटरियां दुर्गम क्षेत्रों तक बिछ गई हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में हाथियों की मौत ट्रेन की चपेट में आने से होती है। आरटीआइ से मिली जानकारी के मुताबिक, पिछले तेरह वर्षों में 191 हाथियों की मौत शिकारियों के हाथों हुई। शिकारी हाथी दांत की चोरी के लिए हाथियों को मार देते हैं। कुछ समय पहले मलप्पुरम में एक गर्भवती हथिनी की निर्मम हत्या ने मीडिया जगत में खूब सुर्खियां बटोरी थी। कुछ लोगों ने उस हाथी को जानबूझ कर पटाखों से भरे फल खिलाकर मौत के घाट उतार दिया था। वह कोई पहली घटना नहीं थी, जब नागरिकों ने जानवरों की हत्या की। आंकड़ों के मुताबिक, 191 नर हाथियों को जानबूझ कर मार दिया गया। इस पर वनरक्षक खामोश रहे, तो कई सवाल उठने स्वभाविक हैं। वैसे तो जंगलों से गुजर रही रेल लाइनों का विद्युतीकरण और गाड़ियों की तेज रफ्तार हाथियों की आकस्मिक मौत की बड़ी वजह हैं।

हाथियों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने बासठ नए 'एलिफेंट कारिडोर' को मंजूरी दी है। अब एलिफेंट कारिडोर की संख्या बढ़कर 150 हो गई है। यह वन्यजीव संरक्षण की दिशा में महत्त्वपूर्ण पहल है। चूंकि हाथी हमारा 'राष्ट्रीय विरासत पशु' है और तीन राज्यों- झारखंड, कर्नाटक और केरल सरकार ने हाथी को 'राजकीय पशु' की मान्यता दी है, इसके संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। वरना, मानव-वन्यजीव टकराव का सबसे भयावह प्रभाव झेलने को हमें तैयार रहना होगा। इसका एलान मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व पर जारी 'वर्ल्ड वाइल्ड फंड' और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की संयुक्त रपट में पहले ही किया जा चुका है।

वैसे भी देखा जाए तो संविधान सिर्फ मानव को जीवन जीने की स्वतंत्रता नहीं देता, बल्कि अनुच्छेद 48 (ए) में कहा गया है कि राज्य का दायित्व है कि वह पर्यावरण संरक्षण तथा उसको बढ़ावा देगा और देश भर में जंगलों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए काम करेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 51(ए) कहता है कि जंगल, तालाब, नदियों, वन्यजीवों सहित सभी तरह की प्राकृतिक पर्यावरण संबंधी चीजों की रक्षा करना और उनको बढ़ावा देना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। फिर अधिकार के लिए आंदोलित होने वाला मानव समाज क्यों अपने कर्तव्यों के निर्वहन से दूर भागता है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तक सह-अस्तित्व की भावना नहीं होगी, मनुष्य और वन्यजीवों के बीच टकराव कम नहीं होने वाला।

जिजीविषा की राह

संदीप पांडे 'शिष्य'

दुनिया मेरे आगे

उत्सव कभी भी आडंबर का मोहताज नहीं है। खूब तड़क-भड़क और खोखले शोर का नाम उत्सव नहीं है। उत्सव तब भी है, जब एक कचरे वाला एक ट्रक कचरा भरकर ले जाता है और उसे एक नियत जगह खाली करता है। जीवन हर पल ही एक जश्न है। ऐसी तितलियां भी होती हैं, जो रेगिस्तान में भी पंख फैलाकर उड़ती रहती हैं। बहुत छोटी-सी जिंदगी होने के बावजूद जीवन पूरा होने से पहले वे तितलियां कैसे अपने लिए नखलिस्तान खोज पाती हैं? वैज्ञानिकों का कहना है कि वे अपने शरीर के भीतर नई कोशिकाएं बनाने और ऊर्जा देने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं को बदल लेती हैं। वैज्ञानिक शब्दावली को छोड़ दें तो वे तितलियां यह मानती हैं कि मुझे जरा-सा और उड़ कर जाना होगा और पास ही कहीं मेरे लिए एक फूलों की घाटी जरूर होगी। फिर फूल और गुलशन से उसकी मुलाकात होती भी है। तब वह तितली पिछला सब कुछ भूल कर जश्न और उत्सव में डूब जाती है। यहां तक कि उसको अंतिम सांस का आभास तक नहीं होता है। यही है असली समझ। लोगों को नहीं मालूम कि हमारा जीवन इतना नीरस इसलिए है कि यहां कोई आशा पैदा नहीं हो रही। हम सोचते हैं, विधि का विधान है!

हम अपने जीवन में यही सोचते हैं कि अमुक सुखी है, क्योंकि वह धनवान है। हकीकत यह है कि सबके पास खुशी और ऊर्जा का अथाह भंडार समान रूप से भरा हुआ है। पर हम इस बात से अनजान हैं। गांठ बांध लेना चाहिए कि हमारी जिंदगी में भी गुलशन को आना है। यह मन की तितली एक दिन जीवन रूपी बगीचे को हरा-भरा कर देगी। इसके बाद उस सुगंध को महसूस किया जा सकेगा। यही है असली जानना... जीवित होने के अवसर को समझना। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने सोने का थाल त्याग कर पत्तल में आहार लिया। जो विरासत मे मिला, उसे अपना नहीं माना। अपनी चेतना को विकसित किया और ऐसी साधना करते चले कि अभाव का भी भरपूर उमंग से जश्न मनाया।

अब तक तो हमारे पास वह तराजू है, जो किसी और ने दिया है। इसके एक पलड़े में हम और दूसरे पलड़े में अन्य चीजों को रखकर एक संतुलन बनाने की कोशिश हुई। अगर हम अपने अंदर स्थित सच्चाई को देखना चाहें तो भीतरी समझ का तराजू लेना ही होगा। हमेशा बाहरी जगत ही हमको सिखाने और परिपक्व बनाने का काम नहीं करता है। हमारी सारी समझ और हमारे उत्साह की सदैव ही एक अलग दुनिया है। वह है चेतना की दुनिया। रिमझिम हो तो नाचने लगना या गीत गुनगुना देना। दौलत के ढेर की बनिस्पत हरा-भरा आंगन देखकर खुश हो जाना। इस समझ का आलम है कि वह चाहती है जीवन में इस तरह की सरलताएं बनी रहें। मगर जो लोग भौतिकता मे भरे हुए इस जिंदगी का बोझ ढोते हैं, उन्हें उदास होने से कौन रोक सकता है।

किसी की मदद करना जीवन का सबसे बड़ा सुख है। अगर हम परेशान हैं, तो कोशिश करें कि अपने आसपास किसी जरूरतमंद का सहारा बनें। चाहे हमारी घरेलू सहायिका हो, माली हो या चौकीदार या फिर जरूरतमंद बच्चे। इसके अलावा किसी समाजसेवी कार्यों से जुड़कर भी जीवन को एक नई पहचान दी जा सकती है, जिससे असीम सुख की प्राप्ति होगी। घर पर या कार्यस्थल पर किसी से हुआ मनमुटाव हमें कई दिनों तक परेशान रखता है। हम उस छोटी-सी बात को इतनी गहराई से सोचते हैं कि मन ही मन परेशान रहने लगते हैं। नतीजतन, घर में बच्चों या जीवनसाथी पर कई बार बेवजह झल्ला जाते हैं। यह धीरे-धीरे हमारे रिश्तों में कड़वाहट का कारण भी सिद्ध हो सकता है। ऐसे में अगर किसी ने कुछ कहा, तो उस बात को वहीं खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए और मन ही मन उस शख्स को कोसने की बजाय उसे माफ कर देना चाहिए। पंछी को दाना दे दिया जाए... उपवास का आनंद लिया जाए।

यह सच है कि इस जगत में अब भी कुछ लोग बचे हुए है जो बैंक में जमा पैसे या फिर बंगले वाहन की लाइन लगाकर धनाढ्य नहीं बनना चाहते। ऐसे लोग टिकट कटा कर पुरानी जगहों की यात्राएं करते हैं और आधुनिक हुए शहर में पुराने शहर और लोगों को खोजते रहते हैं। उन लोगों में इतनी खूबसूरती होती है कि संसार ऐसे लोगों के कारण बचा हुआ है। जे कृष्णमूर्ति यही कहते हैं कि हो सकता है पूरी जिंदगी लोग तुमसे यह कहते रहे हों कि तुम कितने अधूरे हो। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम एकदम पूर्ण हो। हो सकता है, लोगों ने तुम्हें यह बताने की कोशिश की हो कि तुम्हारी चीजें अवास्तविक हैं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम वास्तविक हो। यह शरीर मिट्टी का बना है और यह मिट्टी एक दिन फिर मिट्टी में मिल जाएगी।

> **जीवन के बगीचे में उन बीजों को बो देना चाहिए और उन्हें हृदय के फूलों के रूप में खिलते व विकसित होते हुए देखना चाहिए। एक दिन आएगा, जब सांसों की यह बारिश बंद हो जाएगी। उस समय के आने के पहले ही अपनी समझ और स्पष्टता के बीजों को बो देना चाहिए।**

इस बारे में किसी को सोचना भी अच्छा नहीं लगता। पर यह सच्चाई की याद दिलाता है। सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है। सांस की यह बारिश अपनी इस देह पर बिना रुके लगातार हो रही है। जीवन के बगीचे में उन बीजों को बो देना चाहिए और उन्हें हृदय के फूलों के रूप में खिलते व विकसित होते हुए देखना चाहिए। एक दिन आएगा, जब सांसों की यह बारिश बंद हो जाएगी। उस समय के आने के पहले ही अपनी समझ और स्पष्टता के बीजों को बो देना चाहिए। जब इस जीवन रूपी, देह रूपी मिट्टी पर सांस रूपी बारिश गिरना बंद हो जाती है तो यह फिर एक रेगिस्तान बन जाता है। इसे ऐसा नहीं बनने देना चाहिए। इसका बेहद सरल समाधान है एक अच्छा नजरिया और अपनी एक सुलझी हुई सोच।

भूख और भोजन

संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रपट दुनिया भर में पर्याप्त खाद्य उत्पादन और उपलब्धता के बावजूद अस्थिर भोजन बर्बाद करने की आदतों के कारण भोजन के दुरुपयोग के संबंध में कुछ आवश्यक पहलुओं को रेखांकित करती है। 2022 में 1.05 बिलियन टन भोजन की बर्बादी हुई, जो प्रति व्यक्ति 132 किलोग्राम है। दूसरी ओर, लगभग 78.3 करोड़ लोग भूख से जूझते हैं और 19 फीसद खाना बर्बाद हो जाता है। रपट ने कुछ मिथों को भी तोड़ा है। जैसे कि भोजन की बर्बादी एक समृद्ध देश की समस्या है। भारत संसाधनों तक असमान पहुंच से भी जूझ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप भोजन का एक तिहाई हिस्सा उपभोग से पहले बर्बाद या खराब हो जाता है। लोगों को भोजन की बर्बादी के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल शून्य अपशिष्ट दिवस आता है। इससे दुनिया को अपशिष्ट शमन पर कदम उठाने के लिए सामूहिक कार्रवाई के लिए प्रेरित होना चाहिए और उत्पन्न अधिशेष को अफ्रीकी और एशियाई देशों की ओर मोड़ना चाहिए जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं और अल्पपोषित हैं और भोजन की कमी से जूझ रहे हैं।

– विजय सिंह अधिकारी, नैनीताल

पढ़ाई के नाम पर

देश में युवा बेरोजगारों की भीड़ है। तमाम युवा नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटकने को मजबूर है। जितनी भी सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन होता है, उनमें अक्सर शिक्षा माफिया हावी होते दिख जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अनैतिक कार्य करने के बाद भी बच निकलने में सक्षम कई लोग हैं, जो विभिन्न कानूनी और नैतिक मानदंडों का उल्लंघन करते हैं। कई बार नकल के कारोबार हिस्सा रहने के कारण कुछ लोगों को बच निकलने के रास्तों का पता होता है। कुछ निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के विभिन्न हथकंडों में शामिल हैं- फीस में बेहिसाब वृद्धि करना, अपने 'ब्रांड' के नाम के इस्तेमाल की भारी कीमत वसूलना और ब्रांड का उपयोग करने वालों को तंग करना। कुछ निजी शिक्षण संस्थानों पर शिक्षा की गुणवत्ता का प्रचार करके मोटी रकम लेकर डिग्रियां बेचने का आरोप भी लगते रहे हैं। शिक्षा माफिया हर साल हजारों छात्रों को अपने जाल में फंसाकर उनका भविष्य बर्बाद कर रहा है।

– योगेंद्र गौतम, उन्नाव

मन की भाषा

अगर किसी का मन पढ़ना हो तो आंखें पढ़ें। हर इंसान की आंखों में उसके मन की भाषा का सीधा प्रसारण चलता रहता है। जिसके मन में चोर होता है, वे नजरें मिला कर बातें नहीं करते। अक्सर हम सभी ऐसा करते हैं, जब दिल में कुछ और हो और जुबान पर कुछ और, तो हम सब अपनी नजरें चुराने से नहीं चूकते। आंखें माध्यम हैं किसी के प्रति प्रेम या ईर्ष्या भांपने के लिए। आंखों में नफरत देख कर भी जब हम किसी के फरेब को नहीं पढ़ पाते है तो समझिए वहां हमारा हृदय हावी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अपनी शब्दावली को आसानी के साथ तेजी बढ़ाने के लिए जरूरी है कि उसे खास चीज से जोड़ कर देखा जाए। बहुत-सी तारिख, अंक और बहुत से फोन नंबर याद रखने वाले लोग ऐसा ही करते हैं। यानी अपने में उसे किसी खास चीजों से जोड़ कर उसे क्रम में सजा लेते हैं।

– रानी प्रियंका वल्लरी, बहादुरगढ़,

सेहत की खातिर

नकली और मिलावटी दवाओं के खिलाफ लड़ाई एक सच्चाई के साथ जुड़ी है- स्वास्थ्य की रक्षा मुख्य मकसद है। यह विवादग्रस्त विषय अब एक नई दिशा में बदल रहा है, जहां साधारण लोगों की सेहत के प्रति सावधानी और संज्ञान लेने का महत्त्व बढ़ रहा है। नकली दवाओं के विरुद्ध लड़ाई में हमें समूह चरणबद्धता का सहयोग अपनाना होगा। लोगों को उनकी सेहत के मामले में शिक्षित करना होगा। इसके लिए सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रम, सोशल मीडिया, अखबारों और टीवी जैसे माध्यमों का सहयोग लेना होगा। दूसरा कदम, सामूहिक अभियान चलाना है। इससे समाज में एक साथ आने का अहसास होगा और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर समस्याओं के समाधान का उचित विकल्प को तलाश कर पाएंगे। तीसरा कदम, सबको साथ मिलकर दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए काम करना होगा।

– अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़, उप्र

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid
www.readwhere.com

वैश्विक आतंकवाद का बढ़ता खतरा

मास्को के बाहर आईएसआईएस-के के हमले की दुनिया भर में निन्दा हुई है। इससे दुनिया भर में आतंकवाद के बढ़ते खतरे के प्रति चिन्ता प्रकट हुई है।

सुधीर हिंदवान
(लेखक, रणनीति विशेषज्ञ हैं)

मॉस्को के बाहर आईएसआईएस-के के हमले की दुनिया भर में निन्दा हुई है। इससे दुनिया भर में आतंकवाद के बढ़ते खतरे के प्रति चिन्ता प्रकट हुई है। मास्को के बाहर हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस-के, यानी खुरासान ने ली है। इस हमले में 130 से ज्यादा लोगों की मौत हुई तथा 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसकी कठोरतम वैश्विक निन्दा तथा ऐसे हमलों के खिलाफ कार्रवाई की आवश्यकता उजागर हुई है। 'खुरासान' आईएसआईएस से अलग हुआ आतंकी समूह है जिसकी जड़ें ईरान, तुर्कमानिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हैं। इस आतंकी हमले ने दुनिया को चार सबक दिए हैं। पहले का संबंध आतंकी हमलों पर होने वाली राजनीति से है। थामस हाब्स ने 'लेवियाथन' में कहा है कि यह व्यापक रूप से मनुष्यों की प्रकृति, लालच और भय से जुड़ा है जो टकरावों को जन्म देता है। विश्व स्तर पर भू-राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद आज भी सत्ता का वैसा ही संघर्ष बना हुआ है जिसके कारण प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वाले युग में गैर-राज्य कारकों की गतिविधियां बढ़ी हैं जिनको शीतयुद्ध तथा इसके बाद होने वाले अनेक टकरावों ने बढ़ावा दिया है। दूसरे, आंतरिक टकरावों में विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप के कारण दुश्मनी बढ़ती है तथा आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। इसका एक उदाहरण रूस द्वारा आईएसआईएस के खिलाफ कार्रवाई में सीरिया की असद सरकार का रूस द्वारा समर्थन है। इसके कारण आईएसआईएस आतंकी समूह को बढ़ावा मिला। तीसरे, हो सकता है कि किसी समय अंतरराष्ट्रीय आतंकी समूह निष्क्रिय दिखें, पर वे बाद में नई ऊर्जा के साथ पुन: उभर सकते हैं। इसका उदाहरण मध्य एशियाई गणतंत्रों में आतंकवादी समूहों के गोपनीय संपर्क हैं।

इसके साथ ही आंतकी समूहों के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता उजागर होती है। आईएसआईएस जैसे आतंकी समूहों के खिलाफ बदले की किसी कार्रवाई में पड़ोसी देशों का सहयोग जरूरी है ताकि उनको बढ़ने से रोका जा सके। मास्को के बाहर हुआ हालिया आतंकी हमला रूस में हुए पुराने आतंकी हमलों की याद दिलाता है। इनमें 2002 में मास्को थियेटर बंधक संकट तथा 2004 में काकेशस में हुई बंधक त्रासदी शामिल हैं। हालिया आतंकी हमले ने रूसी सुरक्षा व्यवस्था की अंतर्निहित कमियां रेखांकित की हैं। इन कमियों के चलते आंतकी समूह मीडिया पर अधिकाधिक प्रभाव डालने के लिए अपने द्वारा निर्धारित समय और स्थान पर हमला करने में सफल होते हैं और इसका लाभ उठाते हैं।

इस आतंकी हमले की विश्व स्तर पर हुई आलोचना से स्पष्ट है कि अंतरराष्ट्रीय आतंक का मुकाबला करने के प्रति व्यापक चिन्ता विद्यमान है। भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद अमेरिका ने दुनिया भर में आतंकी हमलों से पैदा खतरों से निपटने की आवश्यकता जताई है और उसके प्रति प्रतिबद्धता प्रकट की है। लेकिन दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच वर्तमान समय में व्याप्त विश्वास के संकट के कारण आतंकवाद-विरोधी संघर्ष में सहयोग करने में बाधा आती है। रूस ने हालिया हमले में यूक्रेन का हाथ होने का आरोप लगाया था। हालांकि, यूक्रेन ने इसमें अपनी किसी प्रकार की संलिप्तता से इनकार किया है, पर संघीय सुरक्षा एजेंसी-एफएसबी को संदेह है कि हमला करने वाले आतंकियों का संबंध यूक्रेन से हो सकता है। ऐसे आरोप-प्रत्यारोप से आंतकवाद के खिलाफ वैश्विक संघर्ष में बाधा आती है। मध्य एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव क्षेत्रीय राजनीति को और जटिल बना रहा है। मध्य एशियाई गणतंत्रों-सीएआर को लगातार आतंकी खतरों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अनेक गैर-राज्य कारक अपने दुष्टतापूर्ण उद्देश्यों के लिए विभिन्न देशों की जनता के बीच सांस्कृतिक संबंधों का लाभ उठाते हैं। इससे आतंकवाद से मुकाबला करने में बहु-स्तरीय सुरक्षा सहयोग तथा तकनीकी खोजों के प्रभावी उपयोग की आवश्यकता उजागर होती है। खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों के बावजूद गलत तरीके की धार्मिक व्याख्याओं के कारण आतंकवादियों से निपटने में समस्यायें बनी हुई हैं। पड़ोसी देशों से आने वाले शरणार्थी भी सुरक्षा परिदृश्य में जटिलतायें पैदा करते हैं। सहयोग के माध्यम से आतंकवाद का मुकाबला करना क्षेत्रीय स्थायित्व के लिए उम्मीद पैदा करता है।

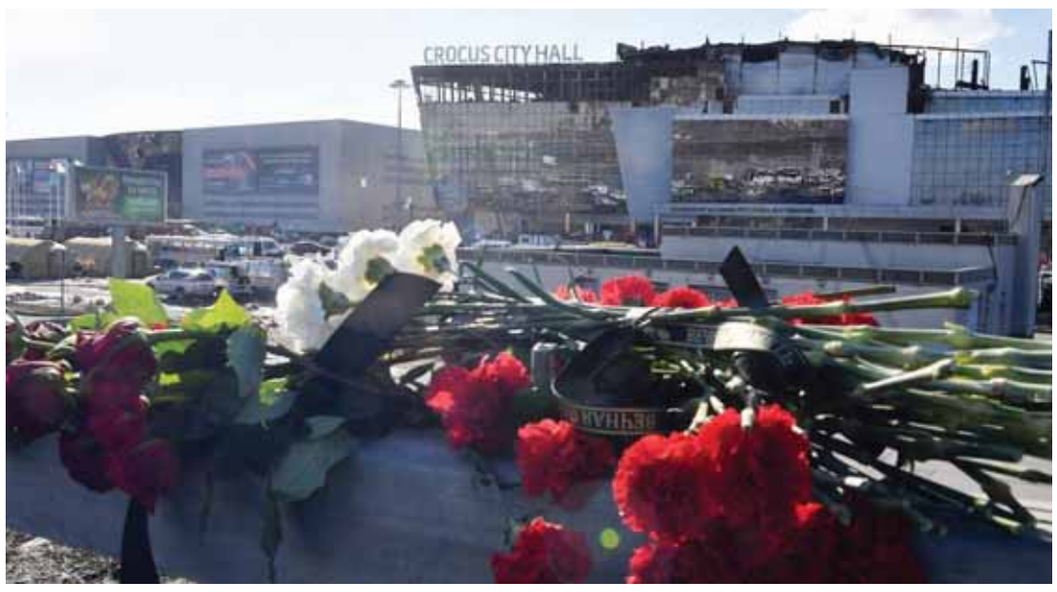

आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए हुई समरकंद बैठक ऐसे सहयोग का उदाहरण है। लेकिन आर्थिक असमानताओं तथा सरकारी नीतियों में निरंतरता के अभाव से इस क्षेत्र में आतंकी खतरा और गंभीर होता है। 'हिज्ब-उत-तहरीर' जैसे इस्लामवादी आतंकी संगठनों की उपस्थिति के कारण सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा होती हैं। आतंकवाद-विरोधी अभियानों के बावाजूद मध्य एशियाई देशों ने ईराक, अफगानिस्तान व सीरिया जैसे संकटग्रस्त क्षेत्रों में आतंकवाद के निर्यात के प्रयास भी किए हैं। अवैध आप्रवासियों की संख्या में भारी वृद्धि तथा उनकी बढ़ती आतंकी गतिविधियों ने चीन और रूस को अनेक देशों में फैले आतंक का मुकाबला करने में सहयोग को मजबूर किया है। मध्य एशिया में बढ़ता रूढ़िवाद एक अंतरराष्ट्रीय यथार्थ है जिसे असंतुष्ट समूहों तथा बाहरी प्रभावों से और बढ़ावा मिलता है। मध्य एशिया का रणनीतिक महत्व तथा इसके समृद्ध संसाधन इसे वैश्विक सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण बना देते हैं।

रूस और सीएआर में आर्थिक सशक्तीकरण तथा सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए समन्वित कार्रवाई तथा परस्पर सहयोग की आवश्यकता है। इससे अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को जन्म लेने और फलने-फूलने से रोकने में सहायता मिलेगी। आर्थिक परिवर्तन व सशक्तीकरण के लिए मुद्रास्फीति से मुकाबला करना तथा जीवन्त आतंकवाद-विरोधी व्यवस्थाओं का विकास करना जरूरी हो गया है। यह पहचान करने की नितान्त आवश्यकता है कि कानून-व्यवस्था और आतंकवाद में अंतर जरूरी है, लेकिन अक्सर ये दोनों मुद्दे एक-दूसरे से मिल जाते हैं।

नीति निर्माताओं को यह अवश्य समझना चाहिए कि आज देशों के समक्ष उपस्थित विभिन्न सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए उपयुक्त रणनीतिक नीतियां अपनाना जरूरी हो गया है। वर्तमान समय में आतंकवादी अत्यधिक संगठित तथा पेशेवर हैं। वे आधुनिकतम तकनीकों से स्वयं को लैस करने तथा अपनी आवश्यकतानुसार उनका अधिकतम प्रयोग करने या उनमें अनुकूल परिवर्तन को तत्पर रहते हैं। इसके देखते हुए सुरक्षा रणनीतियों में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है। सुरक्षा एजेंसियों को ज्यादा सतर्क बनाने तथा खुफिया पुलिस व अर्धसैनिक बलों को ज्यादा प्रभावी बनाना जरूरी हो गया है। हालांकि, विभिन्न समितियों की संस्तुतियों का वर्तमान यथार्थ से संगति में होना जरूरी नहीं है। यह बात खासकर भारत के आतंकवाद, नक्सलवाद व विद्रोही गतिविधियों से निपटने के मामले में सही है।

अब आतंकवाद को केवल सामाजिक स्थितियों या ढांचागत समायोजनों से जोड़ना ठीक नहीं है। इसके बजाय उन मनोवैज्ञानिक तत्वों का गंभीर विश्लेषण किया जाना चाहिए जो आतंकवाद को प्रेरित करते हैं। इस प्रकार के गंभीर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से हम आतंकवाद के बारे में ज्यादा गहरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी प्रभावी आतंकवाद-विरोधी रणनीतियां बनाने और उनके आधार पर प्रभावी तात्कालिक कदम उठाने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगी। हमें आतंकवाद, संगठित अपराधों, हथियारों के सौदागरों, नशे के व्यापारियों तथा स्मगलरों के वित्तीय संपर्कों को समझना जरूरी होगा। इन तत्वों के वित्त पोषणों को समझना उनके खिलाफ कार्रवाई के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ऐसे क्षेत्रों में आतंकवाद से मुकाबले के लिए विशेष बल भेजे जाने चाहिए जहां हिंसा की प्रवृत्ति रही है।

विभिन्न देशों के बीच सहयोगी प्रयास अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए जरूरी हैं। इन प्रयासों में संयुक्त राष्ट्रसंघ की प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने में भारत केन्द्रीय भूमिका निभा सकता है। नीति निर्माताओं को सुरक्षा खतरों की बदलती प्रकृति पहचान कर उसके अनुरूप नीतियां बनानी चाहिए। सतर्क खुफिया, पुलिस व अर्धसैनिक बलों का नेटवर्क आधुनिक आतंकियों द्वारा प्रयुक्त संवदेनशील रणनीतियों का मुकाबला कर सकते हैं। आतंकवाद विरोधी संघर्ष में अपने संसाधनों और विशेषज्ञता के साथ सहयोग कर अमेरिका और भारत केन्द्रीय भूमिका निभा सकते हैं।

विस्तारा एयरलाइन
समस्याओं का सामना

विस्तारा एयरलाइन को कर्मियों की कमी के कारण उड़ानों में व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है। टाटा समूह की विस्तारा एयरलाइन्स अपनी उत्कृष्ट सेवाओं तथा विश्वसनीयता के लिए भारतीय विमानन क्षेत्र में लोकप्रिय रही है। लेकिन हाल में वह उड़ानें रद्द होने या उनमें विलम्ब के कारण परेशानियां झेल रही है। 'विस्तारा' टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइन्स के बीच संयुक्त उद्यम है जो कर्मियों की कमी के कारण व्यवधान का सामना कर रहा है। इसके कारण यात्री एक जगह फंस जाते हैं और उनको असुविधा होती है। इनमें से कुछ को जल्दी से अपनी यात्रा योजनायें बदलने में कठिनाई होती है। विस्तारा की समस्यायें ऐसे समय सामने आई हैं जब विमानन क्षेत्र कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के प्रभाव से उबर रहा है तथा घरेलू उड़ानों में पुनर्जीवन के संकेत मिलने लगे हैं। विमानन उद्योग बढ़ती मांग पूरी करने के लिए अपनी गतिविधियां बढ़ाने तथा आपरेशनल बाधाओं और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच नाजुक संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है। कर्मियों की कमी से संकट का सामना कर रहे विस्तारा ने यात्रियों को आश्वस्त किया है कि वह इस मुद्दे को संबोधित करने तथा उड़ान सेवाओं में बाधाओं को न्यूनतम करने पर ध्यान दे रहा है। एयरलाइन सक्रिय रूप से नए कर्मियों की भर्ती कर उन्हें प्रशिक्षण दे रही है ताकि उसका कार्यबल आपरेशनल आवश्यकताओं के अनुरूप बन सके। उड़ानें रद्द होने या उनमें विलम्ब के कारण प्रभावित यात्रियों के लिए विस्तारा ने पुन: बुकिंग या टिकटों की पुन: फंडिंग के विकल्प दिए हैं। इसके साथ ही वैकल्पिक उड़ान व्यवस्थाओं के रूप में भी

सहायता दी जा रही है। एयरलाइन ने पुन: जोर दिया है कि वह यात्रियों को संतुष्ट रखने तथा व्यवधानों के कारण पैदा असुविधाओं को न्यूनतम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस स्थिति में नागरिक उड्डयन के महानिदेशक-डीजीसीए ने हस्तक्षेप कर एयरलाइन से उसकी उड़ान कार्रवाइयों, कर्मियों की उपलब्धता तथा यात्रियों पर व्यवधानों का प्रभाव समाप्त करने के उपायों की दैनिक रिपोर्ट मांगी है। कर्मियों की कमी का मुद्दा खासकर कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद विमानन उद्योग की बदलती परिस्थितियों में एयरलाइन द्वारा अपने कार्यबल प्रबंधन की समस्या से जुड़ा है। घरेलू उड़ानों में बाधायें आई हैं जिनमें छंटनी, 'फर्लाग' तथा यात्रा मांग पैटर्नों में परिवर्तन शामिल हैं जिनके कारण यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकरण से प्रभावी कार्यबल प्रबंधन तथा आकस्मिक नियोजन की आवश्यकता उजागर होती है ताकि एयरलाइनें अपनी उड़ानें सहज व निर्बाध रूप से जारी रख सकें। विमानन उद्योग वर्तमान समय में वैश्विक महामारी से पैदा चुनौतियों से निपट कर उभर रहा है, ऐसे में जीवन्त व उपयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त कार्यबल बनाए रखना जरूरी है ताकि यात्रियों की बदलती आवश्यकताओं की पूर्ति कर विमानन क्षेत्र का समुचित विकास सुनिश्चित किया जा सके। डीजीसीए को भी इसे प्राथमिकता मानना चाहिए। विस्तारा अब कर्मियों के संकट से जूझते हुए विमानन गतिविधियों में सामान्य स्थिति बनाने का प्रयास कर रही है। यह विमानन उद्योग की जटिल व परिवर्तनशील प्रकृति के लिए भी एक चेतावनी है। विभिन्न एयरलाइनों, नियामकों तथा साझीदारों के बीच प्रभावी सहयोग चुनौतियों से जल्दी निपटने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि विमानन इकोसिस्टम बिना किसी बाधा के सुचारु रूप से काम करता रहे।

स्वच्छ जल के लिये टिकाऊ समाधान

"स्वच्छ जल तक पहुंच, संघर्ष, सहयोग और जलवायु परिवर्तन के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है; सबके लिए पानी जरूरी है।"

पूनम सेवक
(लेखिका, सेफ वाटर नेटवर्क इंडिया से जुड़ी हैं)

इस वर्ष विश्व जल दिवस की थीम शांति के लिए जल है। यह स्वच्छ, सुरक्षित और किफायती पेयजल पर दुनिया के फोकस और संघर्ष, सहयोग और जलवायु परिवर्तन के साथ इसके जटिल संबंधों को नवीनीकृत करता है। दुनिया भर में लगभग 2 अरब लोगों को अभी भी सुरक्षित पानी उपलब्ध नहीं है।

भारत भी, प्रत्येक घर में नल के पानी के वादे के साथ अपने नागरिकों की पानी की जरूरतों को पूरा कर रहा है, खासकर पिछले दशक में, जहां भारत के 75 प्रतिशत घरों तक पाइप से पानी की पहुंच हो गई है। समुदाय-आधारित जल उपचार संयंत्र ऐसी नागरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूजल को शुद्ध करने में मदद करते हैं। विकेंद्रीकृत सुरक्षित जल उद्यम (एसडब्ल्यूई), जिन्हें लोकप्रिय रूप से वाटर एटीएम कहा जाता है, ने गुणवत्ता से प्रभावित समुदायों और उपभोक्ताओं के लिए कम लागत, 24×7, सुरक्षित पेयजल पहुंच समाधान प्रदान किए हैं।

2018 में, हरियाणा अपने शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर हर 400 मीटर पर एक वाटर एटीएम लगाने की नीति विकसित करने वाला पहला राज्य बन गया। दिल्ली सरकार ने 2023 में झुग्गी-झोपड़ियों और अन्य घनी आबादी वाले इलाकों में 500 ऐसे ही वाटर एटीएम लगाने की भी घोषणा की।

सेफ वॉटर नेटवर्क इंडिया (एसडब्ल्यूएन), आईजेल स्टेशन नामक अपने वॉटर एटीएम के माध्यम से, भारत में तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1.3 मिलियन से अधिक लोगों को सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने में मदद करता है। 2023 में, उपभोक्ताओं ने इसके द्वइ्डुय स्टेशनों से 350 मिलियन लीटर से अधिक पानी खरीदा, जिसका पूरे वर्ष में 98 प्रतिशत से अधिक अपटाइम था। इन 350 वॉटर एटीएम में से लगभग 56 प्रतिशत का प्रबंधन और संचालन महिलाओं द्वारा किया जाता है जिन्हें उनके समुदाय प्यार से वॉटर आंटी कहते हैं। उपभोक्ता इन आईजल स्टेशनों से अपने 20-लीटर के डिब्बे में सुरक्षित पानी इकट्ठा करते हैं। यह एकल-उपयोग प्लास्टिक बोतलबंद पानी के संकट को रोकता है, कम आय वाले समुदायों को स्वतंत्रता और आजीविका प्रदान करता है, पानी के टैंकरों के लिए अंतहीन इंतजार को समाप्त करता है, और इलाकों को प्रदूषण मुक्त पीने योग्य पानी प्रदान करता है।

तेलंगाना में वाटर आंटी सिंदुजा ने कहा, विशेष रूप से चिलचिलाती गर्मी और गंभीर सूखे की स्थिति में स्टेशन मरुस्थल साबित हुए हैं। भारत अब 30 राष्ट्रीय स्तर के कार्यान्वयनकर्ताओं और राज्य सरकारों द्वारा स्थापित लगभग 65,000 जल एटीएम का घर है।

समस्या केवल सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था, पहुंच या प्रबंधन तक सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए, एसडब्लूआई द्वारा सस्टेनेबल एंटरप्राइजेज फॉर वॉटर एंड हेल्थ सीवाह नामक तीन-वर्षीय परियोजना की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन जल एटीएम से होने वाला राजस्व जमीनी स्तर पर कई कार्यान्वयनकर्ताओं के लिए अस्थिर हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएआईडी) के साथ सहयोग और दस अन्य कार्यान्वयनकर्ताओं से डेटा। अध्ययन में पाया गया कि इन वॉटर एटीएम में पानी का राजस्व, जिनकी कीमत 1 रुपये प्रति लीटर और 5 रुपये प्रति 20 लीटर है, मुश्किल से मौजूदा स्थानीय परिचालन लागत, जैसे कच्चे पानी, बिजली और ऑपरेटर के वेतन को पूरा करता है। फ़ील्ड सेवा लागत, जैसे तकनीशियन की फीस और उच्च-मूल्य वाले स्पेयर पार्ट्स, ऑपरेटर के खर्च को बढ़ा देते हैं। कार्यान्वयनकर्ता क्लस्टर पर्यवेक्षण, गुणवत्ता निगरानी, उपकरण या सुविधा उन्नयन आदि से संबंधित खर्चों को भी कवर नहीं करते हैं।

एसडब्ल्यूएनआई की रिपोर्ट, जिसे 2023 में जल एटीएम का वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन कहा जाता है, ने भारत में जल एटीएम की स्थिरता पर फिर से विचार करने की आवश्यकता जताई। इस बार, एक नए लेंस के माध्यम से, जो सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रणालियों के लिए कुल लागत बोझ को ऑपरेटरों से दूर करदाताओं के रुपये या अनुदान-वित्त पोषित प्रणालियों के लिए इच्छुक कंपनियों के सीएसआर अनुदान पर स्थानांतरित कर देगा। रिपोर्ट में विशेष रूप से एक परिणाम-आधारित फंडिंग मॉडल प्रस्तावित किया गया है जिसमें एसडब्ल्यूई को बेचे गए पानी की मात्रा, सुविधा अप-टाइम या एकत्र किए गए राजस्व और गुणवत्ता अनुपालन के आधार पर फंडिंग प्राप्त होती है। एक वैश्विक परिणाम-आधारित फंडिंग संगठन, अपटाइम कैटलिस्ट फैसिलिटी ने कार्यान्वयनकर्ताओं के लिए एक स्थायी प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन मॉडल के लिए एसडब्ल्यूएन के जल स्टेशनों का चयन किया। आदर्श स्टेशन उपयुक्त विभेदक साबित हुए क्योंकि उनकी दूरस्थ निगरानी प्रणाली और जल मीटर संयंत्र के प्रदर्शन, उत्पादित और बेचे गए पानी की मात्रा और एकत्रित राजस्व पर वास्तविक समय डेटा प्रदान करते हैं। एकत्रित राजस्व की आसानी से निगरानी की जाती है क्योंकि पानी प्री-पेड आरएफआईडी कार्ड, डिजिटल क्यूआर कोड या सिक्का वितरण का उपयोग करके खरीदा जाता है। एक दशक से अधिक के संचालन अनुभव को देखते हुए, कर्नाटक सरकार ने ग्राम पंचायत, ऑपरेटरों, ठेकेदारों और ग्रामीण विकास और पंचायती राज को प्रशिक्षण देकर राज्य में 18,000 से अधिक सामुदायिक जल उपचार संयंत्रों (या जल एटीएम) के संचालन में मदद करने के लिए एसडब्ल्यूएन का चयन किया। जिला स्तर पर कर्मचारी. यह परियोजना 2019 में शुरू होने वाले कोविड के चरम के दौरान चार वर्षों के लिए प्रशिक्षण, निगरानी और संयंत्र के संचालन की सर्वोत्तम प्रथाओं को लेकर आई।

एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का अब राज्यों में परीक्षण किया जा रहा है, और सैकड़ों सिस्टम अब उन मापदंडों पर निर्यात के लिए तैयार हैं जिनमें जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण के लिए भौतिक और प्रशिक्षण घटक और सूचना शिक्षा और संचार अभियान शामिल हैं।

आप की बात

चुनाव की चुनौतियां

भारत में चुनाव की दो माह से भी लंबी मैराथन शुरू हो चूकी है। इसी के साथ चुनाव आयोग की चुनौतियां भी बढ़ने लगी हैं। इस बार चुनाव आयोग को न सिर्फ नेताओं के मिथ्या प्रचार, दुष्प्रचार वे पैसे के अवैध लेनदेन से जूझने के साथ ही आधुनिकतम डीपफेक वीडियो से भी जूझना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता-एआई के बल पर उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत तमिल नाडु से हुई है। कहा जाता है कि यहां दिवंगत जयललिता व करुणानिधि के फेक वीडियो फैलाए जा रहे हैं। जयललिता की 2016 में मृत्यु हो गई थी, पर एक ध्वनि संदेश में उन्हें राज्य की वर्तमान द्रमुक सरकार की घोर आलोचना करते बताया गया है। इसी प्रकार 2018 में दिवंगत करुणानिधि को एक एआई-जनरेटेड वीडियो में अपने बेटे स्टालिन की प्रशंसा करते हुए दिखाया गया है। आशंका है कि एआई तकनीक के प्रयोग से पूरे देश में फेक वीडियो-आडियो की बाढ़ आ सकती है। इससे मतदाता तो भ्रमित होंगे ही, इनकी जिम्मेदारी किसी राजनीतिक दल पर डालना तथा उसे सिद्ध करना भी आसान नहीं होगा। ऐसे में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है तथा उसकी चुनौतियां गंभीर होती जा रही हैं। इनसे निपटने के लिए उसे शासन-प्रशासन का पूरा सहयोग चाहिए।

– **जंग बहादुर सिंह,** जमशेदपुर

कोटा में आत्महत्यायें

कोटा कोचिंग के मामले में हमेशा मशहूर रहा है। कोटा को राजस्थान की कोचिंग सिटी भी कहा जाता रहा है। मगर इन दिनों यहां पढ़ने आने वाले अनेक छात्रों में फांसी लगाकर आत्महत्या की बेहद चिन्ताजनक प्रवृत्ति विकसित हुई है। आखिर इन ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों पैदा डर और निराशा की भावना पर लगाम क्यों नहीं लग रही है? इस महीने कोटा में किसी कोचिंग छात्र के आत्महत्या करने की दूसरी तथा इस वर्ष की सातवीं घटना सामने आई है। इसके बावजूद इस परिघटना पर कोई व्यापक उच्चस्तरीय जांच क्यों नहीं बैठाई गई है? हाल ही में अखबारों में एक विज्ञापन जारी कर कोटा के कोचिंग संस्थानों ने पूरे मामले पर लीपापोती करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन वहां की शिक्षा प्रणाली तथा पढ़ने वाले बच्चों की कौसिंलिंग व उनके माता-पिता से नियमित संपर्क की कोई सुपरिभाषित व सुनिश्चित व्यवस्था शायद विकसित नहीं हुई है। नई शिक्षा नीति-2020 जारी करते समय केन्द्र सरकार ने कहा था कि वह शिक्षा के व्यवसायीकरण तथा कोचिंगों की अनिवार्यता पर लगाम लगाने का प्रयास करेगी। राजस्थान में हाल में बनी भाजपा सरकार को इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाने चाहिए।

– **एमएम राजावत,** शाजापुर

मोदी की विदेश नीति

मोदी सरकार विदेश नीति के क्षेत्र में कारगर नीतियां बनाने और उनके क्रियान्वयन में सफल रही है। विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने, फांसी की सज़ा पाए भूतपूर्व नौसैनिकों को बचाने, चीन की कुटिलता का मुंहतोड़ जवाब देने तथा अमेरिका के दबाव में रुस से आयात पर रोक न लगाने जैसे हर मामले में सरकार ने देशवासियों को गदगद कर दिया है। आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो साख है, वैसी पहले कभी नहीं थी। मोदी की रोज 18 घंटे सक्रियता उनकी पूरी टीम के लिए प्रेरणा स्त्रोत है। मोदी किसी भी जटिल अंतरराष्ट्रीय समस्या पर संबंधित देशों के राष्ट्राध्यक्षों व शासनाध्यक्षों से सीधे संपर्क कर उसके समाधान का सर्व-सम्मत हल तलाशने का प्रयास करते हैं। इससे अनिवासी भारतीयों, भारतीय मूल के विदेशियों तथा देश से बाहर कामकाज या पढ़ाई की इच्छा से जाने वाले नौजवानों में मोदी के प्रति जबरदस्त उत्साह पैदा हुआ है। मोदी सरकार की विदेश नीति के प्रति देश के नौजवानों में पैदा यह उत्साह निश्चित रूप से तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के साथ ही भाजपा की सीटें बढ़ाने में योगदान करेगा। विडंबना है कि विपक्ष इस सकारात्मक परिवर्तन के प्रति अंध मोदी-विरोध के कारण अपनी आंखें बंद किए है।

– **विभूति बुपक्या,** खाचरोद

जल संरक्षण

इंदौर में जल संरक्षण के लिए अभियान शुरू हुआ है जिसके अंतर्गत रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को 50 हजार तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। संघमित्र एवं विश्वम के तत्वावधान में भूजल संरक्षण के उद्देश्य से वंदे जल महाअभियान की शुरुआत की गई है। लगातार देश का सबसे स्वच्छ शहर होने का गौरव प्राप्त करने वाला इदौर अब पर्यावरण व जल संरक्षण के क्षेत्र में भी अग्रणी बनने का प्रयास कर रहा है। इस कार्य को प्रदेश के सभी शहरों से लेकर गांव तक ही नहीं, बल्कि देशभर में प्रारंभ किया जाना चाहिए। इससे बेंगलुरु जैसी जल संकट वाली स्थिति नहीं पैदा होगी। इसके साथ ही जल संरक्षण से कृषकों व आम जनता को बारहों महीने जल उपलब्धता बनी रहेगी। इससे मवेशियों और वृक्षों तक को प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। अक्सर तालाबों तथा नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र में निर्माण के कारण जल संरक्षण में बाधा आती है तथा भूजल लगातार दोहन के कारण घटता चला जाता है। जल संरक्षण हेतु ऐसे अवरोध यथासंभव हटाकर जनता के व्यापक सहयोग से देश भर में पुरानी जल संरचनाओं को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए।

सुभाष बुडावन वाला, रतलाम

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 42

विमानन कंपनियों में कर्मी प्रबंधन

कंपनियों के विलय और अधिग्रहण के मामलों में मानव संसाधन के मुद्दे बड़ी चुनौती साबित होते हैं। टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस के स्वामित्व वाली विमानन कंपनी विस्तारा को यह सबक थोड़ा कड़े अंदाज में मिला। बीते कुछ दिनों में विमानन कंपनी को मुश्किलों से गुजरना पड़ा। पूर्व में सरकारी कंपनी रही एयर इंडिया के साथ विलय के पहले विमान चालकों के साथ जो नया अनुबंध किया गया उसके प्रति असंतोष दिखाते हुए बड़ी संख्या में चालकों ने बीमारी का हवाला देकर अवकाश लिया और रोजाना 350 के करीब उड़ान संचालित करने वाली कंपनी को लगभग 10 फीसदी उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। यह एक ऐसी दुविधा है जिससे एयर इंडिया के पुराने मालिक परिचित हैं। कम से कम 2007 में एयर इंडिया और घरेलू विमानन कंपनी इंडियन एयरलाइंस के विलय के समय ऐसी ही परिस्थितियां थीं। वह संकट महीनों तक चला था और मौजूदा संकट के समय उसे चेतावनी के तौर पर याद किया जाना चाहिए था। विस्तारा का संकट हमारे सामने इस बात का अच्छा उदाहरण है कि कर्मचारियों की कठिनाइयों का प्रबंधन किस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए?

फरवरी के अंत और मार्च के आरंभ में इस आसन्न संकट के संकेत नजर आने लगे थे जब कुछ विमान चालकों ने बीमारी की बात कही थी। समस्या के मूल में है विस्तारा के विमान चालकों के वेतन पैकेज का पुनर्गठन ताकि उसे एयर इंडिया के समकक्ष किया जा सके। विमान चालकों को नया वेतन पैकेज 15 मार्च तक स्वीकार करना था जिसका मतलब होता फर्स्ट ऑफिसर के वेतन में भारी कटौती। विलय के बाद उन्हें मौजूदा 70 घंटों की उड़ान के बजाय न्यूनतम 40 घंटों की गारंटीड उड़ान भरनी होगी। कैप्टन और सीनियर कैप्टन के लिए उड़ान का समय कम होकर क्रमशः 52 और 60 घंटे होगा। निश्चित तौर पर इस कमी के बदले एकबारगी क्षतिपूर्ति भुगतान किया जाएगा लेकिन नए वेतन पैकेज को लेकर नाराजगी के साथ कुछ अन्य आपत्तियां हैं। इनमें से एक है नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा बेहतर फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल्स (एफडीटीएल) को घरेलू विमानन कंपनियों के दबाव में निरंतर टालना जबकि इसके लिए 1 जून की समय सीमा तय की गई थी। नया एफडीटीएल समूचे विमानन उद्योग के विमान चालकों की शिकायतों के बाद पारित किया गया था और इसमें आराम के अधिक घंटों, रात में लैंडिंग कम करने, विमानन कंपनियों द्वारा और विमान चालकों को भर्ती करने जैसे प्रावधान थे। इसके अलावा विमान चालक विलय का असर अपनी वरिष्ठता पर पड़ने को लेकर भी चिंतित थे। कई चालकों का भय यह था कि उड़ान अनुभव से इतर उन्हें विलय के बाद अपनी वरिष्ठता गंवानी पड़ेगी। वरिष्ठता का मसला विमान चालकों के लिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें अपना बेस और विमान चुनने का अधिकार मिलता है।

दुनिया भर की विमानन कंपनियां यह समझती हैं कि संस्थान के भीतर विमान चालकों के पास मोलतोल की विशिष्ट क्षमता होती है। ऐसे में वेतन व्यवस्था, वरिष्ठता और रोस्टर में बदलाव के लिए अत्यधिक ऊर्जावान प्रबंधन की आवश्यकता होती है ताकि बदलाव की प्रक्रिया को सहज बनाया जा सके। विस्तारा ने संकट उत्पन्न होने यानी बड़ी संख्या में उड़ान निरस्त होने, देरी होने और ग्राहकों को असुविधा होने के बाद अपने विमान चालकों के साथ एक बैठक आयोजित की। इसमें दो राय नहीं कि विस्तारा-एयर इंडिया के विलय में एयर इंडिया एक्सप्रेस और एआईएक्स कनेक्ट (पूर्व में एयर एशिया जो टाटा समूह की किफायती विमान सेवा है) के विलय के लिए भी सबक छिपे होंगे। समूह विमानन कारोबार को लेकर प्रतिबद्ध है और कोविड के बाद तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के मद्देनजर उसे प्रबंधन में कुशल लोगों की आवश्यकता है। अनुमान है कि वित्त वर्ष 25 में अकेले घरेलू विमानन परिवहन 8 फीसदी बढ़ेगा। वित्त वर्ष 24 में भी ऐसी वृद्धि देखने को मिली थी। विमान चालकों को प्रशिक्षित करने वाले संस्थान मांग और गुणवत्ता के आधार पर पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में चालकों को लेकर कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है और अभी बीमारी के इस प्रकरण के बाद विमान चालकों में भगदड़ की स्थिति भी नजर आ सकती है।

अजय मोहंती

जारी रहने वाला है रुपये की स्थिरता का दौर

मौजूदा हालात को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी रुपये की कीमत स्थिर बनी रहेगी। इसकी मुख्य वजह होगी भारत की आर्थिक स्थिति। बता रहे हैं मदन सबनवीस

मार्च 2023 और मार्च 2024 के बीच रुपये की कीमत में 0.9 फीसदी की गिरावट आई। इस दौरान अमेरिकी मुद्रा (डॉलर) यूरो की तुलना में 1.5 फीसदी गिरी। रुपये का प्रदर्शन रेनमिनबी, वॉन, रैंड, रिंगित, रुपिया और बाह्त की तुलना में बेहतर रहा। मार्च 2024 तक हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 64.2 अरब डॉलर बढ़ा जबकि मार्च 2023 में यह 55.6 अरब डॉलर बढ़ा था। बाहरी मोर्चे पर शानदार प्रदर्शन है और इस वजह से 2024 में चालू खाते के घाटे में कमी आएगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर है लेकिन वह अनिश्चित समय से गुजरी है। इन अनिश्चितताओं ने केंद्रीय बैंक के कदमों को लेकर काफी अटकलों को जन्म दिया।

अब जबकि नया वित्त वर्ष आरंभ हो रहा है, अनिश्चितता में कमी आई है। पहली बात तो यह है कि यूक्रेन और फिलिस्तीन में छिड़ा संघर्ष शायद मायने न रखे। दूसरी बात, विश्व अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रहेगी। तीसरा, कच्चे तेल की कीमत में इजाफा नहीं होगा। चौथा, केंद्रीय बैंक, खासकर फेडरल रिजर्व और यूरोपीय केंद्रीय बैंक दरों में कमी करेंगे, हालांकि यह कब होगा इस पर बहस हो सकती है। इसका अर्थ यह भी है कि अक्टूबर-दिसंबर 2022 में डॉलर में मजबूती का जो सिलसिला देखने को मिला वह दोहराया नहीं जाएगा। सवाल यह है कि भारतीय रुपये के भविष्य के लिए इसका क्या अर्थ होगा?

इस वर्ष रुपये की कीमत दो कारकों से प्रभावित होगी। इसकी प्राथमिक ताकत होगी भुगतान संतुलन की आधारभूत स्थिति जो विदेशी मुद्रा की कुल आवक और निकासी को शामिल करता है। दूसरा कारक होगा डॉलर की मजबूती की बाहरी शक्ति।

आधारभूत बिंदुओं की बात करें तो रुपया मजबूत स्थिति में नजर आता है। वित्त वर्ष 24 की निर्यात वृद्धि 11 महीनों में 12 फीसदी के साथ काफी अच्छी है। खासकर ऐसे समय में जबकि विश्व अर्थव्यवस्था से मिलेजुले संकेत मिल रहे हैं। 2024 में वृद्धि दर के स्थिर होने का अनुमान है और जिंस कीमतों में भी सुधार हो सकता है। इस वर्ष निर्यात की स्थिति भी बेहतर हो सकती है। यही बात निर्यात सेवाओं पर भी लागू है। इनका प्रदर्शन अनुमान के अनुरूप नहीं रहा है और वित्त वर्ष 24 में यह 5 फीसदी की दर से वृद्धि हासिल करने में कामयाब रहीं। अगर मान लिया जाए कि कच्चे तेल की कीमतें 80-90 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में रहेंगी तो व्यापार घाटा और चालू खाते का घाटा नियंत्रण में रहना चाहिए। वित्त वर्ष 24 में इस घाटे के एक फीसदी या उससे कम रहने की उम्मीद है।

हालांकि अधिक आशावाद पूंजी खाते की स्थिति से उत्पन्न हुआ है। जून के बाद भारतीय सरकारी बॉन्डों को जेपी मॉर्गन बॉन्ड सूचकांक में शामिल किए जाने और उसके बाद जनवरी 2025 से उन्हें ब्लूमबर्ग में शामिल किया जाना है। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफपीआई) में उछाल आएगी। बीते कुछ वर्षों में एफपीआई मोटे तौर पर इक्विटी केंद्रित रहा है। ऐसा तब से है जब से पश्चिमी केंद्रीय बैंकों ने वित्तीय संकट के बाद किए गए आपात उपायों को वापस लेने के लिए मौद्रिक सख्ती को अपनाने का निर्णय किया। इसका अर्थ यह हुआ कि उभरते बाजारों में निवेश के लिए आवंटन योग्य फंड कम रह गया। पश्चिम में बढ़ती ब्याज दरों का अर्थ यह हुआ कि उभरते बाजारों का ऋण कम आकर्षक हुआ और फंड इक्विटी बाजार में जाने लगे।

बहरहाल, भारत के वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में शामिल होने के बाद डेट बाजार में अपने आप महत्त्वपूर्ण निवेश आने लगेगा जो हमारे भुगतान संतुलन के लिए अच्छी बात है।

सूचकांक में 10 प्रतिशत भार को कवर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से भारतीय बांडों को शामिल करने से 20-30 अरब डॉलर का निवेश आ सकता है।

इन फंडों की आवक के तरीके के मुताबिक यह जिम्मेदारी केंद्रीय बैंक पर होगी कि वह नकदी और अस्थिरता दोनों का प्रबंधन सुनिश्चित करे। ऐसे में रुपये में कुछ अस्थिरता नजर आ सकती है।

बाजार के लिए अन्य सकारात्मक बातों का उल्लेख करें तो बाह्य वाणिज्यिक उधारी पर अधिक निर्भरता भी इसकी एक वजह होगी। फिलहाल तो यही देखा गया है कि घरेलू वित्तीय व्यवस्था प्राथमिक तौर पर घाटे की शिकार है क्योंकि ऋण की गति जमा दर से तेज है। यह सिलसिला थोड़ी धीमी गति के साथ वित्त वर्ष 25 में भी जारी रह सकता है। केंद्रीय बैंकों द्वारा दरों में कमी और रुपये में स्थिरता के साथ कंपनियां बाह्य वाणिज्यिक उधारी तक पहुंच बनाने का प्रयास करेंगी जिससे आवक बढ़ेगी। वित्त वर्ष 24 में बाह्य वाणिज्यिक ऋण का प्रदर्शन बेहतर था और वित्त वर्ष 23 के पहले 10 महीनों के 22 अरब डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष 24 के पहले 10 महीनों में 30 अरब डॉलर के फंड तैयार हुए।

बीते दो वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कम रहा है। वित्त वर्ष 23 और 24 के पहले 10 महीनों में यह औसतन 60 अरब डॉलर रहा है जबकि वित्त वर्ष 21 और 22 में यह 71 अरब डॉलर था। इस क्षेत्र में यथास्थिति बनी रह सकती है जिससे अस्थिरता सुनिश्चित होगी। ऐसे में कुल मिलाकर यह उम्मीद की जा सकती है कि वित्त वर्ष 24 की तरह अर्थव्यवस्था विदेशी मुद्रा के मामले में बेहतर स्थिति में रहेगी और यह राशि 40-50 अरब डॉलर रहेगी। ऐसे में रुपये में मजबूती अपेक्षित है।

बाहरी ताकतों की भी अपनी भूमिका होगी। 2022 के अंत में जब डॉलर में मजबूती आई और वह यूरो के करीब पहुंच गया तब वही दौर था जब फेड दरों में इजाफा कर रहा था तथा अधिक इजाफे के संकेत दे रहा था। वह चक्र समाप्त हुआ और फेड ने दरों को 5.25-5.5 फीसदी पर रखा। इसमें कटौती की चर्चा है लेकिन वह मुद्रास्फीति पर निर्भर होगा। फेड द्वारा दरों में इजाफा रोकने के बाद से डॉलर कमजोर हुआ है। फेड द्वारा दरों में कमी किए जाने के बाद (जो दो-तीन बार में 75 आधार अंक तक हो सकती है) डॉलर में और कमजोरी आ सकती है। इससे अन्य मुद्राओं पर दबाव बनेगा और रुपये को मजबूत होने में मदद मिलेगी।

इस परिदृश्य में रुपया 0.5 फीसदी के सकारात्मक बदलाव के साथ 82.50 प्रति डॉलर और 83.50 प्रति डॉलर के दायरे में स्थिर रह सकता है। ऐसे में रिजर्व बैंक को निरंतर गतिविधियों की निगरानी करनी होगी और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करना होगा।

(लेखक बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। लेख में उनके निजी विचार हैं)

शहरों के लिए एकीकृत परिवहन प्रणाली प्राधिकरण आवश्यक

केंद्र सरकार ने वर्ष 2006 में शहरी विकास मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति जारी की थी। इस नीति में 10 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों के लिए एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) के गठन का सुझाव दिया गया था। वर्ष 2011 की गणना के अनुसार देश में ऐसे 53 शहर थे। अगस्त 2017 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई मेट्रो रेल नीति को मंजूरी दी थी। इस नीति में उन शहरों के लिए ढांचा तैयार किया गया था, जो मेट्रो रेल प्रणाली शुरू एवं इसका विस्तार करना चाह रहे हैं।

वैसे तो कई शहरों ने नई मेट्रो रेल परियोजनाएं शुरू करने की ठान ली है मगर इस बात को समझने के व्यापक प्रयास नहीं हो रहे हैं कि किसी शहर एवं इसके लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कोई मेट्रो रेल परियोजना किस तरह फिट बैठती है। इस नीति में स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर कोई शहर अपनी मेट्रो परियोजना के लिए केंद्र सरकार से सहायता चाहता है तो संबंधित राज्य सरकार को यूएमटीए संचालित करने का आश्वासन देना होगा। यूएमटीए एक इकाई है जो सभी प्रकार के शहरी परिवहन के लिए उत्तरदायी होगी। यह फिर उस शहर में यातायात के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण शुरू करेगा। जिन शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, उन्हें एक वर्ष के भीतर यूएमटीए स्थापित करने पर विचार करना होगा। आवास एवं शहरी मामलों पर संसद की स्थायी समिति की 16वीं रिपोर्ट में मेट्रो रेल परियोजनाओं के विषय पर कहा गया है कि 'यह देखकर हैरानी हो रही है कि चार वर्ष बीतने के बाद भी राज्यों ने यूएमटीए का गठन नहीं किया है'।

लगभग सभी राज्यों में इस स्थिति को समझने के लिए 'द इन्फ्राविजन फाउंडेशन' ने दो विशेष शोध शुरू किए हैं। इनमें एक शोध आईआईटी दिल्ली की गीतम तिवारी और दूसरा शोध आईआईएम अहमदाबाद के संदीप चक्रवर्ती ने किया है। ये दोनों जाने-माने परिवहन विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर तिवारी ने 'ए फ्रेमवर्क फॉर सलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडियन सिटीज' शीर्षक के साथ अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में पांच स्पष्ट सिफारिशें की गई हैं।

1. यातायात के अलग-अलग रूपों के लिए अलग-अलग सार्वजनिक परिवहन प्रणाली उपयुक्त होते हैं। यातायात के इन रूपों का निर्धारण दूरी से निर्धारित किया जाता है। किस मार्ग पर किसी तरह की परिवहन प्रणाली की जरूरत है यह बात यातायात का विकल्प चुनने में मदद करती है। इससे उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के सभी लाभ (सामाजिक लाभ सहित) लोगों को देना सहज हो जाता है।

2. उच्च क्षमता वाली परिवहन प्रणाली जैसे मेट्रो रेल लंबी दूरी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। 80 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों में 300-400 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइनें बिछाई जा सकती हैं। हालांकि ऐसे शहरों में एक मजबूत एवं विश्वसनीय बस सेवा भी होनी चाहिए जो सभी प्रमुख एवं मझोले मार्गों पर चलाई जा सके। इनकी कुल लंबाई लगभग 800-1,000 किलोमीटर होना चाहिए। अंत में गंतव्य तक पहुंचने के लिए पैदल या मध्यस्थ सार्वजनिक परिवहन विकल्पों जैसे ऑटो रिक्शा आदि का सहारा लिया जा सकता है। नीति, नियोजन, खाका और नियामकीय स्तरों पर तीनों प्रणालियों के एकीकरण से एक उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित हो पाएगी। फीडर बसों के जरिये यात्रियों को मेट्रो स्टेशनों तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे विशेष फीडर बसों की जरूरत नहीं रह जाएगी।

बुनियादी ढांचा

विनायक चटर्जी

3. जिन शहरों की आबादी 40 से 80 लाख है वहां सभी प्रमुख एवं उप-मार्गों पर बस प्रणाली संचालित कर यातायात की जरूरत पूरी की जा सकती है। 10 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले मार्गों के लगभग 20 प्रतिशत हिस्से पर लाइट रेल ट्रांसपोर्ट (एलआरटी) इस्तेमाल में लाया जा सकता है। यह यातायात व्यवस्था में बस सेवाओं के साथ मिलकर काम करेगा। अंत में गंतव्य तक पहुंचने के लिए पैदल जाया जा सकता है या मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सहारा लिया जा सकता है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को एकीकृत प्रणाली के रूप में बीआरटीएस/मेट्रो लाइन जैसी उच्च क्षमता वाली प्रणाली इस्तेमाल करने पर विचार कर सकते हैं।

4. जिन शहरों की आबादी 10 लाख से कम है उन्हें यातायात के झंझट का समाधान करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली बस प्रणाली में निवेश करना चाहिए। उच्च क्षमता वाली परिवहन प्रणाली जैसे मेट्रो की योजना पर तभी विचार किया जाना चाहिए जब शहर की आबादी बढ़कर 10 लाख से अधिक होने का अनुमान हो और माना जा रहा हो कि अगले 10 वर्षों में यह बढ़कर 2.40 करोड़ से अधिक हो जाएगी।

5. 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों में परिवहन की मांग मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के जरिये पूरी की जा सकती है। इसके साथ ही प्रमुख एवं उप-मार्गों पर छोटे स्तर पर बस सेवा का संचालन किया जा सकता है।

डॉ. चक्रवर्ती की रिपोर्ट 'स्ट्रैटजीज टू इम्प्रूव द फाइनैंशियल परफॉर्मेंस ऑफ मेट्रो रेल सिस्टम्स इन इंडिया' मुख्य रूप से यूएमटीए पर ध्यान केंद्रित करता है। वह चतुर्आयामी कदम का सुझाव देते हैं।

1. यूएमटीए को शहर में सभी गैर-निजीकृत परिवहन ढांचे और सार्वजनिक परिवहन के सभी साधनों का नियंत्रण, संचालन और रखरखाव अपने हाथों में लेना चाहिए। इस तरह, परिणामस्वरूप पूरे शहर या महानगर क्षेत्र के परिवहन से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी यूएमटीए की होनी चाहिए। इन कार्यों में नीति तैयार करना, रणनीतिक नियोजन, परियोजना मूल्यांकन एवं मंजूरी, परियोजना क्रियान्वयन, संचालन एवं रखरखाव, धन की उपलब्धता और शोध शामिल होंगे।

2. यूएमटीए इनमें किसी भी कार्य के लिए ठेकेदार (कॉन्ट्रैक्टर) नियुक्त कर सकता है और जरूरत पड़ने या संभावनाएं बनने पर निजी क्षेत्र के साथ इक्विटी साझेदारी कर सकता है। यूएमटीए निजी परिवहन सेवा (ऐप-आधारित टैक्सी सेवा), सूक्ष्म यातायात सेवा (साझा बाइक एवं इलेक्ट्रिक स्कूटर) और शहर लॉजिस्टिक सेवा (ई-कॉमर्स आपूर्ति, वस्तुओं के परिवहन, गोदाम में संरक्षण आदि) के प्रबंधन, नियमन एवं लाइसेंस जारी करने के लिए उत्तरदायी होगा।

3. यातायात नियंत्रण, इंटीग्रेटेड मोबिलिटी पेमेंट सिस्टम्स (ट्रांजिट स्मार्ट कार्ड), मल्टीमोडल सिस्टम डेटा कलेक्शन और वास्तविक समय में यात्रा सूचना प्रावधान का उत्तरदायित्व भी यूएमटीए पर होना चाहिए।

4. यूएमटीए को बड़े संस्थागत बदलाव और शहरों में परिवहन परिसंपत्तियों के मालिकाना नियंत्रण के हस्तांतरण और बड़े कार्यों के लिए पहल करनी होगी।

सार्वजनिक परिवहन के लिए दुनिया के जिन शहरों की मिसाल दी जाती है वहां नियोजन, क्रियान्वयन और शहरी यातायात के सभी पहलुओं के संचालन के लिए एक इकाई होती है। इनमें न्यूयॉर्क सिटी ट्रांजिट अथॉरिटी, ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन और सिंगापुर का एसबीएस ट्रांजिट और एसएमआरटी जैसे कुछ नाम गिनाए जा सकते हैं। भारतीय शहरों को भी परिवहन से जुड़े नीति निर्धारण में यात्रियों को केंद्र में रखना चाहिए। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले एक एकीकृत परिवहन प्राधिकरण स्थापित करना अनिवार्य एवं आवश्यक शर्त है।

(लेखक आधारभूत ढांचा क्षेत्र के विशेषज्ञ और द इन्फ्राविजन फाउंडेशन के संस्थापक एवं प्रबंध न्यासी हैं।)

आपका पक्ष

2047 के लिए विकसित भारत की संकल्पना

समाचार पत्र के 4 अप्रैल के अंक में प्रकाशित संपादकीय मध्य अवधि की आर्थिक नीति विकसित भारत की वर्ष 2047 तक वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में शिखर की ओर यात्रा में संभावनाओं और चुनौतियों पर बहुत गंभीर चर्चा करती है। पिछले दस वर्षों में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में 11वें से पांचवें स्थान पर पहुंच गया है और इसके अगले तीन वर्षों में तीसरे स्थान पर होने की संभावना है। इसके पीछे भारत की वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी आधारित शक्ति और वैश्विक व्यापार में सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक संबंधी उत्पादन और निर्यात हैं। हमारे परंपरागत उद्योग व्यापार और अनाज, परिधान, डेरी, रसायन, आभूषण, कच्चे माल जैसे निर्यात आदि के भरोसे हम विश्व में दसवीं स्थिति पर ही संघर्ष कर रहे थे। जापान की सकल घरेलू उत्पाद की गिरती दर और जर्मनी की वृद्धि दर 1.9 फीसदी से 0.2 फीसदी पर खिसकने से और हमारी 7.5 फीसदी की वृद्धि दर से हम तीसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इसके आगे का मार्ग काफी चुनौतीपूर्ण होगा जहां हमारी प्रतिस्पर्धा अमेरिका की 27 लाख करोड़ डॉलर और चीन की 17 लाख करोड़ डॉलर वाली अर्थव्यवस्था से है जो बहुत दुरूह लक्ष्य है। अमेरिका और चीन भी यह समझने लगे हैं कि अब सिर्फ भारत ही उनकी अर्थव्यवस्था को चुनौती देने में सक्षम है। अमेरिका और चीन का वर्चस्व यूरोपीय, अफ्रीकी और एशियाई देशों में है और भारत का व्यापार भी इन्हीं देशों में है इसलिए मुख्यतः यूरोपीय देश जिनका वर्चस्व संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों में है, वे भी भारत को चुनौती देने में पीछे नहीं हैं। अमेरिका, चीन और यूरोपीय देश भारत और अन्य विकासशील देशों में अपना तो मुक्त व्यापार चाहते हैं परंतु भारत से व्यापार में जलवायु संरक्षणवादी समझौतों पर जोर देते हैं।

विनोद जौहरी, दिल्ली

पिछले 10 वर्षों में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में 11वें से 5वें स्थान पर पहुंच गया है और अगले 3 वर्षों में तीसरे स्थान पर होने की उम्मीद है

ऑनलाइन फर्जी समीक्षाओं पर सख्ती आवश्यक

चूंकि ई-कॉमर्स में उत्पाद को भौतिक रूप से देखने या उसकी जांच किए बिना वर्चुअल खरीदारी का अनुभव शामिल है, इसलिए उपभोक्ता उन उपयोगकर्ताओं की राय और अनुभव देखने के लिए प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई समीक्षाओं पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं, जिन्होंने सामान या सेवाएं पहले खरीदी हैं। हालांकि, नकली समीक्षाएं और स्टार-रेटिंग उपभोक्ताओं को ऑनलाइन उत्पाद और सेवाएं खरीदने के लिए भ्रमित करते हैं। इन फर्जी समीक्षाओं के प्रभाव में उपभोक्ता अनावश्यक रूप से गुमराह हो जाता है। नकली समीक्षाएं करवाना तो भ्रामक प्रचार करने से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि भ्रामक प्रचार के बावजूद उपभोक्ता स्वयं निर्णय ले सकता है परंतु नकली समीक्षाओं से उसके स्वयं भ्रमित होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए आईटी मंत्रालय के तहत नया नियामक निकाय बनाने की सख्त आवश्यकता है जिसके माध्यम से यह निर्धारित किया जा सके कि उत्पाद की गुणवत्ता कितनी सही है।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए स्वदेश में विकसित 'सीएआर टी-सेल' थेरेपी की गुरुवार को शुरुआत की। इस दौरान महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस (बाएं) मौजूद थे।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

महाराष्ट्र के पेच

जिन कुछेक राज्यों में आगामी लोकसभा चुनाव के समीकरण सबसे ज्यादा जटिल माने जा रहे हैं, उनमें महाराष्ट्र प्रमुख है। इसी जटिलता का ताजा उदाहरण है पूर्व मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम का पार्टी से अलगाव सार्वजनिक होने के बाद पूर्वघोषणा के बावजूद यह न बता पाना कि वह किस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। गुरुवार को वह इसकी घोषणा करने वाले थे, लेकिन यह कहते हुए दो-तीन दिनों का और वक्त ले लिया कि अब उसकी जल्दी नहीं है।

बदलेगा राजनीति का स्वरूप?

अनिश्चितता की वजह | अनिश्चितता के पीछे सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि अभी महायुति यानी BJP और उसके अन्य सहयोगी दलों में भी सीटों के बंटवारे की बात पूरी तरह तय नहीं हो पाई है। इससे कई सीटों पर यह निश्चित नहीं हो पा रहा कि वह आखिरकार किस दल के हिस्से में जाएगी और NDA प्रत्याशी को किस निशान पर चुनाव लड़ना होगा।

बढ़ी हुई दावेदारी | इस बार प्रदेश के दो प्रमुख दल– शिवसेना और NCP- दोफाड़ होकर आमने-सामने हैं। ऐसे में सीटों को लेकर पारंपरिक दावे पुराने रूप में नहीं रह गए हैं। दोनों खेमों में हर सीट पर न केवल दलों के बीच दावेदारी बढ़ी हुई है बल्कि संभावित प्रत्याशियों की संख्या भी ज्यादा है। नतीजतन, यह रस्साकशी नेताओं के पार्टी छोड़ने की वजह तो बन ही रही है, कई सीटों पर इसने विचित्र स्थिति पैदा कर दी है।

एक नेता के दो पर्चे | उदाहरण के लिए, विदर्भ की बुलढाणा सीट को लिया जा सकता है, जो महायुति में शिंदे सेना को दी गई, लेकिन उस पर BJP की भी दावेदारी थी। पार्टी के झुकने के बावजूद स्थानीय BJP नेता ने वहां से पर्चा भर दिया। दिलचस्प है कि उस नेता ने दो पर्चे भरे हैं एक BJP नेता के रूप में और दूसरा निर्दलीय के तौर पर।

पवार के खिलाफ पवार | राजनीतिक अंतर्विरोध इस बार पार्टियों पर खास परिवारों के दबदबे की ही नहीं, एक परिवार के अंदर विरासत पर अलग-अलग दावेदारी की भी झलक दे रहा है। यह सबसे स्पष्ट रूप में बारामती सीट पर दिख रहा है, जो पिछले करीब छह दशकों से शरद पवार का गढ़ रही है। इस बार सुप्रिया पिता शरद पवार की ओर से लड़ रही हैं तो सुनेत्रा अपने पति अजित पवार के नाम पर वोट मांग रही हैं।

राजनीतिक संस्कृति का सवाल | जाहिर है, कम से कम महाराष्ट्र में यह चुनाव केंद्र की अगली सरकार तय करने में भूमिका ही नहीं निभाएगा, प्रदेश राजनीति के स्वरूप और उसकी राजनीतिक संस्कृति को भी नए ढंग से परिभाषित कर सकता है।

क्रॉस-वर्ल्ड

इतिहास से प्रेरणा

शैलेंद्र पांडेय

अपनी दूर-अंदेशी के बल पर अंग्रेजों ने इतनी धरती जीत ली थी कि एक वक्त उनके साम्राज्य में सूरज कभी अस्त नहीं होता था। लेकिन, 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में अगर कोई बड़े से बड़े काबिल अंग्रेज से हिंदुस्तान का भविष्य पूछता, तो वह भी आज के दौर की कल्पना नहीं कर पाता। उसकी सुई आकर अटक जाती महारानी के सिंहासन के प्रताप पर, कि उसी की वजह से भारत कुछ काबिल हो सका है वरना तो इस देश में कुछ न था। लेकिन, केवल पांच दशक और लगे इन विद्वानों को झूठा साबित करने में। भारत ने उसकी क्षमता पर शक करने वालों का गुरुर तोड़ा और फिर उस गुरुर के टुकड़ों पर आगे बढ़ गया। बढ़ता ही रहा। अर्थव्यवस्था समेत कई मोर्चों पर उसने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है।

AI Image

भविष्य को देखने में अंग्रेजों से चूक कहां हुई? उनकी सबसे बड़ी गलती कि वह हिंदुस्तान का इतिहास अपने आने के बाद देख रहे थे। उन्होंने उस इतिहास को नजरअंदाज किया, जिसकी आकर्षक कहानियां उन्हें इस देश में खींच लाई थीं। यही इतिहास था, जिसने भारतीयों को प्रेरणा दी आगे बढ़ने की। पुराने वक्त के वैभव और उपलब्धियों की कथाएं, जिन्होंने देश को एक किया। इतिहास से जुड़ा यह राष्ट्रवाद आज भी प्रेरणा के रूप में काम करता है। अतीत के पन्ने पहचान कराते हैं हकीकत से और जनता को किसी लक्ष्य के लिए मेहनत करने की एक वजह देते हैं। इनसे सीखकर आगे बढ़ा जा सकता है। हिस्टोरिकल नैशनलिज्म का यह सहारा कई देशों को है। अमेरिका में कहा जाता है कि हर अमेरिकी को अपना इतिहास पता होना चाहिए। हर अमेरिकी यह जान सके कि आज वह जिस सपने को देख पा रहा है, उसके पीछे कितना संघर्ष है। एक और उदाहरण लिया जा सकता है ग्रीस का। सन 1896 में ओलिंपिक्स दोबारा से शुरू हुए। खेलों की बदौलत ग्रीस ने प्राचीन विरासत को जिंदा करने का प्रयास किया। कई बार यह ऐतिहासिक राष्ट्रवाद कई-कई देशों का साझा होता है, जैसे महात्मा बुद्ध को लेकर भारत और नेपाल का इतिहास। लेकिन, कई बार इसे इग्नोर भी करने का प्रयास किया जाता है। भारत अगर अपने पुराने दिनों को दिलों में जिंदा रखे हुए है, तो उसी से अलग होकर बना और एक ही इतिहास रखने वाला पाकिस्तान इसे भुलाने पर तुला है। वह आज तक उलझन में है कि अपनी कहानी शुरू कहां से करे, बंटवारे से या अलाउद्दीन खिलजी से। उसने एक नया इतिहास लिखने के उतावलेपन में सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध और जैन धर्म समेत तमाम पुरानी पहचान को तवज्जो नहीं दी। वह भूल गया कि इतिहास बनाया नहीं जाता। यह हमें विरासत में मिलता है। हां, यह है कि इतिहास से प्रेरणा लेकर एक नया भविष्य जरूर गढ़ा जा सकता है।

एकदा

गुरु का महत्व

एक बार रूस के महान साहित्यकार मैक्सिम गोर्की महान रचनाकार अंतोन चेखव से मिलने उनके घर पहुंचे। मुलाकात के बाद चेखव और गोर्की में अलग-अलग विषयों पर चर्चा होने लगी। बातचीत एक ऐसे मोड़ पर आई जब गोर्की ने चेखव से पूछा, 'समाज के कई लेयर हैं। आप किस वर्ग को ज्यादा तवज्जो देते हैं?' गोर्की की बात सुनकर चेखव ने एक मिनट रुके बिना कहा, 'वैसे तो समाज के सभी वर्गों की अपनी-अपनी जगह अहमियत है, पर मैं शिक्षक को सबसे अधिक महत्व देता हूं। शिक्षक सम्माननीय और पूजनीय हैं।' गोर्की ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, 'शिक्षक वर्ग की ऐसी कौन सी खासियत है, जिसके कारण आप उन्हें श्रेष्ठ समझते हैं?' चेखव बोले, 'आप जिस भी नजरिए से देखिए, किसी भी देश की नई पीढ़ी को गढ़ने और उसे अच्छे संस्कार देकर आदर्श नागरिक बनाने की जिम्मेदारी शिक्षकों पर होती है। साथ ही कहना चाहता हूं कि शिक्षक का सुखी और समृद्ध होना आवश्यक है ताकि वह निश्चिंत होकर देश की आदर्श पीढ़ी के निर्माण में पूरी लगन से काम कर सकें।' चेखव की बातें सुनकर वह बोले, 'तो ऐसे में आप शिक्षकों की कुछ मदद करना चाहते हैं?' चेखव बोले, 'मैं गुरु के प्रति अपार श्रद्धा रखता हूं। यदि मेरे पास ढेर सारा धन आ जाए तो उससे गांव के शिक्षकों के लिए सुविधाजनक मकान बनवाऊंगा। गोर्की बोले, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। इस पर चेखव बोले, इतना ही नहीं, मैं ऐसे बड़े पुस्तकालय की व्यवस्था भी करूंगा जिसमें अध्यापक, छात्र और गांव के लोग पुस्तकों का अध्ययन कर ज्ञान अर्जित कर सकें। मैं तो शिक्षकों की भूमिका को सबसे अधिक महत्व देता हूं। हमें इस वर्ग के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और इनके उत्थान के लिए सोचना चाहिए। यह सुनकर चेखव के प्रति गोर्की के मन में सम्मान और बढ़ गया।

Subrata Dhar

संकलन : **दीनदयाल मुरारका**

भारत ने 1974 में यह द्वीप श्रीलंका को दिया, बदले में वेज बैंक के रूप में उसे कहीं बड़ा इलाका मिला

कच्चातिवु पर हो रही है सिर्फ राजनीति

रंजीत कुमार

भारत और श्रीलंका के बीच पाक-बे (Palk Bay) समुद्री इलाके में भारत के रामेश्वरम से 33 किलोमीटर और श्रीलंका की जमीनी सीमा से 24 किलोमीटर दूर कच्चातिवु द्वीप 14वीं सदी में ज्वालामुखीय विस्फोट से जन्मा था। आज यही द्वीप भारत की राजनीति में हलचल की वजह बन गया है।

चुनावी मुद्दा | कच्चातिवु द्वीप तमिलनाडु में भावनात्मक मुद्दा है। इसलिए संसदीय चुनावों से पहले इसे हवा दी जा रही है। भारत और श्रीलंका की समुद्री सीमा के बीच यह द्वीप श्रीलंका के अधिक निकट है। इसलिए 1974 में भारत ने महज 285 हेक्टेयर में फैले इस निर्जन द्वीप को एक समझौते के तहत श्रीलंका को सौंप दिया था।

1976 में दूसरा समझौता | इस समझौते के बाद भी इस द्वीप को लेकर दोनों देशों के मछुआरों के बीच विवाद जारी रहा। इसे हल करने के लिए भारत ने 1976 में एक और एग्रीमेंट किया। इसके तहत कन्याकुमारी के निकट Wadge Bank (वेज बैंक) पर भारत का अधिकार हो गया।

फायदे में भारत | Wadge Bank 3,000 वर्ग किलोमीटर में फैला इलाका है। 1976 की संधि के बाद भारतीय मछुआरों को इलाके में मछली पकड़ने का अधिकार मिला। और समझौते के तीन साल बाद श्रीलंकाई मछुआरों के वहां जाने पर रोक लगा दी गई। तब Wadge Bank को कच्चातिवु जैसे निर्जन द्वीप के मुकाबले अधिक सामरिक महत्व का माना गया था

मैप में द्वीप नहीं रहा | कच्चातिवु पर तमिलनाडु की रामनाथपुरम जमींदारी का हिस्सा होने का दावा किया गया है, लेकिन कभी भी इस द्वीप का औपचारिक सीमा निर्धारण नहीं हुआ। इसे भारतीय मानचित्र में भी नहीं दिखाया गया और यह द्वीप दोनों देशों के बीच विवाद का मसला बना रहा।

सेंट एंथनी चर्च | हालांकि, जवाहर लाल नेहरू ने 1.6 किलोमीटर लंबे और 300 मीटर चौड़े कच्चातिवु द्वीप को चट्टानी उभार बताया था, लेकिन तमिलनाडु में यह निर्जन द्वीप 110 साल पुराने सेंट एंथनी चर्च की वजह से जाना जाता है, जहां रामेश्वरम और श्रीलंका से करीब 5000 श्रद्धालु हर साल जाते हैं।

क्या है असलियत

- कच्चातिवु तमिलनाडु में भावनात्मक मुद्दा
- वेज बैंक में तेल और गैस का भंडार मिला
- मछुआरों की दिक्कत है एक साझा समस्या

तेल-गैस भंडार | 1974 और 1976 में हुए समझौते में भारत को कच्चातिवु द्वीप के बदले कई गुना अधिक बड़ा इलाका कोलम्बो से 189 किलोमीटर दूर Wadge Bank के रूप में मिला, जो समुद्री जंतु और मछलियों से समृद्ध इलाका माना जाता है। इसकी अहमियत वहां मिले तेल एवं गैस के बड़े भंडार से और बढ़ गई है, जिसे तेल कंपनियों को देने की प्रक्रिया चल रही है।

मछुआरों को लाभ | सरकार के इस फैसले से Wadge Bank के मछुआरों में भारी रोष है क्योंकि इससे उनकी रोजी-रोटी पर असर तो पड़ेगा ही, वहां के पर्यावरण और पारिस्थितिकी को भी भारी नुकसान पहुंचेगा। हम कच्चातिवु खोने से भारतीय मछुआरों को हुए नुकसान की बात तो करते हैं, लेकिन इससे कई गुना बड़े Wadge Bank इलाके में मछली पकड़ने के एकाधिकार से हुए लाभ को छुपा लेते हैं।

AI Image

राजनीति है जड़ | 1974 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने कच्चातिवु द्वीप श्रीलंका को सौंपने का फैसला तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की सहमति से लिया था। फिर भी तमिल भावनाओं को उभारने के लिए संसद में भारतीय मछुआरों को होने वाले नुकसान के बहाने यह मसला उठाया जाता रहा है। कहा जाता है कि राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर ही करुणानिधि इस मसले पर मौन रहे।

युद्ध नहीं कर सकते | 2014 में तो सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की पार्टियों द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से दलीलें पेश करते हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि कच्चातिवु को हम एक समझौते में श्रीलंका को दे चुके हैं। अब इसे वापस लेने के लिए हमें श्रीलंका से युद्ध लड़ना पड़ेगा।

चीन का पहलू | साफ है कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि को एकतरफा तौर पर निरस्त नहीं किया जा सकता। निश्चित तौर पर, भारत और श्रीलंका के बीच हुई संधि को भारत की संप्रभु गारंटी के तौर पर देखा जाना चाहिए। भारत इस संधि से मुकर नहीं सकता। भारत ने यदि श्रीलंका सरकार के साथ फिर इसे लेकर विवाद खड़ा किया तो इससे दोनों देशों के संबंधों पर बुरा असर पड़ेगा। वह भी ऐसे वक्त, जब श्रीलंका पर चीन तरह-तरह के दवाब और डोरे डाल रहा है। इसलिए इस विवाद को हवा देना भारत के हित में नहीं होगा।

छवि खराब होगी | यदि इस संधि की अवहेलना करते हुए भारत ने कच्चातिवु द्वीप को अपना बताने की कोशिश जारी रखी तो इससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में उसकी छवि खराब होगी। खासकर 'पड़ोसी पहले' की विदेश नीति को झटका लगेगा। श्रीलंका में भारत विरोधी भावनाएं उग्र होंगी और वहां के नेताओं को चीन के साथ सामरिक रिश्ते और गहरे करने का बहाना मिलेगा।

मछुआरों की दिक्कत | वास्तव में, तमिलनाडु के मछुआरों को परेशानी कच्चातिवु के श्रीलंका के पास जाने से नहीं है बल्कि उनके मछली पकड़ने के लिए तय की गई अंतरराष्ट्रीय सीमा से है, जिसे वे अक्सर पार कर जाते हैं। ऐसा होने पर श्रीलंका की नौसेना उन्हें पकड़ लेती है। इसी तरह श्रीलंका के मछुआरों को भी सीमा पार करने पर भारतीय कोस्टगार्ड्स पकड़ लेते हैं। इस मुश्किल को हल करने के लिए दोनों देशों को मिलकर रास्ता निकालना होगा। उन्हें मछुआरों के साथ मानवीय ढंग से पेश आना होगा।

क्या हो रास्ता | श्रीलंकाई नौसेना अक्सर भारतीय मछुआरों पर गोलियां चलाती है और उनकी नौकाओं को जब्त कर लेती है। भारतीय मछुआरे अपनी सीमा में गहरे समुद्र में जाकर आधुनिक मशीनों से मछलियां पकड़ते हैं। इससे श्रीलंका के मछुआरों को नुकसान होता है। मछुआरों की चिंता दूर करने के लिए दोनों देशों ने 2016 में संयुक्त कार्यदल (JWG) भी गठित किया था, लेकिन यह कारगर नहीं साबित हुआ। इसलिए इस मसले का हल निकालने के लिए कोई और रास्ता तलाशना होगा।

(लेखक विदेश और रक्षा मामलों के जानकार हैं)

हिमालय से क्या कहने आया हिम तेंदुआ

क्षेत्र के ग्रामीण भले हिम तेंदुए को देख दहशत में आ गए हों, पर इसे देखना वन्यजीव प्रेमियों का सपना होता है। कहते हैं कर्जन 1902 में स्नो लेपर्ड देखने की ख्वाहिश में गढ़वाल आए थे

व्योमेश चंद्र जुगरान

जोशीमठ के पास स्नो लेपर्ड का नजर आना किसी हिमालयी राज्य के संदर्भ में वाइल्ड लाइफ की अनूठी घटना है। लोगों के बीच किसी मिथक की तरह किस्से कहानियों का पात्र हिम तेंदुआ अमूमन स्नो लाइन के पार यानी 10 हजार फुट की ऊंचाई पर पाया जाता है। मनुष्य को देखकर तुरंत छिप जाने वाला निहायत ही शर्मीला जानवर है यह।

जलवायु परिवर्तन का असर | वाफरवरी के दूसरे सप्ताह जोशीमठ के निकट तपोवन-विष्णुगाड परियोजना क्षेत्र में लोगों ने हिम तेंदुए को विचरते देखा, तो अचरज लाजमी था। यह साइट करीब 4,500 फुट की ऊंचाई पर है। विचरण के लिए इतनी कम ऊंचाई इस जानवर के स्वभाव से जरा भी मेल नहीं खाती। नंदा देवी बायोस्फेयर क्षेत्र के जानकार इस वाकये को जलवायु परिवर्तन से जोड़कर भी देख रहे हैं।

नीचे की राह मुश्किल | वानिचले स्थलों पर बर्फ का बढ़ता जमाव शायद स्नो लेपर्ड को भी नीचे खींच लाया और फिर शिकार की तलाश में उसके कदम बस्ती की ओर मुड़ गए हों। हालांकि बर्फ के अभ्यस्त ऊनी पैरों और भारी-भरकम पंजों वाला यह जीव चट्टानी और पथरीली राहों पर अधिक देर तक टिका नहीं रह सकता। माना जा रहा है कि वह जल्द ही अपनी परंपरागत रिहाइश को लौट गया होगा क्योंकि इलाके में वह फिर नहीं दिखा।

तेंदुए से छोटा जीव | वाहिम तेंदुआ कुछ हद तक स्लेटी फर वाला एक निहायत खूबसूरत जानवर है। सामान्य तेंदुए के मुकाबले यह छोटा होता है, पर पूंछ लंबी होती है। इसकी खाल पर मोटे धब्बे होते हैं और यह अमूमन सवा मीटर लंबा होता है। 'स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट' की 2019 की रिपोर्ट में भारत के हिमालयी क्षेत्र में कुल 718 हिम तेंदुओं का अनुमान लगाया गया है। इसमें 124 के करीब उत्तराखंड में बताए जाते हैं। उत्तरकाशी जिले का गंगोत्री नैशनल पार्क और चमोली जिले का नंदा देवी नैशनल पार्क उनकी पसंदीदा रिहायश है।

बासी खाना पसंद नहीं | उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में ट्रेनर रहे रतन सिंह बताते हैं कि गंगोत्री के भोजवासा क्षेत्र में स्नो लेपर्ड से उनका कई बार सामना हुआ। वह दिखते ही छिप गया। करीब 15 हजार फुट पर चट्टानों पर रहने वाला भरल (सींगों वाला हिरण जैसा पशु) हिम तेंदुए का पसंदीदा शिकार है। इसके अलावा बुग्यालों में चरती भेड़ें भी उसका निवाला होती हैं। आम तेंदुए अधखाए शिकार के आसपास मंडराते रहते हैं और भूख लगने पर इसे फिर खा लेते हैं, वहीं हिम तेंदुआ अपना ही छोड़ा हुआ बासी मांस बिल्कुल नहीं खाता। उसे ताजा शिकार की आदत होती है।

वायसराय की ख्वाहिश | तपोवन-विष्णुगाड परियोजना क्षेत्र के ग्रामीण भले ही हिम तेंदुए को विचरते देख दहशत में आ गए हों, पर इसे देखना वन्यजीव प्रेमियों के लिए किसी सपने की तरह होता है। वर्ष 1899 से 1905 तक ब्रिटिश भारत के वायसराय रहे लॉर्ड कर्जन के बारे में कहा जाता है कि वह 1902 में स्नो लेपर्ड और स्नो बीयर को देखने की ख्वाहिश में गढ़वाल आए थे।

कॉमन रूम

AI Image

कर्जन रोड का किस्सा | खास बात यह है कि दिसंबर 1901 में जब उनके आने की खबर गढ़वाल पहुंची तो सारा प्रशासन हरकत में आ गया। गांवों में काम बंट गए। ग्रामीणों को रात-दिन बेगार में झोंक कर मात्र तीन माह में मध्य और ऊपरी हिमालय के कई सुरम्य स्थलों को समेट कर 200 किलोमीटर लंबा छह फुटा ट्रैक बना दिया। यह आज भी कर्जन रोड के नाम से जाने जाता है और इसे नापने में कम से कम 12 से 15 दिन लग जाते हैं। हालांकि आज इस क्षेत्र के अधिकांश गांव मोटर मार्ग से जुड़ चुके हैं और कर्जन ट्रैक जीर्ण-शीर्ण होकर कई स्थानों पर गुम हो चुका है।

कर्जन निराश लौटे | कहा जाता है कि स्नो लेपर्ड और स्नो बियर देखने का कर्जन का सपना पूरा न हो सका और बीमार होने के कारण वह आधे रास्ते से ही लौट गए। तो क्या नीचे घाटियों से गुजर कर हिम तेंदुआ हिमालय के एक शानदार ट्रैक के जीर्णोद्धार का संदेश छोड़ गया?

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

उत्तराखंड से पलायन रोकने के लिए रोजगार बढ़ाएंगे, शिक्षा-स्वास्थ्य पर भी करेंगे काम

विशुद्ध राजनीति इंटरव्यू

उत्तराखंड में सभी पांच सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। BJP ने यहां की गढ़वाल लोकसभा सीट से पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को उम्मीदवार बनाया है। पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने राज्य की सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव से जुड़े सभी मुद्दों पर **पूनम पाण्डे** ने बात की **अनिल बलूनी** सेः

■ पिछले लोकसभा चुनाव वाला प्रदर्शन दोहराना कितनी बड़ी चुनौती है?

हमने 2014 और 2019 लोकसभा चुनावों में पांचों सीटें जीतीं। पहले हम राजनीतिक दल के तौर पर अपना विजन लेकर लोगों के बीच गए थे, 2019 में हमने जो काम किए थे, उन पर वोट मांगे। अब 10 साल के कार्यकाल के बाद हम अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और उत्तराखंड के स्तर के रिपोर्ट कार्ड को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। यहां लोग ऑल वेदर रोड को देख रहे हैं। केदारनाथ प्राकृतिक आपदा में बर्बाद होने के बाद पूरी केदारपुरी सज गई है। बद्रीनाथ का मास्टरप्लान बन गया है। जोशीमठ का बड़ा ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में एम्स का सैटेलाइट सेंटर आ गया है। कई जगह चॉपर सेवा शुरू कर दी है। रेल, एयर कनेक्टिविटी सब में काम किया है। हर घर नल योजना में उत्तराखंड नंबर एक है। डबल इंजन की सरकार में लगातार काम हुए हैं।

■ डबल इंजन की सरकार तो है, उसकी एंटी-इनकंबेंसी भी होगी, उसका कितना असर होगा?

एंटी-इनकंबेंसी नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत काम हुआ है और लगातार काम हो रहे हैं। यहां BJP के पक्ष में लहर चल रही है।

■ मौजूदा सांसद का टिकट काटकर आपको टिकट दिया गया है। क्या इससे यह संदेश नहीं जाएगा कि कुछ काम नहीं हुआ, इसलिए टिकट बदला?

तीरथ सिंह रावत इतने सीनियर हैं। वह MLC बने, पार्टी के अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय मंत्री, हिमाचल के प्रभारी, दो बार सांसद बने, मुख्यमंत्री भी बने। कोई आदमी किसी नई जिम्मेदारी के लिए तैयार होता है, फिर उसकी जगह कोई और आता है। यह BJP है। यहां एक परिवार का तो विषय है नहीं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हो सकता है तीरथ जी के लिए नया काम पार्टी ने रखा हो। कुछ समय बाद वह काम भी दिखाई देगा।

■ आपकी सीट पर क्या क्या मुद्दे हैं, राज्य में पलायन एक बड़ी चुनौती है?

उत्तराखंड में सबसे बड़ा विषय पलायन का रहा है। जितनी आबादी उत्तराखंड में रहती है, लगभग उतनी ही आबादी बाहर। इसलिए हमारा चिंतन है कि उत्तराखंड में रोजगार आएगा। गांवों में लोगों को रोजगार मिलेगा। स्वयं सहायता समूह में हमने पहली बार देखा कि माताओं-बहनों ने कितना अच्छा काम किया है, जिसकी PM ने भी तारीफ की है। स्वास्थ्य सेवाओं में 'आयुष्मान भारत' से लोगों को लाभ मिल रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठीक किए जा रहे हैं। रोजगार के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य की वजह से भी पलायन होता है और इन सभी पर काम किया जा रहा है। ऐसा होने से लोग यहीं रुकेंगे और जो डेमोग्राफी लगातार बदल रही है वह भी ठीक होगी।

■ विपक्ष का आरोप है कि जब से राज्य में BJP की सरकार है, हिंदू-मुस्लिम दरार बढ़ी है। कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जैसे पहले उत्तराखंड में नहीं होती थीं?

विपक्ष का अपना काम करने का नजरिया है। जैसे- भ्रष्टाचारियों को कई मामलों में ED, CBI बुलाती है तो विपक्ष उसे ऐसे दिखाता है, जैसे घटना कल की हो और मोदी सरकार उन्हें परेशान कर रही है। उसी तरह से उत्तराखंड में हमारी सरकार ने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। जब ऑल वेदर रोड बना तो इतने मंदिर टूटे, इतनी पौराणिक चीजों को शिफ्ट किया गया। यहां तक कि इस देश के उत्थान के लिए जब श्रीनगर का डैम बना, तब धारी देवी जैसी जागृत पीठ को भी अपलिफ्ट कर ऊपर लाया गया। लेकिन, जब अतिक्रमण हटाने का अभियान चला तो पूरे देश में यह नैरेटिव फैलाने की कोशिश हुई कि ये अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं, मजार तोड़ रहे हैं, मदरसे तोड़ रहे हैं। लेकिन, सच यह है कि एक भी घटना ऐसी नहीं हुई। कॉर्बेट के अंदर, राजाजी पार्क के अंदर, हाईवे पर मजार, ये सब अतिक्रमण का आधार है और सरकार ने बस अतिक्रमण हटाने के लिए काम किया।

■ कांग्रेस उम्मीदवार आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती हैं?

कांग्रेस उम्मीदवार के लिए खुद अपनी पार्टी को जिंदा रखना, खुद को लड़ाई में रखना चुनौती हो सकता है। हम अपने विकास के अजेंडे पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस जिस तरह सिमटती जा रही है, उनके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के उत्तराखंड में कुछ पूर्व मंत्री और कुछ विधायक ही बचे रह गए हैं। मेरी लोकसभा सीट में 14 विधानसभा क्षेत्र हैं। उनमें से 13 विधानसभा सीटें पहले से BJP की थीं। जो इकलौती सीट कांग्रेस की थी, उसके विधायक भी कांग्रेस छोड़कर BJP में आ गए। जिस तरह गढ़वाल लोकसभा सीट कांग्रेस मुक्त हो गई, धीरे-धीरे पूरा देश हो जाएगा और यह हो रहा है।

कांग्रेस अग्निवीर को भी मुद्दा बना रही है...

BJP को सफाई देने की जरूरत ही नहीं है कि पार्टी का सेना के लिए क्या नजरिया रहा है। प्रधानमंत्री अपनी दिवाली उनके साथ मनाते हैं बॉर्डर पर। OROP के लिए हमने काम किया। सेना के जो कैंटोनमेंट हैं, जहां सैनिकों के परिवार रहते हैं, वहां कितनी सुविधाएं बढ़ी हैं, ये उनसे पूछिए।

मत-सम्मत www.edit.nbt.in

विषयः केजरीवाल की गिरफ्तारी पर गरमाई राजनीति को लेकर आपका क्या कहना है?

■ आबकारी नीति AAP को ले डूबी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के आंदोलन में भ्रष्टाचार का विरोध किया और अब वे खुद ही भ्रष्टाचारी निकले। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ करोड़ों के घोटाले के आरोप हैं। अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन 15 अप्रैल तक वह जेल की हवा खाएंगे। हालांकि ईडी की रेड में कोई रकम नहीं मिली है। शराब घोटाले की सीबीआई भी जांच कर रही है। शराब घोटाले के आरोपी संजय सिंह को 6 महीने के बाद जमानत मिली है। लेकिन ईडी ने आप पार्टी को कंपनी कहा है। अब आतिशी, सौरभ भारद्वाज पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सभी नेताओं की संपत्ति की जांच होनी चाहिए।

-डॉ मंजु गुप्ता (नवी मुंबई), ईमेल से

■ हठधर्मिता वाली राजनीति

जाहिर है कि आप पार्टी के तीन मंत्री और सांसद पहले से ही जेल में बंद थे, तो केजरीवाल को भी जेल में डालने की जल्दबाजी सरकार की हठधर्मिता को ही उजागर करती है। यह कार्रवाई चुनाव से चार महीने पूर्व या बाद में भी हो सकती थी। हालांकि केजरीवाल का गिरफ्तारी के बाद भी इस्तीफा न देना और पद पर बने रहना भी एक तरह की हठधर्मिता ही कही जाएगी। बीजेपी और आप में हठधर्मिता और एक-दूसरे को नीचा दिखाने की ही राजनीति हो रही है। यह नियम, कानून और नैतिकता से परे लगती है। जेल में बंद लोगों की जमानत होना भी तय है।

-बी. एल. शर्मा, ईमेल से

■ दलदल में फंसी राजनीति

केजरीवाल का प्रादुर्भाव एक गांधीवादी, क्रांतिकारी, आंदोलनकारी अन्ना हजारे के साथ हुई थी। उस समय राजनीतिक गलियारों में सभी जगह भ्रष्टाचार व भ्रष्टाचारियों का बोलबाला था। दिल्ली की जनता ने एक आम आदमी पर विश्वास कर लिया था, लेकिन उसी भ्रष्टाचार की दलदल में केजरीवाल ऐसे फंसे कि अब तिहाड़ जेल से सरकार चलाने की वकालत कर रहे हैं। यह राजनीति का निम्नतम स्तर है। आम जनमानस को सिर्फ एक बार ही मूर्ख बनाया जा सकता है।

-रामलाल एल. राम, ईमेल से

■ बन रहा है अंतरराष्ट्रीय मुद्दा

आश्चर्य है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी न केवल राष्ट्रीय, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। इंडिया गठबंधन में शामिल दल केजरीवाल की गिरफ्तारी से जैसे अशक्त और दिशाहीन हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत आक्षेप और कटाक्ष करने की हिम्मत रखनेवाला वही इकलौता ऐसा व्यक्ति है, जो उनको हराने की हिम्मत रखता है। विपक्ष अपने किसी भी नेता में वह दम-खम नहीं देख पा रहा, इसलिए परेशान और बेचैन है।

-विजय लक्ष्मी शर्मा, ईमेल से

अगली बार का विषयः संजय निरुपम को निकाले जाने पर आपका क्या कहना है?

mat.nbt@gmail.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें hindi.speakingtree.in

दूसरों के प्रति अच्छी भावना का लाभ खुद को पहले मिलता है

बी के शिवानी

आजकल टॉक्सिक रिलेशनशिप पर खूब चर्चा होती है, पर रिश्ते कोई टॉक्सिक नहीं होते। व्यक्ति की सोच टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक होती है, यानी कड़वी, मीठी या नॉर्मल। रिश्ते में दो लोग होते हैं, उनमें से एक अगर अपने सोचने का तरीका सही कर ले, तो रिलेशनशिप मधुर हो जाती है। सामने वाला कैसा भी हो, उसका संस्कार और व्यवहार कुछ भी हो, उसके प्रति विचार और भावनाएं शुभ और सकारात्मक हो जाएं, तो हमारी पॉजिटिव संकल्प की शक्ति धीरे-धीरे उसकी नेगेटिव एनर्जी को समाप्त कर सकती है।

हम खुद ही एक एनर्जी स्पेस हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव यानी हाई और लो एनर्जी लेवल्स होते हैं। इनका प्रभाव दूसरों पर जरूर पड़ता है। अगर हम किसी को अच्छा बोल नहीं पाते हैं, तो कम से कम मन में उसके प्रति शुभ भावना और कामना रखने से हमारी यही हाई थॉट एनर्जी उनके पास पहुंच जाती है और उन्हें अच्छा बना देती है। खास बात यह कि हमारे मन में पैदा हुई हाई एनर्जी का लाभ पहले हमें मिलता है। दूसरे शब्दों में कहें, तो खराब को अच्छा बनाने के प्रयास में सबसे पहले हम अच्छे बन जाते हैं। अगर दूसरों के प्रति हमारे मन में कुछ भी अच्छी भावना नहीं आ रही है तो कम से कम उनके प्रति एक-दो शुभ शब्द बोलते रहो, तो आखिर में उनसे हमारे रिश्ते जरूर बेहतर हो जाएंगे।

यह सच नहीं है कि भावनाएं संकल्पों को जन्म देती हैं। वास्तव में संकल्प से भावना उत्पन्न होती है। अगर किसी के प्रति हमारी भावना ठीक नहीं है, तो भी मन में उसके लिए अच्छे संकल्प लाने से भावनाएं अच्छी हो जाएंगी। धीरे-धीरे ये भावनाएं हमारा दृष्टिकोण बन जाती हैं। एक बार वैसा नजरिया बनने के बाद उसके अनुरूप हमारे कर्म व्यवहार होने लगते हैं। बार-बार ऐसे कर्म करने से वह हमारी आदत, संस्कार और पर्सनैलिटी बन जाते हैं। और जैसी हमारी पर्सनैलिटी होती है, वैसा ही भाग्य बन जाता है। देखा जाए तो हमारी सोच के आधार पर हमारे भाग्य का निर्धारण होता है। इसलिए अगर अपने जीवन, परिवार और रिश्तों को बेहतर बनाना है, तो सबसे पहले हमें संकल्प और सोच को ठीक करना है।

सवाल उठता है कि जब कोई व्यक्ति या सिचुएशन अच्छा नहीं है तो उसके बारे में अच्छे थॉट्स कैसे क्रिएट किए जाएं? हवा पानी का बुरा असर तो शरीर के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन प्रदूषित माहौल के साथ मन को प्रदूषित न होने दें। बाहर का प्रदूषण हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर हम अपने मन की सोच और भावनाओं को तो नियंत्रण में रख सकते हैं। मन को अगर हम आशावादी और सकारात्मक संकल्पों से स्वच्छ, स्वस्थ और शक्तिशाली रखेंगे तो हम प्रदूषित हवा-पानी का बुरा असर अपने शरीर पर कम कर सकते हैं।

वातावरण को अच्छा रखने के साथ-साथ बुरे लोगों को भी बुरे बोल और व्यवहार से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी ही है। इसलिए अपनी सचाई, अच्छाई और पॉजिटिव माइंड पावर के साथ हमें उन्हें टैकल करना है। आज ऐसे लोगों की कमी है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर यह तरीका अपना लें तो आसपास का वातावरण भी सुधर सकता है और रिश्तों में भी वह बात देखने को मिल सकती है। याद रखें अपनी शुभ भावना, शुभ कामना और सद्‌गुणों वाली ऊर्जा से हम न केवल स्वयं में बल्कि दूसरों में भी पॉजिटिव एटिट्यूड विकसित कर सकते हैं।

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्सः(022) 2760 5275। फोन मुंबईः (022) 66353535, 22733535 रेस्पांसः (022) 66353636, 22733636 फैक्सः (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। **स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर** (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

हिन्दुस्तान
1936
सत्य * सार्थक * सदैव

काम करे लोकतंत्र

भारत में चुनावी सरगर्मी के दौर में सत्ता में आने, सत्ता बचाने और सत्ता छीनने की तेज जद्दोजहद के बीच दिल्ली उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी सुखद और स्वागतयोग्य है कि लोकतंत्र को अपना काम करने दिया जाए। दरअसल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के आरोप में पिछले महीने हुई गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली तीसरी याचिका को खारिज कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अगुवाई वाली पीठ ने दिल्ली के उप-राज्यपाल को किसी तरह की सलाह देने से भी मना कर दिया है। केजरीवाल के खिलाफ दायर की गई इन याचिकाओं की दलील है कि अदालत दिल्ली के उप-राज्यपाल को निर्देशित करे और मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया जाए। वास्तव में, पद न छोड़ने या पद से हटाने की राजनीति कतई अदालती विषय नहीं है। किसी भी नेता को किसी पद से हटाने की अपनी स्थापित परंपराएं हैं, उन परंपराओं में अदालती हस्तक्षेप से न्यायपालिका और विधायिका के बीच विवाद की स्थिति बन सकती है। अतः अदालत के रुख की प्रशंसा होनी चाहिए और जो लोग केजरीवाल को हटाने के पक्ष में हैं, उन्हें जिम्मेदार राजनीतिक आकाओं पर दबाव बनाना चाहिए।

नैतिकता का सवाल अलग-अलग ढंग से किसी नेता को परेशान करता है और नेता अलग-अलग ढंग से इस सवाल का जवाब देते हैं। नैतिकता का प्रश्न केवल नेताओं को ही नहीं, बल्कि राजनीतिक पार्टियों को भी परेशान करता है। अब के दौर में जो चलन है, उसके अनुसार, राजनीतिक पार्टियां अपने मतदाताओं के मानस को समझकर ही फैसला लेती हैं। आम आदमी पार्टी में भी चुने हुए सभी विधायक यदि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाए रखने के पक्ष में हैं, तो उन्हें ऐसा करने का हक है। उन्होंने निश्चित ही इस बड़े फैसले के लाभ-हानि पर विचार किया होगा। ऐसे में, उच्च न्यायालय ने उचित ही इशारा किया है कि 'उप-राज्यपाल को हमारे मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। हम उन्हें सलाह देने वाले कोई नहीं हैं। उन्हें कानून के अनुसार, जो भी करना होगा, वह करेंगे।' कहना न होगा, जिस देश में चार करोड़ से ज्यादा मामले अदालत में लंबित हों, वहां राजनीति को अपने हर झगड़े के निपटारे के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहिए। न्यायालय या न्यायपालिका की अपनी सीमा है और राजनीति से जुड़ी नैतिकता की दुहाई देते हुए न्यायालय पहुंचने की परिपाटी हमारी समग्र व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। एक सुखद पहलू है कि इस देश में नैतिकता के सवाल पर पहले अनेक राज्य सरकारें बर्खास्त हुई हैं, पर इधर सरकारों की बर्खास्तगी के प्रति केंद्र सरकार में संवेदना बढ़ी है, तो यह लोकतंत्र की परिपक्वता का भी एक प्रमाण है। सरकारों को मर्जी से नहीं, बल्कि संविधान से प्रेरित होना चाहिए।

जिस देश में चार करोड़ से भी ज्यादा मामले अदालत में लंबित हों, वहां राजनीति को अपने हर झगड़े के निपटारे के लिए अदालत की दहलीज नहीं लांघनी चाहिए।

ध्यान रहे कि अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वह अपनी लड़ाई अदालत और अवाम के बीच बड़ी मुखरता से लड़ रहे हैं। उनके पक्ष में ऐसे नेताओं की बड़ी संख्या है, जो मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को गलत मानते हैं। अदालत भी पहले संकेत कर चुकी है कि अभियोजन चल रहा है और आरोपी को जमानत पर छोड़ा भी जा सकता है। इस मामले के पटाक्षेप में समय लग सकता है, फिर भी अगर कुछ लोग इस मोर्चे पर जल्दी मचाना चाहते हैं, तो उनके पास किसी को पद से हटाने के लिए अकाट्य तर्क होने चाहिए।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 05 अप्रैल, 1949

नेहरू की नसीहत

कांग्रेस ने चूंकि देश का स्वातन्त्र्य-स्वप्न पूरा किया है, स्वतंत्र भारत में उसका महत्व असंदिग्ध है। कांग्रेसजनों की तपस्या से ऐसा हुआ, इसलिए उनके प्रति देश की श्रद्धा भी स्वाभाविक है। आज जब सत्ता उनके पास है, देश का उनसे आशा करना और उन्हें अपना पथ-प्रदर्शक मानना ऐसी बात है जिस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अतः स्वतंत्रता के बाद कांग्रेसजनों की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती बल्कि और बढ़ जाती है। किन्तु, क्या यह कहा जा सकता है कि आम कांग्रेसजनों को इसका खयाल है और वे इस दिशा में उतने सावधान और जागरूक हैं? इधर-उधर की चर्चाएं और सभा-सम्मेलनों एवं समाचारपत्रों में समय-समय पर सामने आने वाली बातें अतिरंजित और अर्द्धसत्य हो सकती हैं, किन्तु यह तो मानना ही चाहिए कि स्थिति जैसी चाहिए वैसी नहीं है।

यह एक शुभ लक्षण है कि कांग्रेस-नेतृत्व दबाव-छिपाव के बजाय स्पष्ट रूप से इसे स्वीकार करके कांग्रेसजनों की दुरुस्ती पर जोर दे रहा है। कांग्रेस के चोटी के नेता सार्वजनिक रूप से कांग्रेसजनों को सदाचरण की प्रेरणा दे रहे हैं और ऐसा रुख अख्तियार करने को कह रहे हैं जो कांग्रेस की शान व महात्मा गांधी का जो नेतृत्व उन्हें मिला उसके अनुरूप हो। प्रधानमन्त्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने युक्त प्रान्त (आज का उत्तर प्रदेश) और बिहार के हाल के दौरे में इस मुद्दे को बड़े जोर के साथ लिया है और ऐसी बातें कही हैं जिनकी ओर हम समस्त कांग्रेसजनों का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक समझते हैं। जवाहरलाल जी ने कहा है, ''कांग्रेस देश के विभिन्न वर्गों के बीच एकता कायम रखने वाली संस्था है। यदि आज कांग्रेस का पतन हो जाता है तो दस-पन्द्रह वर्षों में उसका स्थान ले सकने वाली कोई दूसरी संस्था मुझे दिखलाई नहीं पड़ती। इसलिए कांग्रेसजनों को अपनी जिम्मेदारियां महसूस करनी चाहिए- इसलिए और भी अधिक कि बापू अब हमारे बीच नहीं हैं।'' कांग्रेसजनों की तू-तू मैं-मैं का जिक्र करके नेहरूजी कहते हैं... मतभेद सैद्धान्तिक या विचारधारा को लेकर हों तो समझ में आ सकते हैं और ऐसे मतभेद होना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपसी तू-तू मैं-मैं कभी अच्छी नहीं होती।

महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से बढ़ी बेचैनी

यहां स्कैन करें
रोहित चंदावरकर | वरिष्ठ पत्रकार

यहां 2019 के बाद से सब कुछ बदल गया है। शिव सेना और एनसीपी के दो-दो समूहों में बंटने के बाद, 2024 के चुनाव में चार स्थानीय दल अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं।

लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से लगभग दो सप्ताह पहले महाराष्ट्र में सियासी हलचल अप्रत्याशित मोड़ों से भरी हुई है। दोनों पक्षों के गठबंधन सहयोगियों के बीच आंतरिक कलह की भरमार हो गई है। पिछले सप्ताहांत में तेजी से यह अफवाह फैली कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जनता की नजरों से गायब हो गए हैं। एक क्षेत्रीय समाचार चैनल ने तो यहां तक दावा कर दिया कि भाजपा नेताओं के साथ विवाद के बाद वह 36 घंटे से अधिक समय तक उपलब्ध नहीं थे।

सत्तारूढ़ गठबंधन में ही नहीं, विपक्षी गठबंधन में भी तनातनी का दौर चल रहा है। शिव सेना यूबीटी गुट के नेता उद्धव ठाकरे ने अचानक अपने 17 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए, तो कांग्रेस ने कहा कि पार्टी इस घोषणा से स्तब्ध है, क्योंकि उससे इस बारे में ठीक से सलाह नहीं ली गई थी। अधिकांश पर्यवेक्षकों को महाराष्ट्र के गठबंधनों के बीच ऐसी उथल-पुथल की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही गठबंधन सहयोगियों के बीच सीट-बंटवारे के फॉर्मूले को बिना किसी विवाद के लगभग अंतिम रूप देने के साथ सब कुछ ठीक लग रहा था, पर अब तनाव व्याप्त है।

निस्संदेह, महाराष्ट्र की राजनीति में साल 2019 के बाद से सब कुछ बदल गया है और शिव सेना के साथ-साथ शरद पवार की एनसीपी के भी दो समूहों में विभाजित होने के बाद, अब 2024 की चुनावी लड़ाई में चार दल या चार समूह अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं। इनके अलावा, राज्य में पिछले दो चुनावों में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों का भी उदय हुआ है, जो जोश के साथ लड़ रहे हैं। यह चुनावी लड़ाई बहुरंगी बन गई है। बेशक, विधानसभा में अधिकतम सीटों के साथ भाजपा राज्य की सबसे बड़ी खिलाड़ी है, कांग्रेस अभी दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, क्योंकि शिव सेना और राकांपा दो समूहों में बंट गई हैं। उधर, प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के उद्भव ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग

चार प्रतिशत वोट हासिल किए थे और निर्दलीयों के साथ-साथ असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने भी अनिश्चितता बढ़ा दी है।

एकनाथ शिंदे की शिव सेना को लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर भाजपा के साथ किसी बड़े विवाद की आशंका नहीं थी, क्योंकि महाराष्ट्र में भाजपा के शीर्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने दो साल पहले महायुति सरकार बनाने के बाद से शिंदे से अच्छे रिश्ते साझा किए हैं। हालांकि, पिछले साल जुलाई में सत्तारूढ़ गठबंधन में अजित पवार के अचानक प्रवेश ने स्थिति को अस्थिर कर दिया है। जब से अजित पवार व उनके विधायकों ने सरकार के फैसलों पर दबदबा बनाना शुरू किया है, तब से एकनाथ शिंदे नाराज नजर आ रहे हैं।

शिंदे की बड़ी चिंता यह है कि वह उन सभी 13 लोकसभा सदस्यों को कैसे समायोजित करेंगे, जो उद्धव ठाकरे को छोड़कर उनके साथ आ गए और इससे भी बड़ी चिंता यह है कि अगर भविष्य में भी यही सिलसिला रहा, तो क्या होगा? उन्हें तो अपने 40 विधायकों में से हर किसी का सम्मान करना है, जो उनके साथ आए हैं।

बहरहाल, कुछ सीटें शिंदे और भाजपा में विवाद की वजह बनी रहेंगी। लगभग एक महीने पहले से अचानक भाजपा ने शिंदे पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वह मुंबई उत्तर पश्चिम में गजानन कीर्तिकर को मैदान में न उतारें। शिंदे और कीर्तिकर करीबी हैं, तो शिंदे के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। इसी तरह, पिछले हफ्ते अचानक शिंदे को यह बताया गया कि उनकी पार्टी में बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा को शामिल किया जाना चाहिए। अब शिंदे समूह गोविंदा को उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से लड़वा सकता है। वैसे, मुंबई एकमात्र ऐसी जगह नहीं है, जहां एकनाथ शिंदे को बेचैनी का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीदवारों को लेकर भी असहमति अब गंभीर स्तर पर पहुंचने लगी है। भाजपा की तरफ से शिंदे की शिवसेना के सभी सदस्यों को यह संदेश दिया जा रहा है कि उम्मीदवारों के साथ-साथ चुनाव-चिह्न के बारे में भी अंतिम फैसला भाजपा ही कर रही है।

यह स्पष्ट है कि शिंदे के ज्यादातर सांसद और विधायक इस बात से बहुत चिंतित हैं कि भाजपा लोकसभा चुनाव में हर छोटी चीज पर भी हावी होती जा रही है और सूक्ष्म प्रबंधन कर रही है, ऐसा विदर्भ क्षेत्र में भी दिखने लगा है। कुछ अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि शिंदे सार्वजनिक रूप से शांत दिखते हैं, पर बहुत बेचैन और परेशान हैं। अब यह देखना बाकी है कि क्या उनकी बेचैनी किसी कार्रवाई में तब्दील होगी या वह भाजपा के साथ गठबंधन में मिलकर काम करते रहेंगे।

वैसे, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस दक्षिण मध्य मुंबई में अपने उम्मीदवार के रूप में महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री वर्षा गायकवाड़ और सांगली में विशाल पाटिल के नाम की घोषणा के लिए तैयार थी, जो 2014 की मोदी लहर से पहले कांग्रेस का गढ़ था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भी उद्धव गुट द्वारा अचानक दक्षिण मध्य मुंबई से पूर्व राज्यसभा सदस्य अनिल देसाई की उम्मीदवारी और सांगली से पहलवान चंद्रहार पाटिल की उम्मीदवारी की घोषणा पर आश्चर्य व्यक्त किया। कथित तौर पर राज्य के शीर्ष नेतृत्व ने सांगली व दक्षिण मध्य मुंबई में भी अपने उम्मीदवार खड़े करने की संभावना के बारे में कांग्रेस आलाकमान से परामर्श किया। स्पष्ट है, उद्धव दक्षिण मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई और उत्तर पश्चिम मुंबई से चुनाव लड़कर मुंबई में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं, जबकि अन्य दो गठबंधन सहयोगियों, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के लिए केवल तीन सीटें छोड़ रहे हैं। जाहिर है, उद्धव इस साल के अंत में और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ शहर के नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी के हितों को ध्यान में रख रहे हैं।

भाजपा के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने की बात भले ही पिछले सप्ताह 'इंडिया' की रैलियों में हुई हो, पर जब लोकसभा सीटों के बंटवारे की बात आई, तो इस गठबंधन के सहयोगी एक-दूसरे के लिए इंच भर जमीन छोड़ते नजर नहीं आ रहे। दूसरी तरफ, यानी एनडीए गठबंधन की स्थिति भी इससे बहुत अलग नहीं है। भाजपा हावी होती दिख रही है और एकनाथ शिंदे व अजित पवार जैसे नेता जितना संभव हो, उतना पीछे हटते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर, महाराष्ट्र का चुनाव बहुत ही रोचक बन गया है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

ऊंची उड़ान भरते विमानन क्षेत्र में विस्तारा जैसी चुनौतियां

यहां स्कैन करें
सरस चंद्र त्रिपाठी | पूर्व मेजर व विमानन विशेषज्ञ

विस्तारा एयरलाइन के इस फैसले के बाद कि वह अपनी 300 में से 125 उड़ानें निरस्त कर रहा है, भारतीय उड्डयन क्षेत्र की कमजोरी ही उजागर हुई है। कंपनी का कहना है कि पायलटों की कमी के कारण उसे ऐसा करना पड़ा है, लेकिन वास्तव में पायलटों के अचानक बड़ी संख्या में 'छुट्टी' पर चले जाने के कारण यह समस्या पैदा हुई है। इस पूरे मसले की जड़ में टाटा ग्रुप का वह फैसला है कि वह अपने आधिपत्य वाली दोनों विमानन सेवाओं (विस्तारा और एअर इंडिया) का विलय करेगा। पायलट इसलिए विलय नहीं चाहते, क्योंकि विस्तारा प्रीमियम एयरलाइन मानी जाती है, जबकि सरकारी संरक्षण में होने और घाटे में रहने के कारण एअर इंडिया की छवि बहुत अच्छी नहीं है। एक अन्य वजह, विस्तारा के पायलटों के वेतन-भत्ते में कटौती की आशंका भी है। विश्व में आमतौर पर एक पायलट को महीने में 70 से 80 घंटे तक की फ्लाइट दी जाती है। विस्तारा के पायलट भी करीब 70 घंटे औसतन हवाई जहाज उड़ाते रहे हैं, लेकिन अब उन्हें डर है कि विलय के बाद उनका 'फ्लाइट आवर' 40 घंटा किया जा सकता है, जिससे उन्हें प्रति माह एक से डेढ़ लाख रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ सकता है।

घरेलू उड़ान के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। हमसे ऊपर सिर्फ चीन व अमेरिका ही हैं।

भारत में विमानन क्षेत्र की तस्वीर साल 2003-04 के उस फैसले के बाद बदली है, जब वाजपेयी सरकार ने उड्डयन क्षेत्र के निजीकरण का निर्णय लिया। इसकी शुरुआत हवाई अड्डों से की गई और उनको विमानपत्तन प्राधिकरण से निकालकर निजी हाथों को सौंप दिया गया। इसके अच्छे परिणाम सामने आए। साल 2011-12 तक नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तो दुनिया के बेहतरीन हवाई अड्डों में शुमार हो गया था। यही कारण रहा कि मोदी सरकार ने भी 27 हवाई अड्डों के निजीकरण की नीति अपनाई। आलम यह है कि देश के कई हवाई अड्डे यात्री सुविधा, कमाई, सेवा आदि के मामले में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तो घरेलू उड़ान के मामले में भी भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। हमसे ऊपर सिर्फ चीन और अमेरिका हैं।

देश में विमानन क्षेत्र का विकास इससे भी पता चलता है कि कारोबार व बाजार पर शोध करने वाली प्रसिद्ध संस्था 'मोर्डोरइंटेलिजेंस' के अनुसार, भारत का विमानन क्षेत्र अगले पांच-छह वर्षों में दोगुना हो जाएगा। फिलहाल यह करीब 14 अरब डॉलर का क्षेत्र है, जिसके 2030-31 तक 28 अरब डॉलर का होने का अनुमान है। इतना ही नहीं, आंकड़े ये भी हैं कि 2017 में करीब 14 करोड़ लोगों ने हवाई जहाज से यात्रा की थी, जो 2023 तक बढ़कर 26 करोड़ को पार कर गया था। माना जा रहा है कि 2030 तक सालाना 46 करोड़ यात्री हवाई यात्रा करेंगे। यानी, यात्रियों की संख्या के मामले में प्रति छह वर्ष में लगभग 40 फीसदी की वृद्धि हो रही है।

हालांकि अब भी कुछ चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी बाधा 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' है, यानी इस कारोबारी क्षेत्र को आसान बनाने की जरूरत है। इस पर सरकारी तंत्र का शिकंजा कम हुआ है, फिर भी यह अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर का नहीं हो सका है। इतना ही नहीं, अधिकतर हवाई अड्डे महानगरों और बड़े शहरों में हैं। घरेलू उड़ानों को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि छोटे शहर भी हवाई सेवा से जुड़ें। तीसरी बड़ी बाधा 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' की है, यानी यात्री हवाई अड्डे से अपने घर तक कैसे जाए?

एक बाधा आतंकवाद और उससे संबंधित सुरक्षा व्यवस्था की भी है। यूरोप के अनेक देशों में, विशेषकर नोर्डिक देशों में कोई यात्री हवाई जहाज के पास तक बिना किसी सुरक्षा जांच के जा सकता है, लेकिन हमारे देश में श्रीनगर जैसे एयरपोर्ट पर हवाई अड्डे से करीब दो-ढाई किलोमीटर दूर ही पूरे सामान की एक बार स्कैनिंग होती है, फिर हवाई अड्डे पर उसे दोबारा जांचा जाता है। पांचवीं चुनौती प्रशिक्षित कर्मियों का अभाव है। देश में उड्डयन क्षेत्र से जुड़े विषयों के प्रशिक्षण के लिए अच्छे संस्थानों की कमी है, विश्वविद्यालय तो दूर की बात हैं। जाहिर है, जब देश में आमदनी बढ़ने से हवाई यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, तब यह आवश्यक है कि उन्हें पर्याप्त सुविधाएं भी मिले। उम्मीद है, इन तमाम चुनौतियों का जल्द हल निकाला जाएगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

विराट वृक्षों के बीज

एक राजा रोज सुबह सूर्योदय के समय घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का चक्कर लगाने जाता। वह देखता कि कैसे उसका राज्य विकसित हो रहा है, कैसे रोज-रोज अधिक सुंदर होता जा रहा है और आनंदित होता। उसका सपना था कि उसका राज्य पृथ्वी पर सबसे सुंदर जगह हो।

राजा जब घूमने जाता, तो रोज उसकी नजर एक बूढ़े पर पड़ती, जो लगभग सौ साल का होगा। वह हमेशा अपने बगीचे में काम कर रहा होता- कभी बीज बोता हुआ, तो कभी पौधों को पानी देता हुआ। राजा रोज उसे लगन से काम करते देखकर हैरान होता और कुछ देर घोड़ा रोककर उसे देखता रहता। हैरानी की बात यह थी कि वह जो बीज बो रहा होता, वह उन वृक्षों के थे, जिन्हें अपने यौवन में पहुंचने में दशकों लगने वाले थे। राजा हैरान था कि उस वृद्ध के पांव कब्र में लटके हुए हैं, फिर वह किनके लिए बीज बो रहा है? उसे तो इन वृक्षों के फूल और फल देखने को भी नहीं मिलने वाले थे। यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि वह अपने श्रम का परिणाम देखने के लिए बचेगा।

एक दिन राजा स्वयं को रोक नहीं पाया। वह घोड़े से उतरा और उसने बूढ़े से पूछा, 'मैं रोज यहां से गुजरता हूं और एक प्रश्न रोज मुझमें उठता है। आज वह प्रश्न पूछने से मैं खुद को रोक नहीं सका। आखिर ये बीज आप किसके लिए बो रहे हैं? ये वृक्ष तो आपके जा चुकने के बाद ही प्रौढ़ होंगे।'

बूढ़े व्यक्ति ने राजा को देखा और हंसते हुए बोला, 'महाराज, यदि मेरे पुरखों ने भी ऐसा ही सोचा होता, तो मुझे कभी इस बगीचे में लगे वृक्षों के फूल और फल न मिले होते। मेरे पुरखों ने जो बीज बोए थे, उनके फल मैंने खाए। लोग दूर-दूर से यह बगीचा देखने आते हैं, क्योंकि यहां हजारों साल पुराने वृक्ष खड़े हैं। मैं तो बस वही कर रहा हूं, जो कुछ धन्यवाद के रूप में कर सकता हूं और जहां तक बीज बोने की बात है... तो बसंत में जब इन बीजों से उपजे पौधों में हरे-हरे पत्ते निकलेंगे, तो उतना भर काफी है यह भूल जाने को कि मेरी उम्र क्या है। क्या वह कम आनंद होगा?'

जब आप इस संसार से विदा होंगे, तब संतुष्टि से तभी विदा हो पाएंगे, जब आपने इसे कुछ और अधिक रहने योग्य बनाया होगा, इसमें थोड़ा और अर्थ डाला होगा।

याद रखो, जब आप संसार से विदा होंगे, तब संतुष्टि से तभी विदा हो पाएंगे, जब आपने इसे कुछ और अधिक रहने योग्य बनाया होगा, इसमें थोड़ा और अर्थ डाला होगा। इसमें थोड़ा और नृत्य जोड़ा होगा, थोड़ा और उत्सव भरा होगा। यदि आपने इसमें थोड़ा और हास्य जोड़ा, कुछ नए दीये जलाए, जिन्होंने संसार से थोड़ा-सा भी अंधकार मिटाया, तो आप परम आनंद में विदा होंगे, एक गहन परितृप्ति के साथ!

इसलिए सृजनात्मक बनें, इस अस्तित्व को उससे थोड़ा अधिक सुंदर बनाएं, जैसा आपने इसे पाया था।

ओशो

कैलाश सत्यार्थी | नोबेल विजेता

करुणा हममें से प्रत्येक में छिपी हुई है। हमें तो बस अपने भीतर इसकी चिनगारी को प्रज्ज्वलित करने और एक न्यायसंगत दुनिया के लिए इसे वैश्विक बनाने की जरूरत है।

नियमों के तहत चल रही जेल से सरकार

आम आदमी पार्टी के संयोजक व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से अपनी सरकार चला रहे हैं। वह वहीं से निर्देश भेज रहे हैं। इसके खिलाफ कुछ लोग नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं, मगर हमारे यहां राजनीति में नैतिकता बची ही कहां है? यदि सियासी दलों में नैतिकता होती, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार ही नहीं किए जाते। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री का काम ही होता है नीतियां बनाना, फिर चाहे वह शराब नीति हो या जल और बिजली नीति। उसका फैसला सही था अथवा गलत, उससे राजस्व का फायदा हुआ या नुकसान, इसका निर्णय आम जनता चुनाव में ईवीएम के माध्यम से करती है। सवाल यह भी है कि यदि कोई नीति बनाना गलत है, तब तो इस प्रक्रिया में शामिल सभी मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी और एलजी की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन निशाना बनाया गया सिर्फ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को। अरविंद केजरीवाल से लाख विरोध सही, परंतु वह भ्रष्टाचारी होंगे, यह मान लेना फिलहाल मुमकिन नहीं, इसलिए जेल से सरकार चलाने के उनके फैसले का समर्थन रहेगा। जब इस देश में आदर्श, नैतिकता व शुचिता जैसे शब्द शब्दकोश में ही अच्छे लगते हों, तो फिर शर्म आने की बात ही छोड़ देनी चाहिए। दरअसल, मौजूदा समय में आदर्श, नैतिकता और अंतरात्मा की बातें करने वाले ज्यादातर ढोंगी हैं, जो अपनी सुविधानुसार इनका प्रयोग करते हैं। वे खुद अनैतिक होते हैं, लेकिन जनता को दुहाई नैतिकता की देते हैं। ऐसे लोगों की अंतरात्मा नहीं होती, इसलिए उनकी बातें अनसुनी ही कर देनी चाहिए।

मोहम्मद जाहिद, टिप्पणीकार

उचित फैसला

अरविंद केजरीवाल काफी जहीन नेता हैं। देश की कठिन प्रतियोगी परीक्षा में उन्होंने सफलता हासिल की है। वह जानते हैं कि किन कानूनी दांव-पेच का लाभ उठाकर उनको फंसाया जा सकता है। यही कारण है कि उन्होंने अब तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। वास्तव में, यह घटनाक्रम राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए अध्ययन का विषय है। वे इससे लोकतंत्र व भारतीय संविधान की खूबसूरती सीख सकते हैं। रही बात जेल से सरकार चलाने की, भारत में संभवतः ऐसे सांविधानिक प्रावधान नहीं हैं, जिनमें यह कहा गया हो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को महज आरोप लगने पर या न्यायिक हिरासत में भेजने मात्र से पद से इस्तीफा देना होगा। अगर ऐसा होता रहा, तब तो कोई केंद्रीय जांच एजेंसी किसी भी मुख्यमंत्री पर आरोप मढ़कर उसे सत्ता से दूर कर सकती है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल ने उचित ही अपना इस्तीफा नहीं देने का फैसला किया है।

अहसान अंसारी, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

जेल से सरकार

इस्तीफा देकर नैतिकता दिखाएं मुख्यमंत्री

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश के इतिहास में लंबे समय तक याद रखे जाएंगे। आने वाली पीढ़ियां किताबों में यही पढ़ेंगी कि कैसे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने ऊपर लगे आरोपों के बावजूद नैतिकता को ताक पर रखकर शासन करते रहे। देखा जाए, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को सांविधानिक पद से इस्तीफा देकर संविधान की रक्षा करते हुए अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का मजबूती से सामना करना चाहिए। इस देश में भ्रष्टाचार के आरोपी एकमात्र मुख्यमंत्री केजरीवाल नहीं हैं। इससे पूर्व जयललिता, लालू प्रसाद यादव, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन जैसे तमाम मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरने के बाद जेल जा चुके हैं, पर जेल जाने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दिया। हेमंत सोरेन का उदाहरण तो सबसे ताजा है। मगर केजरीवाल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इससे यही पता चलता है कि वह किसी भी तरह से कुरसी पर बस बने रहना चाहते हैं।

जेल से शासन चलाना हास्यास्पद है। इससे अन्य देशों में भारत की छवि बिगड़ रही है। दूसरे देश तो यही जानना चाह रहे होंगे कि क्या भारत का संविधान इसकी इजाजत देता है? बेशक, भारतीय संविधान इस सवाल पर मौन है, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि संविधान में दर्ज होने से बची रह गई जरूरी बातों को दरकिनार करके हम गलती पर गलती करते जाएं। क्या भारत का लोकतंत्र इस बात की इजाजत देता है कि चोर, डकैतों, अपराधियों के सुधार-गृह, यानी जेल से मुख्यमंत्री अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करें? यह भी तो उचित नहीं है।

ऐसी किसी भी जांच में वक्त लगता है। ऐसा भी नहीं है कि केजरीवाल को जेल में डालकर मामला खत्म कर दिया जाएगा। जांच एजेंसियां सघन जांच में जुटी हुई हैं, इसलिए मुख्यमंत्री को धैर्य रखना चाहिए और न्यायपालिका पर विश्वास करना चाहिए। अगर वह सही हैं, तो बेशक कुछ वक्त लगेगा, लेकिन उनको न्याय जरूर मिलेगा। हालांकि, एजेंसी को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जांच के दायरे में कोई निर्दोष न आ जाए। शराब घोटाले की चिनगारी कहां-कहां उड़ने वाली है, यह अभी तक साफ नहीं हो सका है। हालांकि, आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने यह भी कहा कि एक करीबी के जरिये उनको खरीदने के कोशिश हुई और यह कहा गया कि बात न मानने पर अगले एक महीने में उनके साथ कुछ अन्य आप नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे बयान जांच एजेंसी की छवि धूमिल कर सकते हैं, इसलिए जल्द ही इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।

युगल किशोर राही, टिप्पणीकार

मूल्यों के अभाव में जीवन का कोई औचित्य नहीं

कांग्रेस की बीमारी

चुनावों के अवसर पर नेताओं का इस या उस दल में जाना कोई नई-अनोखी बात नहीं, लेकिन जब दल विशेष से बड़ी संख्या में नेता किनारा करने लगें तो उसके खिलाफ माहौल बनता है और विरोधी दलों को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलती है। कांग्रेस के एक के बाद एक नेता जिस तरह पार्टी छोड़ रहे हैं, उससे तो यह लगता है कि भगदड़ की सी स्थिति है। कांग्रेस छोड़ने वालों में नए नाम हैं मुक्केबाज विजेंदर सिंह, गौरव वल्लभ, संजय निरुपम और बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा। इसके पहले भी कई नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। वास्तव में इसकी गिनती करना कठिन है कि बीते एक माह में कितने नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है। इनमें से कुछ बड़े और जनाधार वाले नेता भी हैं, जैसे अशोक चह्वाण, मिलिंद देवड़ा, रवनीत सिंह बिट्टू आदि। हैरानी नहीं कि आने वाले दिनों में कुछ और नेता कांग्रेस को नमस्ते करते दिखें। यह ठीक है कि अन्य दलों से इक्का-दुक्का नेता कांग्रेस में भी आए हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उसका साथ छोड़ने वालों की संख्या कहीं अधिक है। जब भी कोई नेता अपने दल को छोड़ता है तो कुछ न कुछ कारण बताता है। आम तौर पर उसकी बातों पर गौर करने के बजाय यह कहा जाता है कि वह पार्टी छोड़ने का बहाना तलाश रहा था, लेकिन कई बार वह खरी बात भी कह रहा होता है। बतौर उदाहरण संजय निरुपम का यह कहना सही है कि कांग्रेस में शक्ति के कई केंद्र बन गए हैं और राहुल गांधी तो वामपंथी सोच वालों से घिरे ही हैं, पार्टी पर भी वामपंथियों का कब्जा हो गया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं की ओर से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करने का विषय उठाते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस वाम दलों की अवधारणा वाले उस सेक्युलरिज्म से ग्रस्त हो गई है, जिसमें धर्म और आस्था का कोई मूल्य-महत्व नहीं। निःसंदेह कांग्रेस की तरह कई अन्य दलों के नेता भी अयोध्या नहीं गए, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरह वहां जाने का निमंत्रण ठुकराया, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़ने के कारण गिनाते हुए यह कहा कि वह सनातन धर्म के विरोध में नारा नहीं लगा सकते। ध्यान रहे कि जब द्रमुक नेताओं ने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया जैसा बताया, तब कांग्रेस नेतृत्व उनकी आलोचना करने का साहस नहीं जुटा सका। गौरव वल्लभ ने यह भी कहा कि वह वेल्थ क्रिएटर्स यानी उद्यमियों को सुबह-शाम गाली नहीं दे सकते। राहुल गांधी एक अर्से से ठीक यही कर रहे हैं और वह भी तब, जब खुद उन्होंने कई बड़ी कंपनियों के शेयर ले रखे हैं। इसकी आशा तो नहीं की जाती कि कांग्रेस नेतृत्व संजय निरुपम और गौरव वल्लभ की बातों पर ध्यान देगा, लेकिन सच यही है कि इन नेताओं ने कांग्रेस की बीमारी बताने का काम किया है।

बेहतर समन्वय जरूरी

राजधानी पटना में उत्पाद विभाग ने बीते बुधवार को धान की भूसी के बीच शराब की बड़ी खेप बरामद की। राज्य में पूर्ण शराबबंदी के बीच खासकर चुनाव के मौके पर ऐसी बरामदगी काफी चिंताजनक है। इससे यह भी पता चलता है कि सरकार के हरसंभव प्रयास के बाद धंधेबाजों का सिंडिकेट टूटा नहीं है। इतना ही नहीं, वे परिवहन विभाग के नियमों की भी धज्जियां उड़ा रहे। जिस ट्रक से यह खेप बरामद की गई, उससे बिहार और उत्तर प्रदेश के दो नंबर प्लेट बरामद किए गए। आशंका व्यक्त की गई है कि पंजाब में निर्मित यह शराब धंधेबाजों ने चुनाव में खपाने की मंशा से मंगवाई थी। पंजाब से बड़ी मात्रा में राज्य में शराब की हो रही तस्करी का मामला चुनाव आयोग की भी नजर में है। आंकड़ों के अनुसार दूसरे राज्यों से सबसे अधिक शराब बिहार में पंजाब से आ रही है। इसके बाद हरियाणा और चंडीगढ़ का नंबर आता है। आयोग को भी आशंका है कि तस्करी के शराब का उपयोग लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए हो सकता है। इसे लेकर बीते दिनों दोनों राज्यों के मुख्य सचिव के बीच आनलाइन बैठक भी हो चुकी है। अच्छी बात है कि शिकायत मिलने पर पंजाब सरकार लाइसेंस रद करने तक की भी कार्रवाई कर रही है। किंतु, इस चुनौती से निपटने के लिए उत्पाद व मद्य निषेध विभाग को संबंधित अन्य विभागों के साथ बेहतर समन्वय करने की जरूरत है। यह भी देखना जरूरी है कि पुलिस या किसी भी विभाग का ऐसा कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जिस पर शराबबंदी का उल्लंघन करने या तस्करों का साथ देने का आरोप है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है या नहीं। अगर, ऐसे मामले न्यायालय में लंबित हैं तो उसकी यथोचित पैरवी हो रही अथवा नहीं, ताकि आरोपित को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।

> सरकारी तंत्र द्वारा पूरी तरह यह प्रयास किया जाना चाहिए कि किसी भी स्थिति में वोटरों को लुभाया नहीं जा सके।

कह के रहेंगे माधव जोशी

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या टी-20 विश्व कप टीम में मयंक यादव को शामिल किया जाना चाहिए?

आज का सवाल

क्या एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ना उसकी चुनावी संभावनाओं को कमजोर करेगा?

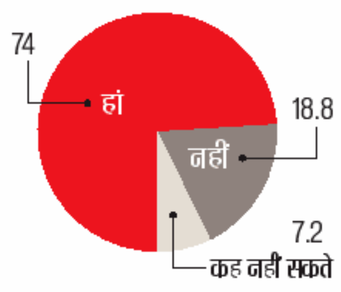

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

सीएए के बाद एनआरसी भी चाहिए

आर. विक्रम सिंह

हमें यह तो जानना ही चाहिए कि आखिर देश में भारतीय नागरिकों की कुल संख्या कितनी है

जो गैर-मुस्लिम 1947 में रेडक्लिफ रेखा के उस पार पाकिस्तान में छूट गए थे, उनका अपराध क्या था? सत्ता अधिग्रहण की जल्दबाजी में भारतीय नेताओं ने जिन्ना की मजहबी सत्ता से उनका सौदा कर लिया। उन्हें राहत पहुंचाने के आवश्यक दायित्व की पूर्ति 75 वर्ष बाद अब नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के माध्यम से की जा रही है। सीएए के बाद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी की जरूरत है। इस बीच सीएए को लेकर कुछ अनावश्यक टिप्पणियां की जा रही हैं, जिनका प्रतिकार भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिकी राजदूत को यह कहकर उचित जवाब दिया, 'आप भारत विभाजन का इतिहास नहीं जानते, लिहाजा सीएए को नहीं समझ सकते। उनके प्रति हमारा ऐतिहासिक दायित्व है, जिनके साथ विभाजन ने अन्याय किया।' 2014 से पहले हमारे स्वयंभू सेक्युलर नेताओं का यह मानना था कि पाकिस्तान को भारत में सांप्रदायिक आतंकवाद का दोषी करार देने का परिणाम वोट बैंक की राजनीति की दृष्टि से बुरा होगा।

राष्ट्रवाद के उभार की संभावना से कभी नेहरू भी परेशान थे, खासकर तब जब तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने का फैसला किया था। इस देश में राष्ट्रीयता के सापेक्ष सांप्रदायिक पक्षधरता का संघर्ष आज से नहीं, बल्कि आजादी के प्रारंभ से ही चल रहा है। याद रहे कि तुर्किये के खलीफा की बहाली का मुद्दा आजादी के आंदोलन की मुहिम के साथ जुड़ा। यह उन शुरुआती कारणों में से एक था, जिनसे भारत विभाजन की भूमिका बनी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने के बाद यही मोपला जैसे भीषण नरसंहार और तमाम दंगों का कारण बना। विभाजन के बाद भी वोट बैंक की चुनावी बाध्यताओं के कारण इतने वर्षों बाद भी यदि वह समीकरण ज्यों का त्यों है तो उसका कारण है विभाजन का आधा-अधूरा अनुपालन।

कांग्रेस नेतृत्व अंग्रेजों के साथ तो भारत के सांप्रदायिक विभाजन पर सहमत हो गया, लेकिन जब जमीनी स्तर पर अनुपालन की बारी आई तो उसकी नीति भारत के मुस्लिम समाज को यहीं रोक लेने एवं सीमापार के हिंदुओं को यहां न आने देने की बन गई। यह बात और है कि तब कांग्रेस के नेता दिल्ली के इलाकों में घूम-घूम कर पाकिस्तान जाने वालों को वहां जाने से रोक रहे थे। शायद कांग्रेस को यह आशंका रही होगी कि भारत यदि हिंदुओं का देश बन गया तो उसकी भावी राजनीति का क्या होगा। इसीलिए नेहरू ने 1950 में हुए नेहरू-लियाकत पैक्ट में आबादी हस्तांतरण में यथास्थिति कायम रखने एवं अपने-अपने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने के वादे पर हस्ताक्षर किए। नेहरू जानते थे कि जो देश मजहब के आधार पर ही बना है, उसके लिए तो हिंदू काफिर मजहबी विस्तार के लक्ष्य हैं। वह भला अल्पसंख्यकों को सुरक्षा क्यों देगा? उस समझौते का परिणाम आज हमारे सामने एक भीषण त्रासदी की तरह है। जहां भारत में अल्पसंख्यक आबादी 9 प्रतिशत से बढ़कर आज 15 प्रतिशत के आसपास है, वहीं पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू 23 प्रतिशत से घटकर करीब 2 प्रतिशत रह गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने इस पर सवाल उठाया कि आखिर कहां गए वे करोड़ों हिंदू? आजादी के 75 वर्षों बाद एक नेता ने यह सवाल तो पूछा। कांग्रेस के पास इन सवालों का कोई जवाब न तब था और न अब है। नेहरू के स्थान पर राष्ट्रवादी चरित्र के किसी नेता के पास उस समय नेतृत्व रहा होता तो संभवतः ऐसी विषम स्थिति निर्मित नहीं हुई होती। तब सिंध के हिंदूबहुल जिलों को लेकर 'स्वायत्त हिंदू एनक्लेव' बनाना हमारा लक्ष्य हो सकता था, लेकिन जब सत्ता वोट बैंक से संचालित हो तो ऐसे लक्ष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्हें हिंदुओं का दमन स्वीकार्य था, लेकिन उनकी सुरक्षा-संरक्षण नहीं।

अवधेश राजपूत

भारत में अल्पसंख्यकों को चुनावी समीकरण का हिस्सा बनाकर भारतीय राजनीति का प्रारंभिक विमर्श गढ़ा गया। इसीलिए पाकिस्तान, उर्दू, अलीगढ़ स्कूल के प्रतिबद्ध इतिहास लेखक भारत के राजनीतिक विमर्श के नियंत्रक बने रहे। वोटों के लालच में असम में इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी बसाए गए कि वहां की जनसांख्यिकी का अनुपात ही बिगड़ गया, लेकिन किसी ने कोई चिंता नहीं की। सत्ताधारी दल के नेताओं ने समझौता एक्सप्रेस बमकांड एवं मुंबई पर हुए आतंकी हमले के बाद हिंदू-आतंकवाद की छद्म परिभाषाएं गढ़ने में बड़ा परिश्रम किया। दूषित लक्ष्यपूर्ति के लिए उन्होंने कर्नल पुरोहित जैसे सेनाधिकारियों को भी नहीं बख्शा।

जब हम सीएए जैसे नागरिकता प्रदान करने वाले कानून का विरोध देखते हैं तब समझ में आता है कि तथाकथित सेक्युलर तत्वों के असल इरादे क्या हैं। हमने अनुच्छेद-370 को हटाने का विरोध भी देखा है। यदि विरोध कश्मीर में हुआ होता तो इसे समझा जा सकता था, लेकिन शेष भारत के अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद-370 से इतना लगाव क्यों? उन्हें तो इसका स्वागत करना चाहिए था कि कश्मीर के मुस्लिम भारत के बृहद् मुस्लिम समाज के साथ मजबूती से जुड़ रहे हैं। इस विरोध ने छिपे हुए सांप्रदायिक राजनीतिक विमर्श के निहितार्थ को पूरी तरह उजागर कर दिया। जब कुछ नेता पाकिस्तान से आए हिंदू-सिख शरणार्थियों को कोसते हुए दिखते हैं, तब हमें 1947 के नेहरू की याद आ जाती है।

सीएए तो वह कानून है जो हमें अपने लोगों की चिंता करना और उनके भविष्य को संवारने की ओर उन्मुख करता है। इस कानून की स्वीकृति के साथ स्पष्ट मानस का एक दूसरा ही भारत उभर रहा है, जिसे हम जाति, संप्रदाय, वैचारिक विभ्रम के जंगल में वर्षों से खोज रहे थे। सीएए के विरुद्ध दो सौ से अधिक याचिकाएं दायर करने वाले लोग राष्ट्र के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। यह तय है कि वे एनआरसी की पहल का और अधिक विरोध करेंगे। समझना कठिन है कि वे यह क्यों चाहते हैं कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी देश को अपने वैध नागरिकों की सूची बनाने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए? सीएए तो एक प्रारंभ है। विलंब से ही सही, लेकिन हमें यह तो जानना चाहिए ही कि आखिर देश में भारतीय नागरिकों की कुल संख्या कितनी है। ध्यान रहे कि असम में एनआरसी बन चुका है और वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है।

(लेखक पूर्व सैन्य अधिकारी एवं पूर्व प्रशासक हैं)

response@jagran.com

राजनीति में नैतिकता का सवाल

हरेंद्र प्रताप

इस्तीफा न देने की केजरीवाल की जिद ने ऐसा संवैधानिक संकट पैदा कर दिया है, जिसका हल नहीं दिखता

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी कह रही है कि वह जेल से ही सरकार चलाएंगे। केजरीवाल भी ऐसा कह रहे हैं। इसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि क्या भारत का संविधान इसकी अनुमति देता है? क्या जेल से सरकार चलाना उचित है? मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है। केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। हालांकि उसने इस पर सुनवाई से इन्कार कर दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि 'इस मुद्दे पर निर्णय लेना दिल्ली के उपराज्यपाल (या भारत के राष्ट्रपति पर निर्भर है। कभी-कभी व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है, लेकिन यह अरविंद केजरीवाल का निजी फैसला होगा कि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना है या नहीं।' अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल इन दिनों मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर जनता के नाम केजरीवाल की भावनात्मक अपील जारी कर रही हैं। इससे चर्चा का बाजार गर्म है कि क्या अरविंद केजरीवाल की पत्नी उनकी उत्तराधिकारी बनने जा रही हैं? ईडी द्वारा पूछताछ के लिए समन पर समन के बाद भी हाजिर न होकर अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव की घोषणा का इंतजार तो नहीं कर रहे थे, ताकि लोगों की सहानुभूति प्राप्त की जा सके? सवाल कई हैं, पर सबसे बड़ा सवाल राजनीति में नैतिकता का है।

यह 12 जून, 1975 की बात है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी मानते हुए उनकी जीत को अवैध करार दिया। इसके साथ ही उनके छह वर्ष के लिए चुनाव लड़ने पर रोक भी लगा दी। उस समय देश में जेपी आंदोलन चल रहा था। उच्च न्यायालय के निर्णय के सिलसिले में पत्रकारों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण से पूछा-इंदिरा गांधी अब क्या करेंगी? उन्होंने कहा-अब वह इस्तीफा देंगी। पत्रकारों ने फिर से पूछा कि अगर वह इस्तीफा देने से इन्कार कर दें तो क्या होगा? जयप्रकाश जी ने कहा-तब अनर्थ हो जाएगा। इतिहास गवाह है कि इंदिरा गांधी ने इस्तीफा न देकर देश पर आपातकाल थोप दिया। एक प्रकार से उन्होंने लोकतंत्र के साथ राजनीतिक नैतिकता का भी अपहरण किया। हालांकि इसका दुष्परिणाम उन्होंने भुगता। 1977 में इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव हार कर सत्ता से बेदखल हो गईं। 1977 की घटना के बाद नेताओं में एक भय पैदा हुआ। चारा घोटाले में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जब जेल जाने लगे तो उन्होंने पद से इस्तीफा देकर पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। चूंकि बिहार में विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी है, अतः राबड़ी देवी को विधान परिषद का सदस्य बनाकर जेल में रहते हुए भी सत्ता संचालन का काम एक तरह से लालू यादव ही करते थे। एक बार मुख्यमंत्री जयललिता के सामने जब जेल जाने की नौबत आई तो उन्होंने इस्तीफा देकर अपने भरोसे के नेता को मुख्यमंत्री बना दिया था। पिछले दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, पर उन्हें भी इस्तीफा देकर चम्पाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। उनकी मंशा तो यही थी कि पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाकर जेल में रहते हुए सत्ता का संचालन करें। इसके लिए जल्दबाजी में एक सीट भी खाली कराई गई, पर एक डर यह था कि अगर छह माह के भीतर चुनाव नहीं हुए तो कल्पना सोरेन को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। हेमंत सोरेन अभी जेल में हैं, पर भविष्य की रणनीति पर काम चल रहा है। उनकी पत्नी राजनीति में आ गई हैं और जल्द चुनाव लड़कर विधायक बनने की तैयारी भी कर रही हैं।

संवैधानिक संकट खड़ा करते केजरीवाल ● फाइल

हेमंत सोरेन की तरह ही जेल गए अरविंद केजरीवाल की पत्नी को उनका उत्तराधिकारी बनाने की मांग उठ रही है। मौजूदा कानूनी प्रविधानों के अनुसार दो या दो वर्ष से अधिक की सजा होने पर जनप्रतिनिधियों को पद छोड़ना पड़ता है, लेकिन नेताओं ने इसका तोड़ पत्नी को सत्ता में भागीदारी देने के रूप में निकाल लिया है। स्थानीय निकाय के चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रविधान के बाद 'मुखिया पति-सरपंच पति आदि' शब्द प्रचलन में हैं। इसका अर्थ है कि पति चुनाव नहीं लड़ सकता, अतः पत्नी को चुनाव लड़वाता है। चुनाव भले उसकी पत्नी जीते, पर अघोषित रूप से मुखिया-सरपंच का काम वही करता है। इन दिनों बिहार में बाहुबली अशोक महतो का विवाह चर्चा में है। चूंकि वह चुनाव नहीं लड़ सकता, अतः उसने आनन-फानन विवाह कर लिया। अब उसकी पत्नी राजद से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। सिवान की जदयू सांसद कविता सिंह की भी कहानी अशोक महतो से मिलती-जुलती है। इसी तरह आनंद मोहन तथा पप्पू यादव की पत्नी भी राजनीति में आईं। भारतीय लोकतंत्र मुखिया पति, विधायक पति, सांसद पति से आगे चलते हुए मुख्यमंत्री पति तक का सफर पूरा कर चुका है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल की मांग को लेकर छिड़े अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल की मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देने की जिद ने देश को एक ऐसे चौराहे पर ला खड़ा किया है, जहां से आगे का रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। भारतीय संविधान निर्माताओं ने ऐसे संवैधानिक संकट की कल्पना भी नहीं की थी। चूंकि उन्होंने ऐसी कोई कल्पना नहीं की थी, इसलिए उन्होंने इस बारे में कुछ तय भी नहीं किया कि यदि किसी मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा तो उसकी सरकार कैसे चलेगी? कायदे से नेताओं को लोकलाज का ध्यान रखना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते तो आंदोलनों पर से भरोसा उठ जाएगा।

(लेखक बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं)

response@jagran.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ऊर्जा

त्यागमय जीवन

कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ त्यागना भी अनिवार्य माना गया है। हमारे शरीर को ही ले लीजिए श्वास लेने के लिए पहले श्वास छोड़नी पड़ती है, तभी इस शरीर की आंतरिक संरचना में नवीनता तथा सक्रियता का संचार होता है। त्याग हमें सांसारिक मोह से अलग करने के साथ हमारे आध्यात्मिक व्यक्तित्व को परिपक्वता प्रदान करता है।

इस संसार की जितनी भी भौतिक संपदा, वस्तुएं एवं पदार्थ हैं वे सभी मनुष्य जीवन को सम्यक प्रकार से निर्वाह करने के लिए ही बने हैं। इस दृश्य संसार की प्रत्येक वस्तु भोग और अपवर्ग की प्राप्ति के लिए बनी है, इसीलिए मनुष्य को सभी सांसारिक भौतिक पदार्थों का त्याग की दृष्टि से उपभोग करना चाहिए। नश्वर भौतिक संपदा का निरंतर संग्रह करने की प्रवृत्ति मनुष्य को लोभ और तृष्णा के बंधन में बांध देती है। जो भी पदार्थ मनुष्य को इस संसार में प्रयोग करने के लिए मिले हैं उनका अंत भी अवश्य होना है। अर्थात एक न एक दिन उन सभी पदार्थों से हमें अवश्य अलग होना है। त्याग से मनुष्य को सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। श्रीराम जब महल में थे तो राजा राम कहलाए और जब उन्होंने महल त्यागा तो पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम कहलाए। सिद्धार्थ गौतम ने जब त्याग के आदर्श को अपनाया तो गौतम बुद्ध के रूप में प्रतिष्ठित हुए।

त्याग के बिना शाश्वत सुख एवं शांति की कल्पना नहीं की जा सकती। त्याग जीवन का एक अनिवार्य नियम है। त्याग के बिना आनंद का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। भौतिक सांसारिक पदार्थों के बंधन में बंधे रहना जीवन में दुखों का मूल कारण है। आनंद की अनुभूति के लिए त्याग के आदर्श को अपनाना पड़ता है। केवल मात्र भौतिक संपदाओं का संग्रह करने की प्रवृत्ति मनुष्य को आंतरिक रूप से भीरू बना देती है। इन नश्वर संपदाओं का संग्रह एक न एक दिन नष्ट अवश्य होगा। जीवन में त्याग के आदर्श का अनुसरण मनुष्य को आंतरिक संतुष्टि एवं आनंद प्रदान करता है।

आचार्य दीप चंद भारद्वाज

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

पाठ्यक्रम के अनुसार हों पाठ्यपुस्तकें

'पाठ्यक्रम परिवर्तन का अधूरा एजेंडा' शीर्षक से लिखे अपने आलेख में राजीव सचान ने कहा है कि मोदी सरकार ने बीते दस वर्षों में बहुत कुछ किया है, लेकिन शिक्षा के मोर्चे पर कुछ विशेष नहीं हो सका। यह विडंबना ही है की नई शिक्षा नीति को लागू हुए चार वर्ष होने को हैं, किंतु इस पर अपेक्षित गंभीरता से काम नहीं हो पा रहा है। आखिर सरकारें इसकी आवश्यकता को कब समझेंगी। लेखक ने स्कूली स्तर पर राजस्थान और दिल्ली में स्कूली पाठ्यक्रम आधारित पुस्तकों में हुई तथ्यात्मक गलतियों का जो विवरण दिया है वह सचमुच चिंतनीय है। छात्र-छात्राएं जब यही गलत जानकारियां पढ़कर आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो उसका दोषी कौन होगा? स्कूली पाठ्यक्रम का निर्धारण होने के पश्चात उसके अनुसार जो पुस्तकें बाजार में आई हैं वे सचमुच में पाठ्यक्रम के अनुसार लिखी गई हैं अथवा नहीं, इसकी जांच करने का फिलहाल कोई तंत्र देश में उपलब्ध नहीं है। वैसे यह केवल स्कूल स्तर की समस्या नहीं, बल्कि कालेज स्तर पर भी छात्र-छात्राएं यही कठिनाई अनुभव करते हैं। कालेज स्तर पर तो प्रकाशक ही पुस्तक लेखक से संपर्क में रहते हैं। लेखक की उस विषय में कोई विशेषज्ञता है कि नहीं, इसकी जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रकाशक, लेखक और पुस्तक विक्रेता ही सब कुछ तय करते हैं। शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) को इसका तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि जो पाठ्यपुस्तकें नई शिक्षा नीति लागू होने के पश्चात बाजार में आई हैं वे नए पाठ्यक्रम के अनुसार विषय विशेषज्ञों द्वारा ही लिखी गई हैं या नहीं। नई शिक्षा नीति की सफलता के लिए समय-समय इसकी समीक्षा भी आवश्यक है।

डा. प्रदीप कुमार संघवी, झाबुआ (मध्य प्रदेश)

भ्रामक प्रचार करते नक्सली

संपादकीय आलेख 'नक्सलियों पर नकेल' में केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित कर नक्सलियों पर लगाम लगाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। आदिवासियों व गरीबों का मसीहा बताने वाले ये नक्सली वास्तव में देशद्रोही हैं। बंदूक की नोक पर साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। ये विदेशी मदद से समय-समय पर सुरक्षा बलों पर धोखे से निर्मम वार करते हैं। बीजापुर में हुई इस मुठभेड़ में छह अप्रैल, 2010 को ताड़मेटला में 76 जवानों के बलिदान होने की घटना में शामिल रहे कुख्यात नक्सली डीवीसी सदस्य पापा राव सहित कई कुख्यात नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। यद्यपि अभी तक उसकी मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पापा राव आठ लाख रुपये का इनामी है। मारे गए नक्सलियों पास से बरामद अत्याधुनिक हथियारों की सघन जांच होनी चाहिए कि ये कहां से आपूर्ति होती है। देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले ये नक्सली वंचितों, गरीबों, आदिवासियों के बीच सरकारों के विरुद्ध भ्रामक प्रचार-प्रसार कर सहानुभूति बटोरते हैं। सरकारों को अस्थिर करने के लिए इन्हें विदेशों से दिशा-निर्देश भी मिलते रहते हैं। चुनाव के पूर्व दर्जन से अधिक नक्सलियों का मारा जाना सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी है। पता चला है कि ये सब चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के लिए इकट्ठा हो रहे थे।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

नई दिशा नहीं दे सकी रैली

राहुल वर्मा द्वारा लिखित आलेख 'कारगर रणनीति के अभाव से ग्रस्त विपक्ष' पढ़ा। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी दल अपनी-अपनी बिसात बिछा चुके है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी विपक्षी दलों के लिए बहुत बड़ा झटका है। दिल्ली के रामलीला मैदान में केजरीवाल की गिरफ्तारी के उपरांत सहानुभूति बटोरने के लिए विपक्षी दलों ने एक रैली की। इस मैदान ने समय-समय पर देश की राजनीति को नई दिशा दी है, परंतु इस बार विपक्षी दल इस मैदान से देश को नई दिशा प्रदान करने में असफल रहे हैं, क्योंकि सभी दल की अलग-अलग समस्याएं हैं। कांग्रेस अपना बैंक खाता फ्रीज होने से परेशान है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने नेता की गिरफ्तारी से मुसीबत में है। एक ओर राहुल गांधी लोकतंत्र व संविधान बचाने की बात करते हैं, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। आम जनता की नजरों में देश के लोकतंत्र पर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आज भी कई राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है। भाजपा देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का वादा कर रही है, तो राहुल गांधी अंबानी व अदाणी को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। देश में मुद्दों की कोई कमी नहीं है। देश की आम जनता महंगाई व बेरोजगारी से त्रस्त है। इस चुनाव में जनता का बुनियादी मुद्दा गायब हो चुका है।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गया

पोस्ट

विजेंदर सिंह एक दिन पहले तक कांग्रेस पार्टी में रहे और अब वह भाजपा में हैं। इससे न तो वह बुरे बाक्सर बनते हैं और न ही अच्छे राजनेता।

विनय सुल्तान@vinay_sultan

प्रतिभाओं को संभाल कर रखने की कांग्रेस की अक्षमता पर राहुल गांधी और प्रियंका ध्यान नहीं देंगे तो भारी भूल करेंगे। हालांकि गौरव वल्लभ पार्टी छोड़ने के और बेहतर कारण भी गिना सकते थे।

पंकज शर्मा@Pankaj__Sharma

पिछले 24 घंटे में कांग्रेस को तीन बड़े झटके लगे हैं। बाक्सर विजेंदर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। संजय निरुपम और कांग्रेस, दोनों ने एक-दूसरे से किनारा कर लिया। फिर गौरव वल्लभ कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए। कुल मिलाकर कांग्रेस में भागमभाग की स्थिति बनी हुई है।

मीमांसा मलिक@mimansa_malik

कांग्रेस से इतनी बड़ी संख्या में नेताओं के पलायन में कुछ भी हैरानी भरा नहीं है, क्योंकि राजनीति एक ऐसा ही पेशा है, जिसमें लोग बेहतर प्रतिफल चाहते हैं। इसका दुखद पहलू यही है कि इस देश में राजनीतिक विचारधारा लोगों के लिए कितनी कम मायने रखती है।

राहुल पंडिता@rahulpandita

जनपथ

राहुल जी की फंस गई वायनाड में सीट,
एनी राजा से दिखे कांग्रेस भयभीत।
कांग्रेस भयभीत लड़ीं यदि बढ़िया मैडम,
तो निश्चित युवराज वहां पर होंगे बेदम।
उत्तर में 'परिवार' की हुई है बत्ती गुल,
दक्षिण में भी जान फंसा बैठे हैं राहुल!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073

E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 24 अंक 350

****

बहादुर आदमी वह नहीं, जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है, जो डर पर विजय पा लेता है। -नेल्सन मंडेला

वर्ष 1999 में ताइवान में आए भूकंप से 2,400 लोगों की जानें गई थीं। लेकिन बीते बुधवार को आए भूकंप से निपटने में ताइवान ने जो तैयारियां दिखाई हैं, वे उसकी इंजीनियरिंग संस्कृति की देन हैं, जिससे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित सभी देश सबक ले सकते हैं।

ताइवान से सीखें

बीते बुधवार को ताइवान में पिछले 25 वर्षों में आए सर्वाधिक शक्तिशाली भूकंप से अब तक दस लोगों की मौत, हजार से ज्यादा घायल और कई के अब तक फंसे होने की खबरें बेशक परेशान करने वाली हैं, लेकिन ऐसी आपदा के बाद भी जिस तरह से स्थितियों पर काबू रखा गया है, वह दिखाता है कि समुचित तैयारियां हों, तो गंभीरतम प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों को भी नियंत्रण में रखा जा सकता है। 7.2 तीव्रता (अमेरिकी एजेंसी के अनुसार, 7.4) वाले इस भूकंप का केंद्र राजधानी ताइपे से 150 किलोमीटर दूर ताइवान के पूर्वी तट पर स्थित ग्रामीण पर्वतीय शहर हुलिएन में था। उल्लेखनीय है कि 2.3 करोड़ की आबादी वाला ताइवान प्रशांत 'रिंग्स ऑफ फायर' क्षेत्र में आता है, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। जाहिर है कि शक्तिशाली भूकंप ताइवान के लिए नए नहीं हैं। अमेरिका के जिओलॉजिकल सर्वे के अनुसार, ताइवान में 1980 के बाद से चार या उससे ज्यादा तीव्रता के करीब 2,000 भूकंप और 5.5 या ज्यादा तीव्रता के सौ से ज्यादा भूकंप आ चुके हैं। इससे पहले, 1999 में यहां आए भूकंप में करीब 2,400 लोग मारे गए थे और एक लाख लोग घायल हुए थे। लेकिन इसके बाद ताइवान में जिस तरह से भूकंप से निपटने की रणनीतियां बनाई गईं और बहुमंजिला इमारतों के नियमों व मानकों में बदलाव लाए गए, उसका ही नतीजा है कि ताजा भूकंप में ज्यादातर इमारतें सिर्फ झुकी हैं, गिरी नहीं हैं, जिससे लोगों को बचाव का अतिरिक्त समय मिल सका। भूकंप से निपटने के लिए ताइवान को दुनिया का सबसे उन्नत देश यों ही नहीं माना जाता। भूकंप पर नजर रखने वाली ताइवानी एजेंसी को इसका अनुमान पहले से ही लग चुका था, लेकिन भूकंप की तीव्रता का अंदाजा लगाने में चूक हो गई। उल्लेखनीय है कि तीन महीने पहले जापान के इशिकावा प्रांत में आए जबर्दस्त भूकंप को लेकर जो तैयारियां दिखी थीं, उनकी भी पूरी दुनिया ने प्रशंसा की थी। दूसरी ओर, तुर्किये-सीरिया में पिछले

वर्ष आए 7.8 तीव्रता के भूकंप में करीब 59 हजार लोग, मोरक्को में आए 6.8 तीव्रता के भूकंप से करीब तीन हजार लोग और अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में आए 6.3 तीव्रता के भूकंप से करीब 1,400 लोगों की मौतें हुई थीं। वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखला के केंद्र ताइवान में आए भूकंप से एशिया की चिप आपूर्ति व्यवस्था कुछ बाधित जरूर होगी, पर भूकंप के खतरों से तालमेल बैठाने वाली इंजीनियरिंग संस्कृति की बदौलत ताइवान और जापान जैसे देश जिस तरह से विनाशकारी भूकंपों से निपट रहे हैं, उससे पूरी दुनिया सीख ले सकती है।

पाकिस्तान में साजिशों का 'जहर'

पाकिस्तान के विपक्षी नेताओं एवं सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा लगाए गए जहर देने और धमकाने के आरोपों से मुल्क में सनसनी फैल गई है। यह निश्चित रूप से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नई सरकार के लिए एक गंभीर मुद्दा है, जो टीटीपी के आतंकवादी हमलों और महंगाई से पहले ही जूझ रही है।

इस हफ्ते पाकिस्तान के अखबारों एवं टेलीविजन चैनलों पर 'जहर' सुर्खियों में रहा। विपक्षी नेताओं एवं हाईकोर्ट तथा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा जहर देने और धमकाने के आरोपों से पूरे मुल्क में सनसनी फैल गई है।

यह निश्चित रूप से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नई सरकार के लिए एक गंभीर मुद्दा है, जो अफगानिस्तान स्थित तहरीक-ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के लगातार आतंकवादी हमलों, आम पाकिस्तानियों की कमर तोड़ने वाली महंगाई और सबसे महत्वपूर्ण पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान के निरंतर पलटवार से निपटने की कोशिश कर रही है। जेल में होने के बावजूद इमरान खान ने 2024 के चुनाव परिणामों को स्वीकारने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया है कि पाकिस्तान चुनाव आयोग ने सुरक्षा प्रतिष्ठान के साथ मिलकर उनकी पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों को मिले वोटों की संख्या में हेराफेरी की और उन्हें चुनाव जीतने से वंचित कर दिया।

मरिआना बाबर
वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार

जहर का आरोप इमरान खान की पत्नी बुशरा बेगम ने लगाया था, जो इस्लामाबाद के बाहरी इलाके बनिगाला में स्थित खान के महलनुमा घर में नजरबंद हैं। यह वही संपत्ति है, जिसे इमरान खान की पूर्व पत्नी जेमिमा खान ने खरीदकर इमरान खान को उपहार में दिया था। बनिगाला स्थित आवास को अदालत द्वारा उप-जेल घोषित कर दिया गया है, जहां बेगम बुशरा रहती हैं। इस बीच उनके पति इमरान खान पंजाब प्रांत के रावलपिंडी की आदिला जेल में कैद हैं।

अपने एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में मीडिया से एक संक्षिप्त बातचीत के दौरान इमरान खान ने पत्रकारों को यह कहकर चौंका दिया कि बुशरा बेगम के खाने में टॉयलेट क्लीनर की तीन बूंदें मिला दी गई थीं, जिससे उनकी आंखों में तकलीफ हुई और पेट एवं छाती में दर्द महसूस हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अदालत को

भी इसके बारे में बताया और अदालत से मांग की कि उनकी पत्नी की पूरी तरह से स्वास्थ्य जांच उनके लाहौर स्थित कुलसुम अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा करवाई जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें अन्य किसी भी डॉक्टर पर भरोसा नहीं है, जिसे सरकार नामित करना चाहती हो।

उस समय बुशरा बेगम भी अदालत में मौजूद थीं, क्योंकि उन्हें अपने खिलाफ एक मामले में पेश होना था, लेकिन उन्होंने वहां मीडिया से बात करने से साफ इन्कार कर दिया और एक असामान्य अनुरोध किया कि वह वहां मौजूद एक व्लॉगर से बात करना चाहती हैं। लेकिन अदालत ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी।

हालांकि जब उनसे पूछा गया कि उन्हें कैसे पता चला कि उनके खाने में टॉयलेट क्लीनर की बूंदें मिलाई गई हैं, तो उन्होंने कहा कि यह सूचना देने वाले का नाम वह उजागर नहीं करेंगी।

दूसरा मामला तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है और यह वाकई अविश्वसनीय है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के छह न्यायाधीशों ने पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश काजी फैज ईसा को पत्र लिखकर शिकायत की कि उन्हें खुफिया एजेंसी की ओर से लगातार धमकाया जा रहा है और वे इससे सुरक्षा चाहते हैं, ताकि बिना भय के अपना काम कर सकें।

इसके बाद प्रधान न्यायाधीश को स्वतः कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्होंने इन छह न्यायाधीशों के आरोपों की सुनवाई करने के लिए एक पीठ का गठन किया। उसके ठीक अगले दिन इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं सात अन्य जजों को संदिग्ध एंथ्रेक्स-युक्त पत्र मिला, जो अब पुलिस के पास है। इन पत्रों में इन न्यायाधीशों को धमकी दी गई है। एक दिन बाद लाहौर उच्च न्यायालय के चार जजों को भी धमकी भरा पत्र मिला।

आखिर इसके पीछे कौन है? और क्या ये वाकई गंभीर धमकियां थीं या किसी ने शरारत की थी? जजों के पते पर भेजे गए पत्र के लिफाफे से पता चला कि उन्हें रेशम नाम की किसी महिला ने भेजा है, लेकिन पुलिस अब भी इन धमकी भरे पत्रों के असली स्रोत की जांच कर रही है। लेकिन तहरीक-ए नामूस-ए पाकिस्तान नामक एक अल्पज्ञात आतंकवादी गुट ने शीघ्र ही इस संबंध में एक बयान जारी किया। यह बयान सार्वजनिक रूप से जारी किया गया और सोशल मीडिया पर भी यह प्रसारित हो रहा है। इस बयान पर खोपड़ी का निशान बना हुआ है। बयान में तहरीक-ए नामूस-ए पाकिस्तान ने इन पत्रों को भेजने की जिम्मेदारी ली है, जिनमें एंथ्रेक्स पाउडर भी था और पाकिस्तान की उच्चतम न्यायपालिका के प्रति स्पष्ट गुस्सा भी दर्शाया गया था। नामूस का मतलब सम्मान होता है, इसलिए यह सम्मान के लिए एक आंदोलन प्रतीत होता है।

जजों को भेजे गए पत्र में लिखा गया है-'अब और नहीं। हम आपको अपने मुल्क को और कमजोर नहीं करने देंगे। पाकिस्तान की अदालतों में बैठे आप लोग इस मुल्क की स्थापना के बाद से ही न्याय करने का दिखावा कर रहे हैं। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट मातृभूमि की समस्या और बीमारी का हिस्सा बन गया है।'

तहरीक-ए नामूस-ए पाकिस्तान नामक इस गुट की जब जांच की गई, तो नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार पता चला कि यह एक नया आतंकवादी गुट है, जिसकी उत्पत्ति और उद्देश्य के बारे में कुछ पता नहीं है।

पिछले वर्ष जब प्रधान न्यायाधीश काजी फैज ईसा ने पद की शपथ ली थी, तो वन्यजीव विभाग की टीम ने इस्लामाबाद के बाहरी इलाके मार्गल्ला हिल्स में रेड जोन स्थित संवेदनशील इमारतों से संबंधित मानचित्रों और विस्फोटकों का पता लगाया था। मार्गल्ला हिल्स पर मिले पत्रों में मुल्क की न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को धमकी दी गई थी।

जहां तक इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के छह न्यायाधीशों की बात है, जिन्होंने खुफिया एजेंसियों पर परेशान करने और धमकाने का गंभीर आरोप लगाया है, ज्यादातर लोगों का मानना है कि इन न्यायाधीशों ने अवैध कार्रवाई को चुनौती दी है, इसलिए लोकतंत्र एवं कानून के शासन के लिए लड़ने वाले लोगों को इनका समर्थन करना चाहिए।

जीवन धारा

रवींद्रनाथ टैगोर

दीपक जलता है दूसरों को प्रकाश देने के लिए। सूर्य तपता है लोकों में जीवन फूंकने के लिए। गाय जंगल-जंगल घूमती है लोगों को दूध देने के लिए। प्रकृति ने यह तप उसे सहज ही बता रखा है।

तप के साथ संग्रह का कोई स्थान नहीं है

जीवन के अपने ध्येय की पूर्ति के लिए कठोर तप की आवश्यकता पड़ती है। मानव जीवन का ध्येय आत्म-तोष प्राप्त करना है और इसकी प्राप्ति का उपाय मानवीय सामर्थ्य का विकास करना है। सामर्थ्य का विकास साधना से होता है और साधना तप के बिना पूरी नहीं होती। निरंतर साधना और परिश्रम ही तप है। किंतु तप के साथ ही त्याग का शब्द भी जुड़ा है। जो तप त्याग के लिए किया जाता है, वही तप है। तप के लिए तप करना, तप नहीं कहा जा सकता। उससे शारीरिक और मानसिक विकारों का प्रादुर्भाव होता है। उससे आत्म परितोष का उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हो सकता। तप के साथ संग्रह का कोई स्थान नहीं है। दीपक जलता है दूसरों को प्रकाश देने के लिए। प्रकृति स्वयं ग्रीष्म में तपती है, धरती पर पावस के आगमन के लिए।

सूर्य तपता है लोकों में जीवन फूंकने के लिए। गाय जंगल-जंगल घूमती है लोगों को दूध देने के लिए। प्रकृति ने यह तप उसे सहज ही बता रखा है। इसीलिए तो कहा गया है-सर्व लोक हिताय-सर्व जन सुखाय।

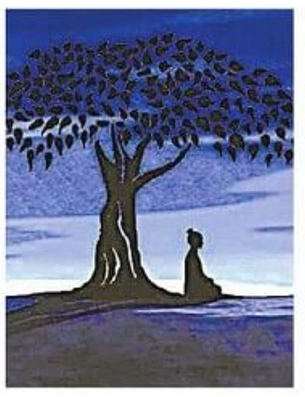

यही नियम मानव जीवन में भी लागू होता है। जीवन की तपस्या सर्व लोक हिताय-सर्व जन सुखाय हो, तभी वह तप की श्रेणी में आती है। एक व्यापारी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए दिन-रात कड़ी मेहनत करता है, एक मजदूर सुबह से शाम तक पसीना बहाता है।

लेकिन इनकी तुलना में निःस्वार्थ भाव से संसार के कल्याण की कामना करने वाले, सबको सन्मार्ग दिखाने वाले लोकसेवी कहीं ज्यादा पूजनीय माने गए हैं, क्योंकि त्याग की व्यापक भावना रखकर श्रम करना ही तप कहलाता है। दूसरे लोगों के हितार्थ, दूसरों की सेवा के लिए अपने शरीर पर कष्ट सहना, समष्टि के लाभ की चिंता रखते हुए कोई भी दृढ़ प्रयत्न करना तप कहलाता है।

स्वार्थ के लिए या तप को लक्ष्य बनाकर किया गया तप आत्म संतुष्टि प्रदान नहीं करता। इससे जीवन में संतोष भी नहीं मिलता, बल्कि इससे अभिमान में वृद्धि होती है और मनुष्य विकारग्रस्त हो जाता है। विश्वामित्र को तप का अभिमान हुआ, जिससे उनका पतन हो गया। रावण के तप से उसकी समृद्धि बढ़ी, किंतु स्वार्थ भाव के कारण उसका पतन हो गया।

महात्मा बुद्ध ने अपने महलों के सारे सुख-वैभव त्याग दिए थे। जंगल में जाकर तप किया। फिर लोक कल्याण के लिए उन्होंने अपने तपस्वी, एकाकी जीवन का त्याग किया, तब उन्हें आत्म-तोष प्राप्त हुआ। उन्होंने तप और त्याग दोनों ही लोक कल्याण के लिए किया। जड़ अथवा जीव जगत के सभी पदार्थ विश्व की विकास यात्रा में अपना योगदान दे रहे हैं। यही बात मनुष्य पर लागू होती है। सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी होने की वजह से मनुष्य की जिम्मेदारी तो और बढ़ जाती है। जो मनुष्य इसे जीवन में स्थान देकर समष्टि के लिए अपना उत्सर्ग करते हैं, उनके विकार स्वतः ही धुलने लगते हैं और उन्हें नवीन जीवन शक्ति, स्फूर्ति, सामर्थ्य प्राप्त होती है।

सच्चा त्याग...

सूत्र

सभी प्रकार के अभिमान का छोड़कर अपनी उपलब्धियों का उत्सर्ग करते रहना ही सच्चा त्याग है। दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं कष्ट सहना, शरीर और मन का उपयोग करना, दूसरों की सेवा में लगना, अपने सुख-भोग, स्वार्थ आदि में मन को न जाने देना ही तप है। महाराज जनक, सम्राट अशोक, बुद्ध, महात्मा गांधी इसी श्रेणी में आते हैं। भगवान राम का जीवन तप और त्याग की सजीव व्याख्या है।

दूसरा पहलू

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से विस्थापित होकर काकड़ी गांव बसाया गया और गांव में घरों के आगे फल व छाया देने वाले पेड़ लगाए गए।

हरियाली से स्वावलंबी बनता एक गांव

मध्य प्रदेश का काकड़ी गांव वैसे तो एक साधारण विस्थापित गांव है, पर यहां के आदिवासियों ने इसे हरा-भरा करने और गांव की अर्थव्यवस्था को पर्यावरण से जोड़ने की जो राह अपनाई है, वह असाधारण है। काकड़ी गांव, सतपुड़ा अंचल का एक विस्थापित गांव है, जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कारण विस्थापित है। इसमें 34 घर हैं, सभी कोरकू आदिवासी हैं।

गांव के जयसिंह बताते हैं कि इस बदलाव की कहानी वर्ष 2015-16 से शुरू हुई, जब यह गांव सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से विस्थापित होकर यहां नए गांव के रूप में बसने के लिए आया। जयसिंह बताते हैं कि आपसी विचार-विमर्श के बाद गांव बसाने की पूरी योजना तैयार की गई। गांव की पुनर्वास समिति के अध्यक्ष, सचिव व सदस्य इन बैठकों में शामिल होते थे। योजना के अनुसार, जब लोगों ने अपना घर बनाना शुरू किया, तो पंक्तिबद्ध मकान बनाए गए। फिर उनके आगे 50 फुट जमीन खाली छोड़ी गई। इन खाली जगहों में दो पंक्तियों में फलदार व छायादार पेड़ लगाए गए। गांव के लोगों ने फैसला किया है कि जब भी यहां की किसी बेटी की शादी होगी, तो उसके ससुराल में दो फलदार पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे उसे इस गांव की याद बनी रहेगी।

बाबा मायाराम

यहां के हर घर की छत का पानी जमीन के अंदर वर्षा जल संचयन पद्धति से डाला जा रहा है, जिससे भूजल का स्तर बढ़ रहा है। गांव में जैविक खेती होने से पर्यावरण की रक्षा भी होती है।

गांव के लोगों ने फैसला किया है कि जब भी यहां की किसी बेटी की शादी होगी, तो उसके ससुराल में दो फलदार पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे उसे इस गांव की याद बनी रहेगी।

पुनर्वास समिति के अध्यक्ष लखनलाल कलमे ने बताया कि हमने वर्षा के पानी की बूंद-बूंद को भूजल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है। यहां के हर घर की छत का पानी जमीन के अंदर वर्षा जल संचयन पद्धति से डाला जा रहा है, जिससे भूजल का स्तर बढ़ रहा है। जयसिंह ने बताया कि उन्होंने जैविक खेती शुरू की है, जिससे जैविक अनाज के साथ पर्यावरण का भी नुकसान नहीं होता है। किसान आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता फागराम कहते हैं कि उनका संगठन हमेशा से ही जंगल बचाने व हरियाली का पक्षधर रहा है। काकड़ी के लोग भी संगठन से जुड़े रहे हैं। यह पहल दूसरे गांव में भी होनी चाहिए, ऐसा प्रयास करेंगे। वैसे इस तरह की एक पहल बैतूल जिले में श्रमिक आदिवासी संगठन भी चला रहा है, जो बारिश के पहले गांव-गांव में हरियाली यात्रा निकालकर पौधे लगाने का संदेश देता है।

जलवायु परिवर्तन के मौजूदा दौर में पेड़ों व हरियाली से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सोखने की क्षमता बढ़ती है। यह जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने का तरीका है। जैविक खेती में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता ही नहीं, दूसरी ओर मिट्टी भी बेहतर होती है। यह पहल सराहनीय होने के साथ-साथ अनुकरणीय भी है।

आंकड़े

श्रमबल में महिलाएं

हाल के वर्षों में अपने देश में श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है और अब एक तिहाई से ज्यादा महिलाएं इसमें शामिल हैं।

स्रोत: PLFS, 2022-23

सभी दुर्गुण हमारे मन के असंयमित और चंचल होने के कारण अंदर से उपजते हैं। इसलिए प्रतिदिन सत्संग, स्वाध्याय और साधना की आवश्यकता होती है।

मन की पवित्रता

अंतर्यात्रा
शिव कुमार गोयल

किसी भी साधना की सफलता के लिए शास्त्रों में मन को शुद्ध, पवित्र, छल-छद्म से रहित बनाने पर जोर दिया गया है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, अपने मन को किसी भी प्रकार के राग-द्वेषों से, तेरा-मेरा की भावना से मुक्त कर उसे परमात्मा की ओर उन्मुख करना चाहिए। मन को भगवान से जोड़ने का नाम ही योग है।

परमहंस बाबा मुक्तानंद कहते हैं, बालक का मन सर्वथा दोषरहित व निश्छल होता है। जैसे-जैसे वह बड़ा होता है, कुसंग के कारण उसका मन चंचल होने लगता है तथा उसमें अनेक दोष आ जाते हैं। सभी दुर्गुण हमारे मन के असंयमित और चंचल होने के कारण अंदर से उपजते हैं। वे कहीं बाहर से नहीं आते, इसलिए प्रतिदिन सत्संग, स्वाध्याय और साधना की आवश्यकता होती है। निरंतर सत्संग, स्वाध्याय से मन पवित्र बना रहता है। यदि मन में परमात्मा को रमाए रखने का अभ्यास हो जाए, तो वह हर क्षण निश्छल बना रहता है। इसलिए परमात्मा को एक क्षण के लिए भी विस्मृत नहीं करना चाहिए। संत रविदास काम करते समय भी मन को भगवान की ओर लगाए रखते थे। इसलिए उन्होंने कठौती में गंगा के दर्शन कराकर सबको चमत्कृत कर दिया था-*मन चंगा तो कठौती में गंगा।*

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 26 जनवरी, 1987

अफ्रीका कोष के लिए भारत ने दिए 50 करोड़ रुपये

अफ्रीका कोष स्थापित
भारत ने ५० करोड़ रु. दिए

गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने दक्षिण अफ्रीका सरकार की रंगभेद नीति से पीड़ित पड़ोसी देशों की मदद के लिए सात करोड़ डॉलर की प्रारंभिक पूंजी से अफ्रीका कोष की स्थापना की, जिसमें भारत ने 50 करोड़ रुपये का अंशदान दिया।

बीमारियों का घर बन रही जेलें

जेलों में क्षमता से अधिक संख्या में एक साथ बंदियों को रखे जाने से एक-दूसरे में बीमारियों के फैलने की आशंका ज्यादा होती है।

जयसिंह रावत — मुद्दा

भारतीय जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों को रखे जाने के कारण उत्पन्न नारकीय स्थितियां न केवल संयुक्त राष्ट्र के नियमों का, बल्कि मानवाधिकारों का भी उल्लंघन है। यह वेदना किसी मानवाधिकार कार्यकर्ता की नहीं, बल्कि स्वयं गृह मंत्रालय के अंतर्गत निदेशक (एसआर) प्रवीन कुमारी सिंह द्वारा सभी राज्यों के प्रमुख सचिव गृह और कारागार तथा पुलिस प्रमुखों के लिए नौ मई, 2011 को जारी सर्कुलर में व्यक्त की गई है। जेलों की इस स्थिति पर संसद में भी निरंतर चिंता प्रकट की जाती रही है।

जेलों में क्षमता से अधिक संख्या में एक साथ बंदियों को रखे जाने से एक-दूसरे में बीमारियों के फैलने की आशंका ज्यादा होती है। मानवाधिकारों के उल्लंघन, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और न्याय-आधारित विकल्पों की अनुपस्थिति के कारण जेलों में बंद लोगों के स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जेलों का भौतिक बुनियादी ढांचा, भीड़-भाड़ का खतरा और कैदियों की लगातार आवाजाही से टीबी

जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है।

विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले भारत की जेलें भी भरी रहती हैं। *लॉन्सेट पब्लिक हेल्थ जर्नल* में प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन के अनुसार, भारत में कैदियों को सामान्य आबादी की तुलना में तपेदिक (टीबी) होने का खतरा पांच गुना अधिक है। जर्नल के जुलाई, 2023 संस्करण में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि भारत की जेलों में प्रति एक लाख कैदियों पर टीबी के 1,076 मामले थे। शोधकर्ताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर तपेदिक की घटनाओं की दर और जेलों में भीड़-भाड़ के बीच एक सीधा संबंध पाया। विशेषज्ञों के अनुसार, जेलों में भीड़-भाड़ और वेंटिलेशन की कमी के चलते तपेदिक (टीबी) रोगियों की संख्या अधिक पाई जाती है। वर्ष 2017 में *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंफेक्शियस डिजीज* में प्रकाशित एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने भारत की जेलों में टीबी के इलाज और जांच की व्यवस्था का अध्ययन किया, तो पाया कि निदान या डाइग्नोसिस की केवल 18 प्रतिशत, इलाज की 54 प्रतिशत और समय-समय पर जांच की 60 प्रतिशत जेलों में ही व्यवस्था थी।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 'प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट-2022' के अनुसार 31 दिसंबर, 2022 को भारत की जेलों में कुल 5,73,220 लोग बंदी थे, जबकि देश की कुल 1,330 जेलों में कुल क्षमता 4,36,266 कैदियों की ही थी। इस प्रकार देखा जाए, तो इन जेलों में क्षमता से 131.4 प्रतिशत अधिक बंदी रखे गए थे। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, मणिपुर और नगालैंड जैसे कुछ राज्यों में क्षमता से कम बंदी थे, जबकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और जम्मू-कश्मीर जैसे कुछ राज्यों की जेलों में भेड़-बकरियों की तरह बंदी ठूंसे जाते हैं। उत्तराखंड जैसे शांत और छोटे राज्य की जेलों में 31 जनवरी, 2024 तक कुल 3,461 बंदियों की क्षमता के विपरीत 6,603 कैदी बंद थे। इन बंदियों में से लगभग 75 प्रतिशत विचाराधीन कैदी थे।

उक्त जेल सांख्यिकी के अनुसार, जेलों में बंद सभी बंदियों में केवल 1,33,415 बंदी ही सजायाफ्ता थे और शेष 4,34,302 विचाराधीन कैदी थे। इन विचाराधीन कैदियों में से कई ऐसे भी हैं, जो अदालत द्वारा दोष सिद्ध होने से पहले ही पांच साल से अधिक समय से जेलों में सजा काट रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा द्वारा 6 फरवरी, 2024 को लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, भारतीय जेलों में दो से तीन साल से 33,980 विचाराधीन कैदी, तीन से पांच साल से 25,869 विचाराधीन कैदी और पांच साल से अधिक समय से 11,448 विचाराधीन कैदी फैसले का इंतजार कर रहे थे। इनमें से कुछ निर्दोष भी हो सकते हैं और कुछ को कम सजा भी मिल सकती है, मगर वे पहले ही अकारण सजा काट रहे हैं।

इन भीड़-भाड़ वाली जेलों में सामान्य मानवीय सुविधाओं का अभाव तो रहता ही है, साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं का भी भारी अभाव रहता है, जिस कारण कैदी जेलों में दम तोड़ते रहते हैं। जेल सांख्यिकी के अनुसार, देश की जेलों में वर्ष 2022 में 1,995 मौतें हुईं, जिनमें 1,773 प्राकृतिक और 159 अप्राकृतिक मौतें थीं, जिनमें आत्महत्याएं भी शामिल थीं। प्राकृतिक मौतों में तपेदिक जैसी बीमारियां शामिल थीं। वर्ष 2022-23 में भारतीय जेलों के लिए कुल बजट 8,725 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था, जिसमें से 7,781.9 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाए। अतः जेलों की व्यवस्था सुधारने पर भी ध्यान देना चाहिए।

edit@amarujala.com

दैनिक जागरण

मूल्यों के अभाव में जीवन का कोई औचित्य नहीं

कांग्रेस की बीमारी

चुनावों के अवसर पर नेताओं का इस या उस दल में जाना कोई नई-अनोखी बात नहीं, लेकिन जब दल विशेष से बड़ी संख्या में नेता किनारा करने लगें तो उसके खिलाफ माहौल बनता है और विरोधी दलों को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलती है। कांग्रेस के एक के बाद एक नेता जिस तरह पार्टी छोड़ रहे हैं, उससे तो यह लगता है कि भगदड़ की सी स्थिति है। कांग्रेस छोड़ने वालों में नए नाम हैं मुक्केबाज विजेंदर सिंह, गौरव वल्लभ, संजय निरुपम और बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा। इसके पहले भी कई नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। वास्तव में इसकी गिनती करना कठिन है कि बीते एक माह में कितने नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है। इनमें से कुछ बड़े और जनाधार वाले नेता भी हैं, जैसे अशोक चह्वाण, मिलिंद देवड़ा, रवनीत सिंह बिट्टू आदि। हैरानी नहीं कि आने वाले दिनों में कुछ और नेता कांग्रेस को नमस्ते करते दिखें। यह ठीक है कि अन्य दलों से इक्का-दुक्का नेता कांग्रेस में भी आए हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उसका साथ छोड़ने वालों की संख्या कहीं अधिक है।

जब भी कोई नेता अपने दल को छोड़ता है तो कुछ न कुछ कारण बताता है। आम तौर पर उसकी बातों पर गौर करने के बजाय यह कहा जाता है कि वह पार्टी छोड़ने का बहाना तलाश रहा था, लेकिन कई बार वह खरी बात भी कह रहा होता है। बतौर उदाहरण संजय निरुपम का यह कहना सही है कि कांग्रेस में शक्ति के कई केंद्र बन गए हैं और राहुल गांधी तो वामपंथी सोच वालों से घिरे ही हैं, पार्टी पर भी वामपंथियों का कब्जा हो गया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं की ओर से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करने का विषय उठाते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस वाम दलों की अवधारणा वाले उस सेक्युलरिज्म से ग्रस्त हो गई है, जिसमें धर्म और आस्था का कोई मूल्य-महत्व नहीं। निःसंदेह कांग्रेस की तरह कई अन्य दलों के नेता भी अयोध्या नहीं गए, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरह वहां जाने का निमंत्रण ठुकराया, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़ने के कारण गिनाते हुए यह कहा कि वह सनातन धर्म के विरोध में नारा नहीं लगा सकते। ध्यान रहे कि जब द्रमुक नेताओं ने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया जैसा बताया, तब कांग्रेस नेतृत्व उनकी आलोचना करने का साहस नहीं जुटा सका। गौरव वल्लभ ने यह भी कहा कि वह वेल्थ क्रिएटर्स यानी उद्यमियों को सुबह-शाम गाली नहीं दे सकते। राहुल गांधी एक अर्से से ठीक यही कर रहे हैं और वह भी तब, जब खुद उन्होंने कई बड़ी कंपनियों के शेयर ले रखे हैं। इसकी आशा तो नहीं की जाती कि कांग्रेस नेतृत्व संजय निरुपम और गौरव वल्लभ की बातों पर ध्यान देगा, लेकिन सच यही है कि इन नेताओं ने कांग्रेस की बीमारी बताने का काम किया है।

झूठी शिकायतें

चुनाव के दौरान किसी जिले में डेढ़ सौ से अधिक शिकायतें दर्ज कराई जाएं और उनमें सिर्फ 10 ही सत्य मिलें तो इसका आशय है कि मतदाताओं में कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो जान-बूझकर संसाधनों से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस तरह के प्रयास चुनाव में लगे अधिकारियों की समस्या बढ़ाते हैं और भ्रमित होते हैं जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित होते हैं। उत्तर प्रदेश में सामने आई इस बात की निंदा की जानी चाहिए। उम्मीदवारों को यह ध्यान देना होगा कि चुनाव में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। इसके लिए उन्हें अपने समर्थकों को भी चेताना चाहिए कि वह ऐसा कोई कदम न उठाएं, जिससे समस्या बढ़े। आयोग ने चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए इस बार डिजिटल फोरम तैयार किया है तो इसका दुरुपयोग न किया जाए। सिर्फ अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचा दिखाने और बदनाम करने के लिए झूठी शिकायतें उचित नहीं हैं। अलबत्ता कहीं पर वास्तविक रूप से आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है तो इसे रोकने के लिए शिकायत जरूर दर्ज कराएं और मौके पर पहुंचे अधिकारियों को इसका प्रमाण भी दें। इस बार आयोग ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन रोकने के लिए खास तौर पर सी-विजिल एप विकसित किया है जिससे आनलाइन निगरानी रखी जा सकती है। इस एप पर आई सूचनाओं पर जिले की उड़नदस्ता टीम सिर्फ 100 मिनट के भीतर एक्शन ले लेती है। पिछले 18 दिनों के भीतर 1800 से अधिक शिकायतें दर्ज कराई गईं जिसमें 817 फर्जी निकलीं। सीतापुर का हाल तो यह रहा कि वहां 151 शिकायतें दर्ज कराई गईं, जिनमें सिर्फ 10 ही सही निकलीं। सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। यह गंभीर बात है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। चुनाव आयोग की इस व्यवस्था को सकारात्मक ढंग से लिया जाना चाहिए, ताकि इसका उद्देश्य सफल हो। चुनाव में धनबल का उपयोग लोकतंत्र के लिए नासूर है और इस पर अंकुश लगाने के लिए ही सारे इंतजाम किए गए हैं।

सीएए के बाद एनआरसी भी चाहिए

आर. विक्रम सिंह

हमें यह तो जानना ही चाहिए कि आखिर देश में भारतीय नागरिकों की कुल संख्या कितनी है

अवधेश राजपूत

जो गैर-मुस्लिम 1947 में रेडक्लिफ रेखा के उस पार पाकिस्तान में छूट गए थे, उनका अपराध क्या था? सत्ता अधिग्रहण की जल्दबाजी में भारतीय नेताओं ने जिन्ना की मजहबी सत्ता से उनका सौदा कर लिया। उन्हें राहत पहुंचाने के आवश्यक दायित्व की पूर्ति 75 वर्ष बाद अब नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के माध्यम से की जा रही है। सीएए के बाद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी की जरूरत है। इस बीच सीएए को लेकर कुछ अनावश्यक टिप्पणियां की जा रही हैं, जिनका प्रतिकार भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिकी राजदूत को यह कहकर उचित जवाब दिया, 'आप भारत विभाजन का इतिहास नहीं जानते, लिहाजा सीएए को नहीं समझ सकते। उनके प्रति हमारा ऐतिहासिक दायित्व है, जिनके साथ विभाजन ने अन्याय किया।' 2014 से पहले हमारे स्वयंभू सेक्युलर नेताओं का यह मानना था कि पाकिस्तान को भारत में सांप्रदायिक आतंकवाद का दोषी करार देने का परिणाम वोट बैंक की राजनीति की दृष्टि से बुरा होगा।

राष्ट्रवाद के उभार की संभावना से कभी नेहरू भी परेशान थे, खासकर तब जब तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने का फैसला किया था। इस देश में राष्ट्रीयता के सापेक्ष सांप्रदायिक पक्षधरता का संघर्ष आज से नहीं, बल्कि आजादी के प्रारंभ से ही चल रहा है। याद रहे कि तुर्किये के खलीफा की बहाली का मुद्दा आजादी के आंदोलन की मुहिम के साथ जुड़ा। यह उन शुरुआती कारणों में से एक था, जिनसे भारत विभाजन की भूमिका बनी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने के बाद यही मोपला जैसे भीषण नरसंहार और तमाम दंगों का कारण बना। विभाजन के बाद भी वोट बैंक की चुनावी बाध्यताओं के कारण इतने वर्षों बाद भी यदि वह समीकरण ज्यों का त्यों है तो उसका कारण है विभाजन का आधा-अधूरा अनुपालन।

कांग्रेस नेतृत्व अंग्रेजों के साथ तो भारत के सांप्रदायिक विभाजन पर सहमत हो गया, लेकिन जब जमीनी स्तर पर अनुपालन की बारी आई तो उसकी नीति भारत के मुस्लिम समाज को यहीं रोक लेने एवं सीमापार के हिंदुओं को यहां न आने देने की बन गई। यह बात और है कि तब कांग्रेस के नेता दिल्ली के इलाकों में घूम-घूम कर पाकिस्तान जाने वालों को वहां जाने से रोक रहे थे। शायद कांग्रेस को यह आशंका रही होगी कि भारत यदि हिंदुओं का देश बन गया तो उसकी भावी राजनीति का क्या होगा। इसीलिए नेहरू ने 1950 में हुए नेहरू-लियाकत पैक्ट में आबादी हस्तांतरण में यथास्थिति कायम रखने एवं अपने-अपने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने के वादे पर हस्ताक्षर किए। नेहरू जानते थे कि जो देश मजहब के आधार पर ही बना है, उसके लिए तो हिंदू काफिर मजहबी विस्तार के लक्ष्य हैं। वह भला अल्पसंख्यकों को सुरक्षा क्यों देगा? उस समझौते का परिणाम आज हमारे सामने एक भीषण त्रासदी की तरह है। जहां भारत में अल्पसंख्यक आबादी 9 प्रतिशत से बढ़कर आज 15 प्रतिशत के आसपास है, वहीं पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू 23 प्रतिशत से घटकर करीब 2 प्रतिशत रह गए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने इस पर सवाल उठाया कि आखिर कहां गए वे करोड़ों हिंदू? कांग्रेस के पास इन सवालों का जवाब न तब था और न अब है। नेहरू के स्थान पर राष्ट्रवादी चरित्र के किसी नेता के पास उस समय नेतृत्व रहा होता तो संभवतः ऐसी विषम स्थिति निर्मित नहीं हुई होती। तब सिंध के हिंदूबहुल जिलों को लेकर 'स्वायत्त हिंदू एनक्लेव' बनाना हमारा लक्ष्य हो सकता था, लेकिन जब सत्ता वोट बैंक से संचालित हो तो ऐसे लक्ष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्हें हिंदुओं का दमन स्वीकार्य था, लेकिन उनकी सुरक्षा-संरक्षण नहीं।

भारत में अल्पसंख्यकों को चुनावी समीकरण का हिस्सा बनाकर राजनीति का विमर्श गढ़ा गया। इसीलिए पाकिस्तान, उर्दू, अलीगढ़ स्कूल के प्रतिबद्ध इतिहास लेखक भारत के राजनीतिक विमर्श के नियंत्रक बने रहे। वोटों के लालच में असम में इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी बसाए गए कि वहां की जनसांख्यिकी का अनुपात ही बिगड़ गया, लेकिन किसी ने कोई चिंता नहीं की। सत्ताधारी दल के नेताओं ने समझौता एक्सप्रेस बमकांड एवं मुंबई पर हुए आतंकी हमले के बाद हिंदू-आतंकवाद की छद्म परिभाषाएं गढ़ने में बड़ा परिश्रम किया। दूषित लक्ष्यपूर्ति के लिए उन्होंने कर्नल पुरोहित जैसे सेनाधिकारियों को भी नहीं बख्शा।

जब हम सीएए जैसे नागरिकता प्रदान करने वाले कानून का विरोध देखते हैं तब समझ में आता है कि तथाकथित सेक्युलर तत्वों के असल इरादे क्या हैं। हमने अनुच्छेद-370 को हटाने का विरोध भी देखा है। यदि विरोध कश्मीर में हुआ होता तो इसे समझा जा सकता था, लेकिन शेष भारत के अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद-370 से इतना लगाव क्यों? उन्हें तो इसका स्वागत करना चाहिए था कि कश्मीर के मुस्लिम भारत के बृहद् मुस्लिम समाज के साथ मजबूती से जुड़ रहे हैं। इस विरोध ने छिपे हुए सांप्रदायिक राजनीतिक विमर्श के निहितार्थ को उजागर कर दिया। जब कुछ नेता पाकिस्तान से आए हिंदू-सिख शरणार्थियों को कोसते हुए दिखते हैं, तब हमें 1947 के नेहरू की याद आ जाती है।

सीएए तो वह कानून है जो हमें अपने लोगों की चिंता करना और उनके भविष्य को संवारने की ओर उन्मुख करता है। इस कानून की स्वीकृति के साथ स्पष्ट मानस का एक दूसरा ही भारत उभर रहा है, जिसे हम जाति, संप्रदाय, वैचारिक विभ्रम के जंगल में वर्षों से खोज रहे थे। सीएए के विरुद्ध दो सौ से अधिक याचिकाएं दायर करने वाले लोग राष्ट्र के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। यह तय है कि वे एनआरसी की पहल का और अधिक विरोध करेंगे। समझना कठिन है कि वे यह क्यों चाहते हैं कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी देश को अपने वैध नागरिकों की सूची बनाने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए? सीएए तो एक प्रारंभ है। विलंब से ही सही, लेकिन हमें यह तो जानना चाहिए ही कि आखिर देश में भारतीय नागरिकों की कुल संख्या कितनी है। ध्यान रहे कि असम में एनआरसी बन चुका है और वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है।

(लेखक पूर्व सैन्य अधिकारी एवं पूर्व प्रशासक हैं)

response@jagran.com

राजनीति में नैतिकता का सवाल

हरेंद्र प्रताप

इस्तीफा न देने की केजरीवाल की जिद ने ऐसा संवैधानिक संकट पैदा कर दिया है, जिसका हल नहीं दिखता

संवैधानिक संकट खड़ा करते केजरीवाल। फाइल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी कह रही है कि वह जेल से ही सरकार चलाएंगे। केजरीवाल भी ऐसा कह रहे हैं। इसने एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि क्या भारत का संविधान इसकी अनुमति देता है? क्या जेल से सरकार चलाना उचित है? मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है। केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। हालांकि उसने इस पर सुनवाई से इन्कार कर दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि 'इस मुद्दे पर निर्णय लेना दिल्ली के उपराज्यपाल या भारत के राष्ट्रपति पर निर्भर है। कभी-कभी व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है, लेकिन यह अरविंद केजरीवाल का निजी फैसला होगा कि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना है या नहीं।' अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल इन दिनों मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर जनता के नाम केजरीवाल की भावनात्मक अपील जारी कर रही हैं। इससे चर्चा का बाजार गर्म है कि क्या अरविंद केजरीवाल की पत्नी उनकी उत्तराधिकारी बनने जा रही हैं? ईडी द्वारा पूछताछ के लिए समन पर समन के बाद भी हाजिर न होकर अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव की घोषणा का इंतजार तो नहीं कर रहे थे, ताकि लोगों की सहानुभूति प्राप्त की जा सके? सवाल कई हैं, पर सबसे बड़ा सवाल राजनीति में नैतिकता का है।

यह 12 जून, 1975 की बात है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी मानते हुए उनकी जीत को अवैध करार दिया। इसके साथ ही उनके छह वर्ष के लिए चुनाव लड़ने पर रोक भी लगा दी। उस समय देश में जेपी आंदोलन चल रहा था। उच्च न्यायालय के निर्णय के सिलसिले में पत्रकारों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण से पूछा-इंदिरा गांधी अब क्या करेंगी? उन्होंने कहा-अब वह इस्तीफा देंगी। पत्रकारों ने फिर से पूछा कि अगर वह इस्तीफा देने से इन्कार कर दें तो क्या होगा? जयप्रकाश जी ने कहा-तब अनर्थ हो जाएगा। इतिहास गवाह है कि इंदिरा गांधी ने इस्तीफा न देकर देश पर आपातकाल थोप दिया। एक प्रकार से उन्होंने लोकतंत्र के साथ राजनीतिक नैतिकता का भी अपहरण किया। हालांकि इसका दुष्परिणाम उन्होंने भुगता। 1977 में इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव हार कर सत्ता से बेदखल हो गईं। 1977 की घटना के बाद नेताओं में एक भय पैदा हुआ। चारा घोटाले में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जब जेल जाने लगे तो उन्होंने पद से इस्तीफा देकर पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। चूंकि बिहार में विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी है, अतः राबड़ी देवी को विधान परिषद का सदस्य बनाकर जेल में रहते हुए भी सत्ता संचालन का काम एक तरह से लालू यादव ही करते थे। एक बार मुख्यमंत्री जयललिता के सामने जब जेल जाने की नौबत आई तो उन्होंने इस्तीफा देकर अपने भरोसे के नेता को मुख्यमंत्री बना दिया था। पिछले दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, पर उन्हें भी इस्तीफा देकर चम्पाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। उनकी मंशा तो यही थी कि पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाकर जेल में रहते हुए सत्ता का संचालन करें। इसके लिए जल्दबाजी में एक सीट भी खाली कराई गई, पर एक डर यह था कि अगर छह माह के भीतर चुनाव नहीं हुए तो कल्पना सोरेन को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। हेमंत सोरेन अभी जेल में हैं, पर भविष्य की रणनीति पर काम चल रहा है। उनकी पत्नी राजनीति में आ गई हैं और जल्द चुनाव लड़कर विधायक बनने की तैयारी भी कर रही हैं।

हेमंत सोरेन की तरह ही जेल गए अरविंद केजरीवाल की पत्नी को उनका उत्तराधिकारी बनाने की मांग उठ रही है। मौजूदा कानूनी प्रविधानों के अनुसार दो या दो वर्ष से अधिक की सजा होने पर जनप्रतिनिधियों को पद छोड़ना पड़ता है, लेकिन नेताओं ने इसका तोड़ पत्नी को सत्ता में भागीदारी देने के रूप में निकाल लिया है। स्थानीय निकाय के चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रविधान के बाद 'मुखिया पति-सरपंच पति आदि' शब्द प्रचलन में हैं। इसका अर्थ है कि पति चुनाव नहीं लड़ सकता, अतः पत्नी को चुनाव लड़वाता है। चुनाव भले उसकी पत्नी जीते, पर अघोषित रूप से मुखिया-सरपंच का काम वही करता है। इन दिनों बिहार में बाहुबली अशोक महतो का विवाह चर्चा में है। चूंकि वह चुनाव नहीं लड़ सकता, अतः उसने आनन-फानन विवाह कर लिया। अब उसकी पत्नी राजद से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। सिवान की जदयू सांसद कविता सिंह की भी कहानी अशोक महतो से मिलती-जुलती है। इसी तरह आनंद मोहन तथा पप्पू यादव की पत्नी भी राजनीति में आईं। भारतीय लोकतंत्र मुखिया पति, विधायक पति, सांसद पति से आगे चलते हुए मुख्यमंत्री पति तक का सफर पूरा कर चुका है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल की मांग को लेकर छिड़े अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल की मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देने की जिद ने देश को एक ऐसे चौराहे पर ला खड़ा किया है, जहां से आगे का रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। भारतीय संविधान निर्माताओं ने ऐसे संवैधानिक संकट की कल्पना भी नहीं की थी। चूंकि उन्होंने ऐसी कोई कल्पना नहीं की थी, इसलिए उन्होंने इस बारे में कुछ तय भी नहीं किया कि यदि किसी मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ा तो उसकी सरकार कैसे चलेगी? कायदे से नेताओं को लोकलाज का ध्यान रखना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते तो आंदोलनों पर से भरोसा उठ जाएगा।

(लेखक बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं)

response@jagran.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ऊर्जा

त्यागमय जीवन

कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ त्यागना भी अनिवार्य माना गया है। हमारे शरीर को ही ले लीजिए श्वास लेने के लिए पहले श्वास छोड़नी पड़ती है, तभी इस शरीर की आंतरिक संरचना में नवीनता तथा सक्रियता का संचार होता है। त्याग हमें सांसारिक मोह से अलग करने के साथ हमारे आध्यात्मिक व्यक्तित्व को परिपक्वता प्रदान करता है।

इस संसार की जितनी भी भौतिक संपदा, वस्तुएं एवं पदार्थ हैं वे सभी मनुष्य जीवन को सम्यक प्रकार से निर्वाह करने के लिए ही बने हैं। इस दृश्य संसार की प्रत्येक वस्तु भोग और अपवर्ग की प्राप्ति के लिए बनी है, इसीलिए मनुष्य को सभी सांसारिक भौतिक पदार्थों का त्याग की दृष्टि से उपभोग करना चाहिए। नश्वर भौतिक संपदा का निरंतर संग्रह करने की प्रवृत्ति मनुष्य को लोभ और तृष्णा के बंधन में बांध देती है। जो भी पदार्थ मनुष्य को इस संसार में प्रयोग करने के लिए मिले हैं उनका अंत भी अवश्य होना है। अर्थात एक न एक दिन उन सभी पदार्थों से हमें अवश्य अलग होना है। त्याग से मनुष्य को सर्वोच्च प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। श्रीराम जब महल में थे तो राजा राम कहलाए और जब उन्होंने महल त्यागा तो पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम कहलाए। सिद्धार्थ गौतम ने जब त्याग के आदर्श को अपनाया तो गौतम बुद्ध के रूप में प्रतिष्ठित हुए।

त्याग के बिना शाश्वत सुख एवं शांति की कल्पना नहीं की जा सकती। त्याग जीवन का एक अनिवार्य नियम है। त्याग के बिना आनंद का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। भौतिक सांसारिक पदार्थों के बंधन में बंधे रहना जीवन में दुखों का मूल कारण है। आनंद की अनुभूति के लिए त्याग के आदर्श को अपनाना पड़ता है। केवल मात्र भौतिक संपदाओं का संग्रह करने की प्रवृत्ति मनुष्य को आंतरिक रूप से भीरू बना देती है। जीवन में त्याग के आदर्श का अनुसरण मनुष्य को आंतरिक संतुष्टि एवं आनंद प्रदान करता है।

आचार्य दीप चंद भारद्वाज

बच्चों पर गृहकार्य का बढ़ता दबाव

डा. कुमारेंद्र सिंह सेंगर

गृहकार्य के नाम पर जिस तरह का मानसिक बोझ बच्चों पर लाद दिया जाता है, उससे वे छुट्टियों का आनंद उठाना भूल ही गए हैं

एक समय था जबकि परीक्षा समाप्त होने के बाद कुछ दिनों तक सभी बच्चे दबाव मुक्त होकर अपनी छुट्टियों को बिताया करते थे। आजकल देखने में आ रहा है कि परीक्षा के दबाव से निकलते ही उनके ऊपर परीक्षा परिणाम का दबाव हावी होने लगता है। अंक कैसे आएंगे? कौन सा ग्रेड मिलेगा? प्रवीणता सूची में नाम आएगा या नहीं? ऐसे एक-दो नहीं सैकड़ों सवाल उनके मन-मष्तिष्क पर दबाव बनाने लगते हैं। इसके साथ-साथ एक दूसरी तरह का दबाव भी अपनी गिरफ्त बनाने की कोशिश करने लगा है। गर्मी की छुट्टियों के लिए बच्चों के बस्तों में इतना सारा अनावश्यक काम गृहकार्य के नाम पर ठूंस दिया जाता है कि न केवल बच्चे, बल्कि उनके माता-पिता तक भूल जाते हैं कि वे छुट्टियों का आनंद उठा रहे हैं।

मई-जून माह में होने वाली गर्मी की छुट्टियां बच्चों में अपने परिजनों से मिलने, अपने आसपास के वातावरण को देखने-समझने, देशाटन करने, बिना किसी तरह का मानसिक बोझ लेकर साथियों संग समन्वय-सामंजस्य आदि की समझ विकसित करती हैं। अब गृहकार्य के नाम पर जिस तरह का मानसिक और किताबी बोझ बच्चों पर लाद दिया जाता है, उससे बच्चे गर्मी की छुट्टियों का आनंद उठाना भूल ही गए हैं। क्या आज के बच्चे गर्मी की छुट्टियों में आम के बगीचों का आनंद ले पा रहे हैं? क्या वे ग्रामीण अंचलों में रह रहे अपने दादा-दादी, नाना-नानी अथवा अन्य रिश्तेदारों के पास जा पा रहे हैं? क्या आज के बच्चों द्वारा तालाब, नहर आदि में तैरने का मजा लिया जा रहा है? क्या वे खेतों-खलिहानों को वास्तविक रूप में आत्मसात कर पा रहे हैं?

ऐसा नहीं कि गर्मी की छुट्टियों में मिलने वाला गृहकार्य आवश्यक नहीं, इसके द्वारा भी बच्चों का मानसिक और शैक्षणिक विकास होता है। छुट्टियों के दिनों में दिए गए प्रोजेक्ट द्वारा उनके भीतर कुछ न कुछ नया सीखने की ललक पैदा होती है, लेकिन बजाय इसके विद्यालयों से गृहकार्य के नाम पर पाठ्यक्रमों की पूर्ति करवाई जाने लगी है। लंबे-लंबे लिखित किताबी कार्य देकर बच्चों को चौबीस घंटे किताबों में ही घुसे रहने को मजबूर किया जा रहा है। गृहकार्य द्वारा अब न बच्चों के सामान्य ज्ञान को बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है, न उनकी हस्तलिपि को सुधारने पर जोर दिया जा रहा है, न ही कला-संगीत आदि किसी शौक को विकसित करने की पहल की जा रही है। अधिक से अधिक अंक लाने की अंधी दौड़, प्रवीणता सूची में सबसे ऊपर आने की कशमकश, अधिक से अधिक किताबी ज्ञान को दिमाग में भर लेने की कवायद द्वारा बच्चों का बचपन तो पहले ही छीन लिया गया है, अब गर्मी की छुट्टियों पर अप्रत्यक्ष डाका डालकर एक तरह से उनको समाज, परिवार, संस्कृति आदि से भी दूर किया जा रहा है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

पाठ्यक्रम के अनुसार हों पाठ्यपुस्तकें

'पाठ्यक्रम परिवर्तन का अधूरा एजेंडा' शीर्षक से लिखे अपने आलेख में राजीव सचान ने कहा है कि मोदी सरकार ने बीते दस वर्षों में बहुत कुछ किया है, लेकिन शिक्षा के मोर्चे पर कुछ विशेष नहीं हो सका। यह विडंबना ही है की नई शिक्षा नीति को लागू हुए चार वर्ष होने को हैं, किंतु इस पर अपेक्षित गंभीरता से काम नहीं हो पा रहा है। आखिर सरकारें इसकी आवश्यकता को कब समझेंगी। लेखक ने स्कूली स्तर पर राजस्थान और दिल्ली में स्कूली पाठ्यक्रम आधारित पुस्तकों में हुई तथ्यात्मक गलतियों का जो विवरण दिया है वह सचमुच चिंतनीय है। छात्र-छात्राएं जब यही गलत जानकारियां पढ़कर आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो उसका दोषी कौन होगा? स्कूली पाठ्यक्रम का निर्धारण होने के पश्चात उसके अनुसार जो पुस्तकें बाजार में आई हैं वे सचमुच में पाठ्यक्रम के अनुसार लिखी गई हैं अथवा नहीं, इसकी जांच करने का फिलहाल कोई तंत्र देश में उपलब्ध नहीं है। वैसे यह केवल स्कूल स्तर की समस्या नहीं, बल्कि कालेज स्तर पर भी छात्र-छात्राएं यही कठिनाई अनुभव करते हैं। कालेज स्तर पर तो प्रकाशक ही पुस्तक लेखक से संपर्क में रहते हैं। लेखक की उस विषय में कोई विशेषज्ञता है कि नहीं, इसकी जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रकाशक, लेखक और पुस्तक विक्रेता ही सब कुछ तय करते हैं। शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) को इसका तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि जो पाठ्यपुस्तकें नई शिक्षा नीति लागू होने के पश्चात बाजार में आई हैं वे नए पाठ्यक्रम के अनुसार विषय विशेषज्ञों द्वारा ही लिखी गई हैं या नहीं। नई शिक्षा नीति की सफलता के लिए समय-समय इसकी समीक्षा भी आवश्यक है।

डा. प्रदीप कुमार संघवी, झाबुआ (मध्य प्रदेश)

विपक्ष की परेशानी

'कारगर रणनीति के अभाव से ग्रस्त विपक्ष' शीर्षक आलेख में राहुल शर्मा ने विपक्ष के कारगर रणनीति के अभाव की चर्चा की है, जिससे कि वह भाजपा के खिलाफ सही रूप में मुकाबला कर सके। वर्तमान समय में भाजपा के मुकाबले विपक्ष की स्थिति चुनौतीपूर्ण है। हालांकि ऐसा नहीं है कि विपक्ष उसके खिलाफ सही रणनीति नहीं बना सकता। विपक्ष को ध्यान में रखना होगा कि केवल भाषण देकर ही वह चुनाव नहीं जीत सकता, बल्कि सकारात्मक विकल्प प्रस्तुत करे, जो समाज के हित में हो। विपक्ष सिर्फ राजनीतिक बदलाव का वादा नहीं करे, बल्कि क्रियान्वयन के माध्यम से भी लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश करे। विपक्ष को सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे कि वह आम जनता की समस्याओं का हल प्रस्तुत कर सके। आम चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए विपक्ष को अपने राजनीतिक अभियान को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना होगा। वह भाजपा के सामने नए विचारों और नीतियों को प्रस्तुत करे, ताकि लोगों का भरोसा जीत सके।

अवनीश कुमार गुप्ता, प्रयागराज

नक्सलवाद की समस्या

हाल में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा कर्मियों ने 10 से अधिक नकसलियों को ढेर कर दिया। देश में एक समय नक्सलवाद आतंकवाद से भी खतरनाक समस्या थी, लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास से अंतिम सांसें गिन रहा है। देश में नक्सलवादी सरकार और सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार के सताए गरीब लोगों को बहला फुसलाकर हिंसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। नक्सलवादियों तक हथियार कैसे पहुंचते हैं या फिर उन्हें हमले करने की ट्रेनिंग कौन देता है? इन सवालों का हल सरकार को ढूंढ़ना चाहिए। भारतीय खुफिया एजेंसियों को भी सतर्क होना चाहिए। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकारों को सबका साथ सबका विकास के नारे पर अमल करते हुए नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों की तरफ गंभीरता से ध्यान देते हुए वहां विकास के कार्यों पर जोर देना चाहिए, वहां के पीड़ित और शोषित वर्ग की तरफ सबसे पहले ध्यान देना चाहिए।

raju09023693142@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

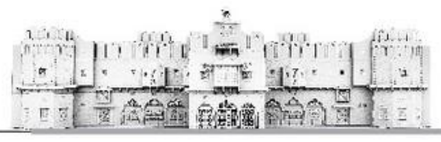

स्वास्थ्य उत्पादों के लिए रखने होंगे ऊंचे मानक

देश में स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता ने इससे जुड़े बाजार के लिए संभावनाओं के नए-नए द्वार खोले हैं। लेकिन, बाजार की इन्हीं संभावनाओं ने आम लोगों के लिए खतरे भी बढ़ा दिए हैं। सेहत ठीक रखने के नाम पर बाजार में कुछ भी बेचा जाने लगा है। हेल्थ और वेलनेस क्षेत्र की कंपनियों के उत्पादों का कथित झूठा प्रचार और भ्रमित करने वाले दावे जोखिम बढ़ा रहे हैं। इसे रोकने की जिम्मेदारी, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन (सीडीएससीओ), राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण (एनआरए) और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) की है।

पिछले दिनों ऐसे ही मामले में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश होकर माफी मांगनी पड़ी। एक अन्य मामले में एफएसएसएआइ ने एनर्जी ड्रिंक और हेल्थ ड्रिंक के नाम पर बिक रहे पेय पदार्थों को लेकर ई-कॉमर्स कंपनियों को चेतावनी भी जारी की है। उन्हें डेयरी, अनाज और माल्ट आधारित पेय पदार्थों को हेल्थ ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक की श्रेणी से हटाकर उचित वर्गीकरण का आदेश दिया गया है। नियमों में हेल्थ ड्रिंक की कोई श्रेणी नहीं है। इसके बावजूद लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसा किया जा रहा था। सेहत से खिलवाड़ को रोकने के लिए जिम्मेदार एजेंसियां कोरी चेतावनी देकर या गाइडलाइन जारी कर अपने दायित्वों की इतिश्री कर लेती हैं। ऐसा नहीं होता तो संबंधित मामलों को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आती। एक तथ्य यह भी है कि सरकारें भी हेल्थ और वेलनेस सेक्टर में बड़ी संभावनाएं देख रही हैं। स्वास्थ्य पर्यटन का बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है। बाजार में इसकी हिस्सेदारी 6 फीसदी है। स्वास्थ्य, सौंदर्य और एंटी एजिंग उत्पादों की बाजार हिस्सेदारी करीब 24 फीसदी है। अनुमान है कि भारत सहित एशिया प्रशांत क्षेत्र में यह हिस्सेदारी 2030 तक 6.3 फीसदी की दर से बढ़ेगी। यह दुनिया में सबसे तेज वृद्धि दर है। विशाल आबादी, बढ़ता शहरीकरण व औद्योगीकरण इत्यादि कारणों से यह क्षेत्र हेल्थ उत्पादों के लिए काफी अवसरकारी माना जा रहा है।

चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया से इस बाजार को काफी उम्मीदें हैं। अमरीका और यूरोप के देशों में सेचुरेशन सा आता जा रहा है। दुनिया की निगाहें एशिया प्रशांत क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से भी यह क्षेत्र स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का ज्यादा ही सामना कर रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर उच्च मानकों का पालन कराना जरूरी है। हेल्थ सेक्टर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश को बढ़ावा देने की मंशा से जरा भी ढील बड़ी समस्या का कारण बन सकती है।

भाजपा के 224 में से 2 प्रत्याशी ही जीते

वर्ष 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 224 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए थे, लेकिन इनमें से 2 प्रत्याशी ही जीत पाए। इस चुनाव में भाजपा को 7.74 प्रतिशत मत मिले।

पत्रिका लोकतंत्र का उत्सव

लोकसभा चुनाव 2024

4263 की हो गई थी जमानत जब्त

वर्ष 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में कुल 5312 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। इनमें से 4263 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। भाजपा के 108 और कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों की भी जमानत जब्त हुई थी।

Q&A राजस्थान में पूरी हो रही है मोदी की गारंटी, हमने राजस्थान में पेपर लीक पर एसआइटी बनाई

कांग्रेस राजस्थान में 25 प्रत्याशी नहीं ढूढ़ पा रही है

70% वोट के साथ सभी 25 सीटों पर लगेगी हैट्रिक – अमित शाह

इंटरव्यू विशेष

भाजपा के चुनावी रणनीतिकार और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार राजस्थान की सभी 25 सीटों को जीतकर हैट्रिक लगाने की तैयारी में हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी और चेहरे के दम पर भाजपा चुनाव में उतरी है। चुनावी गहमागहमी के बीच राजस्थान पत्रिका समूह के डिप्टी एडिटर भुवनेश जैन से शाह की हुई विशेष बातचीत के मुख्य अंश...

पत्रिका: बॉर्डर स्टेट होने की वजह से राजस्थान में ड्रग्स हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है। ड्रग्स के खिलाफ आपकी क्या रणनीति है?

अमित शाह: देखिये, ड्रग के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत से कदम उठाए। जिसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। हमने एनसीओआरडी (राष्ट्रीय नारकोटिक्स समन्वय पोर्टल) की स्थापना की है। इसकी स्थापना हमने तीन स्तर पर - जिला स्तर तक की है। 'टॉप टू बॉटम' और 'बॉटम टू टॉप' अप्रोच के साथ केस का सम्पूर्ण अनुसंधान किया जाता है। सारी एजेंसियां मिलकर काम करती हैं। 2006-13 में पकड़े गए 1 लाख 52 हजार किलो की तुलना में 2014-23 में 3 लाख 95 हजार किलो, यानी 160% अधिक ड्रग्स जब्त किए गए। पहले सिर्फ 768 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़े गए थे, मोदी सरकार की प्रभावी कारवाइयों के बाद 22 हजार करोड़ रुपए यानी 30 गुना अधिक ड्रग्स पकड़ा गया। पहले कुल 1,257 मामले दर्ज हुए थे, अब 3,755 हुए हैं। यह 199% की बढ़ोतरी है। पहले 1,363 गिरफ्तारियां हुईं थीं, अब 321% बढ़कर 5,745 हुए हैं। पिछले एक वर्ष में लगभग 12 हजार करोड़ रुपए के मूल्य के 10 लाख 18 हजार किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किया गया है। इसका परिणाम ये उपलब्धियां हैं।

विवरण	2006-2013	2014-2022	परिवर्तन (%)
जब्त ड्रग्स	1,52,000	3,95000	160% अधिक
कीमत में	5,933 करोड़	18 हजार करोड़	3 गुना
कुल मामले	1,257	3,755	199%
कुल गिरफ्तारी	1,363	5,745	321%

पिछले एक वर्ष में लगभग 12 हजार करोड़ रुपए के मूल्य का 10 लाख 18 हजार किलोग्राम मादक पदार्थ डिस्पोजल किया गया है। (ड्रग्स किग्रा में)

https://t.me/AHNewsPaperPaid

चुनावी गहमा गहमी के बीच **अमित शाह** पत्रिका समूह के डिप्टी एडिटर **भुवनेश जैन** से बातचीत करते हुए। फोटो : *अनुग्रह सोलोमन*

पत्रिका: चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही कह रहे हैं कि हम राजस्थान को नंबर 1 बनाएंगे। जनता किस की बात पर विश्वास करे?

शाह: आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी कहा था कि हम राजस्थान को नंबर 1 बनाएंगे, और उन्होंने राजस्थान को नंबर 1 बनाया भी। उन्होंने राजस्थान को भ्रष्टाचार में नं. 1 बनाया, महिलाओं के खिलाफ अपराध में नं. 1 बनाया, महिलाओं से दुष्कर्म में नं. 1 बनाया, साइबर क्राइम में नं. 1 बनाया, बिजली की दरों में, पेट्रोल-डीजल पर वैट लगाने में, महंगाई इंडेक्स में और परिक्षाओं के पेपर लीक में नंबर 1 बनाया। तो, कांग्रेस वाले गलत नहीं कहते हैं कि उन्होंने नंबर नहीं बनाया। हम जब कहते हैं कि हम राजस्थान को नंबर 1 बनाएंगे, तो हमारा मतलब होता है कि हम राजस्थान को महिला सुरक्षा में नंबर 1 बनाएंगे, खुशहाली के मामले में नंबर 1 बनाएंगे, साक्षरता दर के मामले में नंबर 1 बनाएंगे, रोजगार के मामले में नंबर 1 बनाएंगे, टूरिज्म के मामले में नंबर 1 बनाएंगे और जीएसडीपी में नंबर 1 बनाएंगे। यह एक बहुत ही बड़ा फर्क है कांग्रेस के नंबर 1 राजस्थान और हमारे नंबर 1 राजस्थान बनाने की बात में।

पत्रिका: राजस्थान की जनता ने 2014 हो या 2019, दोनों बार 25 की 25 सीटें भाजपा की झोली में डाली। इस बार भी आप राजस्थान की जनता से 25 सीटें मांग रहे हैं। जनता को क्या लाभ हो रहा है?

शाह: इसका हमारा आधार है। राजस्थान के विकास के लिए भाजपा की सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। 2014 से पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही और बाद में 10 साल हमारी सरकार रही। डिवोल्युशन ग्रांट इन ऐड फण्ड का ही कम्पैरिजन देखिए। एक लाख 61 हजार करोड़ रुपए यूपीए ने राजस्थान को दिए थे और एनडीए की मोदी सरकार ने 6 लाख 24 हजार करोड़ रुपए दिए। यानि चार गुना ज्यादा पैसा हमने दिया। इसके अलावा 80 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि, 32 लाख नल कनेक्शन, 1 करोड़ 10 लाख आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी, 5 लाख नए शौचालय, उज्ज्वला योजना के 71 लाख कनेक्शन और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 19 लाख आवास दिए गए। एक प्रकार से राजस्थान के गरीबों के लिए और फण्ड देने के ढेर सारे कार्य हुए हैं। इसके अलावा बीते 9 वर्षों में पीएम ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 70 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ, तो वहीं राजस्थान में सड़क निर्माण के लिए 50 हजार करोड़ रुपए दिए गए। मोदी जी ने रेलवे के विकास के लिए 57 हजार करोड़ रुपए की राशि से 10 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने का निर्णय किया। इसके अलावा एक तरफ राजस्थान को अत्याधुनिक वंदे भारत ट्रेन का तोहफा मिला है, तो दूसरी ओर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 82 रेलवे स्टेशनों का भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है। 6 हजार करोड़ रुपए से कोटा में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है तो वहीं उड़ान योजना के अतर्गत बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ हवाई अड्डे की भी शुरुआत की गई है और 500 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर एयरपोर्ट में नई टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। पहले राजस्थान में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 10 थी, आज 35 हो गई है। इसके अलावा 7 नए बन रहे हैं। 1500 करोड़ रुपए से 5 और नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हो रहा है। विकास के कार्यों में राजस्थान के लिए बहुत कुछ किया गया है। पीने के पानी की समस्या का समाधान हुआ। युवाओं के पेपर लीक बंद हुए। मोदी सरकार ने दस साल में विकास के इतने कार्य किए, जिन्हें राजस्थान की जनता जानती भी है और मानती भी है।

पत्रिका: पहले कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज, फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री का जेल जाना, लोकसभा चुनाव से पहले इन कार्रवाई से सवाल उठ रहे हैं कि आप विपक्ष को खत्म करने के लिए ऐसा कर रहे हैं?

शाह: इनकम टैक्स की अनियमितता का मामला लगभग 4 साल से चल रहा है। ये लोग उसको लटका रहे थे। उसका फैसला चुनाव के वक्त आया। केजरीवाल जी को भी नौ महीने से समन मिल रहे थे। उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया। फिर हाईकोर्ट में रिजेक्ट होने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। ऐसा नहीं कि केवल चुनाव के वक्त यह किया गया। उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। हाईकोर्ट में अपील करनी चाहिए।

पत्रिका: अरविंद केजरीवाल जेल से सरकारी ऑर्डर दे रहे हैं। शराब घोटाले जैसे गंभीर आरोप के बाद वे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। क्या जेल से सरकार चलाना वाकई मुमकिन है?

शाह: यह संवैधानिक मामला नहीं है। यह नैतिकता का मामला है। व्यक्ति को खुद ही यह तय करना है कि यह उचित है या नहीं है। संविधान में यह इस प्रकार का ग्रे एरिया रहा है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने ऐसी स्थिति की कल्पना ही नहीं की होगी कि जेल में जाने का वक्त आए तो भी कोई इस्तीफा ही नहीं देगा। जो लोग समाज सेवा के लिये राजनीति में जुड़ने का दावा करते थे, इनकी राजनीति कहां तक पहुंची है कि वे अपनी पार्टी के किसी साथी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इस्तीफा देकर और कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या हो जाएगा? ढेर सारे कार्यकर्ता होते हैं, इतनी बड़ी पार्टी है। मगर किसी पर भरोसा ही नहीं है। स्वयं के हाथ में सत्ता रखना और जेल से ही सरकार चलाने का प्रयास करना। देश की जनता और दिल्ली की जनता सब जानती है और देख भी रही है।

पत्रिका: ईडी ने हाल ही में आम आदमी पार्टी के गोवा प्रदेश अध्यक्ष से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ की है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में शराब घोटाले के पैसे गोवा भेजे गए हैं या विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है?

शाह: गोवा पैसे गए इसका ट्रेल मिला है, इसीलिए कन्फर्मेशन के लिए उनको बुलाया गया है। किसी को अरेस्ट नहीं किया गया है, पूछताछ की है।

पत्रिका: जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और पत्थरबाजी हमेशा से बड़ी समस्या रही है। घाटी में शांति के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं और इसके परिणाम क्या आए हैं?

शाह: हमने आतंकवाद और आतंककारियों के इको-सिस्टम को ध्वस्त किया है और इसके कारण औसतन 70 प्रतिशत की कमी आतंकवाद में आई है। धारा 370 हट चुकी है। आज वहां निवेश हो रहा है। दो करोड़ से ज्यादा टूरिस्टों ने वहां पर एक साल में यात्रा की है। पत्थरबाजी शून्य हो चुकी है। आतंककारियों के समर्थको को नौकरियों से हटाया गया है। आतंककारियों के सार्वजनिक जनाजे पर पाबंदी लगा दी गई है। और भी कठोर कदम हमने टेररिस्ट इको-सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए उठाए हैं। जिसके नतीजन कुल घटनाओं में 69% कमी आई, कुल मृत्य में 68% कमी, नागरिकों की मृत्यु में 81% कमी और सिक्युरिटी फोर्सेज की मृत्यु में 46% कमी आई है।

पत्रिका: विपक्ष का आरोप यह भी है कि एक तरफ आप ईडी सीबीआई के जरिए विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ सीबीआई और ईडी जैसी संस्था बीजेपी के साथ जाने वाले नेताओं को क्लीन चिट दे रही है। इस पर आप क्या कहेंगे?

शाह: एक सेकंड के लिए इनके आरोपों को सच मान लीजिए। अगर बीजेपी के लोगों में भ्रष्टाचार है, तो पीआइएल करने से कौन रोक रहा है? जब उनका शासन था, तो हमने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए 12 लाख करोड़ रुपए के घपले घोटाले उजागर किए थे। कोर्ट भी गए थे, कैग में भी गए थे, पार्लियामेंट में भी उजागर किए थे। ये तो पार्लियामेंट में चर्चा ही नहीं करते। बहिष्कार कर जाते हैं। उनको कौन रोक रहा है? मामले ढूंढकर कोर्ट में जाएं। कैग में एप्लिकेशन दायर करें। सच यह है कि मोदी जी ने 12 लाख करोड़ रुपये के घपले घोटाले करने वाली कांग्रेस पार्टी को 10 साल में अंगुली उठाने का मौका नहीं दिया है। एक व्यक्ति 24 साल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहता है और उस पर 10 पैसे का आरोप विपक्ष नहीं लगा पाया है। इतनी पारदर्शिता के साथ मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया है और अब प्रधानमंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर

इंडीकेटर	2004-14	2014-2024	कमी
कुल घटनाएं	7,217	2,227	69%
कुल मृत्यु	2,829	915	68%
नागरिक की मृत्यु	1769	341	81%
सिक्योरिटी फॉर्सेज की मृत्यु	1,060	574	46%

- *सुरक्षा उपकरणों का आधुनिकीकरण*
- *उच्च सुरक्षा मॉडल वाले हाई सिक्योरिटी जेल*

पत्रिका: आपने जम्मू-कश्मीर में कई संगठनों को बैन किया है। क्या आपको लगता है कि संगठनों को बैन करने जैसी कार्रवाई से आतंकवाद में कमी आएगी?

शाह: हमने जम्मू-कश्मीर में लगभग 12 आतंकी संगठनों को प्रतिबंधित किया है। 36 लोगों को टेरेरिस्ट घोषित किया है। टेरर फाइनेंस के लिए भी हमने केस रजिस्टर किए हैं। मैं मानता हूं कि ये सारी चीजें कुल मिलाकर कश्मीर के अंदर शांति स्थापित करने के लिए बड़ी जिम्मेदार रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर की जनता के साथ सीधा संवाद कर उनके विकास के लिए भी ढेर सारे काम किए हैं। आज कश्मीर के हर व्यक्ति को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिला है। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का शत प्रतिशत क्रियान्वयन कश्मीर में हुआ है। अभी प्रधानमंत्री जी ने जो रैली की है, उसमें कश्मीर की जनता ने पलक पांवड़े बिछाकर प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया है। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस और वहां की परिवारवादी पार्टियों ने जिस कश्मीर को दहशतगर्दी के गर्त में डाला था, उसे मोदी जी ने फिर स्वर्ग बनाने का काम किया है।

पत्रिका: दशकों से देश वामपंथी उग्रवाद की समस्या से जूझ रहा है। आखिर कब तक देश को इस समस्या से पूर्ण मुक्ति मिल सकेगी?

शाह: मैं विश्वास से आपके पाठकों को बताना चाहता हूं कि अगले तीन साल में देश में वामपंथी उग्रवादी एक भी क्षेत्र नहीं होगा। 2005 से 2014 और 2014 से 2023 के आंकड़ों के अनुसार सुरक्षा बलों की मृत्यु में 72% की कमी आई है, नागरिकों की मृत्यु में 68% की कमी है और कुल हिंसक घटनाएं 52% कम हुई हैं। वहीं हिंसा रिपोर्ट करने वाले जिले 96 से घटकर 45 हो गए हैं। बहुत से जिले वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हुए हैं, वहां भी मोदी जी के विकास का संदेश नीचे तक पहुंचा है। टेलीफोन टावर लगे हैं। सड़कें बनीं हैं। स्कूल बने हैं। प्राइमरी हैल्थ सेंटर पहुंचे हैं। ये सारी चीजें आज जमीन पर पहुंचाने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है।

पत्रिका: सीएए के बाद देश में यूसीसी पर काफी चर्चा हो रही है। हाल ही में आपने कहा भी था कि शरिया लागू करना है तो पूरी तरह करो, चोरी करने पर हाथ काट दो या चौराहे पर लटका दो। क्या आप लोगों को डरा रहे हैं?

शाह: देखिये, यूसीसी भाजपा की स्थापना से हमारा तो एजेंडा रहा ही है। परंतु यूसीसी पर हमारे संविधान निर्माताओं ने भी हमसे अपेक्षा की है। गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर स्टेट जो बनाए गए हैं, आर्टिकल 44 में, उसमें यूसीसी रखा गया है। किसी भी पंथ निरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर कानून कैसे हो सकता है? कांग्रेस इस पर सरासर झूठ बोल रही है और जो लोग मांग कर रहे हैं कि शरिया के आधार पर हम जीना चाहते हैं, तो कांग्रेस के जमाने से आप नहीं जी रहे हो भाई? क्रिमिनल एक्ट में शरिया नहीं है। सिविल एक्ट में शरिया नहीं है। सिर्फ फैमिली कानूनों में ही शरिया है क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता।

वामपंथी उग्रवाद

इंडीकेटर्स	2005-2014	2014-2023	परिवर्तन
हिंसा की घटनाएं	14862	7128	52% की कमी
वामपंथी उग्रवाद से संबंधित मौतों	6035	1868	69% की कमी
सुरक्षा बलों की मृत्यु	1750	485	72% की कमी
नागरिकों की मृत्यु	4285	1383	68% की कमी
हिंसा की रिपोर्ट करने वाले जिले	96 (2010)	45 (2022)	53% की कमी
हिंसा की सूचना देने वाले पुलिस स्टेशन	465 (2010)	176 (2022)	62% की कमी

पत्रिका: हनुमान बेनीवाल इंडी एलायंस के साथ चले गए हैं। क्या लगता है इससे बीजेपी को नुकसान होगा?

शाह: देखिए, विधानसभा चुनाव में भी वे लड़े थे, फिर भी हमारी सरकार बनी। जाट बेल्ट पूरी मोदी जी के साथ है। सभी जातियां मोदी जी के साथ हैं। कांग्रेस की स्थिति तो यह है कि उनको 25 प्रत्याशी ढूंढ़ने में भी दिक्कत आ रही है। दो प्रत्याशियों ने टिकट वापस दे दिए। दो टिकट पार्टी को बदलने पड़े। स्थिति यह है, तीन माह पहले जिनकी राजस्थान में सरकार थी, उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे। पूरे राजस्थान में मोदी जी की एक लहर है। मुझे पूरा विश्वास है इस बार फिर हैट्रिक करके राजस्थान की 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।

पत्रिका: पूर्वोतर भारत लंबे समय से हिंसक घटनाओं से प्रभावित रहा है। आज भी वहां नस्लीय हिंसा और उग्रवादी गुट एक्टिव हैं। नॉर्थ-ईस्ट में शांति के लिए आपकी क्या रणनीति है?

शाह: वहां 9 हजार उग्रवादी हथियार डाल चुके हैं, एएफएसपीए (सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम) की परिधि के अंदर 80 प्रतिशत क्षेत्र से हमने एएफएसपीए हटा लिया है। पूर्वोत्तर में मोदी जी के प्रयास से हिंसक घटनाओं में 73% की कमी, हताहत सुरक्षा बालों की संख्या में 71% की कमी और हताहत नागरिकों की संख्या में 86% की कमी आई है। इसके अलावा हमने विभिन्न उग्रवादी संगठनों से शांति समझौते भी किए। जिसके नतीजन वर्ष 2019 से 2023 तक और 9 हजार के करीब उग्रवादी सरेंडर हुए हैं। एनएलएफडी/एसडी समझौता (2019), बोडो समझौता (2020), ब्रू समझौता (2020), कार्बी समझौता (2021), आदिवासी शांति समझौता (2022), डीएनएलए समझौता (2023), उल्फा शांति समझौता (2023), यूएनएलएफ शांति समझौता (2023), असम-मेघालय अंतरराज्यीय सीमा समझौता (2022), असम-अरुणाचल प्रदेश अंतरराज्यीय सीमा समझौता (2023) और टिपरा-मोथा समझौता हुए।

नस्लीय हिंसा

इंडीकेटर्स	2004-14	2014-2023	कमी
हिंसक घटनाएं	11,121	3,114	73%
हताहत सुरक्षा बल	458	132	71%
हताहत नागरिक	2,625	363	86%

- *2014 से अब तक 8900 से अधिक उग्रवादियों ने सरेंडर किया है।*
- *अफस्पा की परिधि में कमी आई है।*

पत्रिका: धारा 370 की समाप्ति से जम्मू-कश्मीर में बीते 5 साल में क्या बदलाव आया है?

शाह: जम्मू-कश्मीर में 33 साल बाद थियेटर खुले हैं। 34 साल बाद मुहर्रम का जुलूस निकला है। जो घाटी कभी आतंकवाद और पत्थरबाजी के लिए बदनाम था, वहां जी-20 की बैठक हुई है। जहां कभी लोग हाथ में तिरंगा उठाने से डरते थे, वहां घर-घर तिरंगा अभियान चलाया गया है और हाल ही में विश्वप्रसिद्ध डल झील के किनारे फार्मूला-4 की कार रेसिंग तो पूरी दुनिया ने देखी है। लगभग दो करोड़ से ज्यादा टूरिस्टों का जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कश्मीर में हमने हालात बदले हैं। आज दो दरबार की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है और आज जम्मू-कश्मीर में 'एक विधान, एक निशान, एक प्रधान' के स्वप्न को हमने पूरा किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो को इंट्रोड्यूस किया है। पठानकोट का नाका परमिट भी समाप्त हो चुका है।

पत्रिका: आपने जम्मू-कश्मीर में कई संगठनों को बैन किया है। क्या आपको लगता है कि संगठनों को बैन करने जैसी कार्रवाई से आतंकवाद में कमी आएगी?

शाह: हमने जम्मू-कश्मीर में लगभग 12 आतंकी संगठनों को प्रतिबंधित किया है। 36 लोगों को टेरेरिस्ट घोषित किया है। टेरर फाइनेंस के लिए भी हमने केस रजिस्टर किए हैं। मैं मानता हूं कि ये सारी चीजें कुल मिलाकर कश्मीर के अंदर शांति स्थापित करने के लिए बड़ी जिम्मेदार रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर की जनता के साथ सीधा संवाद कर उनके विकास के लिए भी ढेर सारे काम किए हैं। आज कश्मीर के हर व्यक्ति को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिला है। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का शत प्रतिशत क्रियान्वयन कश्मीर में हुआ है। अभी प्रधानमंत्री जी ने जो रैली की है, उसमें कश्मीर की जनता ने पलक पांवड़े बिछाकर प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया है। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस और वहां की परिवारवादी पार्टियों ने जिस कश्मीर को दहशतगर्दी के गर्त में डाला था, उसे मोदी जी ने फिर स्वर्ग बनाने का काम किया है।

चिंतन

सैन्य क्षमता में वृद्धि करते रहना आवश्यक

भारत आर्थिक रूप से जितना अधिक मजबूत होगा, उसकी सामरिक चुनौतियां उतनी ही बढ़ेंगी। महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य के शब्दों में किसी भी प्रकार के आक्रमण से अपनी जनता की रक्षा करना प्रत्येक राजसत्ता का सर्वप्रथम उद्देश्य होता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि एक संप्रभु सक्षम राष्ट्र को चार अलग-अलग तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। आंतरिक, बाह्य, बाह्य रूप से सहायता प्राप्त आंतरिक और आंतरिक रूप से सहायता प्राप्त बाहरी। संयोग से इस वक्त भारत इन चारों तरह के मिश्रित खतरों का सामना कर रहा है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि-प्राइम' के सफल परीक्षण से भारत की सैन्य शक्ति में और वृद्धि हुई है। भारत को चीन और पाकिस्तान सीमा पर अधिक खतरा है, पाकिस्तान से 2016 से और चीन से 2020 से रिश्ते सबसे खराब के स्तर पर हैं। चीन की लगातार कोशिश है कि भारतीय सीमा एलएसी पर विवाद बना रहे। एलएसी पर चीनी कारस्तानियां चलती रहती हैं, चीनी फौज सुनियोजित साजिश के तहत भारतीय सीमा पर षड्यंत्र करती रहती है, इससे दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव बना रहता है। पाकिस्तान एलओसी पर कश्मीर में आतंकी घुसपैठ कराने के मकसद से सीजफायर का उल्लंघन करता रहा है। चीन और पाकिस्तान का एकमेव कृत्य है, सीमा पर भारत को परेशान करते रहना। चीन नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार आदि भारत के पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक व सामरिक संबंध मजबूत कर भी भारत के लिए सैन्य मुश्किल खड़ी करता है। इसके अलावा भी कई अदृश्य शक्तियां हैं, जो भारत की आस्तीन में रहकर भारत के खिलाफ एक्शन में लिप्त रहती हैं। ऐसे में भारत की सामरिक चुनौतियां बड़ी हैं। इस चुनौतियों का सामने करने के लिए भारत को सामरिक रूप से निरंतर मजबूत बनना पड़ेगा। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि-प्राइम' जैसी मिसाइल भारत की सैन्यशक्ति में इजाफा करती है। पिछले महीने, भारत ने अपने 'मिशन दिव्यास्त्र' के तहत मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (एमआईआरवी) के साथ देश में विकसित अग्नि-पांच मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया था। एमआईआरवी सुविधा यह सुनिश्चित करती है कि एक ही मिसाइल विभिन्न स्थानों पर विभिन्न लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। अग्नि-पांच मिसाइल की मारक क्षमता 5,000 किमी तक है। मिसाइल की जद चीन के उत्तरी भाग समेत लगभग पूरे एशिया और साथ ही यूरोप के कुछ क्षेत्रों तक है। अग्नि-1 से अग्नि-4 श्रेणी की मिसाइलों की मारक क्षमता 700 किमी से 3,500 किमी तक है और इन्हें पहले ही तैनात किया जा चुका है। पिछले साल जून में भारत ने 'अग्नि प्राइम' का रात के दौरान सफल परीक्षण किया था। भारत पृथ्वी की वायुमंडलीय सीमा के अंदर और बाहर किसी शत्रु की तरफ से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता विकसित कर रहा है। भारत मिसाइल, फाइटर प्लेन समेत सभी प्रकार के स्वदेशी सैन्य उपकरण से लैस हो रहा है, साथ ही अनेक आयातित डिफेंस सिस्टम से सेना मजबूत हो रही है। भारतीय सेना परंपरागत वार के अलावा हाईटेक वार में भी दक्ष है, आज भारत विश्व की चौथी बड़ी सैन्य शक्ति है। सामरिक चुनौतियों का सामना करने के लिए खुफिया तंत्र की मजबूती, सैन्य शक्ति व युद्ध नीति का आधुनिकीकरण, उन्नत अस्त्र-शस्त्र के साथ सीमा क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

विडंबना
डॉ. अश्विनी महाजन

उत्तर-दक्षिण विभाजन की झूठी कहानी

लंदन से प्रकाशित एक पत्रिका में लेख के जरिये उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजन की नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश की है। पत्रिका यह दावा करने की कोशिश करती है कि दक्षिण भारतीय राज्य आर्थिक दृष्टि से शेष भारत से अलग हैं, क्योंकि भारत की केवल 20 प्रतिशत आबादी पांच दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में रहती है, लेकिन इन राज्यों को कुल विदेशी निवेश का 35 प्रतिशत प्राप्त होता है। इन राज्यों ने देश के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक विकास किया है और जहां 1993 में ये राज्य देश की जीडीपी का 24 प्रतिशत उत्पन्न करते थे, वहीं अब यह बढ़कर 31 प्रतिशत हो गया है।

हाल ही में लंदन से प्रकाशित 'द इकोनॉमिस्ट' नाम की एक पत्रिका ने एक बेहद शरारती लेख के जरिये उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजन की नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश की है। पत्रिका यह दावा करने की कोशिश करती है कि दक्षिण भारतीय राज्य आर्थिक दृष्टि से शेष भारत से अलग हैं, क्योंकि भारत की केवल 20 प्रतिशत आबादी पांच दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में रहती है, लेकिन इन राज्यों को कुल विदेशी निवेश का 35 प्रतिशत प्राप्त होता है। इन राज्यों ने देश के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक विकास किया है और जहां 1993 में ये राज्य देश की जीडीपी का 24 प्रतिशत उत्पन्न करते थे, वहीं अब यह बढ़कर 31 प्रतिशत हो गया है। 46 प्रतिशत टेक यूनिकॉर्न दक्षिण भारत से हैं और भारत का 46 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात इन्हीं पांच दक्षिणी राज्यों से होता है। इतना ही नहीं, पत्रिका लिखती है कि 66 फीसदी आईटी सेवाओं का निर्यात भी दक्षिणी राज्यों से होता है।

कुछ एजेंडाधर्मी लोगों को छोड़ सारा विश्व जानता है कि उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक भारत एक है। यह सच है कि भारत में अलग-अलग क्षेत्रों पर अलग-अलग समय में अलग-अलग शासकों का शासन था, लेकिन पूरे भारत में रहने वाले सभी लोगों के बीच एक अटूट संबंध बना रहा, लेकिन अफसोस की बात है कि विदेशी शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा ऐसा साहित्य रचा गया और जानबूझकर इतिहास लेखन के माध्यम से झूठी कहानियां गढ़ी गईं, जिससे दक्षिण भारत के लोगों के मन में उत्तर भारत के लोगों के खिलाफ जहर भर गया। झूठा इतिहास रचा गया कि, आर्य विदेशों से आए थे और उनके क्रूर आक्रमण से द्रविड़ लोग आहत होकर दक्षिण की ओर जाने को मजबूर हुए। ऐसी स्थिति में हिंदी भाषा के प्रति शत्रुता को दक्षिणी राज्यों में, तमिलनाडु में और भी अधिक तीव्रता से बढ़ावा दिया गया। कहा जाता है कि इस झूठी कहानी की शुरूआत एक जर्मन प्राच्यविद् और भाषाशास्त्री ने की थी। आज प्रचुर मात्रा में वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि आर्य आक्रमण सिद्धांत पूरी तरह से एक मिथक, मनगढ़ंत और काल्पनिक है। भारत, अमेरिका और अन्य देशों के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में प्रकाशित शोध पत्रों के अनुसार, हड़प्पा काल के वैज्ञानिक तथ्यों के साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मध्य एशिया से आर्यों का इतने बड़े पैमाने पर प्रवास कभी नहीं हुआ। इसके अलावा कई इतिहासकारों ने भी इस झूठी कहानी को उजागर करने का काम किया है। उसके बावजूद भारत में हो रहे तेजी से विकास से ईर्ष्या करने वाले पश्चिमी दुनिया के देशों द्वारा यह एजेंडा लगातार चलाया जा रहा है। दक्षिण में हुए विकास के आंकड़ों का सहारा लेकर, पत्रिका ने शरारतपूर्ण तरीके से इस मुद्दे को राजनीति से जोड़ा और कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पास दक्षिणी राज्यों में मजबूत आधार नहीं है। पत्रिका का यह भी तर्क है कि इसलिए यह कहा जा सकता है कि वर्तमान सरकार के पास पूरे देश का जनादेश नहीं है। गौरतलब है कि जिस देश (ब्रिटेन) में

The Economist

इकोनॉमिस्ट पत्रिका प्रकाशित होती है, वहां अब तक किसी भी प्रधानमंत्री को चुनाव में पूरे देश से समान जनादेश नहीं मिला है। क्या इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री के पास पूरे देश का जनादेश नहीं है? दुनिया भर के लोकतंत्र के इतिहास में ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जब सभी क्षेत्रों से समान रूप से बहुमत वोट प्राप्त करके सरकार बनाई गई हो। इसी तरह दक्षिण भारत के कुछ नेता भी इसी प्रकार के तर्क देकर अपनी अलगाववादी राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। हम जानते हैं कि देश में कुछ भ्रष्ट नेताओं के कारण कई राज्यों का विकास बाधित हुआ, जिनमें दक्षिणी राज्य भी शामिल थे। पूर्वोत्तर के कई राज्य पूर्ववर्ती केंद्र सरकार की उपेक्षा के शिकार रहे हैं, लेकिन जम्मू-कश्मीर जैसे कई राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक संसाधन मिलते रहे। जहां तक विकास का सवाल है, देश में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले दस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल दो दक्षिण से हैं और वह भी पांचवें और छठे स्थान पर हैं और वह भी आईटी सेक्टर के कारण, जहां भारत के सभी हिस्सों से आने वाले लोग काम कर रहे हैं।

जहां हमारे देश में खाद्यान्न उपलब्ध कराने में उत्तरी राज्यों का महत्वपूर्ण योगदान है, उसी प्रकार औद्योगिक उत्पादन, विशेषकर इलेक्ट्रिक और आईटी उत्पाद उपलब्ध कराने में दक्षिणी राज्यों के योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। राजनीतिक उद्देश्यों वाले लोगों ने अब दक्षिणी राज्यों को कर धन के हस्तांतरण में भेदभाव का मुद्दा उठाकर उत्तर-दक्षिण विभाजन को एक और आयाम दे दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सहित कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं ने यह कहते हुए विरोध प्रदर्शन किया कि दक्षिणी राज्यों को केंद्रीय करों से उनके वैध हिस्से से वंचित किया गया है। उल्लेखनीय है कि कर हिस्सेदारी वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय की जाती है। 15वें वित्त आयोग की कार्यवाही के दौरान इन राज्यों ने केंद्र सरकार के समक्ष संदर्भ की शर्तों के बारे में अपनी शिकायत व्यक्त की, जिसके अनुसार वित्त आयोग को पिछले आयोग द्वारा उपयोग की जाने वाली जनसंख्या को 1971 के बजाय 2011 की जनगणना के अनुसार उपयोग करने का निर्देश दिया गया था। उनका आरोप था कि यह दक्षिणी राज्यों के ख़िलाफ़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जनसंख्या को कई अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर तरीके से नियंत्रित किया है। इन चिंताओं को दूर करने के लिए, 15वें वित्त आयोग ने जनसांख्यिकीय प्रदर्शन यानि जनसंख्या नियंत्रण को भी महत्व दिया।

इसके अलावा, केंद्रीय करों के कुल हस्तांतरण में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल की हिस्सेदारी पिछले वित्त आयोग की तुलना में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों में कमोबेश वही रही। हालांकि, कर्नाटक की हिस्सेदारी 4.71 प्रतिशत से घटकर 3.64 प्रतिशत हो गई। केरल का हिस्सा इस अवधि में में 2.5 प्रतिशत से घटकर 1.92 प्रतिशत हो गया, लेकिन केंद्रीय राजस्व में हिस्सेदारी के अलावा, इन राज्यों को महत्वपूर्ण राजस्व घाटा अनुदान भी दिया गया। आंध्र प्रदेश के मामले में यह 2021-22 से 2023-24 के लिए 30,497 करोड़ रुपये और कर्नाटक के लिए 2021-22 के लिए 1,631 करोड़ रुपये बैठता है। केरल के लिए, यह 2021-22 से 2023-24 के लिए 37,814 करोड़ रुपये और तमिलनाडु के लिए 2021-22 के लिए 2,204 करोड़ रुपये था, इसलिए आंकड़े किसी भी तरह से वित्त आयोग के कथित पूर्वाग्रह को साबित नहीं करते। हमें यह समझना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय सद्भाव के मुद्दों पर, हमें अलगाववादी बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि यह हमारे राष्ट्र की राष्ट्रीय एकता और जान कल्याण पर काफी हद तक प्रभाव डाल सकता है। अलगाववादी आवाजों पर अंकुश लगाने की जरूरत है और अलगाववादी एजेंडे में शामिल अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और मीडिया से भी सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

(लेखक डीयू में प्रोफेसर हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

सारा संसार

मैसूर महल का निर्माण 14वीं सदी में वाडयार राजाओं ने करवाया था, जबकि इसका डिजाइन प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन ने तैयार किया था। यह वाडियार महाराजाओं का निवास स्थान हुआ करता था। मैसूर पैलेस दविड़, पूर्वी और रोमन कला का अद्भुत संगम है। सलेटी पत्थरों से बना यह महल गुलाबी रंग के पत्थरों के गुंबदों से सजा है।

तन, मन, धन सब निरंकार, नहीं करना चाहिए अहंकार

संकलित
दर्शन

सद्गुरु ने ब्रह्मज्ञान प्रदान करने से पहले पांच प्रण लिए हैं। पहला प्रण है तन, मन, धन का अहंकार नहीं करना, इसे निरंकार का ही समझना है। इस प्रण को मानने से अहंकार नहीं आएगा और न ही हम में जलन-द्वेष का भाव आएगा। दूसरे प्रण में कहा कि जाति-पाति, वर्ण, आश्रम आदि का अभिमान नहीं करना। इससे भी जलन, द्वेष का भाव मनुष्य में नहीं आएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय के कारण शरीर में जो विकृतियां पैदा होती हैं और कभी-कभी जो रोग पैदा होते हैं, सभी विकार भी दूर रहेंगे। ये सभी हमारे जीवन में आनंद में रुकावट का कारण बनते हैं। कभी-कभी अकेले में निरंकार प्रभु को अपने साथ समझते हुए निरंकार प्रभु के चरणों में हाथ जोड़कर सुमरिन करें और प्रार्थना करें, हे निरंकार प्रभु अंतर्यामी, कृपा करें। मेरे सभी अवगुणों को बख्श दें और दया करें कि मेरे अंदर बुरे विचार न आएं। केवल अच्छे विचार आएं। इस शरीर से अच्छे-अच्छे कर्म हों। मेरे मुख से मधुर वाणी ही निकले। ये शरीर तेरे संतों की संगत में दौड़-दौड़ कर जाए। आप मेरे को शक्ति दें ताकि मैं संतों की बढ़-चढक़र सेवा कर पाऊं और अंतिम श्वास तक तेरे चरणों से जुड़ा रहूं। एक प्रेरणा युक्त संत के जीवन की घटना है। महान दार्शनिक और तत्त्ववेत्ता सुकरात का चेहरा बहुत कुरूप था, फिर भी वे दर्पण में बहुत बार अपना चेहरा देखते रहते थे। जब-जब सुकरात दर्पण के सामने खड़े होकर अपना चेहरा देखते, उनके शिष्य हंसने लगते किंतु सुकरात को कुछ नहीं कह पाते।

विनम्रता ही दर्शाती है मनुष्य की श्रेष्ठता व विद्वता

संकलित
प्रेरणा

सद्गुरु की शिक्षाओं के अनुरूप कार्य सुखदायी होता है। किसी मनुष्य की निंदा न करें। सबके भले में ही हमारा भला है, यही सोचें। संत महात्मा कहते हैं कि जिन व्यक्तियों का स्वभाव झगड़ालू है, क्रोधी है, मानने वाले नहीं हैं, उन पर आप क्रोध न करें। विनम्रता मनुष्य की श्रेष्ठता दर्शाती है। निरंकार प्रभु से उनका भला मांगें। जहां तक हो सके उनका भला करें। आप अपने मन पर बोझ न डालें और अपने आपको परेशान न करें। गुरसिख तो सद्गुरु के चरणों में अरदास ही करता है। क्योंकि सबका भला करने वाला निरंकार दातार है। हमारी हिम्मत नहीं कि किसी का भला कर पाएं। हमें अपने मन, बुद्धि को निरंकार प्रभु से जोडऩा है। बाकी जो प्रभु करेगा ठीक करेगा। हमें भूल कर भी किसी का बुरा नहीं मांगना है। विनम्रता से दूसरे को सुनने और अपनी बात सुनाने में आसानी होती है। बड़े ध्यान से बात सुनी व सुनाई जाती है। विनम्रता मनुष्य की श्रेष्ठता दर्शाती है। हां, कोई स्वार्थवश ऊपर से विनम्रता दिखाता है, तो वह अपने आपको धोखा देता है। इसलिए जीवन में विनम्रता अपनाना दिव्य गुण है। विनम्रता के बिन मनुष्य अभिमानी, क्रोधी लगता है। सद्विचार हैं तो मनुष्य विनम्र भी बनेगा। आप निरंतर अपने आपको निरंकार प्रभु के निकट ही अनुभव कीजिए। वो जितने आपके निकट हैं, उतने निकट तो आपके कोई भी नहीं है, यहां तक कि आपके अंग भी नहीं। आपके निकट है आपका हाथ, जहां जरूरत होती है, पहले हाथ पहुंचता है।

रिपोर्ट
डॉ. मोनिका शर्मा

खुशी मापने का दोहरा पैमाना

हाल ही में आई विश्व खुशहाली रिपोर्ट-2024 में भारत को 126वें स्थान पर रखा गया है। जीवनयापन की बेहतरी और कमतरी मापने के जाने कौन से पैमाने रहे कि हमारे देश को इस सूची में युद्ध की विभीषिका झेल रहे देशों से भी पीछे स्थान दिया गय। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि सामुदायिक जीवन में उत्सवीय मेलजोल और आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ने के कई मापदंडों पर रेखांकित करने योग्य उपलब्धियों के बावजूद इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कम कैसे है? सवाल यह भी है कि लंबे समय से अस्थिरता और आतंक का दंश झेल रहे देशों की खुशहाली किस आधार तय की गई है? ज्ञात हो कि भारतीय नागरिकों की खुशहाली को कम आंकने वाली इस सूची में युद्ध से जूझ रहे रूस और यूक्रेन की रैंकिंग काफी ऊंची है।सुखी देशों की रैंकिंग वाली इस सूची में रूस का 70वां और यूक्रेन का 92वां स्थान है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 136 से 126 तक आने और सुधार होने की बात कही गई है, पर नेपाल, चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से पीछे होना परेशान करने वाली बात है, जबकि हाल ही में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और स्त्री सुरक्षा और स्थिति के लिए समर्पित मंच सीएसडब्लू के उद्घाटन सत्र में स्वयं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने महिलाओं पर युद्धों से होने वाले असंगत प्रभाव की बात कही थी। अवसाद और तनाव के बढ़ते आंकड़ों के बीच पारिवारिक व्यवस्था मन को थामने का आधार बनी हुई है। बड़ी आबादी और विभिन्न समुदायों वाले भारतीय समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ा है, पर सांस्कृतिक भाव कायम है। यही जुड़ाव तो इन्सानों के मन को खुशी देता है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि सामुदायिक जीवन से जुड़ाव बने रहने का मनुष्य के सुख से सीधा नाता है। ध्यातव्य है कि इस बार सूचकांक में विकसित और सुविधासंपन्न जीवनशैली वाला देश अमेरिका, शीर्ष 20 देशों में भी जगह नहीं बना सका। रिपोर्ट कहती है विकास पथ अग्रसर अमेरिकी समाज में बच्चे अकेलेपन का शिकार हैं। ध्यान इस ओर भी देना होगा कि इस सूची में शीर्ष स्थान पाने वाले फिनलैंड की आबादी ही बहुत कम है। 140 से अधिक देशों का मूल्यांकन करने वाली रिपोर्ट में सामाजिक सुरक्षा, आय, स्वतन्त्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति और जीवनकाल जैसे बिन्दुओं पर देशों की खुशहाली का आकलन किया जाता है। मानव मन और जीवन की बेहतरी से जुड़े इन मानकों पर स्थितियों को आंकने वाली इस सूची में पाकिस्तान 108वें स्थान पर हैं। व्यावहारिक रूप से आर्थिक बदहाली और कर्ज के बोझ तले दबे हमारे इस पड़ोसी देश के नागरिकों का भारतीयों से ज्यादा खुशहाल होना समझ से परे लगता है। निस्संदेह, नागरिकों की ख़ुशी के बिना आर्थिक विकास और समृद्धि के सारे मापदंड अर्थहीन लगते हैं, पर भारत में बेहतरी के प्रयास हर पक्ष पर जारी हैं। रेखांकित करने बात यह भी है कि भारत का सामाजिक-पारिवारिक मानस आज भी साझे सुखद को जीने और सद्भाव को सींचने का भाव लिए हैं। यह किसी भी समाज के सुखी होने के लिए सबसे जरूरी है।

(लेखिका फ्रीलांसर हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

इफ्तार

अजमेर में गुरुवार को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह में रमजान के पवित्र महीने के दौरान मुसलमान इफ्तार में शामिल होते हैं।

आज की पाती

चुनाव के समय अभद्र भाषा का प्रयोग अशोभनीय

देश में आम चुनाव का मौसम है। राजनीतिक दल मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन कुछ राजनेता अभद्र, बेतुकी बयानबाजी भी इस दौरान करते हैं। हाल ही में कंगना रनौत और ममता बनर्जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ, वो मामला सुर्खियों में है। हिमाचल प्रदेश में सुप्रिया श्रीनेत, जो कि कांग्रेस से संबंधित हैं, द्वारा कंगना रनौत पर जो भद्दी टिप्पणी का मामला सामने आया है, उसके लिए सुप्रिया श्रीनेत ने स्पष्ट किया है कि यह टिप्पणी उनके द्वारा नहीं कि गई है।

-राजेश कुमार चौहान, रायपुर

करंट अफेयर

'ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका न लांघे अपनी सीमा'

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने अमेरिकी समकक्ष जो बाइडन से फोन पर बात की थी, जो पिछले नंबर में सैन फ्रांसिस्को में उनके ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली बातचीत थी। बाइडन को बातचीत के दौरान जिनपिंग ने कहा कि ताइवान पहली लाल रेखा है, जिसे अमेरिका द्वारा पार नहीं किया जाना चाहिए, साथ ही टो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि चीन हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा। हालांकि व्हाइट हाउस ने 1 घंटे 45 मिनट की बातचीत को कई मुद्दों पर स्पष्ट और रचनात्मक बताया है। जारी बयान के मुताबिक, बाइडन ने ताइवान जलडमरूमध्य में शांति और स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। साथ ही रूस के रक्षा उद्योग के लिए चीन के समर्थन पर भी चिंता जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने दक्षिण चीन सागर में कानून के शासन और नेविगेशन की स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया। चीन के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि दोनों नेताओं के बीच स्पष्ट और गहन बातचीत हुई। मंत्रालय ने कहा कि शी जिनपिंग ने अमेरिका-चीन संबंधों को स्थिर होने की शुरुआत बताया। दोनों पक्षों से ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि, ताइवान पर चीन का बयान सामने आया है। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी स्व-शासित लोकतंत्र को अपने क्षेत्र के रूप में दावा करती है और यदि

ऑफ बीट

सूर्य ग्रहण में दान करें इनमें से कोई भी एक चीज

साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को लगने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण को बेहद महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से कई तरह के परिवर्तन देश-दुनिया में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही इस दिन आप भी कुछ चीजों का दान करके और कुछ आसान उपाय करके अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। गेहूं: सूर्य ग्रहण के दिन गेहूं का दान करने से करियर से जुड़ी समस्याओं का अंत होता है। करियर में आ रही सभी रुकावटों को दूर करने के लिए आप ये उपाय आजमा सकते हैं। चना: अगर घर में सुख-समृद्धि की कामना करते हैं तो सूर्य ग्रहण पर चना दान करना चाहिए। इससे सूर्य के साथ ही बृहस्पति ग्रह की भी आपको कृपा प्राप्त होती है। लाल वस्त्र: सूर्य ग्रहण के दिन लाल वस्त्र दान करके आप सूर्य की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और सफलता के द्वारा आपके लिए खुलते हैं। गुड़: गुड़ का दान करके आर्थिक स्थिति सुधरती है, अटका धन वापस मिलता है। स्वर्ण: सोने का दान करना सबके सामर्थ्य में नहीं होता लेकिन फिर भी अगर आपकी सामर्थ्य हो तो आप सूर्य ग्रहण के दिन थोड़ी मात्रा में स्वर्ण दान कर सकते हैं। इससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं हर क्षेत्र में सफलता आप पाते हैं।

ट्रेंड

कांग्रेस ने अपमान किया

एक तरफ विकास के पथ पर बिहार को तेजी से आगे ले जाने में जुटी एनडीए सरकार है, तो दूसरी तरफ वे लोग हैं, जो राज्य को लालटेन युग में ही रखना चाहते हैं। कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार और बिहारी गौरव का हमेशा अपमान किया है। इसके एक नहीं, अनेक उदाहरण हैं(

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या

आगे कोई पूछे कि इस समय इस देश के सामने सबसे बड़ी क्या समस्या है, तो बिना झिझके बोलना होगा बेरोज़गारी। बेरोज़गारी सबसे भयावह समस्या है और अब सिर्फ़ सिंपल ग्रेजुएट ही नहीं, आईआईटी जैसे संस्थान भी बेरोज़गारी से अछूते नहीं।

-सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस नेता

मेरी पीढ़ी को फायदा

नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाले उदारीकरण कार्यक्रमों से मेरी पीढ़ी को अत्यधिक लाभ हुआ। उन लाभों ने आत्मविश्वास के स्तर को बदल दिया और इस प्रतिभाशाली, आत्मविश्वास से भरी युवा पीढ़ी को जन्म दिया जो भारत को उस चीज़ से आगे ले जा रही है।

-हर्षा भोगले, क्रिकेट एक्सपर्ट

मोदी के भारत में विकास

पीएम मोदी के भारत में ये हो रहा है- 2014 के बाद से शेयर बाजार का बाजार तीन गुना बढ़ गया है। अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना हो गया है। शेयरों में निवेश करने वालों की संख्या 2% से बढ़कर 5% हो गई है।

-हर्ष गोयनका, उद्योगपति

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से **aapkepatra.haribhoomi@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid